

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

अंक संख्या 13



भारतीय रिज़र्व बैंक
जून 2016

©भारतीय रिज़र्व बैंक

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है, बशर्ते स्रोत को दर्शाया जाए।

यह प्रकाशन इंटरनेट में <http://www.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

कृपया इसके संबंध में प्रतिक्रिया fsu@rbi.org.in को भेजें।

वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई 400 001 द्वारा प्रकाशित तथा अल्को कॉर्पोरेशन, गाला सं. ए-25, ए विंग, तल मंज़िल, वीरवानी इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, गोरेगांव पूर्व, मुंबई-400 063 द्वारा अभिकल्पित एवं मुद्रित।

प्रस्तावना

विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की बहाली की स्थिति कमजोर और असमान है। कुछ भागों में अवस्फीति का दवाब है तथा कुछ क्षेत्राधिकारों में मौद्रिक नीति के रुझान की दिशा के बदलने की संभावना के कारण अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनैतिक जोखिम भी बढ़ता जा रहा है।

इस चुनौतिपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में नीति-निर्माण के दौरान ऐसे निर्णय लिये जा सकते हैं जिनसे अन्य देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। यद्यपि, भारत ने अपेक्षाकृत अधिक मजबूत वृद्धि दर्ज करते हुए मूलभूत आर्थिक सुधार किए हैं, हमें ठोस घरेलू नीतियों तथा संरचनागत सुधार के मार्ग पर डटे रहने की जरूरत है। हमें उन पारंपरिक मुद्दों का समाधान करना है जिनके कारण वृद्धि अवरुद्ध हो रही है तथा अपनी कारोबारी प्रक्रियाओं और आचरण की दक्षता में वृद्धि हेतु परिवर्तन करने हैं। बैंकिंग क्षेत्र पर पड़ रहे दवाब को कम करने की जरूरत है क्योंकि यह कॉरपोरेट क्षेत्र पर पड़ रहे दबाव को दर्शाता है। ऋण वृद्धि को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है।

घरेलू वित्तीय प्रणाली के बदलते फ्रेमवर्क में दक्षतापूर्ण जोखिम विभाजन और मध्यस्थता के साथ-साथ मौद्रिक नीति के संकेतों के प्रभावी संप्रेषण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का यह अंक “बैंक बनाम बाजार” पर विषय आधारित चर्चा को स्थान देता है क्योंकि हम वित्तीय क्षेत्र के लिए ऐसी संरचना स्थापित करने की ओर बढ़ रहे हैं जो संपदा क्षेत्र के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा।

इस परिप्रेक्ष्य में, यह रिपोर्ट घरेलू वित्तीय प्रणाली के सामर्थ्य, कमजोरी और लचीलेपन के संबंध में गुणात्मक व मात्रात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है, इसके अलावा कुछ प्रासंगिक मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया है।

रघुराम जी. राजन

गवर्नर

23 जून 2016

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	
चयनित संक्षिप्ताक्षरों की सूची	i-iii
विहंगावलोकन	1
अध्याय I : समष्टि-वित्तीय जोखिम	3-20
वैश्विक पृष्ठभूमि	3
घरेलू अर्थव्यवस्था	8
कॉरपोरेट क्षेत्र	14
अध्याय II : वित्तीय संस्थाएं: सुदृढ़ता और लचीलापन	21-48
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	21
निष्पादन	21
जोखिम	29
लचीलापन - दबाव परीक्षण	29
अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	41
निष्पादन	41
लचीलापन - दबाव परीक्षण	41
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	42
निष्पादन	42
लचीलापन - दबाव परीक्षण	43
परस्पर संबद्धता	43
अध्याय III : वित्तीय क्षेत्र विनियमन	49-76
भाग I: वित्तीय प्रणाली हेतु अधिकतम उपयोग संरचना- बैंक बनाम बाजार	49
भाग II: भारत में वित्तीय क्षेत्र - विनियमन और विकास	57
अंतरराष्ट्रीय विनियामक सुधार कार्यसूची	57
घरेलू वित्तीय प्रणाली	58
बैंकिंग क्षेत्र	58
वित्तीय समावेशन	63
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	64
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	65
पूँजी बाजार	67
कृषि पण्य बाजार	71
पण्य डेरिवेटिव बाजार	72
बीमा क्षेत्र	74
पेंशन क्षेत्र	74
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद	76
अनुबंध 1: प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण	77
अनुबंध 2: कार्यप्रणालियाँ	81

बाँकसों की सूची

1.1	ऋणात्मक नीतिगत दरें - वित्तीय स्थिरता के मुद्दे	5
1.2	नैतिक संकट एवं नैतिकता	12
2.1	बैंकिंग क्षेत्र में दबाव - सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपाय	25
3.1	प्रौद्योगिकी : सकारात्मकता और नकारात्मकता की सहमूर्ति	53
3.1	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016	60
3.2	ऋण गारंटी योजनाओं का विनियमन	63
3.3	वित्तीय समावेशन संबंधी मध्यावधि मार्ग पर बनी समिति की प्रमुख सिफारिशें	64

चार्ट की सूची

1.1	वैश्विक संवृद्धि का परिदृश्य और यूएस के लिए समष्टि संकेतक	3
1.2	सोने और ब्रेंट कच्चा तेल की कीमतों की प्रवृत्ति, पण्यवस्तु और यूएसडी सूचकांक	4
1.3	फेड ब्याज दरों की अंतर्निहित प्रायिकता की ऐतिहासिक प्रवृत्ति	4
1.4	मुद्रास्फीति की 10 वर्षीय ब्रेक-ईवन दरों की प्रवृत्ति	6
1.5	यूएस में इक्विटी और गृह मूल्य सूचकांकों तथा मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति	6
1.6	उभरते बाज़ार बॉण्ड और मुद्रा सूचकांकों की प्रवृत्ति	7
1.7	विश्व व्यापार और अमेरिकी डॉलर की प्रवृत्ति	7
1.8	वैश्विक चालू खाते में संतुलन और सकल पूंजी प्रवाह	7
1.9	वास्तविक जीडीपी की वृद्धि की प्रवृत्ति एवं बाजार कीमत पर जीडीपी की संरचना	8
1.10	क्षमता उपयोग एवं औद्योगिक उत्पादन	8
1.11	व्यावसायिक क्रियाकलाप की सूचक प्रवृत्ति एवं बचत की संरचना	9
1.12	केंद्रीय सरकार के राजस्व एवं व्यय	9
1.13	बड़ी सव्ब्सिडियों एवं कुल सव्ब्सिडियों में प्रवृत्ति	9
1.14	बाह्य क्षेत्र इंडीकेटर, कच्चे तेल की कीमतें एवं व्यापार घाटा	10
1.15	कच्चे तेल की कीमतें एवं निजी अंतरण	10
1.16	वर्षा, कृषि में वृद्धि, खाद्य पदार्थ का उत्पादन एवं मुद्रास्फीति	11
1.17	कृषि क्षेत्र को बैंक ऋण	11
1.18	स्टॉक सूचकांकों की प्रवृत्ति	13
1.19	घर कीमतों की प्रवृत्ति	13
1.20	एनजीएनएफ सूचीबद्ध कंपनियाँ: कमजोर कंपनियाँ - वर्तमान प्रवृत्ति	15
1.21	चुनिंदा उद्योगों का जोखिम प्रोफाइल (मार्च 2016)	15
1.22	कारपोरेट क्षेत्र स्थिरता संकेतक और मानचित्र	16

	पृष्ठ सं.
1.23 कारपोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन के संकेतक: आकार के अनुसार वर्गीकरण	17
1.24 कारपोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन के संकेतक: चुनिंदा उद्योग : 2014-15	17
1.25 एनजीएनएफ कमजोर कंपनियां	18
1.26 एनजीएनएफ कमजोर कंपनियां: चुनिंदा उद्योग : 2014-15	19
2.1 ऋण और जमाराशि में वृद्धि: वर्ष-दर-वर्ष आधार पर	21
2.2 पूंजी पर्याप्तता और लीवरेज अनुपात	22
2.3 आरडब्ल्यूए डेंसिटी	22
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	23
2.5 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का एनएनपीए	23
2.6 जीएनपीए की वर्ष दर वर्ष वृद्धि	23
2.7 आस्ति गुणवत्ता की संभाव्यता घनत्व कार्यप्रणाली	24
2.8 बड़े क्षेत्रों में आस्ति गुणवत्ता	24
2.9 उद्योग के बड़े उप-क्षेत्रों का दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात	24
2.10 मानक खातों का एनपीए श्रेणी में वार्षिक स्लीपेज़ - क्षेत्रवार	25
2.11 मानक खातों का एनपीए श्रेणीमें वार्षिक स्लीपेज़ - ऋण के आकार के अनुसार	26
2.12 एससीबी के ऋण पोर्टफोलियो में बड़े उधारकर्ताओं का हिस्सा	26
2.13 सितंबर-15 और मार्च-16 के बीच बड़े उधारकर्ताओं की आस्ति गुणवत्ता के प्रतिशत में बदलाव	27
2.14 बड़े उधारकर्ताओं का जीएनपीए तथा एसएमए-2	27
2.15 आय के साधन: वर्ष दर वर्ष वृद्धि	28
2.16 आरओए (वार्षिक) पर आधारित एससीबी का वितरण	28
2.17 आरओए की संभाव्यता सघनता कार्यप्रणाली	29
2.18 बैंकिंग स्थिरता संकेतक	29
2.19 बैंकिंग स्थिरता मानचित्र	29
2.20 एसबीसी के प्रणालीगत स्तर पर जीएनपीए अनुपात तथा सीआरएआर का अनुमान	30
2.21 बैंक समूहवार जीएनपीए अनुपात एवं सीआरएआर का अनुमान	31
2.22 विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत अनुमानित क्षेत्रगत जीएनपीए	31
2.23 ऋण जोखिम- आघात और असर	32
2.24 सीआरएआर के अनुसार बैंकों का वितरण	32
2.25 ऋण संकेंद्रण जोखिम: वैयक्तिक उधारकर्ता- एकसपोजर	33
2.26 ऋण संकेंद्रण जोखिम: वैयक्तिक उधारकर्ता- दबावग्रस्त अग्रिम	34
2.27 बाटम-अप दबाव परीक्षण - ऋण एवं बाजार जोखिम - सीआरएआर पर प्रभाव	39

2.28	बॉटम अप दबाव परीक्षण - तरलता जोखिम	40
2.29	कुल डेरिवेटिव के एमटीएम - चुनिंदा बैंक - मार्च 2016	40
2.30	दबाव परीक्षण-चुनिंदा बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर आघातों का असर	41
2.31	एनबीएफसी क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता	42
2.32	अंतर बैंक बाजार का आकार (टर्नओवर)	43
2.33	अंतरबैंक बाजार में विभिन्न बैंक समूहों का हिस्सा	44
2.34	अंतरबैंक बाजार में निधि आधारित दीर्घावधि तथा अल्पावधि एक्सपोजरका हिस्सा	44
2.35	अल्पावधि निधि आधारित अंतरबैंक बाजार की संरचना	44
2.36	भारतीय बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना (मार्च 2016)	45
2.37	बैंकिंग प्रणाली की संबद्धता सांख्यिकी	45
2.38	वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क प्लॉट	46
2.39	उसी ट्रिगर बैंक से प्रभावित बैंक	48
3.1	बैंकों और गैर बैंक स्रोतों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों का प्रवाह	55
3.1	प्रमुख वैश्विक बैंकों की पूंजी अनुपात और जोखिम -भारित आस्तियों की प्रवृत्तियाँ	57
3.2	बाज़ार सूचकांक से संबंधित बैंकिंग सूचकांक में प्रवृत्तियाँ	59
3.3	कुल बैंक अग्रिमों में लघु उद्योगों को ऋण का हिस्सा	62
3.4	बैंकों के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में प्रगति	64
3.5	भुगतान प्रणाली संकेतक	65
3.6	आई एम पी एस की मात्रा में वृद्धि	66
3.7	ईक्विटी और डेट पब्लिक इश्यू में प्रवृत्ति	67
3.8	प्राथमिक बाजार गतिविधि	67
3.9	कॉरपोरेट कार्पोरेट बॉन्ड इश्यू	67
3.10	कुल टर्नओवर में शीर्ष स्टार्कों और सदस्यों का शेयर	68
3.11	एनएसई में एलगोरिथमिक आर्डर और कुल ट्रेड का अनुपात	68
3.12	बी-15 शहरों के म्यूचुअल फंड परिसंपत्तियों का शेयर	69
3.13	ऋण म्यूचुअल फंडों का एयूएम और कारपोरेट बांड में एक्सपोजर	70
3.14	एनएसई निफ्टी कंपनियों के स्वामित्व का पैटर्न	70
3.15	एनएसई में सूचीबद्ध शीर्ष की कंपनियों के प्रोमोटरों द्वारा गिरवी रखे गये शेयरों का अनुपात	70
3.16	ऑफसोर डेरिवेटिव लिखत और एफपीआई का एयूसी	71
3.17	कृषि पण्य डेरिवेटिव में ट्रेडिंग की मात्रा	72
3.18	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदान की प्रवृत्ति और एयूएम	74

सारणियों की सूची

1.1	सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियों के कार्य निष्पादन के चुनिंदा वित्तीय अनुपात	14
1.2	सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियाँ : कॉरपोरेट लीवरेज में समान्यतर जोखिम	14
1.3	एनजीएनएफ कंपनियों द्वारा बैंक ऋणों की कर्ज चुकौती क्षमता में कमजोरी का प्रभाव	19
2.1	एससीबी का बड़े उधारकर्ताओं के प्रति एक्सपोजर	27
2.2	एससीबी की लाभप्रदता	28
2.3	समष्टि आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत मान्यताएँ (2016-17)	30
2.4	ऋण संकेंद्रण जोखिम:समूह उधारकर्ता	34
2.5	क्षेत्रगत ऋण जोखिम: उद्योग -आघात एवं असर	35
2.6	क्षेत्रगत ऋण जोखिम: आधारभूत संरचना -आघात एवं असर	36
2.7	क्षेत्रगत ऋण जोखिम: चुनिंदा उद्योग	37
2.8	ब्याज दर जोखिम-बैंक समूह-आघात एवं असर	37
2.9	चलनिधि जोखिम - आघात एवं असर	38
2.10	चलनिधि जोखिम - आघात एवं असर - एलसीआर निधिप्रणाली	39
2.11	एनबीएफसी क्षेत्र का समेकित तुलन पत्र : वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)	42
2.12	एनबीएफसी क्षेत्र का वित्तीय निष्पादन (प्रतिशत)	42
2.13	इंटर सेक्टर परिसंपत्तियां और देनदारियां	46
2.14	बैंकों में बीमा कंपनियों और एएमसी-एमएफ के एक्सपोजर का पैटर्न (मार्च 2016)	47
2.15	एनबीएफसी में एससीबी, एएमसी-एमएफ तथा बीमा कंपनियों का एक्सपोजर	47
2.16	निवल उधारकर्ता बैंकों से प्रारम्भ हुई संक्रामकता	47
2.17	निवल उधारदाता बैंकों द्वारा प्रारम्भ की गई संक्रामकता	47

चयनित संक्षिप्ताक्षरों की सूची

ईई	उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ	डीडीओएस	सेवाएँ न देने की धमकी/ बहुस्तरीय सेवा वंचन
एएफआई	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं	डीईआर	इक्विटी अनुपात की तुलना में ऋण
एएफएस	बिक्री के लिए उपलब्ध	डीआईसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
एआईएफ	वैकल्पिक निवेश निधि	डीआरटी	ऋण वसूली अधिकरण
एएमसी-एमएफ	आस्ति प्रबंधन कंपनी - म्यूचुअल फंड	ईबीआईटी	ब्याज कर से पूर्व आमदनी
एएमएल	धनशोधन निवारण	ईबीआईटीडीए	ब्याज, कर, मूल्यहास तथा परिशोधन से पूर्व आमदनी
एपीएमसी	कृषि उत्पाद बाजार समिति	ईबीपी	इलेक्ट्रॉनिक बुक कार्यप्रणाली
एक्यूआर	आस्ति गुणवत्ता समीक्षा	ईबीपीटी	प्रावधान और कर से पूर्ण आमदनी
एयूसी	संरक्षणाधीन आस्तियां	ईएमई	उभरती बाजार अर्थव्यवस्था
एयूएम	प्रबंधनाधीन आस्तियां	ईएसएमए	यूरोपियन प्रतिभूति तथा बाजार प्राधिकरण
बीसीबीएस	बैंक पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति	एफबी	विदेशी बैंक
बीसी-आईसीटी	कारोबार प्रतिनिधि - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	एफएटीएफ	वित्तीय कार्रवाई कार्य बल
बीएसबीडीए	साधारण बचत बैंक जमा	एफआईपी	वित्तीय समावेशन योजना
बीएसआई	बैंकिंग स्थिरता सूचकांक	एफआईयू	वित्तीय इंटेलिजेंस इकाई
सीसीआईएल	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	एफएलसी	वित्तीय साक्षारता केंद्र
सीसीपी	केंद्रीय प्रतिपक्षी	एफपीआई	विदेशी संविभाग निवेश
सीडी	जमा प्रमाणपत्र	एफआरबीएम	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन
सीईआरएसएआई	भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री	एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
सीजीएफएसईएल	शैक्षणिक ऋण क्रेडिट गारंटी निधि योजना	एफएसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
सीजीएफएसएसडी	कौशल विकास ऋण गारंटी निधि योजना	जी2पी	सरकार से व्यक्ति
सीजीटीएमएसई	सूक्ष्म और लघु उद्योग ऋण गारंटी योजना	जीसीसी	सामान्य क्रेडिट कार्ड
सीपी	वाणिज्यिक पत्र	जीएफसी	वैश्विक वित्तीय संकट
सीआरएआर	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात	जीएनपीए	सकल अनर्जक आस्तियां
सीआरजीएफटी-एलआईएच	निम्न आय वर्ग आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि	एचएफटी	व्यापार के लिए धारित
सीआरआईएलसी	बड़े ऋणों के संबंध में सूचना का केंद्रीय भंडार	एचक्यूएलए	उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां
सीआरआर	प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात	एचटीएम	परिपक्वता तक धारित
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय	आईएबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता
		आईसीएमए	अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ
		आईसीआर	ब्याज कवरेज अनुपात

आईईए	अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी	एनएनपीए	निवल अनर्जक अग्रिम
आईआईपी	औद्योगिकी उत्पादन का सूचकांक	एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	एनपीएस	अनर्जक अग्रिम
आईएमपीएस	तत्काल भुगतान सेवा	ओडीआई	सीमा पार डेरिवेटिव लिखत
आईएनडीसी	लक्षीभूत राष्ट्रीय निर्धारित योगदान	पीएटी	कर पश्चात लाभ
आईआरडीएआई	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	पीबी	भुगतान बैंक
जेएलएफ	संयुक्त उधारदाता मंच	पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड	पीएमजेडीवाई	प्रधानमंत्री जन धन योजना
केपीआई	मूल कार्यनिष्पादन सूचकांक	पीएन	सहभागिता नोट
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानों	पीपीएसी	पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण कक्ष
एलसीआर	चलनिधि कवरेज अनुपात	पीएसबी	सरकारी क्षेत्र के बैंक
एमएफआई	सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं	क्यूआईबी	अहर्ताप्राप्त संस्थागत क्रेता
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	क्यूआईपी	अहर्ताप्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	आरटीजीएस	तत्काल सकल निपटान
एनएएम	राष्ट्रीय कृषि बाजार	आरडबल्यूए	जोखिम भारित आस्तियां
एनबीएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एनसीजीटीसी	राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी	सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण	एसएफबी	लघु वित्त बैंक
एनजीएनएफ	गैर सरकारी गैर वित्तीय	एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
एनआईआईएफ	राष्ट्रीय निवेश और आधारभूत संरचना निधि	एसयूसीबी	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
एनआईआरपी	ऋणात्मक ब्याज दर नीति	टीआरडीडीएस	व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली
		यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
		यूपीआई	एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

समष्टि-वित्तीय जोखिम

वैश्विक अर्थव्यवस्था और बाज़ार

कमज़ोर व विषम संवृद्धि, विश्व व्यापार में सुस्ती तथा वित्तीय व पण्यवस्तु बाज़ारों में अनिश्चितताओं के चलते वैश्विक सुधार संकट के दौर से गुजर रहा है। साथ ही, कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही मौजूदा अति-सहज मौद्रिक नीति के अवांछित दुष्प्रभाव दिखाई पड़ रहे हैं, यहां तक कि संवृद्धि को गति प्रदान करने में उनके कारगर रहने के संबंध में अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके अलावा, निकास कार्यनीति का कोई स्पष्ट संकेत दिखाई नहीं देने की वजह से इस बात को लेकर चिंता और बढ़ रही है कि ऐसी नीतियां कब तक जारी रहेंगी।

घरेलू अर्थव्यवस्था और बाज़ार

वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था संवृद्धि और निवेश की संभावनाओं की दृष्टि से अन्य उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति में है। तथापि, संवृद्धि के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए सकल नियत पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ खपत के प्रति कारगर रुख रखना ज़रूरी है। जहां राजकोषीय अनुशासन के पथ पर अग्रसर होने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता तो बरकरार है, वहीं राजस्व घाटे को काबू में रखने और सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के प्रति किए जा रहे प्रयासों को और बल देना ज़रूरी है। जहां तक भारत के बाह्य क्षेत्र का प्रश्न है उससे अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति के संकेत मिल रहे हैं। तथापि, मात्रा की दृष्टि से बात करें तो भारत के तेल आयात में तेजी से वृद्धि दर्ज हुई है, जिससे पण्यवस्तु चक्र के प्रत्यावर्तन के जोखिमों के प्रति सजग रहना ज़रूरी हो गया है।

चूंकि 2016-17 का मॉनसून सामान्य होने का अनुमान जताया गया है, अतः कृषि क्षेत्र के लिए अनुकूल नीतिगत उपाय ज़रूरी है ताकि खाद्य-वस्तुओं के सतत मूल्यगत दबावों और समग्र ग्रामीण विपत्ति को दूर किया जा सके। 2015-16 में कॉरपोरेट क्षेत्र में विपत्ति के कम होने के आसार दिखाई पड़े, लेकिन निम्नतर मांग और कर्ज चुकौती की क्षमता में कमज़ोरी बरकरार है।

जहां तक भारत का मामला है मौजूदा अनिश्चितताओं और विश्व के अन्य देशों की गतिशीलता

के बढ़ते प्रभावों के मद्देनज़र सुस्थिर देशी नीतियां और संरचनात्मक सुधारों के पथ पर अग्रसर होना बेहद ज़रूरी हो जाता है।

वित्तीय संस्थाएं : सुदृढ़ता व लचीलापन

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक - कार्यनिष्पादन और जोखिम

मुख्य रूप से आस्ति की गुणवत्ता के और घटने तथा कम लाभप्रदता के कारण दिसंबर 2015 में प्रकाशित पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के बाद से भारत के बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम बढ़ गया है। हालांकि सितंबर 2015 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण व जमाराशि की संवृद्धि दर में भारी गिरावट दर्ज हुई थी, फिर भी सितंबर 2015 से मार्च 2016 तक की अवधि में जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के समग्र स्तर में वृद्धि दर्ज हुई। इस अवधि में जोखिम-भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के घनत्व में गिरावट आई।

मार्च 2016 में सकल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) के अनुपात का स्तर तेजी से वृद्धि दर्ज करते हुए 7.6 प्रतिशत पर पहुंच गया, जबकि सितंबर 2015 में यह 5.1 प्रतिशत था, जोकि मोटे तौर पर आस्ति की गुणवत्ता की समीक्षा (एक्यूआर) के बाद एनपीए के रूप में पुनर्संचित अग्रिमों के पुनर्वर्गीकरण का संकेत है। परिणामस्वरूप, समग्र दबावग्रस्त अग्रिमों के सितंबर 2015 के 6.2 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2016 में गिरावट दर्ज करते हुए 3.9 प्रतिशत पर पहुंच जाने के कारण समग्र दबावग्रस्त अग्रिम इसी अवधि में 11.3 प्रतिशत से मामूली बढ़ोतरी दर्ज करते हुए 11.5 प्रतिशत पर पहुंच गया।

दबाव परीक्षण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

समष्टि दबाव परीक्षणों से यह पता चला कि बेसलाइन परिदृश्य में जीएनपीए अनुपात मार्च 2016 के 7.6 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर मार्च 2017 में 8.5 प्रतिशत पर पहुंच सकता है। यदि भविष्य में समष्टि स्थिति में और गिरावट आए तो जीएनपीए अनुपात मार्च 2017 में 9.3 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। ऐसे अत्यंत दबाव की दशा में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का प्रणाली स्तरीय अनुपात मार्च 2016 के 13.2 प्रतिशत से घटकर मार्च 2017 में 11.5 प्रतिशत पर पहुंच सकता है।

शहरी सहकारी बैंक

जहां तक राज्य शहरी सहकारी बैंकों के प्रणाली स्तरीय सीआरएआरका प्रश्न है वह चरम परिदृश्य को छोड़कर न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से ऊपर बरकरार रहा। तथापि, पृथक रूप से देखें तो 52 राज्य शहरी सहकारी बैंकों में से 30 बैंक ऐसे हैं जो चरम परिदृश्य में अपेक्षित सीआरएआरस्तरों को प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दबाव परीक्षण से यह पता चला कि प्रणाली स्तरीय सीआरएआरकेवल मामूली ढंग से प्रभावित रहा और वह 15% के न्यूनतम विनियामक स्तर से काफी ऊपर रहा। तथापि, जीएनपी के 3 मानक विचलन से बढ़ने के चरम परिदृश्य में कुछ एनबीएफसी का सीआरएआर न्यूनतम अपेक्षित स्तर से कम हो सकता है।

वित्तीयक्षेत्र का विनियमन और बुनियादी संरचना

बैंकिंग क्षेत्र का विनियमन

अंतरराष्ट्रीय स्थिति की बात करें तो बैंकों की पूंजी और चलनिधि कीस्थिति में सुधार लाने संबंधी उपायों के प्रति ध्यान दिए जाने को छोड़कर नीतियों का उद्देश्य जनता में विश्वास बढ़ाना और बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा अस्थिरता को बनाए रखना था। इसके अंतर्गत पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों को अधिक महत्व दिया गया।

क्योंकि भारतीय बैंक वर्तमान में तुलन पत्र को चुस्त-दुरुस्त करने के प्रति ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अतः सरकार विपत्तिग्रस्त औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों को दूर करने के लिए अनेक उपाय कर रही है। रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को आर्थिक विकास संबंधी मुद्दों की समय रहते पहचान, व्यवहार्य आस्तियों की समय रहते पुनर्संरचना और अव्यवहार्य आस्तियों की वसूली या बिक्री करने में समर्थ बनाने के साथ साथ ऋणदाताओं को दबावग्रस्त आस्तियों की दिशा में कार्रवाई करने में सशक्त बनाने के लिए उपाय किए हैं।

प्रतिभूति और पण्य वस्तु डेरिवेटिव बाजार का विनियमन

बड़ी संख्या में सूचीबद्ध कंपनियों के शामिल होने के कारण भारतीय इक्विटी बाजार पर्याप्त रूप से विकसित हुए हैं, फिर भी इक्विटी बाजार में गतिविधियां कुछेक स्टाकों तक ही संकेंद्रित हैं और वह कुछ संस्थागत सहभागियों के दबदबे में है। जहां तक कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार का संबंध है, निजी स्थानन के आधार पर कर्ज प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए सेबी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक बही तंत्र से कार्यक्षमता में सुधार, मूल्य डिस्कवरी में पारदर्शिता के साथ-साथ ऐसे निर्गमों की लागत व समय में कटौती की संभावनाएं दिख रही हैं।

विनियामक संवेग से पण्य वस्तु डेरिवेटिव बाजार में नए उत्पाद और नए वर्ग के सहभागी आने की संभावना है जिससे चलनिधि की बेहतर स्थिति और अपेक्षाकृत अधिक कारगर मूल्य डिस्कवरी को मूर्त रूप मिलेगा। कृषि की पण्य वस्तुओं के लिए एकीकृत व समेकित राष्ट्रीय बाजार प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम) की स्थापना के लिए की गई पहल से अंतर्निहित बाजारों को कारगर बनाने और एक समान हाजिर भाव को साकार करने में मदद मिलेगी।

बीमा और पेंशन क्षेत्र

सुदृढ पुनर्बीमा कार्यक्रम प्राथमिक बीमा कंपनियों के तुलन-पत्रों को अप्रत्याशित हानियों से सुरक्षा प्रदान करेगा और जोखिम मूल्यांकन में सुधार लाएगा, तथापि, कुछ पुनर्बीमा संस्थाओं में आकस्मिक देयताओं के बढ़ते संकेंद्रण की दशा में पुनर्बीमा कंपनियों की आघात-सहनीयता का मूल्यांकन करना ज़रूरी है।

पेंशन क्षेत्र के विनियामक द्वारा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण को अपनाने हेतु उठाए गए कदम से पर्यवेक्षी संसाधनों के कुशल आबंटन को मूर्त रूप मिलने की संभावना है।

मूल्यांकन

भारतीय वित्तीय प्रणाली स्थिर रहा, भले ही बैंकिंग क्षेत्र के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं और परिवर्तनशील भू-राजनीतिक जोखिम से भारत पर असर पड़ रहा है, फिर भी सुदृढ देशी नीतियां व संरचनागत सुधार समष्टि-आर्थिक स्थिरता के लिए अहं भूमिका निभा रहे हैं।

अध्याय I

समष्टि-वित्तीय जोखिम

वैश्विक संवृद्धि की संभावनाएं मंद पड़ी हैं। कुछ क्षेत्राधिकारों में अपारंपरिक नीतिगत उपायों व ऋणात्मक ब्याज दरों के मेल के कारण वित्तीय स्थिरता जोखिमों के अवांछित परिणाम हो सकते हैं, वहीं उससे संवृद्धि को तुलनात्मक रूप से बढ़ावा नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई) उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में होने वाले नीतिगत बदलावों व जोखिम रूपों के प्रभावों से बच नहीं सकतीं, इसलिए बड़े पैमाने पर समष्टि-नीतिगत सतर्कता बरतना ज़रूरी हो गया है।

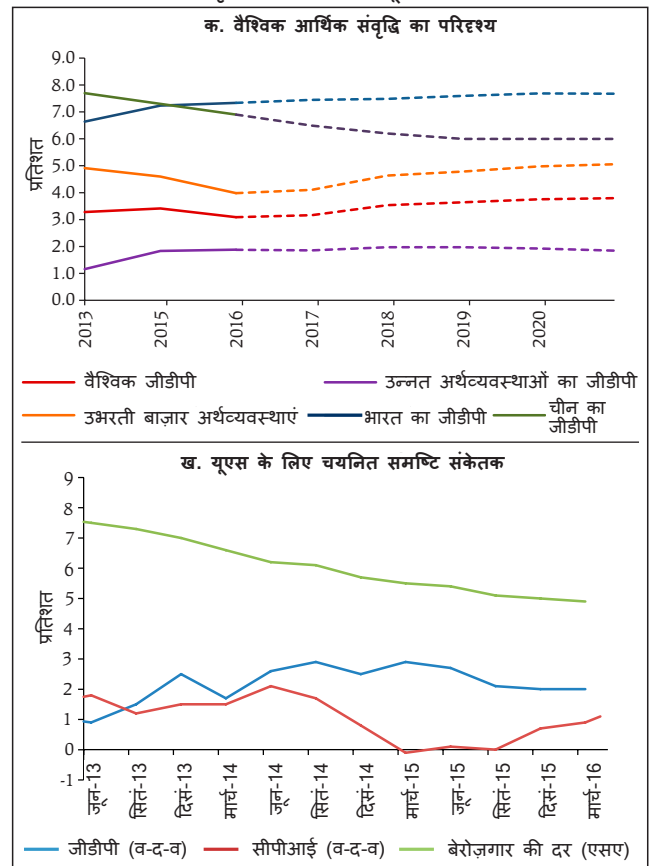
जहां तक भारत का सवाल है वह काफी व्यापार-जन्य लाभों की वजह से वर्तमान दौर में आगे है, फिर भी भविष्य में वैश्विक पण्य-वस्तु कीमतों के रुख के बदलने को ध्यान में रखना ज़रूरी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अत्यधिक क्षमता और कॉरपोरेट विपत्ति के चलते निजी निवेश प्रभावित हो रहा है। लगातार दो वर्ष सूखा पड़ने के कारण कृषि क्षेत्र के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके कारण बृहत् राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने के अलावा जीविका और मुद्रास्फीति पर भी असर पड़ता है। हालांकि इस वर्ष सामान्य मानसून होने का अनुमान जताया गया है, फिर भी अंतिम प्रभाव स्थानिक व सामयिक संवितरण पर निर्भर करेगा।

कॉरपोरेट क्षेत्र में विपत्ति 2009-10 से उच्च स्तर पर है, 2015-16 में उसमें गिरावट आने के कुछ संकेत दिखाई पड़े। इसका असर बेहतर लाभप्रदता के रूप में दिखाई दिया, लेकिन कॉरपोरेट लीवरेज के स्तर चिंताजनक है।

वैश्विक पृष्ठभूमि

1.1 कमज़ोर व विषम संवृद्धि, वैश्विक व्यापार में मंदी तथा वित्तीय व पण्य वस्तु बाज़ारों में बरकरार अनिश्चितता के कारण वैश्विक आर्थिक सुधार संकट में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2016 के लिए आकलित वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर¹ को पुनः घटाकर 3.2 प्रतिशत कर दिया है (चार्ट 1.1ए)। हालांकि 2016 की पहली तिमाही के लिए यूरो क्षेत्र में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर बाज़ार की प्रतीक्षाओं को पार कर गई, फिर भी विविध राजकोषीय परिस्थितियों और नीतिगत प्राथमिकताओं की स्थिति में एकल मौद्रिक नीति की अंतर्निहित आंतरिक विषमताओं को लेकर चिंता बरकरार है। इसी प्रकार जापान में पहली तिमाही में संवृद्धि का प्रदर्शन 0.5 प्रतिशत दर्ज करते हुए अनुमान से अधिक रहा, फिर भी अपस्फीति-जन्य दबावों के बढ़ने से औद्योगिक गतिविधि में सुस्ती कायम है। चीन में मंदी (भले ही 2016 की पहली तिमाही में मामूली सुधार दर्ज हुआ है) और आर्थिक स्थिति में भारी गिरावट वैश्विक संवृद्धि की संभावनाओं पर काफी असर कर रही है, जबकि तुलनात्मक रूप से भारत की सुदृढ संवृद्धि आवश्यक समर्थन प्रदान कर रही है। यूएस में 2016 की पहली तिमाही में दोबारा गिरावट दर्ज होना संभवतः इस बात का संकेत है कि तेजी व टिकाऊ सुधार

चार्ट 1.1 : वैश्विक संवृद्धि का परिदृश्य और यूएस के लिए समष्टि संकेतक



नोट : देश-विशेष आधार वर्षों का प्रयोग करते हुए जीडीपी (स्थिर मूल्य) में वार्षिक प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों का आईएमएफ सूचकांक; एसए का तात्पर्य मौसम के अनुसार समायोजित संख्याओं से है।

स्रोत : ब्लूमबर्ग

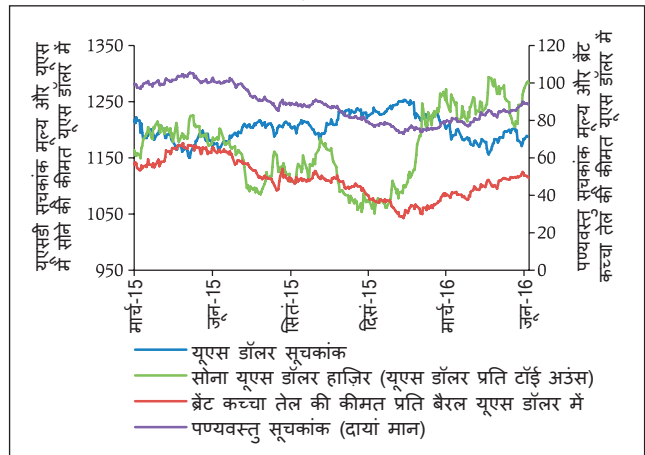
¹ आईएमएफ (2016) वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल

को हासिल करने में और समय लगने वाला है (चार्ट 1.1बी)।

1.2 कुछ उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में समष्टि-आर्थिक स्थिरता की बहाली और पण्य वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता के कुछ संकेत दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन भू-राजनीतिक परिस्थिति को लेकर रहने वाली अनिश्चितता के काले बादल निवेश के रुख पर मंडरा रहे हैं। सोने के बढ़े हुए मूल्य मौजूदा परिस्थिति में सुरक्षा की ओर संकेत कर रहे हैं और यूएस डॉलर फेड के भावी मौद्रिक नीतिगत निर्णयों की प्रत्याशाओं में परिवर्तनों को दर्शा रहा है (चार्ट 1.2)। इस बीच यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में की जाने वाली बढ़ोतरी को लेकर अनिश्चितता बरकरार है (चार्ट 1.3)।

1.3 बहरहाल, यह बता पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में नीति-निर्माता मौजूदा अति-सुलभ मौद्रिक नीति को कब तक जारी रखेंगे। किसी स्पष्ट निकास कार्यनीति के अभाव में 'इज़िंग बिगेट्स इज़िंग' और 'प्रतिस्पर्धात्मक सुलभता' (टेयलर, 2013 2015; और राजन, 2014)² वाली स्थिति पैदा हो सकती है। मिसाल के तौर पर, यूरो और जापानी यन में मूल्यवृद्धि एक अनभिप्रेत परिणाम है। यह इस संकल्पना को रेखांकित कर रहा है कि अल्पावधिक राजकोषीय व मौद्रिक उपाय

चार्ट 1.2 : सोने और ब्रेंट कच्चा तेल की कीमतों की प्रवृत्ति, पण्यवस्तु और यूएसडी सूचकांक

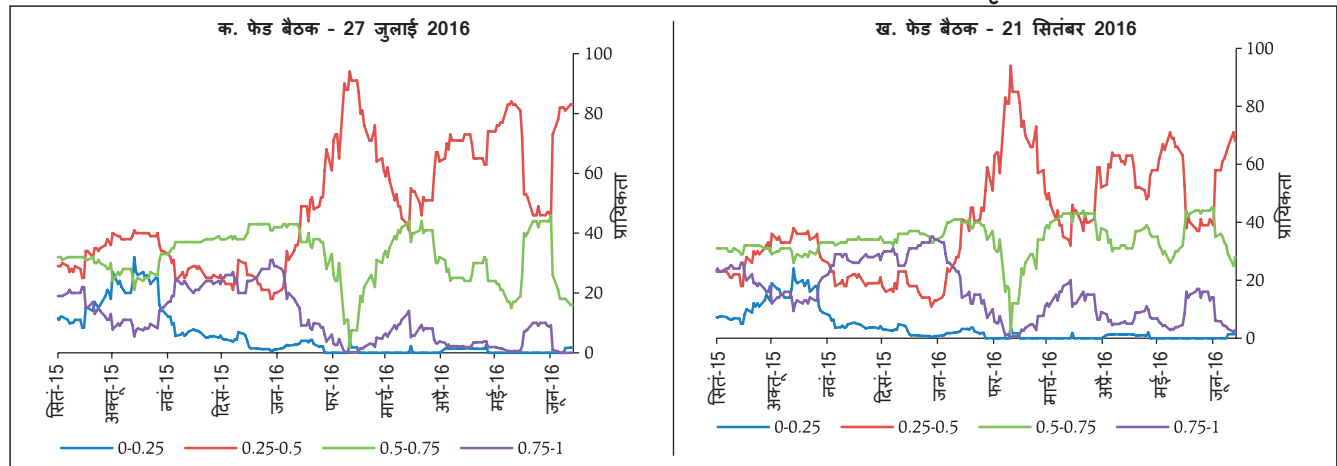


स्रोत : ब्लूमबर्ग (15 जून 2016 तक के आंकड़े)

दीर्घावधिक संरचनात्मक सुधारों व निवेश का स्थान नहीं ले सकते।

1.4 पृथक रूप से देखें तो कुछ नीतिगत उपायों का वित्तीय व आर्थिक स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव रहा है, लेकिन उनके अनभिप्रेत प्रतिकूल प्रभाव जाहिर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर, केंद्रीय बैंकों द्वारा आस्ति की खरीद किए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च गुणवत्ता वाले पेपर के बाज़ार दबदबे में आ गए। इसके अलावा, बहुत ही कम ब्याज दरें (कुछ मामलों में ऋणात्मक) संभवतः पेंशन

चार्ट 1.3 : फेड ब्याज दरों की अंतर्निहित प्रायिकता की ऐतिहासिक प्रवृत्ति[#]



नोट : अंतर्निहित प्रायिकता मूल्य ब्याज दरों के दायरों से संबंधित है जो कि प्रतिशत में हैं - लेजेंडयथानिर्देशित
स्रोत : ब्लूमबर्ग

² राजन, आर. (2014); 'प्रतिस्पर्धात्मक मौद्रिक सुलभता : क्या कल इसका दोहराव हुआ?' 10 अप्रैल: टेयलर, जे. (2013); 'अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक समन्वय और अत्यधिक विचलन', जर्नल ऑफ पॉलिसी मॉडलिंग, खंड 35, सं.3 और (2015); 'अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार', मौद्रिक नीति का पुनर्विचार पर कैटो इंस्टिट्यूट मौद्रिक सम्मेलन

निधियों³ और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में जोखिम बढ़ा रही हैं। ऐसी पॉलिसियां लोगों को खपत करने के लिए नहीं, बल्कि बचत करने के लिए लोगों को प्रेरित कर शामिल कर रही हैं और वे 'सर्च फॉर यील्ड'

वाली कार्यनीतियां अपना रही हैं। ऋणात्मक ब्याज दर नीति (एनआईआरपी) जैसे अपारंपरिक उपायों पर दीर्घकालिक निर्भरता एक अन्य संभावित वित्तीय स्थिरता का मुद्दा है (बॉक्स 1.1)। जहां तक उभरती बाज़ार

बॉक्स 1.1 : ऋणात्मक ब्याज दरें - वित्तीय स्थिरता के मुद्दे

कुछ अधिकार-क्षेत्रों, यथा- डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूरोपीय संघ (ईयू) और हाल ही में जापान में केंद्रीय बैंकों ने ऋणात्मक ब्याज दर नीति (एनआईआरपी) के अपरिचित क्षेत्र पर पदार्पण किया है, जो कि आर्थिक वृद्धि हासिल करने तथा उधार लेने और जोखित उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए अपस्फीतिकारी परिस्थितियों का सामना करने की चेष्टा है। तथापि, अब भी इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि यह नीति किन संचारण माध्यमों से काम करेगी तथा संवृद्धि व मुद्रास्फीति पर सही मायने में वस्तु क्षेत्र का प्रभाव उत्साहजनक नहीं रहा है (मौद्रिक नीति रिपोर्ट, आरबीआई, अप्रैल 2016)। साथ ही, बैंक की लाभप्रदता, आस्ति की बढ़ी हुई कीमतों, विनिमय दर के प्रभुत्व व राजकोषीय प्रभुत्व के संदर्भ में वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने रहने वाले वित्तीय स्थिरता के जोखिम महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

बैंक और वित्तीय संस्थाएं : यदि लंबे समय तक इसे जारी रखा जाए तो एनआईआरपी से तुलन-पत्र का संकुचन हो सकता है, साथ ही, इससे बैंक की लाभप्रदता उस हद बाधित हो सकती है जिस हद तक बैंक अपने जमाकर्ताओं को ऋणात्मक ब्याज दरों को पास ऑन कर पाते हैं। आम तौर पर ब्याज दरों की निश्चलता आस्ति और देयता पक्षों पर एनआईआरपी के अनुकूलन को लेकर असंतुलन पैदा करती है। जो बैंक, गैर-प्रणालीगत हैं और मोटे तौर पर रिटेल कारोबार में संलिप्त हैं, वे कॉर्पोरेट बैंकिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करने वाले बैंकों की तुलना में अधिक बाधित होते हैं, क्योंकि रिटेल ग्राहकों की तुलना में कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋणात्मक दरें पास करना आसान हो सकता है (जैक्सन, 2015)। इनमें से कुछ अर्थव्यवस्थाओं के वास्तविक आंकड़ों से यह पता चला कि अर्थव्यवस्था को पास थू सीमित था, क्योंकि बैंकों ने वैयक्तिक जमाकर्ताओं⁴ को ऋणात्मक दरें पास ऑन करना नहीं चाहा। इस बात को लेकर भी चिंता जताई गई कि बैंक केंद्रीय बैंकों से कम धनराशि उधार ले सकते हैं ताकि बेशी रिज़र्व को कम किया जा सके और ऋणात्मक जमा दर से बचाया जा सके। इससे अंतरबैंक और बाण्ड बाज़ार में दरें बढ़ाने का दबाव पैदा होगा, जिससे ऋणात्मक नीति दर का प्रेरणात्मक प्रभाव ही खत्म हो जाए (कॉयर, 2014)। जहां तक बीमा और पेंशन क्षेत्रों का मामला है, लंबे समय तक कम व ऋणात्मक दरों के रहने से इन क्षेत्रों में मौजूद संस्थाओं की व्यवहार्यता बाधित हो जाएगी तथा दीर्घ अवधि में पेंशन संवितरण की भावी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में कई चुनौतियां पैदा हो जाएंगी (जीएफएसआर, अप्रैल 2016)।

प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन और पूंजी प्रवाह : ऋणात्मक ब्याज दरों से या तो पूंजी अर्थव्यवस्था के बाहर चली जाने की

संभावना है जिससे मुद्रा का मूल्यहास होकर निर्यात की मात्रा बढ़ने और आयात की मात्रा घटाने की स्थिति पैदा हो सकती है (जो कि प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन के बराबर है) या उससे कुछ आस्तियों, जैसे आवास, की कीमतें बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण समष्टि विवेकपूर्ण उपायों का प्रयोग करने की स्थिति पैदा हो जाएगी (लिप्टन, 2016)। जब सभी देश डीलीवरेज करने में जुट जाए तब कोई स्विचिंग प्रभाव न हो तो इन मूल्यहासों का कोई वांछित वास्तविक क्षेत्र प्रभाव नहीं रह जाएगा।

राजकोषीय समेकन : ऋणात्मक ब्याज दरें ऐसे मामलों में राजकोषीय समेकन और संरचनात्मक सुधारों के प्रोत्साहन को कम कर देंगी, जहां इनकी आवश्यकता पड़ती हो। वे कर्ज सर्विसेंग क्षमता को भी कम कर देती हैं, जिसके कारण कर्ज धारणीयता की सही स्थिति का पता नहीं चलता और इससे राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा नहीं मिल सकता (हैनाउन, 2015)। चूंकि ऋणात्मक ब्याज दरों से सरकार द्वारा उधार लिया जाना आसान हो सकता है, अतः यह सुझाव दिया जाता है कि इसे कम करने के एक उपाय के रूप में राष्ट्रिक आस्तियों पर जोखिम भार लगाया जाए। अतः मौद्रिक नीति उपाय (ऋणात्मक ब्याज दरें) के एक अनभिप्रेत वित्तीय स्थिरता परिणाम को वित्तीय क्षेत्र के एक नीतिगत उपाय के माध्यम से कम किया जा रहा है जिसके कारण अत्यंत समाष्टि व मौद्रिक नीतिगत प्रभाव पैदा हो सकता है।

संदर्भ :

कॉयर, बी. (2014); 'लाइफ बिलो जीरो: लर्निंग अबाउट नेगटिव इंटरस्ट रेट्स'। ईसीबी मुद्रा बाज़ार कान्टैक्ट समूह में दिया गया भाषण।

हैनाउन, एच (2015); 'अल्ट्रा-लो ऑर नेगटिव इंटरस्ट रेट्स: वॉट दे मीन फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ', यूरोफाई उच्च स्तरीय सेमिनार, रिगा में दिया गया भाषण।

आईएमएफ (2016); *ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट*, अप्रैल।

जैक्सन एच (2015); 'द इंटरनेशनल इक्सपीरिअंस विथ नेगटिव पॉलिसी रेट्स', *स्टाफ चर्चा पत्र*, बैंक ऑफ कनाडा।

लिप्टन, डेविड (2016); 'पॉलिसी इंफ्लेक्शन फॉर बूस्टिंग ग्लोबल ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी', एनएबीई, वॉशिंगटन।

आरबीआई (2016); *मौद्रिक नीति रिपोर्ट*, अप्रैल।

³ पेंशन योजनाओं में एक प्रतिफल लक्ष्य होता है, जो कि यूएस में निजी क्षेत्र की पेंशन योजनाओं के लिए 2.5 प्रतिशत से लेकर सार्वजनिक योजनाओं के लिए 7.5 प्रतिशत के दायरे में होता है। इसका उपयोग सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को किए जाने वाले भुगतान के संबंध में भविष्य का अनुमान लगाने में किया जाता है।

⁴ आम तौर पर ब्याज दरों के अनुरूप औसत ब्याज दरों में गिरावट नहीं आई है, मुद्रा बाज़ार दरों पर उनका स्प्रेड 0.5 से 0.7 प्रतिशत अंकों के दायरे में है।

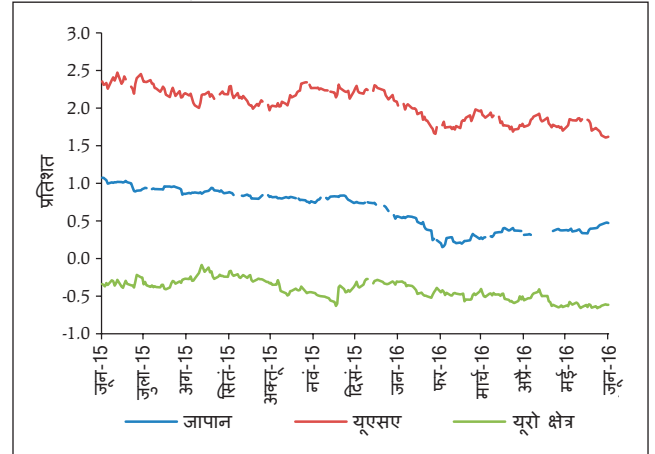
अर्थव्यवस्थाओं का प्रश्न है, इससे संभवतः विदेशी मुद्रा कर्ज और आकर्षक बनेगा, जिसके कारण वित्तीय स्थिरता को लेकर कई चुनौतियां हैं ही।

1.5 इस परिप्रेक्ष्य में एक और प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या एनआईआरपी असल में मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं को प्रेरित कर रही है, जो कि उसके अभीष्ट उद्देश्य के विपरीत है। हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति की ब्रेक-ईवन दरें अपनी उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं (चार्ट 1.4)। तथापि, बाजारों में इस बात को लेकर संदेह जताया रहा है कि अपस्फीतिकारी परिदृश्य में मुद्रास्फीति के संरक्षण-प्राप्त उत्पादों की पर्याप्त मांग नहीं रह जाएगी।

1.6 इसके अलावा, आस्तियों की बढ़ती कीमतों की परिस्थिति में निम्न या ऋणात्मक ब्याज दरों के वेल्थ प्रभाव साफ-साफ दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि निम्नतर उधार लागतों के माध्यम से सकल मांग और मुद्रास्फीति पर उनका प्रभाव स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ा है। उदाहरण के लिए, यह स्थिति यूएस के मामले में देखा जा सकता है (चार्ट 1.5)। हाल के वर्षों में अपारंपरिक मौद्रिक नीति के दीर्घकालीन प्रयोग पर अत्यधिक निर्भरता सिद्ध प्रज्ञान को लेकर भी प्रश्न खड़ा कर रही है। उदाहरण के लिए, 'वित्तीय प्रबलता, विनिमय दर प्रबलता और राजकोषीय प्रबलता की तुलना में'⁵ मौद्रिक नीति का गौण रहने का जोखिम बढ़ता रहा है। अब इस बात पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि क्या केंद्रीय बैंकों को अनुमान करने योग्य रीति से कार्य करना चाहिए और उन्हें कभी बाजारों को विस्मित नहीं करना चाहिए। अतः बाजारों को दिए जाने वाले अत्यधिक आश्वासनों के लागत-लाभों का मूल्यांकन करना ज़रूरी है।

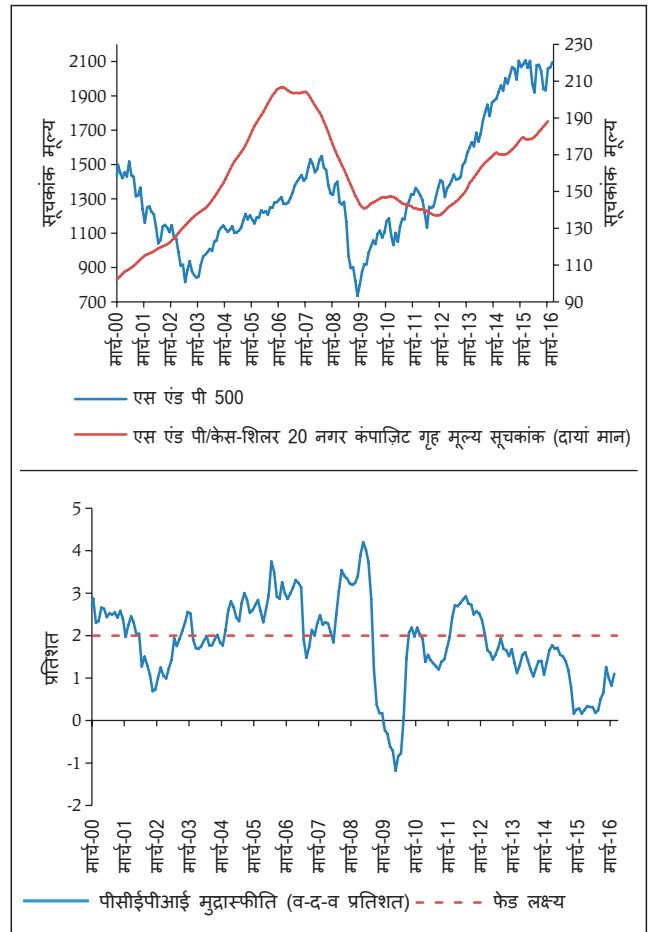
1.7 इस बीच, हाल के वर्षों में प्रमुख ईएमई मुद्राओं की मूल्य-वृद्धि और ईएमई बॉण्ड प्रतिफलों में गिरावट ने ईएमई को पूंजी प्रवाह के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। तथापि, यह देखा जाना है कि ईएमई मुद्राओं और बॉण्डों में आया सुधार कितने समय के लिए टिक पाता है

चार्ट 1.4 : मुद्रास्फीति की 10 वर्षीय ब्रेक-ईवन दरों की प्रवृत्ति



स्रोत : ब्लूमबर्ग (15 जून 2016 तक अद्यतन किए गए आंकड़े)

चार्ट 1.5 : इन्विटी और गृह मूल्य सूचकांकों तथा यूएस में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति



स्रोत : फेड रिज़र्व सेंट लूई

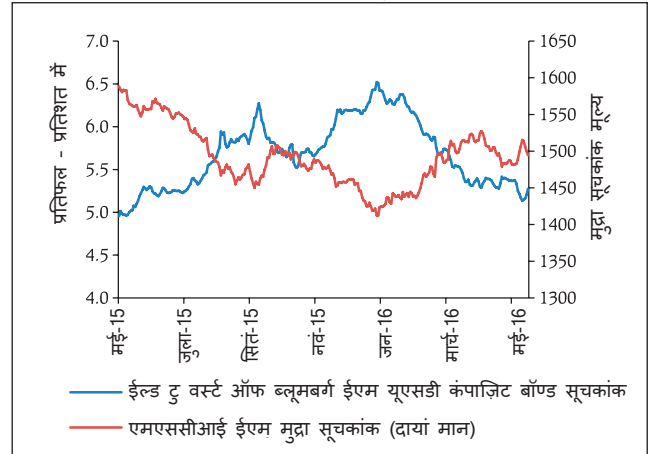
⁵ हैनाउन, (2015), 'अत्यंत कम या ऋणात्मक ब्याज दरें : वित्तीय स्थिरता और संवृद्धि में उनका कितना महत्व रखती हैं'। यूरोपी उच्च स्तरीय सेमिनार, रीगा, अप्रैल में प्रस्तुत टिप्पणी। यह <http://www.bis.org/speeches/sp150424.pdf> पर उपलब्ध है।

(चार्ट 1.6)। किंतु यह चिंता जताई जा रही है कि सुस्त वैश्विक व्यापार, मूल्य के संदर्भ में वैश्विक व्यापार में आई गिरावट यूएस डॉलर के मूल्यांकनों में परिवर्तनों को दर्शा रही है (चार्ट 1.7)।

1.8 अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली (आईएमएफएस) में यूएस डॉलर का प्रभुत्व एक और मुद्दा है, जिस पर व्यापक स्तर पर बहस हो रही है, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। आम तौर पर इस धारणा, कि यूएस को विश्व के अन्य देशों को डॉलर की चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए चालू खाता घाटा उठाना है, क्योंकि 'यूएस डॉलर की चलनिधि का निर्माण इच्छा के अनुसार किया जा सकता है, चाहे यूएस के चालू खाते की स्थिति कुछ भी हो', पर प्रश्न उठाया जा रहा है (बोरिओ और दिश्यटेट, 2015)⁶ तदनुसार, यह सुझाव दिया गया है कि 'समाधानों का उद्देश्य चालू खता असंतुलनों पर कम तथा वित्तीय असंतुलनों पर अधिक ध्यान देने पर हो' (बोरिओ, 2016)⁷ और साथ ही, निवल पूंजी प्रवाहों पर कम, बल्कि सकल पूंजी प्रवाहों पर एवं संबंधित स्टॉकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने पर हो (चार्ट 1.8)।

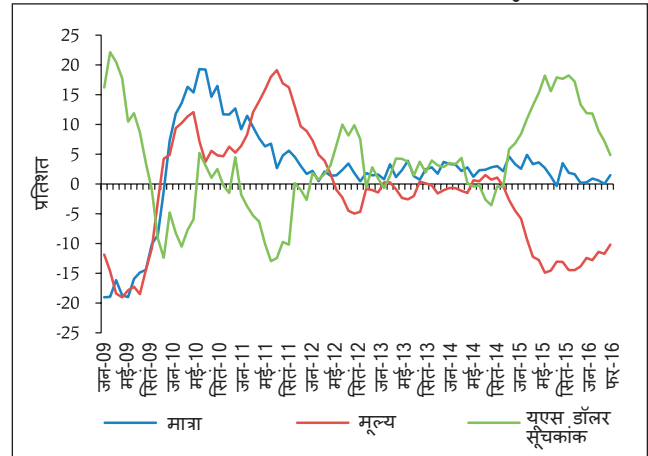
1.9 जहां तक कच्चे तेल की कीमतों का मामला है, जब कीमतों में गिरावट आती हो तो एक नए आपूर्ति-मांग संतुलन उभरकर आना चाहिए ताकि कीमतों का समायोजन हो सके। तथापि, तेल बाजार में ऐसा नहीं हो रहा है,

चार्ट 1.6 : उभरते बाजार बॉण्ड और मुद्रा सूचकांकों की प्रवृत्ति



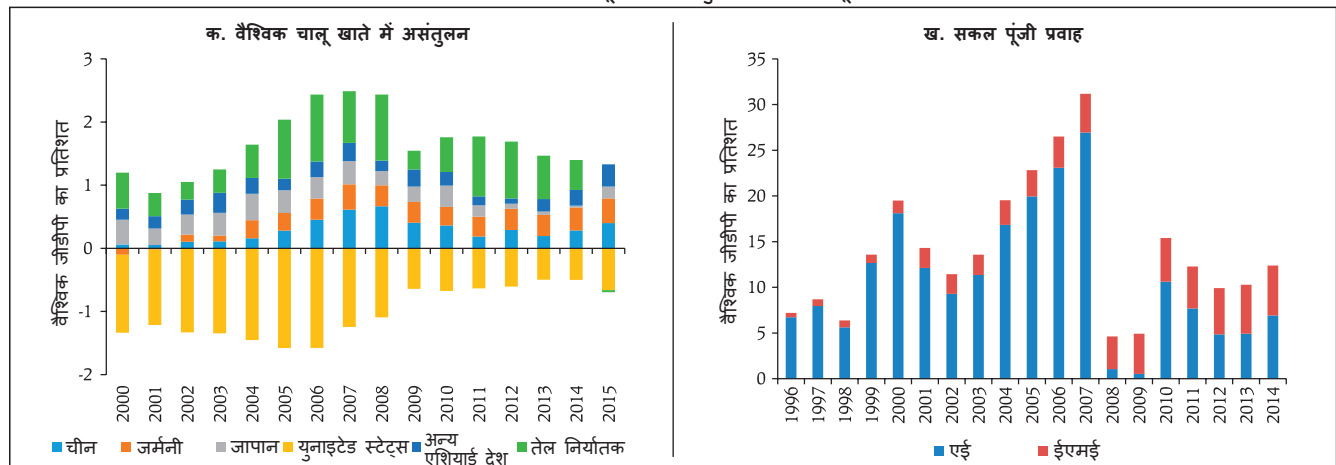
स्रोत : ब्लूमबर्ग (15 जून 2016 तक अद्यतन)

चार्ट 1.7 : विश्व व्यापार और अमेरिकी डॉलर की प्रवृत्ति



स्रोत : ब्लूमबर्ग, सीपीबी विश्व व्यापार मॉनिटर

चार्ट 1.8 : वैश्विक चालू खाते में संतुलन और सकल पूंजी प्रवाह



स्रोत : विश्व आर्थिक आउटलुक डेटाबेस और भुगतान संतुलन सांख्यिकी, आईएमएफ

⁶ बोरिओ, क्लॉडिओ और पिटी दिश्यटेट (2015), 'पूंजी प्रवाह और चालू खाता : वित्तपोषण को और (अधिक) गंभीर लेना' बीआईएस वर्किंग पेपर सं.525 अक्टूबर।

⁷ बोरिओ, क्लॉडिओ (2016), 'मोर प्लुरलिज़म, मोर स्टेबिलिटी?' जुरिच में 10 मई 2016 में आयोजित सातवें उच्च स्तरीय एसएनबी-आईएमएफ सम्मेलन में दी गई प्रस्तुति।

क्योंकि आपूर्ति पक्ष को लेकर मदभेद है, भले ही उसकी अगुवाई कार्टेल द्वारा की जाती हो। हालांकि हाले के महीनों में यूएस में शेल गैस उत्पादन में गिरावट आई है, फिर भी तेल बाजारों में समग्र गतिकी इस बात का संकेत हो सकती है कि आर्थिक औचित्य की तुलना में राजनीतिक विचार का वर्चस्व अधिक है।

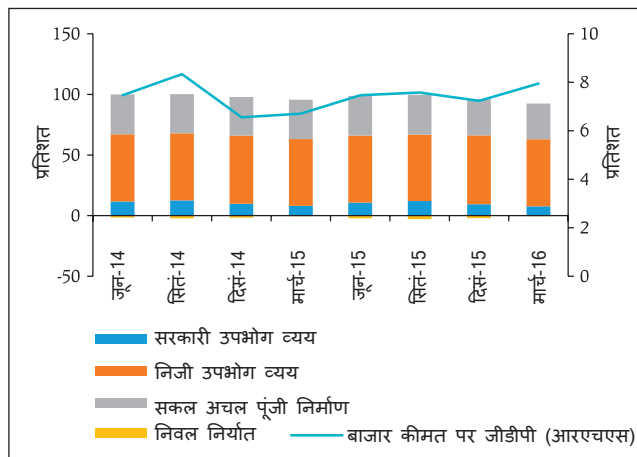
घरेलू अर्थव्यवस्था

संवृद्धि, बचत एवं निवेश

1.10 चूंकि वैश्विक अनिश्चितताएं एवं गतिकी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के अपने बढ़ते स्तर के साथ भारत को प्रभावित करते हैं, स्वस्थ घरेलू नीतियों एवं संरचनात्मक सुधारों को जारी रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक निवल पण्य आयतक होते हुए एवं 'व्यवसाय करने की सुगमता' में सुधार के प्रयासों के साथ, भारत इस मोड़ पर संवृद्धि के मामले में उभरते हुए बाजारों के साथ खड़ा है।⁸ तथापि, संवृद्धि के उच्च स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से उपभोग की सुदृढ़ प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए सकल निर्धारित पूंजी निर्माण को सहारा देने की आवश्यकता है (चार्ट 1.9)।

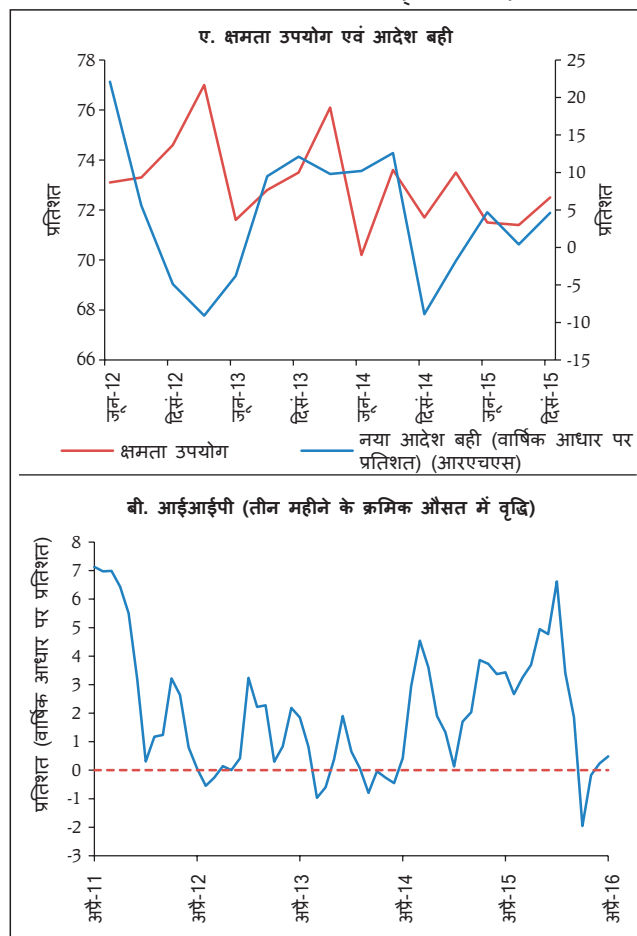
1.11 दो महीनों के दौरान कमी के बाद अप्रैल 2016 में खुदरा मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी जो आगे मई 2016 में और आगे बढ़ती गई। 2015-16 के दौरान वास्तविक सावधि निवेश की गति में कमी आई। धीमे निवेश में सुधार के मामले को का कॉरपोरेट्स को अपेक्षानुसार डिलीवरेज करने एवं बैंकिंग उद्योग के तुलन-पत्र में सुधार के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जबकि क्षमता उपयोग में कुछ सुधार हुआ है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की प्रवृत्ति एवं क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) इस तरफ इशारा करते हैं कि विनिर्माण क्रियाकलापों को और बढ़ाने की आवश्यकता है। सकल बचत दर में गिरावट यह दर्शाता है कि घरेलू (हाऊसहोल्ड) बचत में संतुलन बना हुआ है (चार्ट 1.10 एवं 1.11)।

चार्ट 1.9: वास्तविक जीडीपी की वृद्धि की प्रवृत्ति एवं बाजार कीमत पर जीडीपी की संरचना⁹



नोट: # स्टॉक, कीमती वस्तुओं एवं विसंगति में परिवर्तन को छोड़कर। कुल मिलाकर जीडीपी में निवल निर्यात का योगदान (-)2.8 से (-)0.5 रहा।
स्रोत: सीएसओ

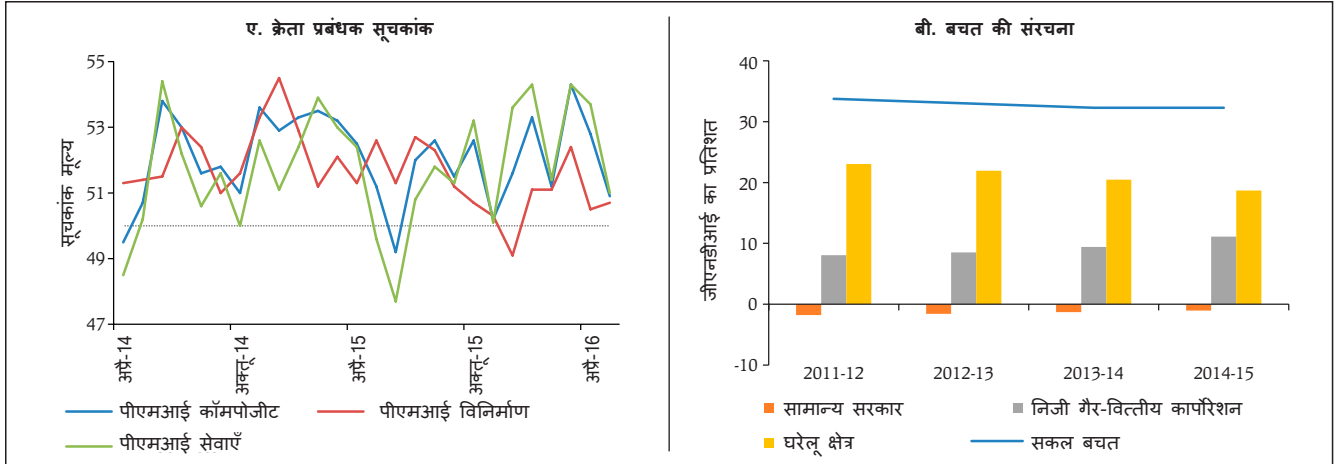
चार्ट 1.10 : क्षमता उपयोग एवं औद्योगिक उत्पादन



स्रोत : आरबीआई एवं एमओएसपीआई

⁸ विश्व बैंक समूह की 'व्यवसाय करने में आसानी' सूचकांक में भारत का स्थान 2015 के 134 से सुधरकर 2016 में 130 हो गया। यह निम्नलिखित लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है : <https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ>.

चार्ट 1.11 : व्यावसायिक क्रियाकलाप की सूचक प्रवृत्ति एवं बचत की संरचना

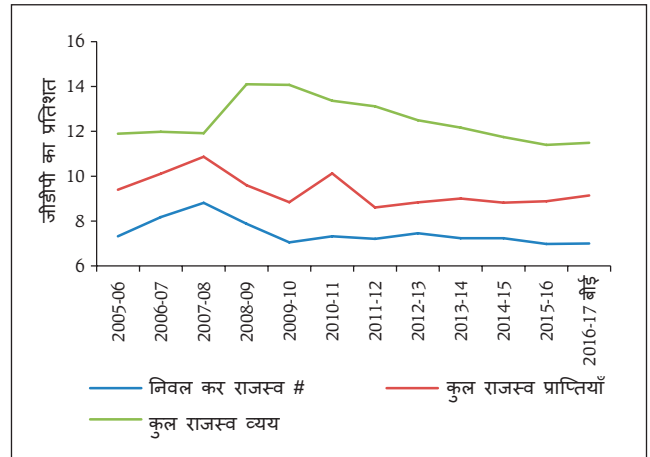


नोट: 50 से अधिक पीएमआई का अर्थ विस्तार है।
 स्रोत : एमओएसपीआई तथा ब्लूमबर्ग

राजकोषीय अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता

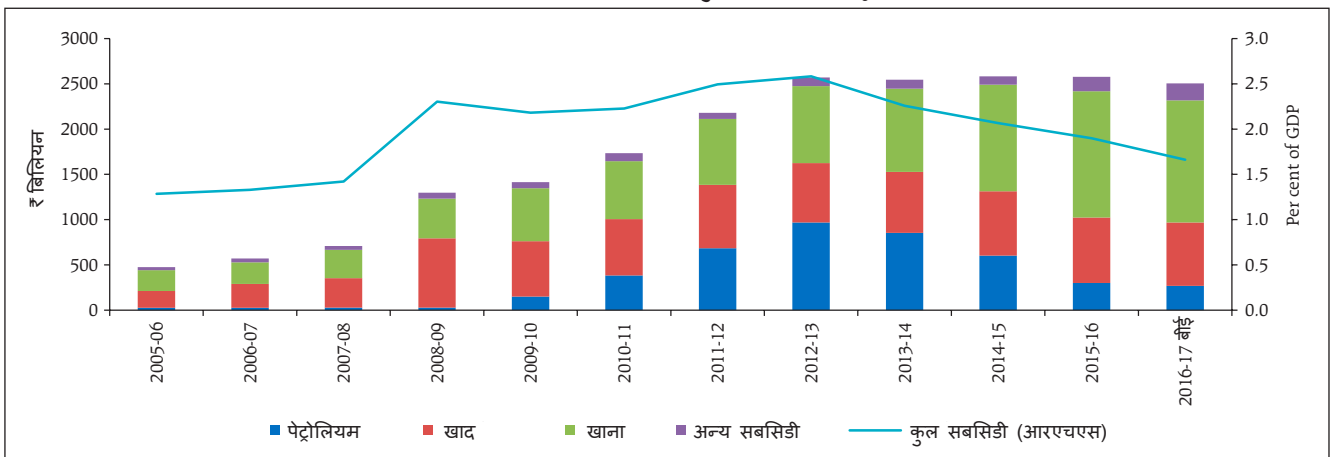
1.12 सरकार के राजकोषीय अनुशासन के प्रति झुकाव के बावजूद भी सरकार के हाल ही के यूनिबन बजट में पूंजीगत व्यय के लिए उच्चतर आबंटन किया गया। राजस्व घाटा को नियंत्रित करने एवं सब्सिडी को युक्तियुक्त बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं (चार्ट 1.12 एवं 1.13)। आगे, कर आधार का दायरा बढ़ाकर कर राजस्व को बढ़ाने की जरूरत होगी। इसी बीच भारत सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) रोडमैप की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। हाल के ही वर्ष में राजकोषीय समेकन

चार्ट 1.12 : केंद्रीय सरकार के राजस्व एवं व्यय



नोट : # राज्यों के हिस्से के समायोजन के बाद केंद्र सरकार के नेट फिगर को संदर्भित करता है।
 बीई - 2016-17 के लिए बजट अनुमान
 स्रोत : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट 1.13 : बड़ी सब्सिडियों एवं कुल सब्सिडियों में प्रवृत्ति



नोट: बीई - 2016-17 के लिए बजट अनुमान
 स्रोत: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

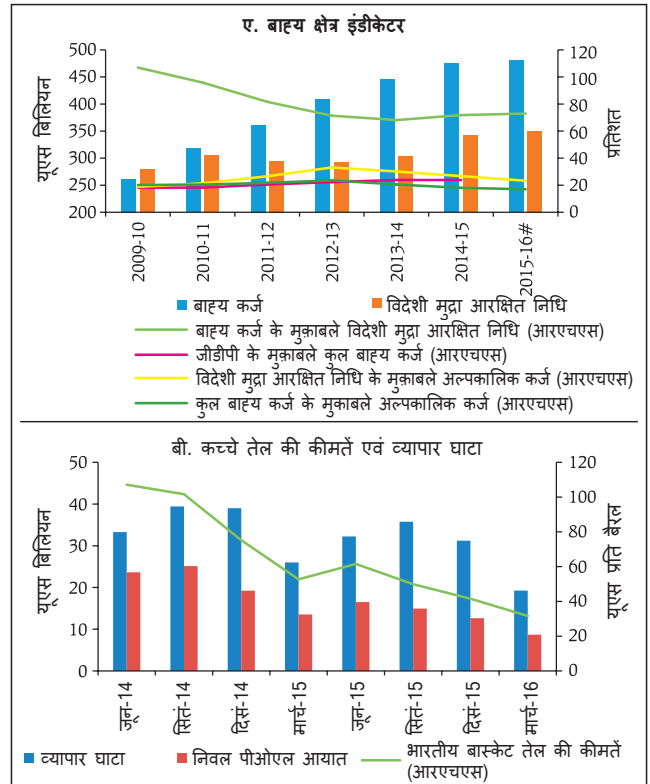
द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR)⁹ में कमी की गई है ताकि वित्तीय बाजार का विकास और किया जा सके।

पण्य कीमतों के प्रत्यावर्तन से होने वाले जोखिम

1.13 2014-15 के तीसरी तिमाही (Q3) में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट से पहले की तुलना में कम आयात से व्यापार को लाभ हुआ है और बाह्य प्रवणता (बुल्नेरिबिलिटी) में कमी हुई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार हाल ही अवधि में जी-20 के सभी देशों में से भारत के व्यवसाय लाभ को उच्चतम आंका गया है। दूसरी तरफ, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार भारत तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है एवं चाईना को पिछे छोड़ दिया है क्योंकि यह मुख्य वृद्धि बाजार है। इस संदर्भ में पण्य कीमत चक्र प्रत्यावर्तन एवं अर्थव्यवस्था के पुनःसमायोजन के लिए तैयार रहने संबंधी जोखिमों के प्रति सजग रहने की जरूरत है। पहले ही, तेल की कीमतें फरवरी 2016 से बढ़ी हुई हैं और यह 30 यूएस डालर प्रति बेरल से कम है।

1.14 अब तक भारत की बाह्य स्थिति विदेशी मुद्रा रिज़र्व की ऐतिहासिक उंचाइयों और कम व्यापार घाटा के साथ मजबूत दिखाई पड़ती है जिससे मुख्यतः कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं (चार्ट 1.14)। तथापि, लंबी अवधि तक तेल की कम कीमतों में गिरावट को प्राइवेट अंतरण और विप्रेषण से होनेवाले कमी के अनुसार गणना किए जाने की भी जरूरत है (चार्ट 1.15)। अतः वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में आत्मसंतोष के लिए कोई जगह नहीं होगी।

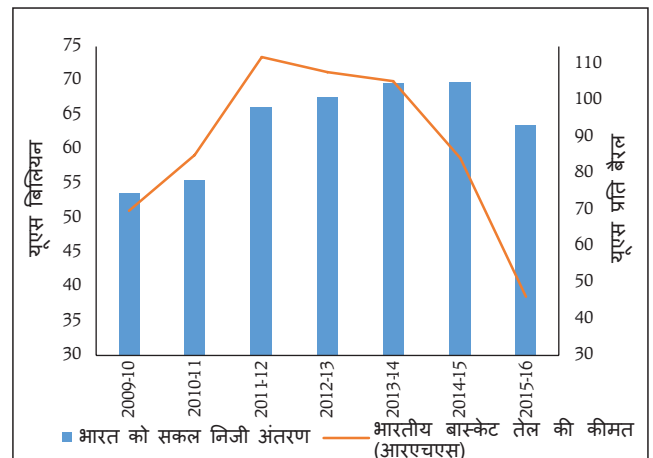
चार्ट 1.14 : बाह्य क्षेत्र इंडीकेटर, कच्चे तेल की कीमतें एवं व्यापार घाटा



नोट: #2015-16 के लिए डाटा अप्रैल से दिसंबर अंत 2015 तक की अवधि के लिए है। जीडीपी के मुकाबले कुल बाह्य कर्ज वर्ष 2015-16 के भाग के लिए नहीं तैयार किया गया है। 3 जून 2016 के अनुसार विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि यूएस डॉलर 363.5 बिलियन रहा। तेल की कीमतें उस अवधि के लिए औसत कीमतें हैं। पीओएल आयात का मतलब पेट्रोलियम, तेल एवं लुब्रिकेंट के आयात से है।

स्रोत: आरबीआई एवं पीपीएसी, पेट्रोलियम मंत्रालय

चार्ट 1.15 : कच्चे तेल की कीमतें एवं निजी अंतरण

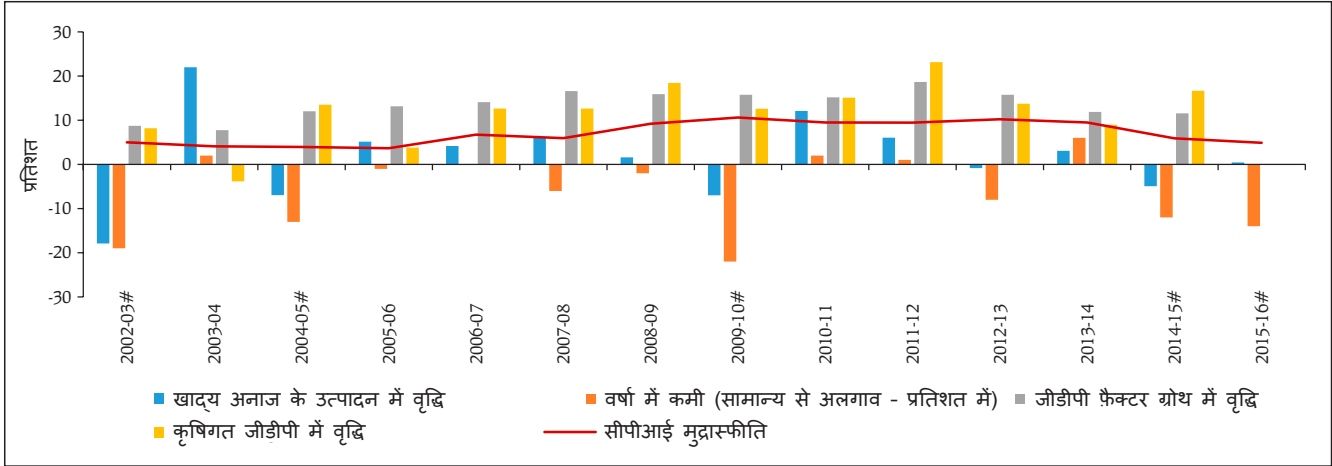


नोट : तेल की कीमतें उस अवधि के लिए औसत कीमतें हैं।

स्रोत : आरबीआई एवं पीपीएसी, पेट्रोलियम मंत्रालय

⁹ भारत में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दैनिक आधार पर सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रूप में किंचित न्यूनतम राशि को भार-रहित स्वामित्व वाले सरकारी एवं स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश करने की जरूरत होती है। वर्तमान में, एसएलआर निवल मांग एवं मीयादी देयताओं का 21.25 प्रतिशत है। भार-रहित स्वामित्व वाले सरकारी एवं स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश के अलावा सोना, नकद, एवं अधिशेष सीआरआर शेष भी एसएलआर के उद्देश्य के लिए चलनिधि आस्तियां मानी जाती हैं।

चार्ट 1.16 : वर्षा, कृषि में वृद्धि, खाद्य पदार्थ का उत्पादन एवं मुद्रास्फीति¹⁰



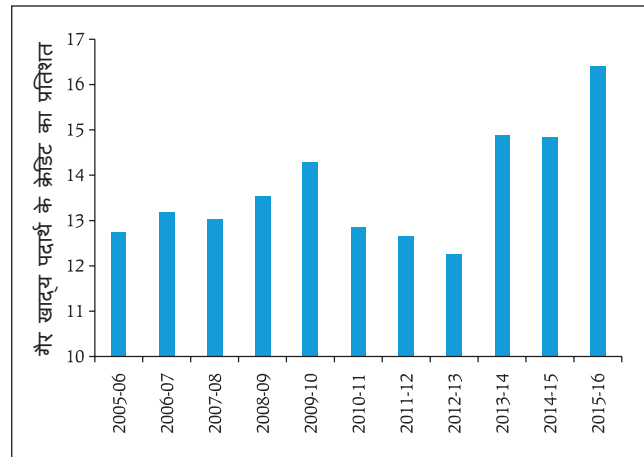
नोट : # लंबी अवधि के औसत के 10 प्रतिशत से ज्यादा की वर्षा में कमी वाले वर्षों को संदर्भित करता है। जीडीपी एवं कृषिगत जीडीपी का आधार वर्ष 2004-05 है।
 स्रोत: सीएसओ, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

ग्रामीण विपत्ति (डिस्ट्रेस) से होने वाले जोखिम

1.15 आजीविका एवं खाद्य पदार्थ की कीमतों के मामले में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है। यद्यपि वर्षा का स्थानिक एवं कालिक वितरण इसकी मात्रा के जैसा ही महत्वपूर्ण है, हाल के वर्षों में कुल मिलाकर कृषिगत सकल घरेलू उत्पाद एवं मुद्रास्फीति पर कम मानसून के प्रभाव ने स्पष्ट बदलाव प्रदर्शित किया है (चार्ट 1.16)। इस तथ्य को देखते हुए कि कृषि क्षेत्र में किसी संकट का राजनैतिक अर्थव्यवस्था पर काफी बड़ा दबाव है, चौतरफा ग्रामीण संकट का समाधान करने वाली अनुकूल नीति पर लगातार बल महत्वपूर्ण हो जाता है तब जबकि सरकार का प्रयास है कि 2022 तक खेती से आय दोगुनी हो जाए।

1.16 बड़ी मात्रा में ऋण आबंटन (चार्ट 1.17) एवं वित्तीय व्यय, ग्रामीण ऋणग्रस्तता और विपत्ति के होते हुए भी नीति में एक व्यापक कार्यनीति के बदलाव की जरूरत को दर्शाता है। इस व्यवस्था को अल्पावधि प्रतिक्रिया (रेस्पॉन्स) यथा लोन माफ करना, सब्सिडीयुक्त अथवा मुफ्त बिजली, पानी एवं खाद से भी अधिक करने की

चार्ट 1.17 : कृषि क्षेत्र को बैंक ऋण



स्रोत- आरबीआई

¹⁰ चार्ट में प्रयुक्त उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई) बैंक सिरीज (2014-15 एवं 2015-16 के डाटा के लिए आधार वर्ष 2102 के साथ) का स्रोत मुद्रा नीति फ्रेमवर्क को मजबूत एवं संशोधित करने वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट (2014) है।

जरूरत है। जबकि नई फसल बीमा योजना, सीधा प्रतिलाभ अंतरण एवं कुछ राज्य सरकारों द्वारा जमीन के टिलटिंग के लिए कानून एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने जैसी पहल करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, अनेक अन्य मामले हैं जो नीतिगत बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जैसे कि वैकल्पिक रोजगार के

अवसर उपलब्ध कराना। जबकि ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान देने वाली नीतियों, जैसे कि कोई लोक नीति पहल 'नैतिक जोखिम' के साथ-साथ आती है, के मामले में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसे कम करने के रास्ते ढूँढे जाएं जिससे कि सीमित संसाधनों का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके (बॉक्स 1.2)।

बॉक्स 1.2 : नैतिक संकट एवं नैतिकता

नैतिक संकट शब्द जो कभी 'बीमा' शब्दकोश से जुड़ा हुआ था वैश्विक वित्तीय संकट (GFC) के बाद जन-सामान्य के विचार विमर्श में आया। नीतियों के विविध प्रकार, जिनमें निक्षेप बीमा, सहिष्णुता (किसी भी प्रकार का), गुणात्मक एवं मात्रात्मक शिथिलता, सब्सिडी, बेलआउट, बैंकर के प्रोत्साहन, कर परिकलन एवं मुफ्त उपहार लेने-देने की प्रथा जो अंतर पीढ़ीगत साम्यता एवं सीमित देयता को भी प्रभावित कर देती है शामिल हैं, ने नैतिक संकट को लेकर विवाद पैदा कर दिये हैं।

नैतिक संकट अपने कृत्यों को दूसरों पर बिना उनकी स्पष्ट सहमति के लादने की क्षमता है और इस तरह यह एक ऐसे तरीके से कार्य करने हेतु प्रबल प्रलोभन देता है जिसे सामान्यतः कोई नहीं अपनाता है (McCaffrey, 2016)। लोक नीति पहल में वास्तविक समस्या तब आती है जब एक व्यक्ति का प्रलोभन प्रयोग में लाये गए संसाधन से ज्यादा संसाधन प्रयोग में लाने का हो, क्योंकि वह जानती है या विश्वास करती है कि इन संसाधनों का कुछ या सभी कोई और मुहैया कराएगा, एवं यह इस स्वामित्व हरण (Hulsmann, 2006) की इच्छा या मंजूरी के विरुद्ध घटित होता है। उदाहरण स्वरूप, सब्सिडी देते समय यह माना जाता है कि अंतिम बोझ करदाता पर होगा। तथापि, यदि विकल्प दिया जाए तो करदाता इस स्वामित्वहरण के लिए मंजूरी देने का इच्छुक नहीं होगा।

अनिश्चितता का सामना करने में फ्रैंक नाइट ने भी नैतिक संकट का हवाला दिया। उनके लिए, अनिश्चितता 'बुनियादी तौर पर एक नैतिक समस्या है'.....एवं.....'...वास्तविक मानवीय कृत्य नैतिक फैसले हैं' (Emmett 2011)। केनेथ एरो ने एक्स एंटे (ex ante) एवं एक्स पोस्ट (Ex post) नैतिक संकट के बीच अंतर को चिह्नित किया है (McCaffrey, 2016)। यह अंतर इस बारे में है कि कैसे व्यक्ति विशेष अग्रिम रूप से बीमाकर्ताओं की हानि की संभाव्यता को प्रभावित करते हैं एवं वे किस प्रकार एक दुर्भाग्य पूर्ण घटना के घटित होने के बाद इसका लाभ उठाते हैं।

कुछ हद तक कि मनुष्य से गलती हो सकती है, कुछ कृत्य जो वास्तविक रूप से किए गए हों उनके कारण उनका

अवांक्षित एवं अकारण जोखिम से सामना हो सकता है। कुछ लोगों का यह भी मत है कि नैतिक संकट एक संविदा के समान हो सकता है (Classen. 2015)। मैककैफरी ने सुझाया है कि मूल्यों का गुप्त निर्धारण नहीं करने कि स्थिति में नैतिक संकट का संविदा विषयक रूप नीतिगत चर्चा के लिए उपयोगी हो जाता है, जबकि यह व्यवहार यथा स्वामित्व के कानूनी अधिकार के उल्लंघन, के नैतिक आयाम का वर्णन भी करता है।

तथापि, जिसकी प्रशंसा की जाए वह यह तथ्य है कि नैतिक संकट किसी लोक नीति पहल में विभिन्न परिमाण में सन्निहित है। जैसा कि लोक नीति उपाय 'घोषित राज्य प्रयोजनों (declared state objectives)' की प्रकृति के हैं जिनका संबंध स्वास्थ्य, नैतिकता एवं नागरिकों के हित से है, नैतिक संकट का पहलू कभी-कभी अपरिहार्य होता है। इसलिए नीति निर्धारक नैतिक संकट के अनुचित प्रभाव को कम करने के लिए incentive framework का निर्माण कर सकते हैं। इसी समय, लॉरेंस समर्स द्वारा तथाकथित 'नैतिक संकट रूढ़िवादिता' से बचने की जरूरत है क्योंकि सरकार की अनौपचारिक तरीके के हस्तक्षेप कभी-कभी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं।

संदर्भ:

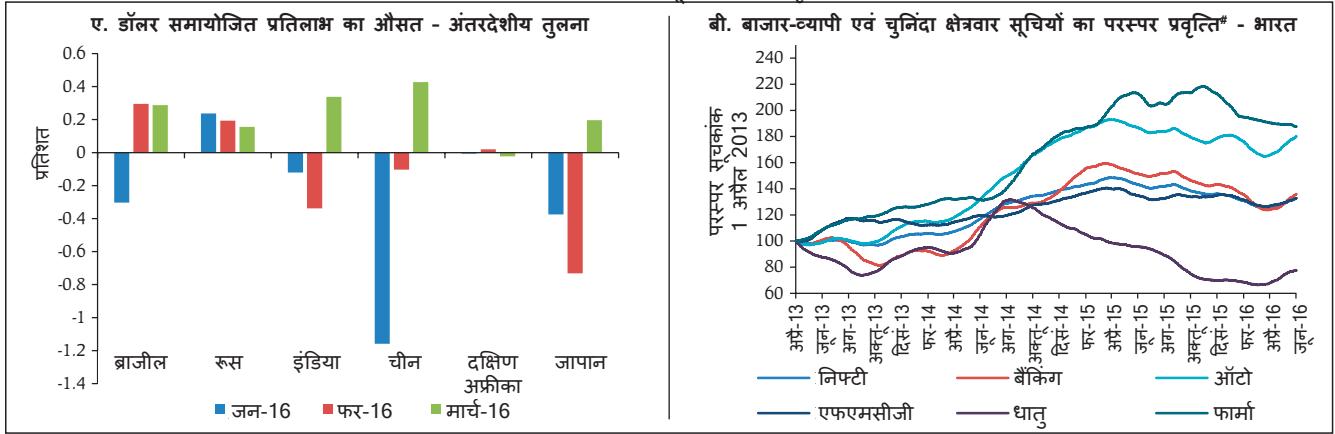
क्लासेन रुगर (2015) 'Financial Crisis and Ethics of Moral Hazard', *Social Theory and Practice*, खंड 41 नं. 31

एम्मेट रॉस बी (2011) ' Frank H. Knight on the "Entrepreneur Function" in Modern Enterprise'. *Ross B. Emmett, Seattle University Law Review*, खंड 34

हल्समन जॉर्ज गीडो (2006) 'The Political Economy of Moral Hazard', *Politická ekonomie*, खंड 54 नं. 1, पीपी 35-47

मैककैफरी एम. (2016) 'The morals of moral hazard: a contracts approach'. *Business Ethics: A European Review*, मई.

चार्ट 1.18 : स्टॉक सूचकांकों की प्रवृत्ति



नोट: # निफ्टी एवं क्षेत्रवार सूचियों के लिए 50 दिन का औसत प्रचालन प्रयोग में लाया गया।
 स्रोत : ब्लूमवर्ग, सेबी - राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज सूचियों (8 जून 2016 को अद्यतन किया गया) पर आधारित।

आस्तियों की कीमतें

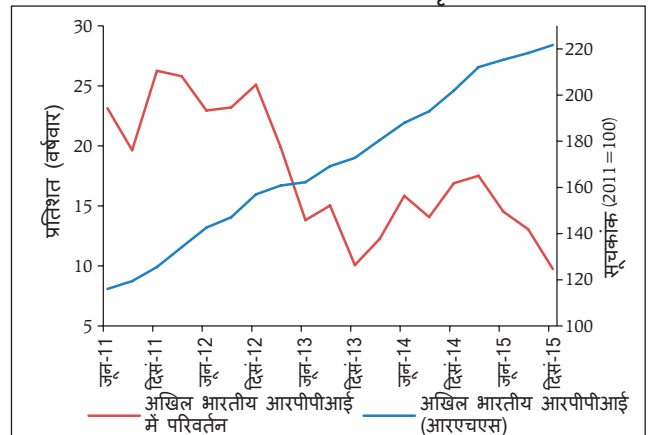
स्टॉक की कीमतें

1.17 विश्व भर के इक्विटी बाज़ार में चीन में हुई गतिविधियों एवं अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट के कारण 2016 के प्रथम दो महीनों के दौरान हलचल रही। तब से बाज़ार में सुधार हुआ है ऐसा लगता है (चार्ट 1.18ए)। भारत के परिप्रेक्ष्य में, जबकि बैंकिंग क्षेत्र ने बाजार-व्यापी सूचकांक के साथ अभिरूपता लाने का प्रयास किया है, दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे ऑटो एवं फार्मा ने बाजार-व्यापी सूचकांक की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया है (चार्ट 1.18बी)।

घरों की कीमतें

1.18 आर्थिक विकास में हाउसिंग क्षेत्र की उत्प्रेरक भूमिका के बावजूद, घरों की कीमतें वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करती हैं। हाल के दिनों में घर की कीमत में वृद्धि काफी कम हुई है (चार्ट 1.19)। सकल गैर-निस्पादक आस्ति (GNPA) अनुपात के करीब 1.3 प्रतिशत¹¹ रहने के साथ, खुदरा हाउसिंग सेगमेंट वर्तमान में भारत के परिप्रेक्ष्य में कोई महत्वपूर्ण प्रणालीगत जोखिम पैदा नहीं करता है।

चार्ट 1.19 : घर कीमतों की प्रवृत्ति



नोट : आरपीआई का अर्थ है : आवासीय प्रॉपर्टी प्राइस सूचकांक (आधार - मार्च 2011)
 स्रोत : आरपीआईएमएस, आरबीआई

¹¹ मार्च 2016 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए (आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियाँ)

कॉरपोरेट क्षेत्र

1.19 चुनिंदा गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (NGNF)सूचीबद्ध कंपनियों¹² से संबंधित अर्ध-वार्षिक डेटा कॉरपोरेट क्षेत्र के निस्पादन में वार्षिक आधार पर कुछ सुधार की ओर इशारा करती हैं (सारणी - 1.1.)।

कॉरपोरेट लीवरेज

प्रवृत्ति

1.20 नमूनों में 'लीवरेजयुक्त' कंपनियों का अनुपात (या तो ऋणात्मक शुद्ध मालियत या कर्ज-इक्विटी अनुपात के रूप में परिभाषित) मार्च 2015 के 19 प्रतिशत के मुकाबले मार्च 2016 में 14 प्रतिशत कम हुआ, एवं कुल कर्ज में उनका हिस्सा भी 33.8 प्रतिशत से घटकर 20.6 प्रतिशत रहा। उसी प्रकार, 'उच्च लीवरेजयुक्त' कंपनियों का अनुपात (कर्ज-इक्विटी अनुपात के साथ 'लीवरेजयुक्त' कंपनियों के रूप में परिभाषित-3), कुल कर्ज में से इन कंपनियों का कर्ज 23.0 प्रतिशत से कम होकर 19.0 प्रतिशत रहा (सारणी - 1.2), 14.2 प्रतिशत से घटकर 12.9 प्रतिशत हो गया।

कर्ज चुकौती क्षमता

1.21 समान नमूनों को लेकर कर्ज चुकौती क्षमता एवं 'कमजोर' कंपनियों (ब्याज व्याप्ति अनुपात वाली कंपनियों के रूप में परिभाषित) के लीवरेज के वर्तमान रुझानों का विश्लेषण किया गया जिसने 2015-16 में कुछ सुधार को इंगित किया है। विश्लेषण यह दिखाता है कि मार्च 2016

सारणी 1.1 : सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियों के कार्य निष्पादन के चुनिंदा वित्तीय अनुपात (2014-15 एवं 2015-16)

	2014-15 की पहली छमाही	2014-15 दूसरी छमाही	2015-16 की पहली छमाही	2015-16 दूसरी छमाही
बिक्री में वृद्धि (वार्षिक आधार पर)	5.8	-2.3	-3.5	2.2
औसत कुल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ (प्रतिशत)	2.6	1.9	2.6	2.1
ऋण-शोधन क्षमता अनुपात (प्रतिशत)	13.8	12.1	14.5	12.9
इक्विटी की तुलना में कर्ज अनुपात #	0.38	0.39	0.38	0.38
ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) (गुना)	5.8	4.9	5.4	5.0
औसत उधारियों की तुलना में ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	10.1	10.1	10.3	10.0

नोट : * औसत छमाही से संबंधित बकाया प्रारंभिक एवं अंत की स्थिति पर आधारित है।

‡ ऋण-शोधन क्षमता को कर पश्चात लाभ (पीएटी) तथा कुल कर्ज की तुलना में मूल्यहास के रूप में परिभाषित किया गया।

कर्ज को दीर्घावधि उधारियों माना गया है तथा इक्विटी निवल मालियत है।

^ वार्षिकीकृत ब्याज भुगतान का प्रयोग किया गया।

स्रोत : भारिबैं (चुनिंदा सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियों के छमाही विवरण)।

के अंत की स्थिति के अनुसार चुनिंदा नमूनों में से 15 प्रतिशत कंपनियाँ मार्च 2015 के 17.8 प्रतिशत की तुलना में 'कमजोर' थीं। इन 'कमजोर' कंपनियों के कर्ज¹³ का हिस्सा 2015-16 के सेकंड हाफ में कुल कर्ज के मुकाबले कम होकर 27.8 प्रतिशत रहा जो 2014-15 के सेकंड हाफ में 29.2 था। हालांकि, इन 'कमजोर' कंपनियों का कर्ज-इक्विटी अनुपात 1.8 प्रतिशत से बढ़कर 2.0 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान 'लीवरेजयुक्त कमजोर'¹⁴ कंपनियों का अनुपात 2.3 प्रतिशत से घटकर 1.6 प्रतिशत हो गया। 'लीवरेजयुक्त कमजोर' कंपनियों के कर्ज का

सारणी 1.2 : सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियाँ : कॉरपोरेट लीवरेज में समान्यतर जोखिम

(प्रतिशत)

लीवरेज	कंपनियों की संख्या (कुल कंपनियों के प्रतिशत के रूप में)				कुल कर्ज की तुलना में कर्ज का हिस्सा			
	सितंबर'14	मार्च'15	सितंबर'15	मार्च'16	सितंबर'14	मार्च'15	सितंबर'15	मार्च'16
ऋणात्मक निवल मालियत या डीईआर ≥ 2	18.4	19.0	19.4	14.0	31.8	33.8	30.5	20.6
ऋणात्मक निवल मालियत या डीईआर ≥ 3	13.6	14.2	15.3	12.9	22.9	23.0	24.9	19.0

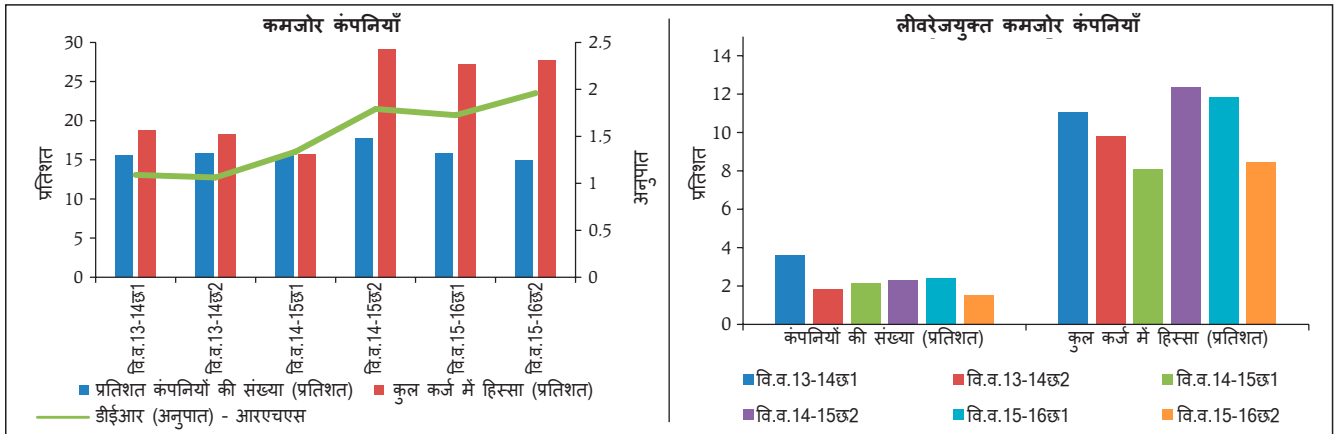
स्रोत : भारिबैं (चुनिंदा सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियों के छमाही विवरण)

¹² सितंबर 2013 को समाप्त प्रथम छमाही से शुरू 1800 से 2600 सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियों से संबन्धित अर्ध-वार्षिक डेटा पर आधारित। वृद्धि की गणना एवं अन्य तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक तरह की कंपनियों को लिया गया है।

¹³ बैंक की उधारियाँ कुल उधारियों का भाग होती हैं, जिसमें अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों तरह की उधारियाँ शामिल हैं।

¹⁴ डीईआर ≥ 2 वाली कंपनियों को लीवरेजयुक्त कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 'लीवरेजयुक्त कमजोर' कंपनियाँ 'कमजोर' कंपनियों में डीईआर ≥ 2 हैं अथवा जिनके पास ऋणात्मक निवल मालियत है वो हैं। लीवरेजयुक्त कंपनियों में ऋणात्मक निवल मालियत वाली कंपनियों को शामिल किया गया है क्योंकि इन कंपनियों के ऋण-शोधन क्षमता के मुद्दे भी होंगे।

चार्ट 1.20: सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियाँ: कमजोर कंपनियाँ - वर्तमान प्रवृत्ति (2013-14 to 2015-16)



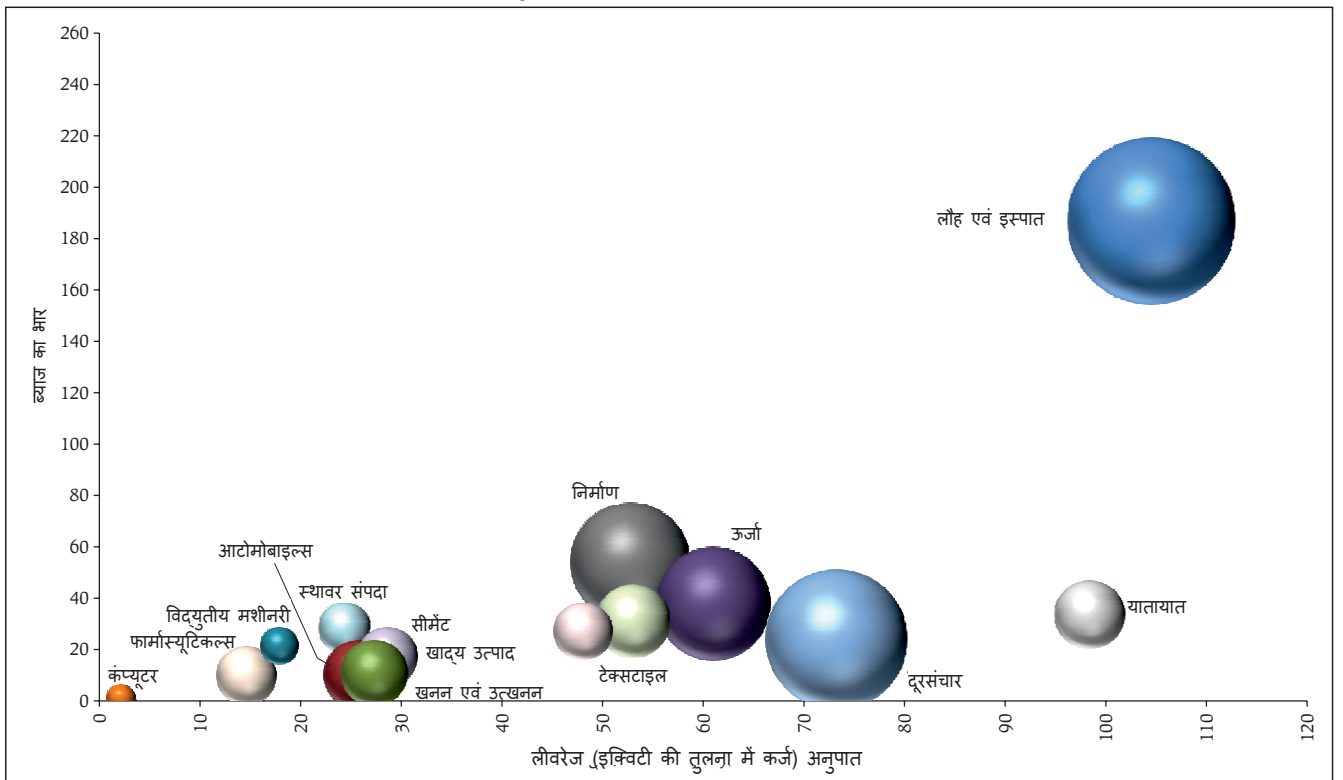
स्रोत - भारिबैं (चुनिदा सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियों के छमाही विवरण)।

हिस्सा भी 12.4 प्रतिशत से कम होकर 8.5 प्रतिशत हो गया (चार्ट 1.20)।

1.22 मार्च 2016 के अंत में, चुनिंदा उद्योगों की जोखिम प्रोफाइल ने यह दर्शाया कि लौह और इस्पात

उद्योगों के लीवरेज के साथ-साथ उन पर ब्याज का भार¹⁵ भी काफी अधिक था। निर्माण(construction), ऊर्जा, दूरसंचार और परिवहन उद्योगों में भी अपेक्षाकृत लीवरेज अधिक रहा (चार्ट 1.21)।

चार्ट 1.21: चुनिंदा उद्योगों का जोखिम प्रोफाइल (मार्च 2016)



टिप्पणी : बलबुले का आकार सभी उद्योगों के कुल कर्ज के तुलनात्मक हिस्से पर आधारित है जो नमूने गत कंपनियों के आधार पर आकलित है।
 स्रोत: भारिबैं (चुनिंदा एनजीएनएफ सूचीबद्ध कंपनियों के छमाही विवरण)

¹⁵ ब्याज के भार को, ईबीआईटीडीए के प्रतिशत के रूप में, ब्याज-व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है।

कारपोरेट क्षेत्र के जोखिमों का विश्लेषण

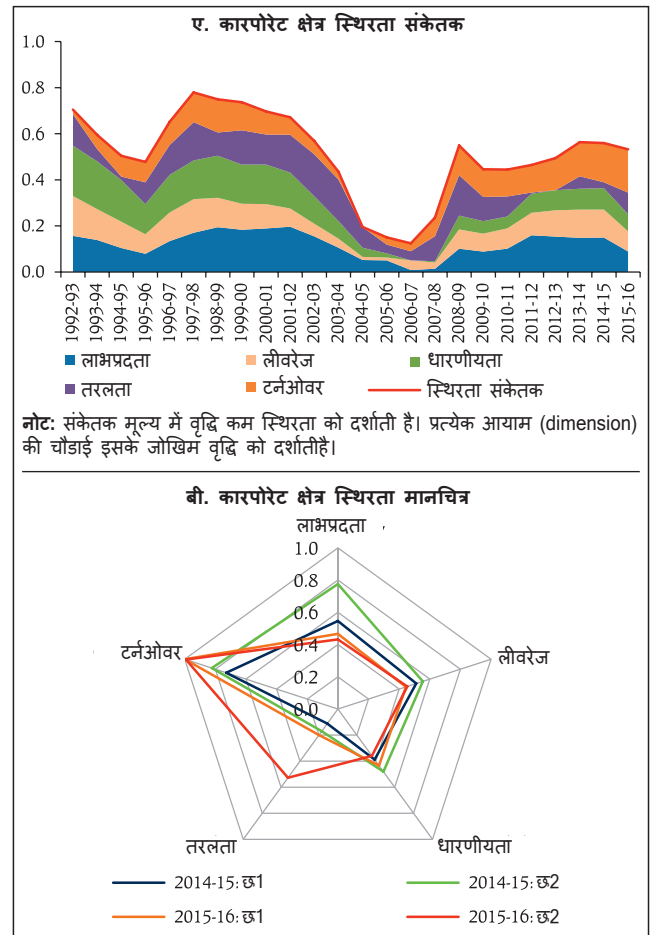
1.23 कारपोरेट क्षेत्र गत स्थिरता संकेतक और मैप¹⁶ यह दर्शाता है कि कारपोरेट क्षेत्र गत समग्र जोखिम, जो कि 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान बढ़ गया था, वह 2015-16 में कुछ हद तक नियंत्रित/संतुलित दिखाई दिया है। हालांकि, मांग की कमी (कारोबार¹⁷) और तरलता दबाव के कारण जोखिम बना हुआ है (चार्ट 1.22)।

वित्तीय सेहत: विशाल डेटाबेस पर आधारित

1.24 वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान कंपनी मामले मंत्रालय, भारत सरकार के बड़े नमूने¹⁸ का इस्तेमाल करते हुए कारपोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन के व्यापक/विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड दोनों क्षेत्रों की कंपनियों की लाभप्रदता¹⁹ में 2014-15 में सुधार हुआ, जबकि लीवरेज अनुपात में वृद्धिशील प्रवृत्ति देखी गई। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में आईसीआर के संदर्भ में मापी गई कर्ज चुकौती क्षमता में सुधार हुआ, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में यह स्थिति लगभग समान ही रही (चार्ट 1.23)।

1.25 इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई), डीईआर, आईसीआर, कुल उधारी और बैंक उधारी के संदर्भ में विभिन्न उद्योगों के तहत आने वाले कारपोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण चार्ट 1.24 में दिया गया है। विश्लेषण से पता चलता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में से सीमेंट उद्योग में सबसे ज्यादा लाभप्रदता थी और उसके बाद एविेशन, वाहन, विनिर्माण(manufacturing), सर्विस एवं कपड़ा उद्योगों में लाभप्रदता देखी गई। निर्माण(construction), रियल इस्टेट, खनन और कागज क्षेत्र में कार्यरत पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की लाभप्रदता कम रही। बिजली उद्योग की पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में

चार्ट 1.22 कारपोरेट क्षेत्र स्थिरता संकेतक और मानचित्र



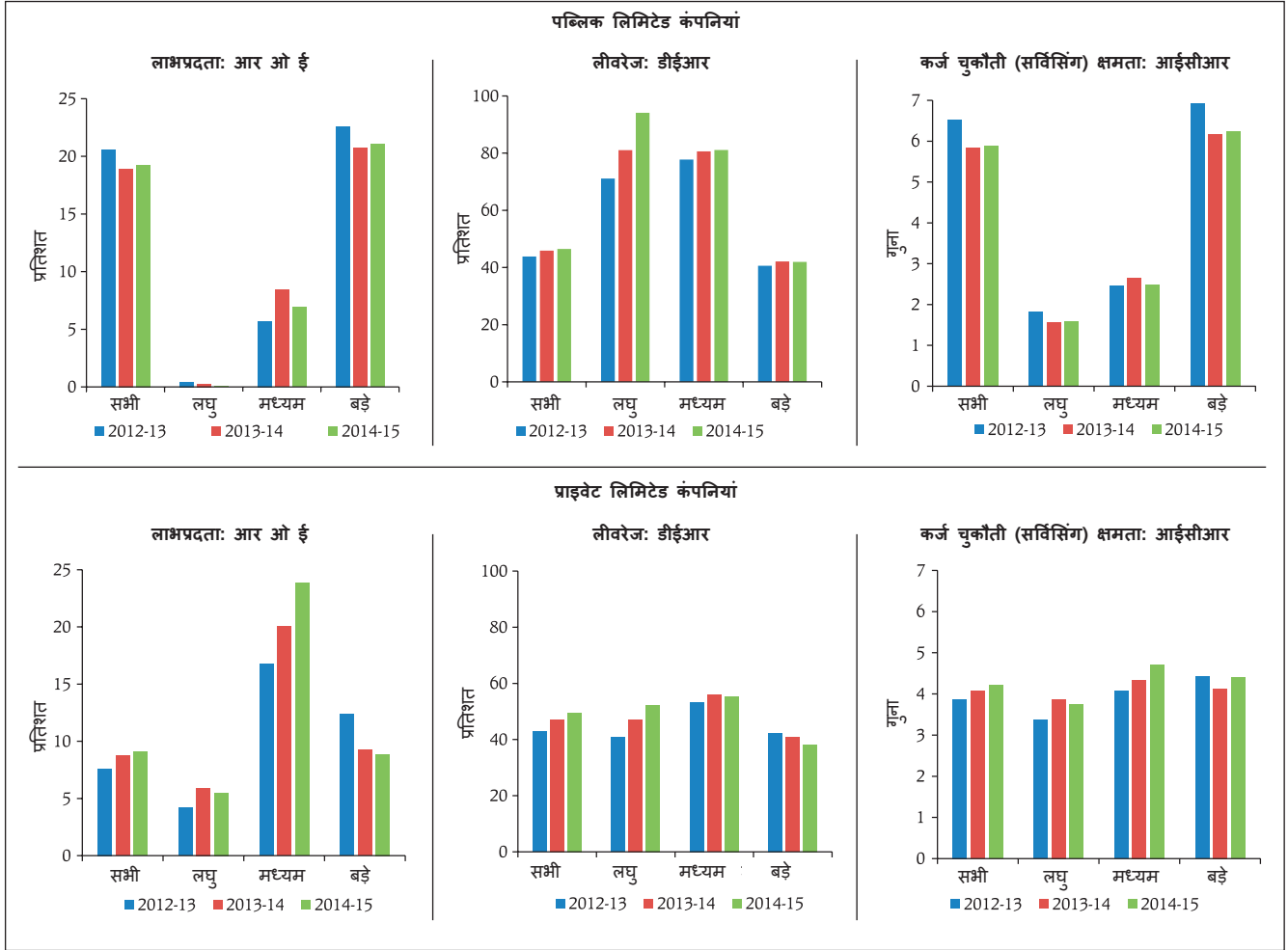
¹⁶ 1992-93 से 2011-12 तक वार्षिक तुलन पत्र का डेटा लिया गया है, जबकि 2012-13 से 2015-16 तक अर्धवार्षिक डेटा का प्रयोग किया गया है। विस्तृत अध्ययन प्रणाली और विभिन्न आयामों के तहत प्रयुक्त मूलभूत संकेतकों ब्योरा अनुबंध 2 में दिया गया है।

¹⁷ परिसंपत्तियों (आस्तियों) से बिक्री के अनुपात से पण्यावर्त आकलित किया गया है।

¹⁸ कारपोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन का अध्ययन कंपनी मामले मंत्रालय के बड़े डेटाबेस के भाग का उपयोग करके किया गया था, जिसमें 16,923 एनजीएनएफ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और 237,398 एनजीएनएफ निजी क्षेत्र की कंपनियां शामिल थीं।

¹⁹ लाभप्रदता के लिए इस्तेमाल किया गया संकेतक निवल मालियत अनुपात की तुलना में आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओई) पर कर पश्चात लाभ है (पीएटी/एनडब्ल्यू)। लीवरेज के लिए संकेतक इक्विटी (निवल मालियत को लिया गया है) की तुलना में दीर्घवधि उधारी अनुपात है, जबकि कर्ज चुकौती क्षमता की माप ब्याज पर किए गए व्यय की तुलना में ईबीआईटीडीए के रूप में ब्याज कवरेज अनुपात द्वारा की गई है।

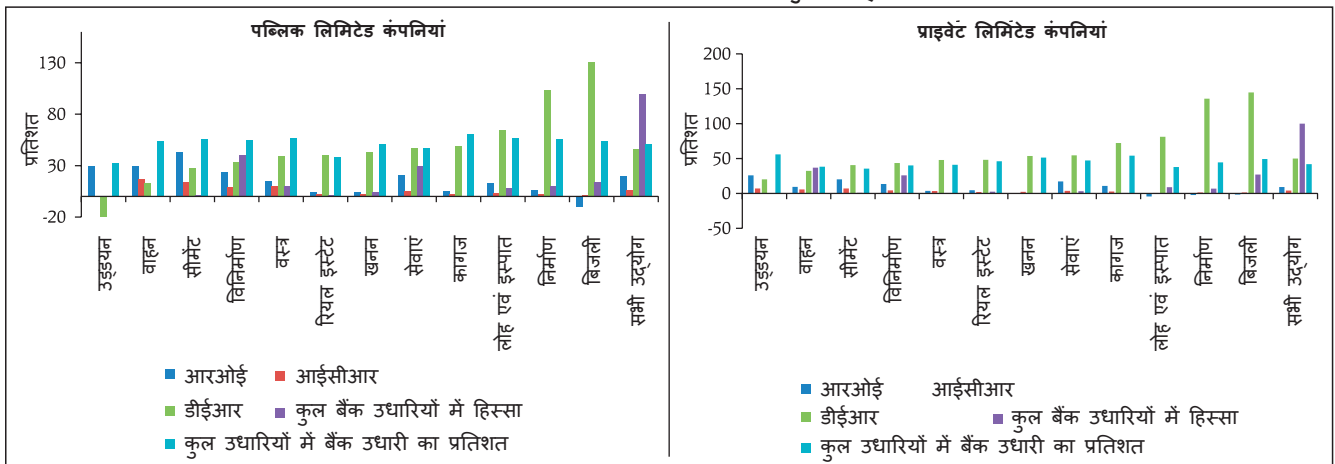
चार्ट 1.23 कारपोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन के संकेतक: आकार के अनुसार वर्गीकरण



स्रोत: एमसीए डेटाबेस (चुनिंदा एनजीएनएफ कंपनियां)

वर्ष 2014-15 में हानि हुई। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में एविएशन, विनिर्माण, कपड़ा, कागज और वाहन कंपनियों ने 2014-15 में लाभ दर्ज किया जबकि सीमेंट, बिजली, रियल इस्टेट और निर्माण उद्योगों को हानि उठानी पड़ी।

चार्ट 1.24 कारपोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन के संकेतक: चुनिंदा उद्योग : 2014-15



स्रोत: एमसीए डेटाबेस (चुनिंदा एनजीएनएफ कंपनियां)

लोहा, इस्पात तथा खनन उद्योगों में कम लाभप्रदता की प्रवृत्ति देखी गई। पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की बिजली और निर्माण उद्योगों में लीवरेज अनुपात अधिक था, जबकि पब्लिक लिमिटेड क्षेत्र की एविएशन कंपनियों में समग्र स्तर पर ऋणात्मक निवल मालियत के कारण लीवरेज ऋणात्मक रहा तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की एविएशन और बिजली कंपनियों में प्राइवेट लिमिटेड की रियल इस्टेट में आईसीआर एक से कम रहा।

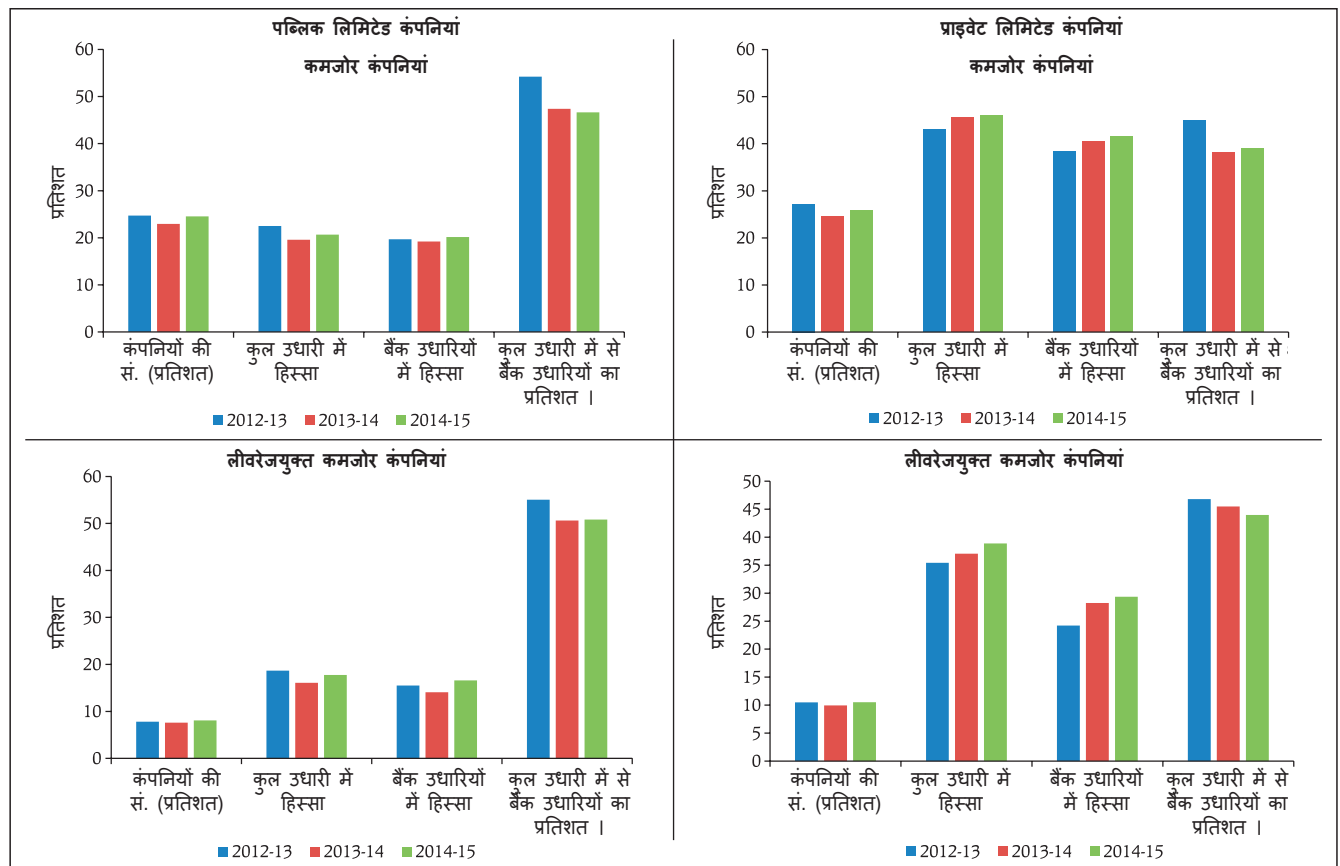
कर्ज चुकौती क्षमता और लीवरेज

1.26 'कमजोर' और 'लीवरेजयुक्त कमजोर' कंपनियों का तथा कुल कर्ज एवं बैंक उधारियों में उनके हिस्से का निर्धारण करने के लिए व्यापक एमसीए डाटा का उपयोग करते हुए एक विश्लेषण किया गया था (चार्ट 1.25)। विश्लेषण से पता चलता है कि 4,151 (24.5 प्रतिशत) पब्लिक लिमिटेड कंपनियां और 61,194 (25.8 प्रतिशत) प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां 2014-15 में संबंधित चुनिंदा

नमूने के अनुसार 'कमजोर' थीं। पिछले वर्ष की तुलना में पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए डीईआर 2.5 से घटकर 3.3 और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए 1.4 से घटकर 1.6 हो गया था। कुछ चुनिंदा नमूनों के अनुसार 1,366 (8.15 प्रतिशत) पब्लिक लिमिटेड कंपनियां और 25,004 (10.5 प्रतिशत) प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां 'लीवरेजयुक्तकमजोर' थीं। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में कुल उधारियों में 'लीवरेजयुक्त कमजोर' कंपनियों की बैंक उधारियों का हिस्सा 16.6 प्रतिशत था। वहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों हेतु 'लीवरेजयुक्त कमजोर' कंपनियों की कुल उधारियों में बैंक उधारियों का हिस्सा 29.4 प्रतिशत था।

1.27 कुछ चुनिंदा उद्योगों की 'कमजोर' व 'लीवरेजयुक्त कमजोर' कंपनियां तथा कुल उधारियों और बैंक उधारियों में उनके हिस्से की पहचान करने के लिए भी एक विश्लेषण किया गया (चार्ट 1.25)। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की

चार्ट 1.25 : एनजीएनएफ कमजोर कंपनियां



स्रोत: एमसीए डाटाबेस (चुनिंदा एनजीएनएफ कंपनियां)

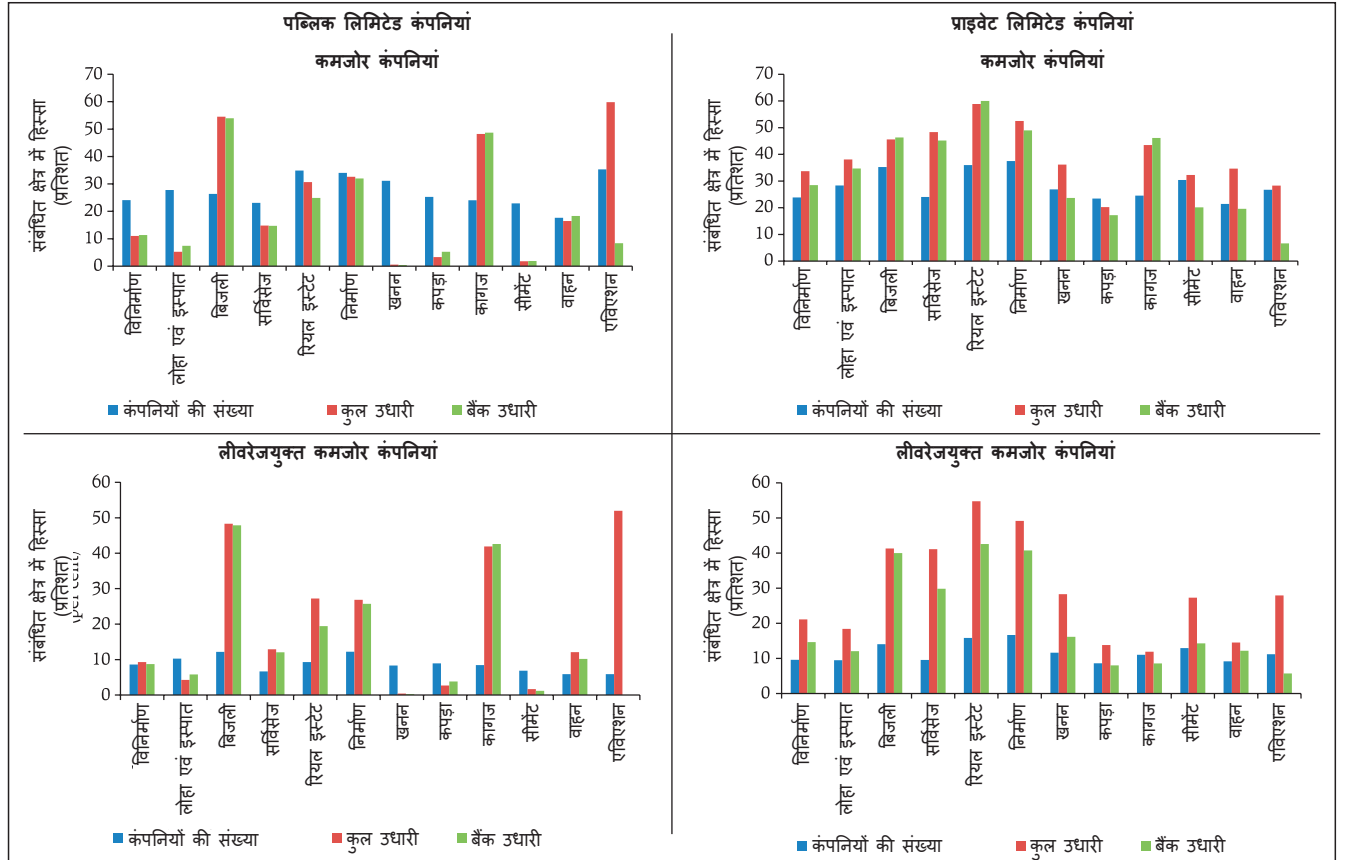
कुल कंपनियों में से 'लीवरेजयुक्त कमजोर' कंपनियों का प्रतिशत संबंधित उद्योगों में बिजली, निर्माण, लोहा एवं इस्पात, रियल इस्टेट, कपड़ा और कागज उद्योगों में अपेक्षाकृत अधिक रहा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में 'लीवरेजयुक्त कमजोर' कंपनियों का प्रतिशत बिजली, निर्माण, रियल इस्टेट, खनन, कागज, एविएशन और सीमेंट में अधिक रहा। 'लीवरेजयुक्त कमजोर' कंपनियों का कुल उधारियों में से बैंक उधारियों का हिस्सा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में बिजली, कागज, निर्माण और रियल इस्टेट उद्योगों में प्रमुखता से रहा तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के मामलों में बिजली, निर्माण,

रियल इस्टेट और सर्विसेज उद्योगों में प्रमुखता से रहा चार्ट (1.26)।

बैंक ऋण पर प्रभाव

1.28 'लीवरेजयुक्त कमजोर' कंपनियों अपनी निम्न कर्ज चुकोती क्षमता एवं उच्च लीवरेज, प्रतिकूल परिस्थितियों में बैंक ऋणों की पहले से ही खराब आस्ति गुणवत्ता पर दबाव डाल सकती हैं। सभी एनजीएनएफ कंपनियों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) का ऋण, मार्च 2015 के अंत में कुल बैंक ऋण का लगभग 40 प्रतिशत था। इसलिए, 'कमजोर' एनजीएनएफ कंपनियों की कल्पित चूक के कारण समग्र प्रभाव²⁰ एससीबी के कुल बैंक ऋण

चार्ट 1.26 : एनजीएनएफ कमजोर कंपनियों: चुनिंदा उद्योग : 2014-15



स्रोत: एमसीए डाटाबेस (चुनिंदा एनजीएनएफ कंपनियों)

²⁰ व्यौरै अनुबंध 2 में दिए गए हैं।

का लगभग 10.4 प्रतिशत हो सकता है। यह प्रभाव 'लीवरेजयुक्त कमजोर' एनजीएनएफ कंपनियों की कल्पित चूक के मामले में 8 प्रतिशत हो सकता है (सारणी 1.3)। हालांकि, इन कंपनियों के बैंक ऋण का एक भाग बैंकों के मौजूदा दबावग्रस्त अग्रिमों (अनर्जक अग्रिम या पुनर्संचित मानक अग्रिम) का पहले से ही हिस्सा हो सकता है।

1.29 इस संदर्भ में, इस बात पर ध्यान देना उचित होगा कि यह स्थिति 2014-15 के एमसीए आंकड़ों पर आधारित है और 2014-15 व 2015-16 के छोटे से नमूने हेतु नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत

सारणी 1.3 एनजीएनएफ कंपनियों द्वारा बैंक ऋणों की कर्ज चुकौती क्षमता में कमजोरी का प्रभाव
(अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल बैंक ऋणों में से अतिरिक्त संदर्भ में बैंक ऋण का हिस्सा)
(प्रतिशत)

	मार्च-13	मार्च-14	मार्च-15
सभी एनजीएनएफ कंपनियां	31.5	38.5	40.0
कमजोर कंपनियां	7.8	9.5	10.4
लीवरेजयुक्त कमजोर कंपनियां	5.6	6.8	8.0

स्रोत: भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मूल सांख्यिकीय विवरणियां (बीएसआर) और एमसीए डाटाबेस (चुनिंदा एनजीएनएफ कंपनियां)

मिलते हैं कि इनमें मामूली सुधार हुआ है जिसकी इस अध्याय में पहले ही चर्चा की गई है।

अध्याय II

वित्तीय संस्थाएं: सुदृढ़ता और लचीलापन

2015-16 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कारोबार काफी मंदा रहा। सकल अनर्जक अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात में तीव्र वृद्धि हुई, जिससे मोटे तौर पर यह पता चलता है कि पुनर्वर्गीकरण के कारण पुनर्संचित हुए मानक अग्रिम अनर्जक बन गए। परिणामस्वरूप, पुनर्संचित मानक अग्रिम अनुपात में गिरावट हुई परंतु दबावग्रस्त समयअग्रिम अनुपात में मामूली वृद्धि होने से वे सितंबर 2015 में 11.3 प्रतिशत के मुकाबले मार्च 2016 में 11.5 प्रतिशत हो गए। एससीबी के जोखिम भारित आस्ति अनुपात में थोड़ा सुधार परिलक्षित हुआ। बैंक समूहों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता में गिरावट हुई जिससे उनका सीआरएआर लगातार न्यूनतम दर्ज हुआ।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एसयूसीबी) और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफएसी) दोनों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ। पीएसबी सेक्टर की तुलना में एनबीएफसी सेक्टर का कार्यनिष्पादन सामान्यतः बेहतर रहा।

बैंकिंग स्थिरता संकेतक के अनुसार, 2015-16 की दूसरी छमाही के दौरान आस्ति गुणवत्ता में कमी आने और लाभप्रदता में गिरावट के कारण बैंकिंग क्षेत्र का जोखिम बढ़ गया। दबाव परीक्षण लचीलेपन को दर्शाता है किंतु समष्टिगत आर्थिक स्थितियां तेजी से बिगड़ने पर बैंकिंग प्रणाली कमजोर हो सकती है।

तुलन पत्र गत हानि के उच्च स्तर को देखते हुए, बैंकों का ध्यान तुलन पत्र की मजबूत करने की ओर रहने से वे जोखिम के प्रति विमुख रह सकते हैं। इसके अलावा, उनकी पूंजी स्थिति उनकी ऋण उपलब्ध कराने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है।

भाग I

अनुसूचित वाणिज्य बैंक¹

2.1 इस भाग में, दो व्यापक उप शीर्षः विभिन्न व्यावहारिक पक्षों के संबंध में बैंकों का कार्यनिष्पादन तथा उनके लचीलेपन के अंतर्गत विभिन्न परिदृश्यों और एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण के जरिए समष्टिगत दबाव परिक्षणों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों² (एससीबी) की सुदृढ़ता और लचीलेपन पर चर्चा की गई है।

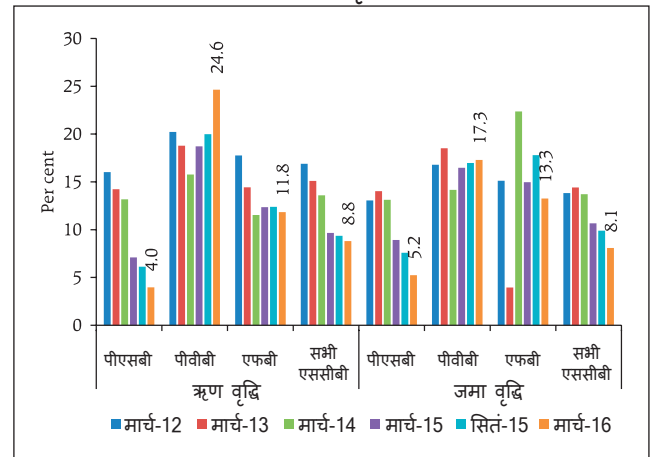
निष्पादन

ऋण और जमा राशि में वृद्धि

2.2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के धीमे कार्यनिष्पादन के कारण एससीबी की ऋण और जमा राशि में कुल वृद्धि एकल अंक में रही। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ऋण वृद्धि कम होकर सितंबर 2015 में 9.4 प्रतिशत से मार्च 2016 में 8.8 प्रतिशत रही जबकि जमा राशि 9.9 के मुकाबले 8.1

प्रतिशत रही। बैंक समूहों का परस्पर कार्यनिष्पादन व्यापक उद्योग गत जारी तुलन पत्र को मजबूत करने और प्राइवेट पूंजीगत खर्च में सुस्त वृद्धि को दर्शाता है (चार्ट 2.1)।

चार्ट 2.1 ऋण और जमा राशि में वृद्धि: वर्ष-दर-वर्ष आधार पर

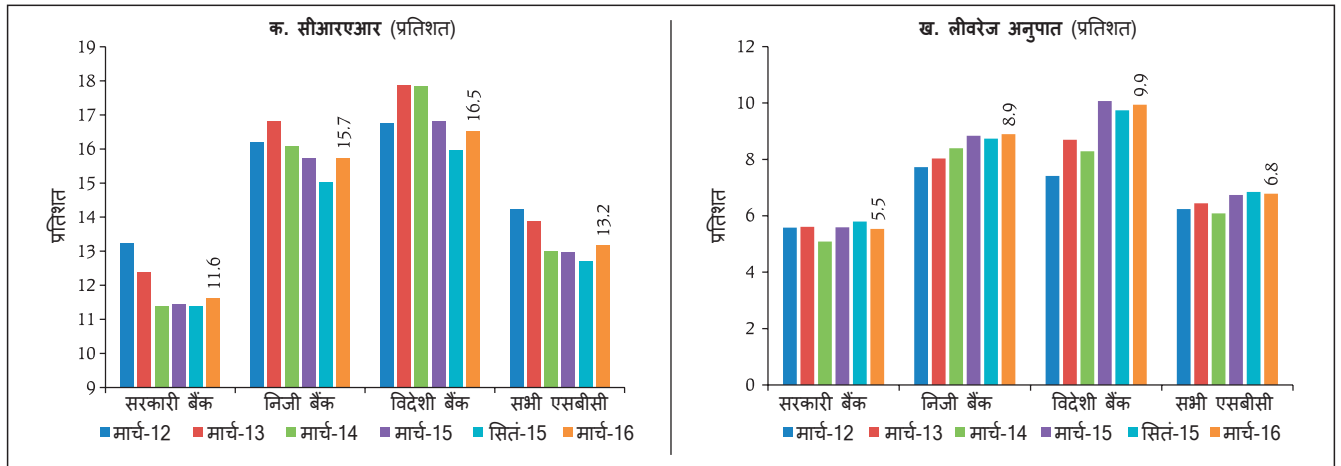


नोट पीएसबी: सरकारी क्षेत्र के बैंक। पीवीबी: निजी क्षेत्र के बैंक। एफबी: विदेशी बैंक स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

¹ इस अध्याय के अंतर्गत किया गया विश्लेषण अनंतिम नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है।

² विश्लेषण पर्यवेक्षी विवरणियों पर आधारित है, जिनमें सिर्फ एससीबी के घरेलू परिचालन शामिल हैं बड़े उधारकर्ताओं संबंधी डेटा को छोड़कर जोकि बैंकों के वैश्विक परिचालन पर आधारित हैं। एससीबी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक शामिल हैं।

चार्ट 2.2: पूंजी पर्याप्तता और लीवरेज अनुपात



स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां

पूंजी, लीवरेज और जोखिम भारित आस्तियां

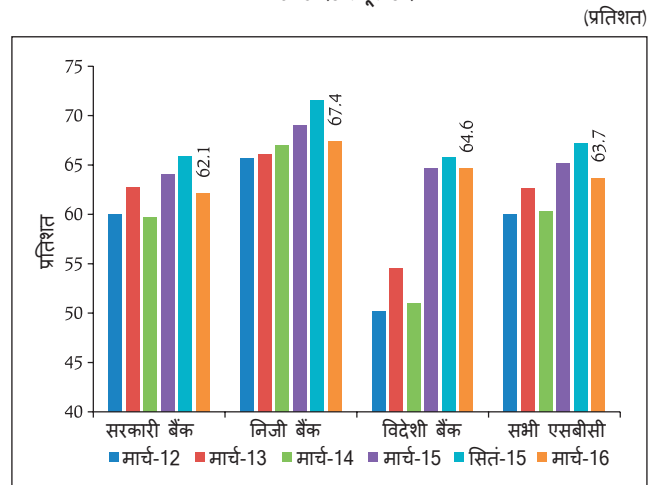
2.3 सितंबर 2015 और मार्च 2016 के बीच प्रणालीगत स्तर पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात में बढ़ोत्तरी हुई। हालांकि इसी अवधि में टियर - I लीवरेज अनुपात³ में कोई परिवर्तन न होते हुए 6.8 प्रतिशत रहा (चार्ट 2.2)।

2.4 सभी एसबीसी की जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) की गहनता (डेंसिटी⁴) जिनमें पहले वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा रही थी, सितंबर 2015 और मार्च 2016 के बीच कम होकर 67.2 प्रतिशत से 63.7 हो गई। यह गिरावट व्यापक आंकड़ों पर आधारित थी (चार्ट 2.3)।

आस्ति गुणवत्ता

2.5 सकल अग्रिम के प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सकल अनर्जक अग्रिम⁵ (जीएनपी) सितंबर 2015 और मार्च 2016 के बीच आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के पश्चात 5.1 से तेजी से बढ़कर 7.6 हो गया (अध्याय III के 3.8 से 3.9 पैराग्राफ देखें)। इसी अवधि के दौरान पुनर्संचित मानक अग्रिम अनुपात में तेजी से कमी होने पर वह 6.2 प्रतिशत से 3.9 प्रतिशत हो गई जिसके परिणामस्वरूप कुल दबावग्रस्त अग्रिम⁶ अनुपात में मामूली रूप से बढ़ोत्तरी होकर वह 11.3

चार्ट 2.3: आरडब्ल्यूए डेंसिटी



स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां

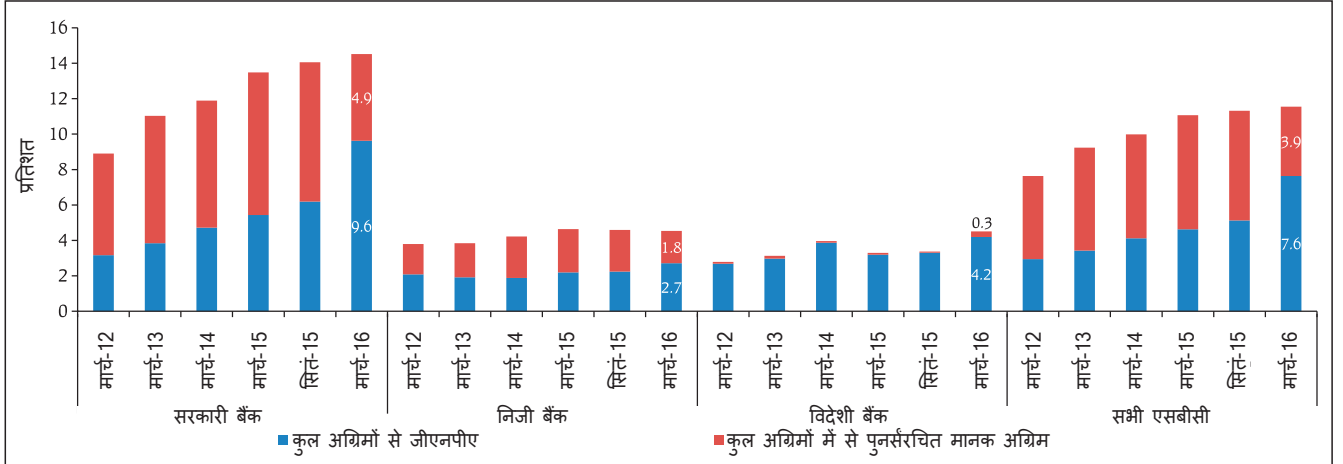
³ टियर I लीवरेज अनुपात को कुल आस्तियों की तुलना में टियर I पूंजी अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। कुल आस्तियों में तुलनपत्र से इतर मर्दों के समतुल्य ऋण शामिल हैं।

⁴ कुल अस्तियों से कुल आरडब्ल्यूए के अनुपात को आरडब्ल्यूए डेंसिटी परिभाषित किया गया है। कुल आस्तियों में तुलनपत्र से इतर मर्दों के समतुल्य ऋण शामिल हैं।

⁵ यहां 'अग्रिमों' और 'ऋणों' को आपस में प्रतिस्थापित करके उपयोग किया गया है।

⁶ आस्ति गुणवत्ता का विश्लेषण करने के प्रयोजन के लिए दबावग्रस्त अग्रिमों को जीएनपीए और पुनर्संचित मानक अग्रिमों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है।

चार्ट 2.4: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

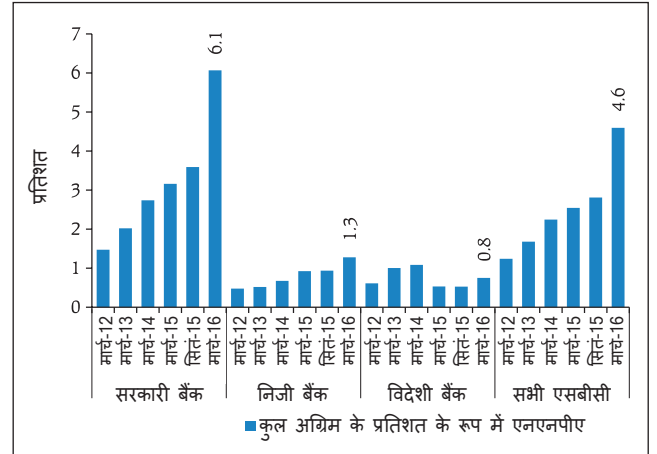


स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां

प्रतिशत से 11.5 प्रतिशत हो गया। सरकारी बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियों का अनुपात 14.5 प्रतिशत रहा जोकि सबसे ज्यादा था जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और विदेशी बैंकों (एफबी) का दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात 4.5 प्रतिशत दर्ज किया गया (चार्ट 2.4)।

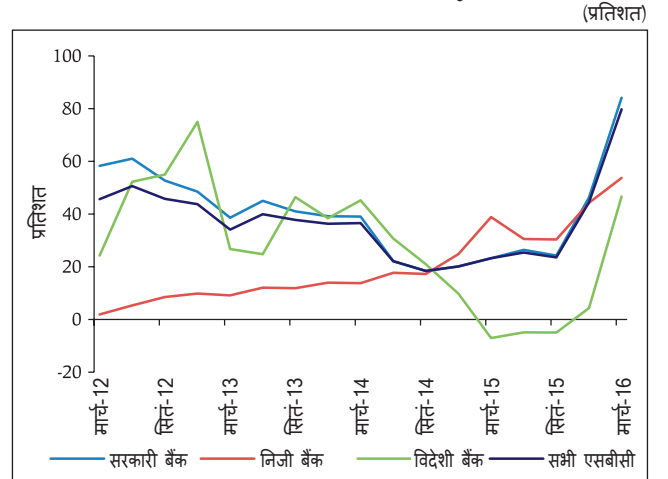
2.6 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए सकल निवल अग्रिम के प्रतिशत की तुलना में निवल अनर्जक अग्रिम (एनएनपीए) सितंबर 2015 और मार्च 2016 के बीच 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान, बैंक-समूह स्तर पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों का एनएनपीए अनुपात 3.6 प्रतिशत से बढ़कर 6.1 प्रतिशत, निजी बैंकों के बैंकों का 0.9 प्रतिशत से बढ़कर 1.3 प्रतिशत तथा विदेशी बैंकों का 0.5 से बढ़कर 0.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट 2.5)।

चार्ट 2.5: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का एनएनपीए



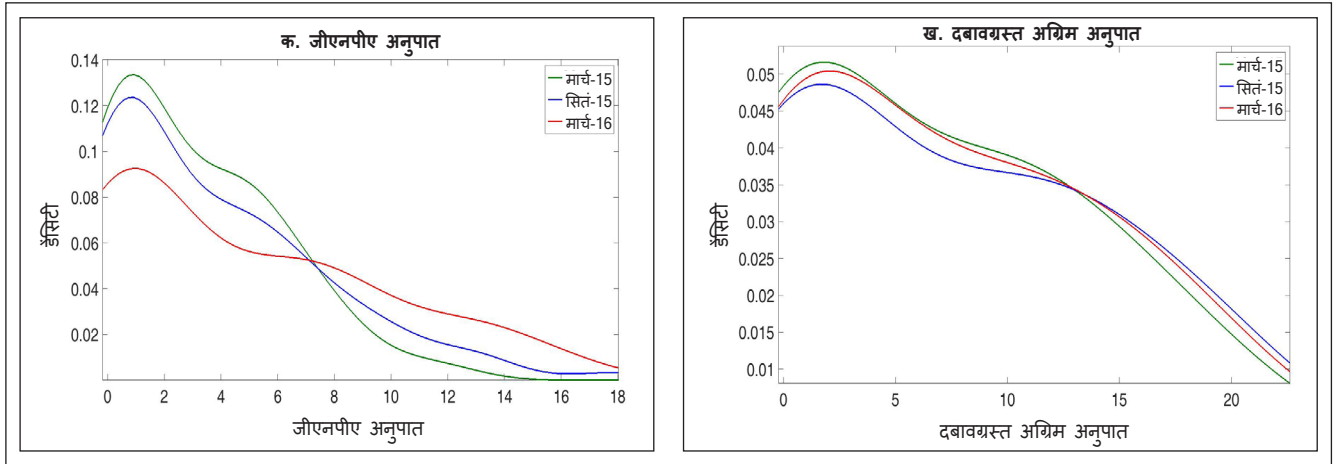
स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.6: जीएनपीए की वर्ष दर वर्ष वृद्धि



स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.7: आस्ति गुणवत्ता की संभाव्यता घनत्व कार्यप्रणाली



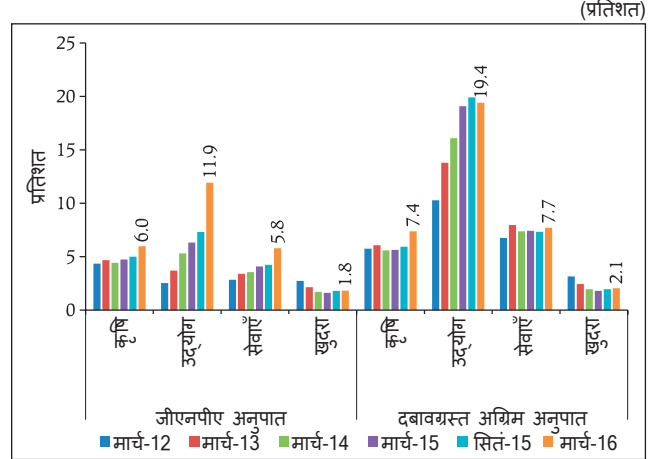
नोट: संभाव्यता वितरण को केरनल डेंसिटी एस्टीमेट का प्रयोग करते हुए आँका गया है।
 स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉक की गणनाएं।

चलता है कि पुनर्चित अग्रिम के बढ़ते हुए अनुपात को अनर्जक के रूप में माना जाता है (चार्ट 2.7)।

2.9 प्रमुख क्षेत्रों के बीच, औद्योगिक क्षेत्र का दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात सितंबर 2015 और मार्च 2016 के दौरान 19.9 प्रतिशत से घटकर 19.4 प्रतिशत तक आ गया। यद्यपि इस क्षेत्र का जीएनपीए अनुपात में तीव्र वृद्धि हुई और वह 7.3 प्रतिशत से 11.9 प्रतिशत हो गया। खुदरा ऋणों पर कम कम दबाव बना रहा (चार्ट 2.8)।

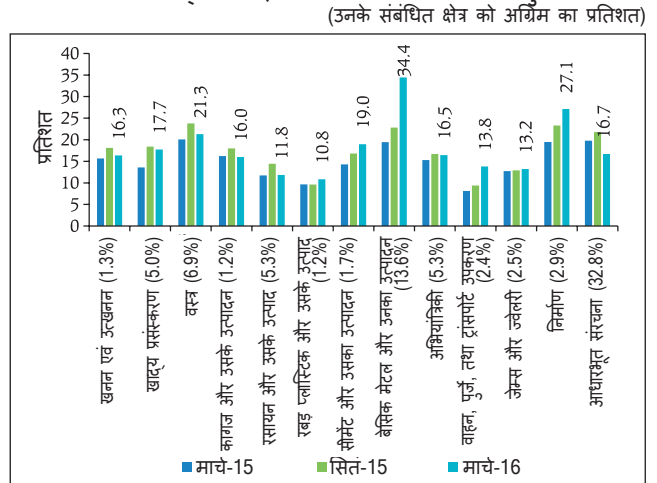
2.10 औद्योगिकी क्षेत्र के प्रमुख उप-क्षेत्रों के बीच 'बुनियादी धातु तथा धातु उत्पादों' को मार्च 2016 के अनुसार सबसे अधिक दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात का कारण माना गया, जिसके बाद 'निर्माण' तथा 'वस्त्र उद्योग' का क्रम आता है। यह ध्यान देने योग्य है कि 'आधारभूत संरचना' क्षेत्र का दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात सितंबर 2015 और मार्च 2016 के बीच 21.8 प्रतिशत से घटकर 16.7 प्रतिशत तक आ गया (चार्ट 2.9)।

चार्ट 2.8: बड़े क्षेत्रों में आस्ति गुणवत्ता



स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां

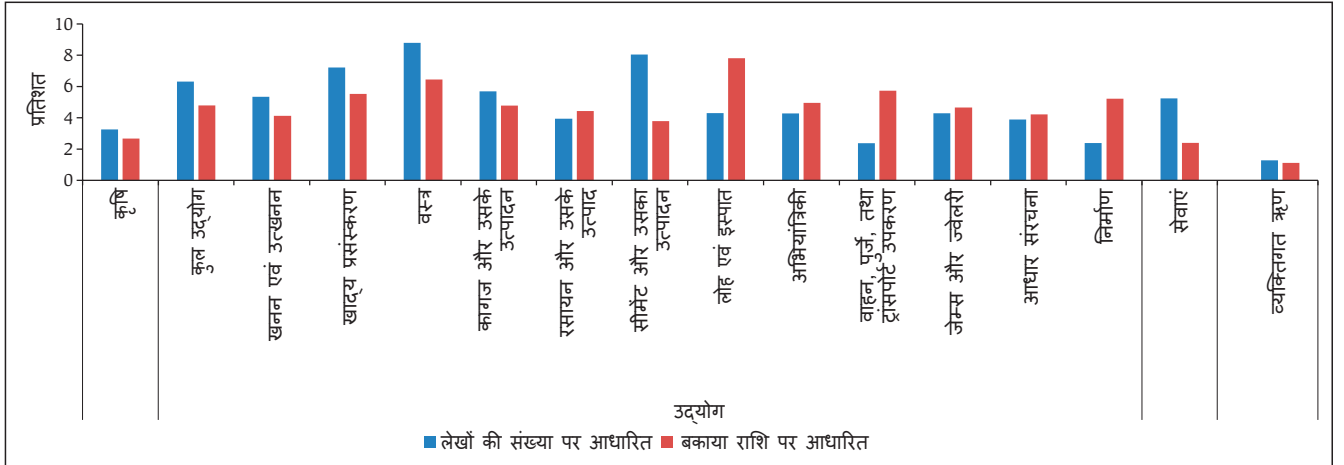
चार्ट 2.9: उद्योग के बड़े उप-क्षेत्रों का दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात



नोट: कोष्ठक में दी गई संख्या उद्योग के कुल ऋण में संबंधित उप क्षेत्रों के ऋण का हिस्सा है।

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.10: मानक खार्तो का एनपीए श्रेणी में वार्षिक स्लीपेज - क्षेत्रवार
(जनवरी से दिसंबर 2015)



स्रोत: बेसिक सांख्यिकी विवरणियाँ, भारिबैं

2.11 दूसरी ओर, दिसंबर 2015⁷ के दौरान प्रमुख क्षेत्रों/ उप-क्षेत्रों के वार्षिक स्लीपेज से पता चलता है कि वस्त्र उद्योग में 8.8 प्रतिशत (पर अनर्जक (एनपीए) श्रेणी में स्लीपिंग (slipping) करने वाले) मानक लेखें एनपीए श्रेणी में अगत जो सबसे अधिक संख्या है। उसके बाद 8.0 प्रतिशत पर सीमेंट उद्योग का क्रम आता है। बकाया

राशियों के संबंध में लौह और इस्पात उद्योग में 7.8 प्रतिशत का उच्चतम स्लीपेज देखा गया, और वस्त्र उद्योग में 6.4 प्रतिशत का स्लीपेज देखा गया (चार्ट 2.10)। इस संदर्भ में, विभिन्न क्षेत्रों में जारी अत्यधिक (prevailing) दबाव नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं (बॉक्स 2.10)

बॉक्स 2.1: बैंकिंग क्षेत्र में दबाव - सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपाय

सरकार ने डूबे हुए ऋणों की वसूली में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके लिए छह नये ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना के अलावा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

दबावग्रस्त इस्पात क्षेत्र के मामले में स्टील उत्पादों के लिए आयात शुल्क बढ़ाया गया, अतिरिक्त रक्षोपाय शुल्क लगाया गया तथा एक न्यूनतम आयात कीमत तय की गई। इसके अतिरिक्त, दीर्घावधि कोयला सहबद्धता की परिकल्पना की जा रही है।

सड़क क्षेत्र के मामले में रुकी हुई परियोजनाओं के मामलों को निपटाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHA) के अनुमोदन से उधारकर्ताओं के अनुरोध पर 'रियायत पाने वाले' को बदलने के व्यवस्था की गई ताकि निर्माण अवधि के दौरान भी बाहर करने का प्रावधान किया जा सके। रियायत पाने वालों को वाणिज्यिक परिचालन तिथि के दो वर्ष बाद 100% इक्विटी की अन्यत्र निवेश करने की भी अनुमति दी गई। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निधि की कमी के कारण प्रभावित हुई परियोजनाओं में बारगी निधि प्रवाह के साथ हस्तक्षेप करेगा ताकि ये परियोजनाएँ पूरी की जा सकें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कई दबावग्रस्त परियोजनाओं के प्रीमियम के रिकॉस्ट (Premium recast) को अनुमोदन दिया है। हाईब्रिड वार्षिक मॉडल तथा

टाल-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल जैसी नई संरचना को अपनाया जा रहा है। इसके अलावा परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए पर्यावरण / वन संबंधी अनुमति लेने जैसे कार्य को डी-लिंक कर दिया गया है।

विद्युत क्षेत्र के लिए वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय तथा परिचालन स्थिति को मजबूत करने के लिए एक योजना⁸ शुरू की गई है। इस योजना में संबंधित राज्य सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के 75 प्रतिशत ऋण के अधिग्रहण की कल्पना है। सरकार ने कोयला लिकेज तथा कोयला ब्लॉकों की निलामी की प्रक्रिया में सुधार किया है। इसके अलावा सरकार ने रुकी पड़ी गैस आधारित बिजली परियोजनाओं को विद्युत प्रणाली विकास निधि (PSDF) के माध्यम से सपोर्ट प्रदान करने के साथ-साथ रि-गैसीफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (आरएलएनजी) की निलामी भी शुरू की है।

वस्त्र उद्योग से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए रोजगार में निवेश के लिए एक बारगी पूंजी सब्सिडी प्रदान करने तथा वस्त्र मूल्य श्रृंखला के प्रौद्योगिकी बहुल क्षेत्रों के लिए एक "संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना" की रूपरेखा बनाई गई है।

⁷ इस अवधि के दौरान वार्षिक स्लीपेज की गणना एनपीए में परिवर्तित हो रहे मानक अग्रिम और इस अवधि की शुरुआत में दिए गए मानक अग्रिमों के अनुपात के आधार पर की गई थी। क्षेत्रगत स्लीपेज आंकड़े रिजर्व बैंक की बैंकिंग सांख्यिकी विवरणी से लिए गए थे। नवीनतम आंकड़े दिसंबर 2015 तक के उपलब्ध थे।

⁸ उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेस योजना (उदय)।

2.12 आकार की दृष्टि से रु.200 मिलियन से रु.500 मिलियन श्रेणी के ऐसे ऋण जो खातों की संख्या तथा बकाया राशि पर आधारित थे, उनमें 2015 के दौरान 6.2 प्रतिशत की सबसे अधिक गिरावट (स्लीपेज) दर्ज की गई। इसी प्रकार की गिरावट रु.500 मिलियन से रु.1000 मिलियन के श्रेणी के ऋणों में भी देखी गई। बकाया राशि पर आधारित कुल गिरावट का अनुपात 3.2 प्रतिशत रहा (चार्ट 2.11)

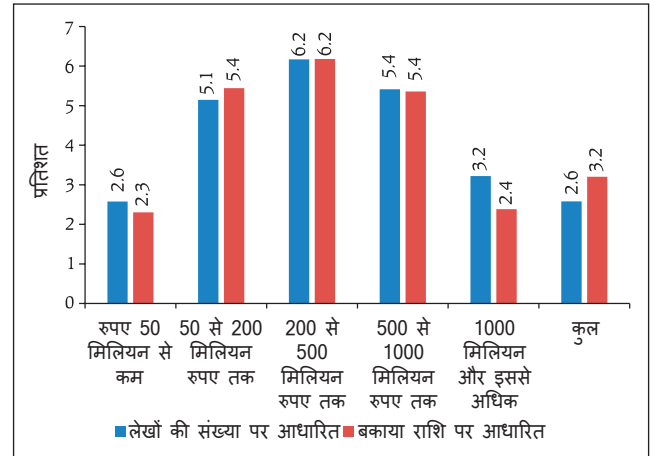
बड़े उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता⁹

2.13 बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए को कम करने के निरंतर प्रयास के रूप में सेंट्रल डिपोजिटरी ऑफ इन्फोर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स¹⁰ (सीआरआईएलसी) आंकड़ों को एकत्रित कर उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा प्रणाली को रेड फ्लैग्ड खातों, धोखाधड़ी वाले खातों का पता लगाने एवं विशेष उल्लेख वाले खातों-2¹¹ (एसएमए-2) की अद्यतन स्थिति, संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) तथा नॉन-कॉपरेटिव ऋणदाताओं की स्थिति पता करने के लिए सुदृढ़ किया गया है। यह प्रणाली काफी हद तक स्थिर हो गई है तथा बैंक इसके द्वारा बड़े उधारकर्ताओं की आस्ति गुणवत्ताकी निगरानी के लिए तथा संभावित ऋणदाताओं के ऋण मूल्यांकी के लिए आंकड़ों का उपयोग कर रहे हैं।

2.14 सितंबर 2015 और मार्च 2016 के बीच कुल ऋण में बड़े उधारकर्ताओं का हिस्सा 56.8 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है। इसी अवधि के दौरान जीएनपीए में भी उनका हिस्सा 83.4 प्रतिशत से बढ़कर 86.4 प्रतिशत हो गया है(चार्ट 2.12)।

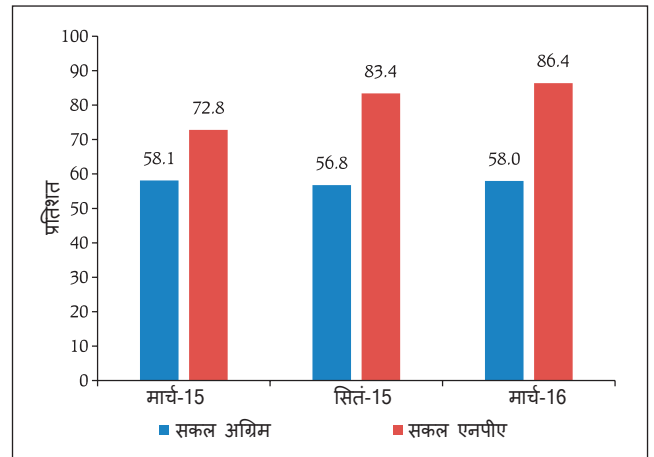
2.15 बड़े उधारकर्ताओं के एसएमए-2 श्रेणी के अग्रिमों में सितंबर 2015 और मार्च 2016 के बीच 40.5 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आई तथा पुनर्संचित मानक अग्रिमों में 25 प्रतिशत की गिरावट हुई जिसके साथ उनके जीएनपीए में 66.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो काफी हद तक पुनर्वर्गीकरण को दर्शाती है। तथापि, एसएमए-1 श्रेणी के बड़े उधारकर्ताओं का अग्रिम सितंबर 2015 और मार्च

चार्ट 2.11 : मानक खातों का एनपीए श्रेणी में वार्षिक स्लीपेज - ऋण के आकार के अनुसार (जनवरी से दिसंबर 2015)



स्रोत: बेसिक सांख्यिकी विवरणियाँ, भारिबैं

चार्ट 2.12: एससीबी के ऋण पोर्टफोलियो में बड़े उधारकर्ताओं का हिस्सा



स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियाँ

⁹ एक बड़े उधारकर्ता के रूप में उस उधारकर्ता को परिभाषित किया जाता है जो कुल निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर 50 मिलियन तथा इससे अधिक रखता है।

¹⁰ सीआरआईएलसी डेटाबेस बैंक के वैश्विक परिचालनों को दर्शाता है।

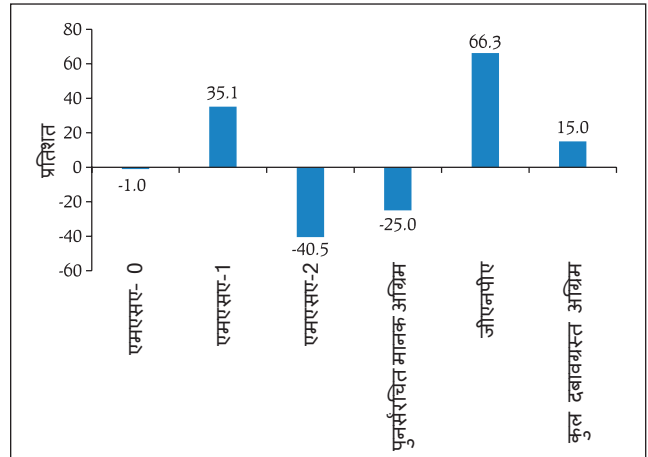
¹¹ ऋण खाते के एनपीए में परिवर्तित होने से पहले बैंकों को चाहिए कि वे एसएमए की तीन सब-एसेट श्रेणी बनाकर खातों में आरंभिक दबाव का पता लगाएं। i) एसएमए-0: मूलधन अथवा ब्याज भुगतान 30 दिनों से अधिक विलंबित नहीं हैं लेकिन खाता आरंभिक दबाव के संकेत को दर्शा रहा हो, ii) एसएमए-1: मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान, 31 से 60 दिनों के बीच विलंबित है तथा iii) एसएमए-2: मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान 61 से 90 दिनों के बीच विलंबित है।

2016 के बीच तेजी से 35.1 प्रतिशत तक बढ़ गया (चार्ट 2.13)।

2.16 बड़े उधारकर्ताओं का जीएनपीए अनुपात सितंबर 2015 से मार्च 2016 के दौरान 7.0 प्रतिशत से 10.6 प्रतिशत तक बढ़ गया और यह वृद्धि सभी बैंक समूहों में स्पष्ट थी। इस संबंध में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 12.9 प्रतिशत का उच्चतम जीएनपीए अनुपात दर्ज किया। दूसरी तरफ, उसी अवधि के दौरान बड़े उधारकर्ताओं का एसएमए-2 अनुपात बैंक समूहों में घट गया (चार्ट 2.14)।

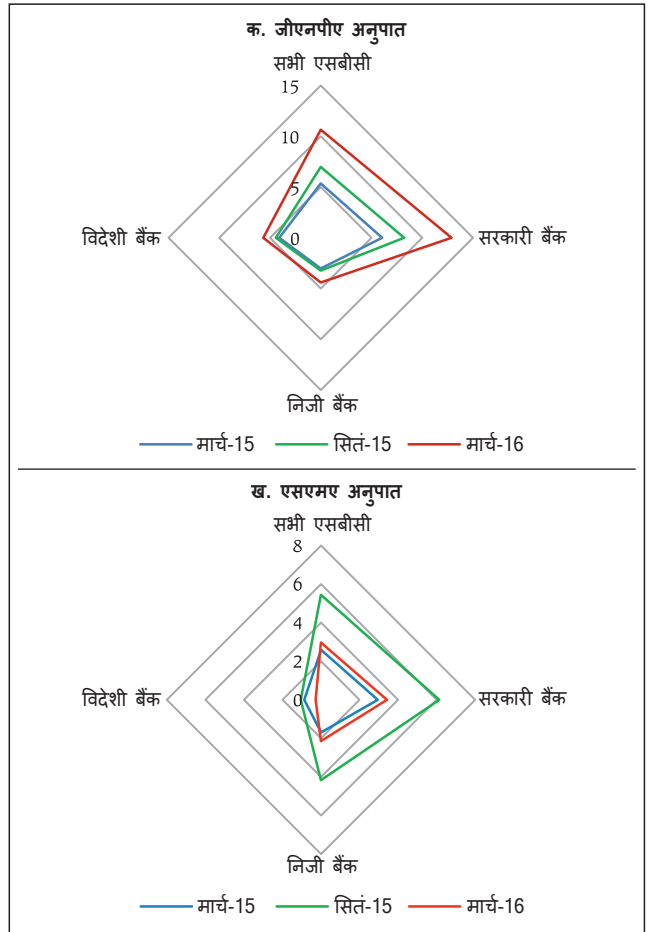
2.17 बड़े उधारकर्ताओं की कुल बकाया उधार राशि में मानक अग्रिमों का हिस्सा सितंबर 2015 और मार्च 2016 के बीच 84.1 प्रतिशत से घटकर 83.2 प्रतिशत तक आ गया। शीर्ष 100 उधारकर्ताओं (बकाया निधिक राशि के संबंध में) को दिया गया ऋण कुल बड़े उधारकर्ताओं को दिए ऋण में 27.9 प्रतिशत रहा और सभी एससीबी के ऋण का 16.2 प्रतिशत था। सभी बड़े उधारकर्ताओं के जीएनपीए की तुलना में इन 100 बड़े उधारकर्ताओं के हिस्सेदारी जो सितंबर 2015 में 3.4 प्रतिशत थी, मार्च 2016 में तेजी से बढ़कर 22.3 प्रतिशत होना पुनः पुनर्वर्गीकरण को दर्शाता है (सारणी 2.1)।

चार्ट 2.13 सितंबर-15 और मार्च-16 के बीच बड़े उधारकर्ताओं की आस्ति गुणवत्ता के प्रतिशत में बदलाव



स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.14: बड़े उधारकर्ताओं का जीएनपीए तथा एसएमए-2 (सकल अग्रिम का प्रतिशत)



स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां

सारणी 2.1: एससीबी का बड़े उधारकर्ताओं के प्रति एकसोजर (प्रतिशत)

	मार्च-15	सितं-15	मार्च-16*
बड़े उधारकर्ताओं की बकाया कुल निधिक राशि की संरचना			
i. मानक	86.2	84.1	83.2
ii. पुनर्संचित मानक	8.4	8.9	6.2
ii. उपमानक	1.7	2.0	3.3
iv. संदिग्ध	3.0	4.2	6.6
v. हानी	0.7	0.8	0.7
शीर्ष 100 उधारकर्ता			
i. कुल सकल अग्रिमों की तुलना में बकाया निधिक राशि	28.1	27.5	27.9
ii. कुल जीएनपीए की तुलना में बकाया निधिक राशि में जीएनपीए	18.3	15.6	16.2
iii. बड़े उधारकर्ताओं के कुल जीएनपीए का जीएनपीए	0.8	3.4	22.3
iv. एससीबी के कुल जीएनपीए का जीएनपीए	0.7	2.9	19.3

नोट: * अनंतमि आंकड़े

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां

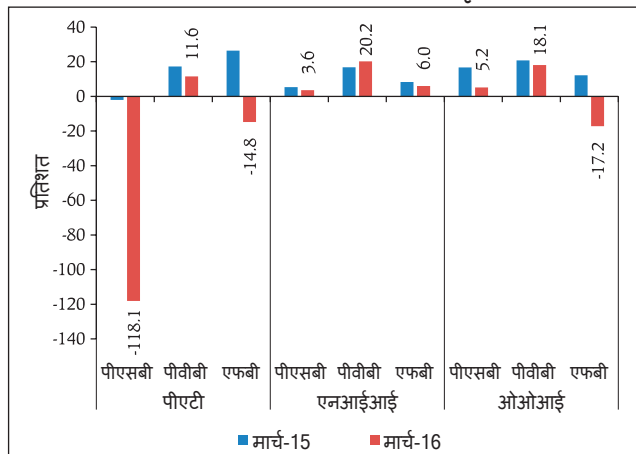
लाभप्रदता

2.18 एससीबी का आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) दोनों, जो मार्च 2015 में क्रमशः 0.8 प्रतिशत और 9.3 प्रतिशत थे मार्च 2016 में घटकर 0.4 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत रह गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कर पश्चात लाभ (पीएटी) में 43.0 प्रतिशत की गिरावट आयी। इसका मुख्य कारण जोखिम प्रावधान तथा राइट-ऑफ में अत्यधिक उच्च वृद्धि का होना रहा (सारणी 2.2)।

2.19 बैंक समूहों के बीच सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 2015-16 के दौरान वर्ष दर वर्ष आधारित पीएटी में गिरावट दर्ज की जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों ने इसमें 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई (चार्ट 2.15)।

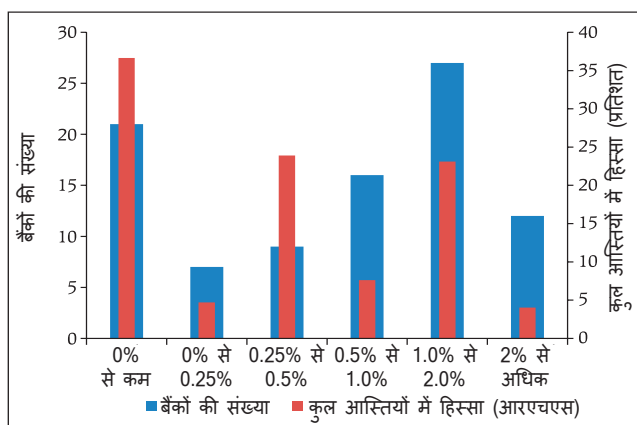
2.20 आस्तियों पर प्रतिलाभ (वार्षिकी) के बैंकवार वितरण से पता चलता है कि एससीबी की कुल आस्तियों में 37 प्रतिशत हिस्से के साथ 21 एससीबी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ऋणात्मक आरओए दर्ज किया। इसके अतिरिक्त, कुल आस्तियों में 5 प्रतिशत के हिस्से के साथ 7 बैंकों ने 0 से 0.25 प्रतिशत के बीच आरओए दर्ज किया है (चार्ट 2.16)।

चार्ट 2.15: आय के साधन: वर्ष दर वर्ष वृद्धि



नोट: एनआईआई= निवल ब्याज आय, ओओआई= अन्य परिचालित आय
 स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.16: आरओए (वार्षिक) पर आधारित एससीबी का वितरण (मार्च 2016)



नोट: मार्च 2016 के अनुसार मेडियन आरओए (वार्षिक) 0.76 प्रतिशत था।
 स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां

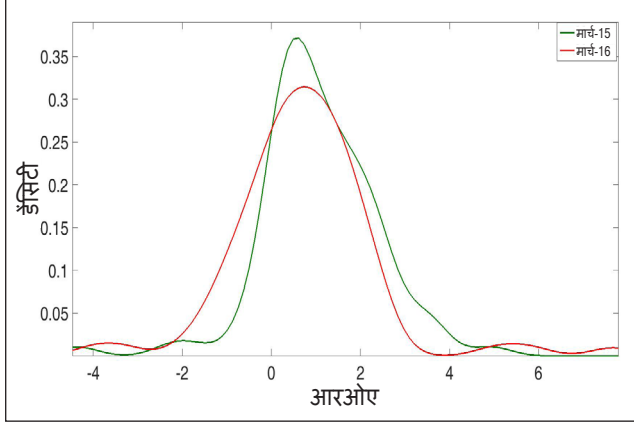
सारणी 2.2: एससीबी की लाभप्रदता

(प्रतिशत)

	आस्तियों पर प्रतिलाभ	इक्विटी पर प्रतिलाभ	वर्ष दर वर्ष वृद्धि					
			पीएटी	प्रावधानीकरण एवं कर वृद्धि पूर्व अर्जन	निवल ब्याज आय	अन्य परिचालगत आय	जोखिम प्रावधान	बढ़ा खाता
मार्च-12	1.1	13.4	14.6	15.3	15.8	7.4	35.6	-13.1
मार्च-13	1.0	12.9	12.9	9.9	10.8	14.4	10.2	-8.5
मार्च-14	0.8	9.5	-14.1	9.5	11.7	16.6	41.9	80.3
मार्च-15	0.8	9.3	10.1	11.4	8.5	17.4	7.0	23.4
मार्च-16	0.4	4.8	-43.0	11.9	8.3	6.7	86.2	27.3

नोट: आरओए तथा आरओई वार्षिक आंकड़े हैं जबकि वृद्धि की गणना वर्ष दर वर्ष आधार पर की जाती है।
 स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.17 आरओए की संभाव्यता सघनता कार्यप्रणाली



नोट: संभाव्यता वितरण को नॉन-पैरामेट्रिक केरनल डेंसिटी एस्टीमेट का प्रयोग करते हुए लाया गया।

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

2.21 बैंकवार आरओए की संभाव्यता घनत्व कार्यप्रणाली से पता चलता है कि अधिकतर बैंकों का 2014-15 की तुलना में 2015-16 में कम आरओए रहा (चार्ट 2.17)।

जोखिम

बैंकिंग स्थिरता सूचक

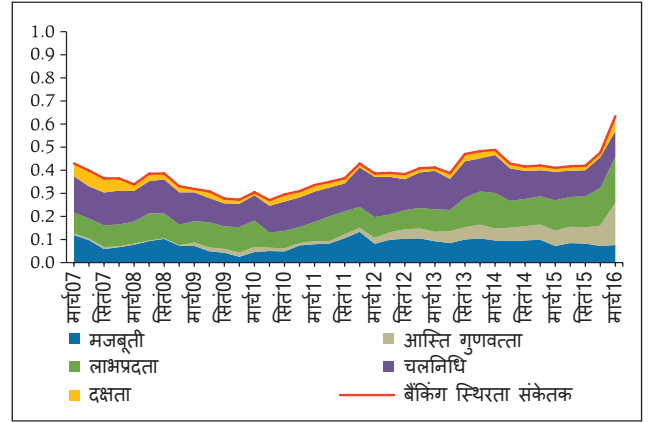
2.22 बैंकिंग स्थिरता संकेतक (बीएसआई)¹² दर्शाता है कि पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट¹³ के प्रकाशन के बाद से बैंकिंग क्षेत्र के लिए जोखिम तेजी से बढ़ गए हैं। बीएसआई के विश्लेषण की प्रवृत्तियों से पता चलता है कि बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता की स्थिति जो 2010 के मध्य में बिगड़नी प्रारंभ हो गई थी, वह अब और भी खराब हो गई है। मार्च 2016 की छमाही के अंत के दौरान खराब आस्ति गुणवत्ता तथा निम्न लाभप्रदता जोखिमों में वृद्धि के कारक हैं (चार्ट 2.18 तथा 2.19)।

आघात-सहनीयता -दबाव परीक्षण

समष्टिगत दबाव परीक्षण - ऋण जोखिम¹⁴

2.23 समष्टिगत आर्थिक आघातों के विरुद्ध भारतीय बैंकिंग प्रणाली का लचीलापन प्रणाली, बैंक समूह तथा क्षेत्रगत स्तर पर ऋण जोखिम के लिए समष्टि आर्थिक दबाव परीक्षणों की ऋणखलाओं के आधार पर था। इन परीक्षणों में परिकल्पित जोखिम परिदृश्य शामिल थे जिसमें मध्यम और अत्यधिक जोखिम को दर्शाने वाली

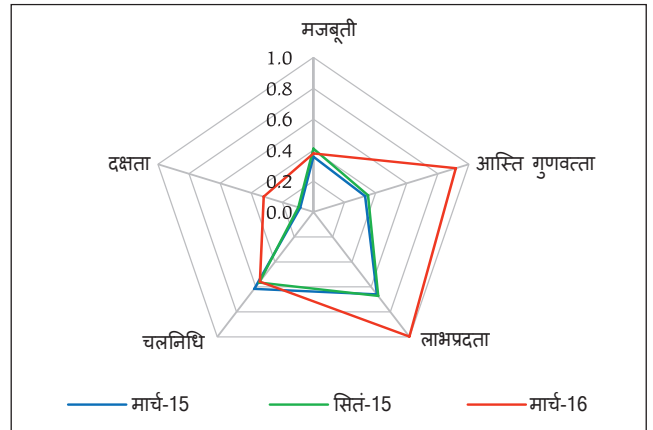
चार्ट 2.18 बैंकिंग स्थिरता संकेतक



नोट: संकेतक अंकों मूल्य में वृद्धि निम्न स्थिरता को दर्शाती है। प्रत्येक पहलू की चौड़ाई, जोखिम में इसके अंश को दर्शाती है।

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

चार्ट 2.19 बैंकिंग स्थिरता मानचित्र



नोट: केंद्र से दूरी जोखिम वृद्धि को दर्शाती है।

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

¹² विभिन्न बीएसआई आयामों के तहत उपयोग की गई पद्धति तथा मूल संकेतक का ब्योरा अनुबंध 2 में दिया गया है।

¹³ एफएसआर, दिसंबर 2015 (सितंबर 2015 के अंत तक के डाटा के संदर्भ में)।

¹⁴ विस्तृत कार्यप्रणाली अनुबंध 2 में दी गई है।

एक आधार रेखा और दो प्रतिकूल समष्टि आर्थिक परिदृश्य शामिल हैं। प्रतिकूल परिदृश्य का आधार मध्यम जोखिम के लिए एक मानक विचलन (एसडी) तक और अत्यधिक जोखिम के लिए दो मानक विचलन (10 वर्ष के ऐतिहासिक आंकड़े) तक लिया गया था (चार्ट 2.3)¹⁵।

ऋण जोखिम¹⁷

2.24 समष्टिगत दबाव परीक्षण से पता चलता है कि आधार रेखा परिदृश्य की स्थिति में जीएनपीए अनुपात जो मार्च 2016 में 7.6 प्रतिशत था वह बढ़कर मार्च 2017 में 8.5 प्रतिशत हो सकता है। यदि भविष्य में समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ती हैं, तो जीएनपीए अनुपात अत्यधिक दबाव की स्थिति में मार्च 2017 तक बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो सकता है। इस प्रकार के परिदृश्य के तहत एससीबी का प्रणाली स्तर का सीआरएआर जो मार्च 2016 में 13.2 प्रतिशत था वह घटकर मार्च 2017 तक 11.5 प्रतिशत हो सकता है (चार्ट 2.20)।

2.25 बैंक समूहों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का जीएनपीए अनुपात सर्वाधिक बना रह सकता है। आधार रेखा परिदृश्य

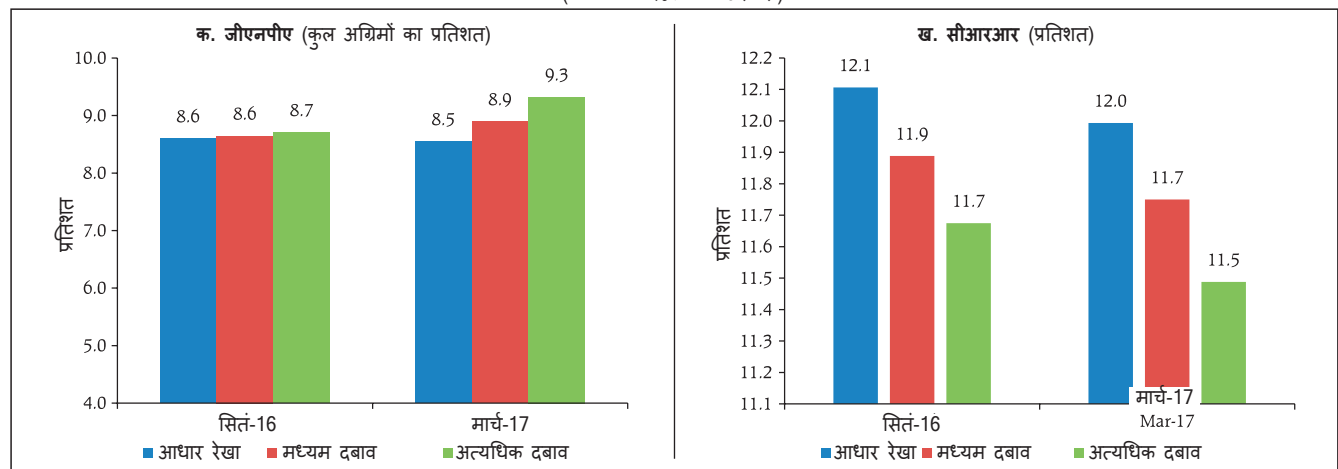
सारणी 2.3: समष्टि आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत मान्यताएँ (2016-17)¹⁶
(प्रतिशत)

समष्टि तथ्य	आधार रेखा	मध्यम दबाव	अत्यधिक दबाव
आधार मूल्य पर जीवीए में वृद्धि	7.6	5.5	2.9
जीडीपी की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा	3.5	4.6	5.9
सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति	5.1	6.9	9.1
भारत औसत उधार दर	11.3	11.9	12.6
जीडीपी की तुलना में पण्य निर्यात अनुपात	12.6	11.1	9.3
जीडीपी की तुलना में चालू घाटा शेष अनुपात	-1.3	-2.4	-4.8

नोट: जीवीए=योजित सकल मूल्य

के तहत उनका जीएनपीए अनुपात जो मार्च 2016 में 9.6 प्रतिशत था, बढ़कर मार्च 2017 में 10.1 प्रतिशत हो सकता है। किन्तु, अत्यधिक दबाव परिदृश्य में यह मार्च 2017 तक 11.0 प्रतिशत तक पहुँच सकता है। आधार रेखा परिदृश्य के तहत, निजी बैंकों का जीएनपीए अनुपात मार्च 2016 के 2.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2017 तक 3.1 प्रतिशत हो सकता है और अत्यधिक दबाव परिदृश्य में बढ़कर 4.9 प्रतिशत हो सकता है। अत्यधिक दबाव परिदृश्य में सरकारी क्षेत्र के बैंक मार्च 2016 के 11.6 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2017 तक लगभग 10.3

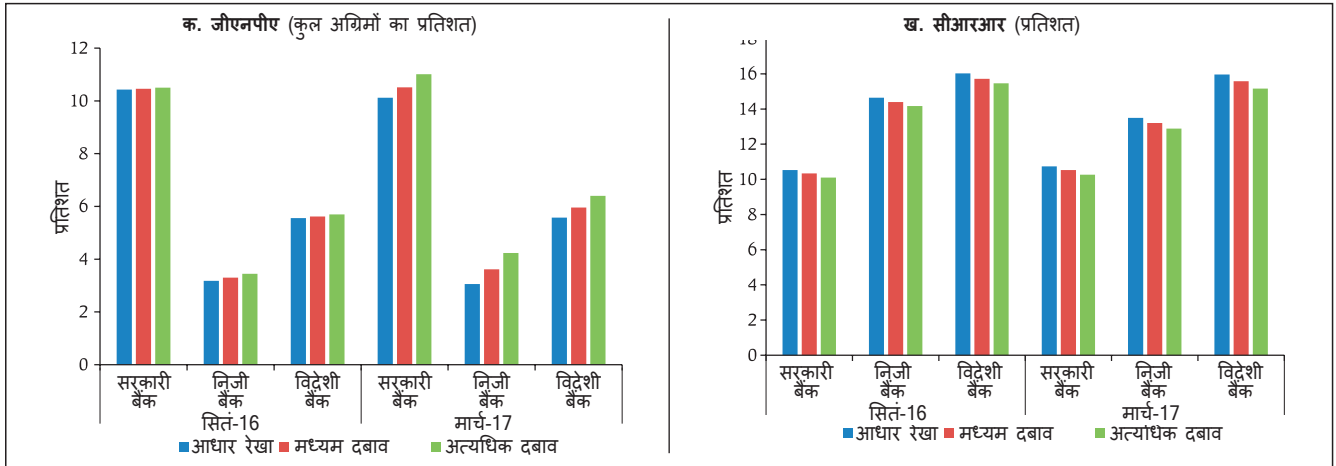
चार्ट 2.20: एसबीसी के प्रणालीगत स्तर पर जीएनपीए अनुपात तथा सीआरएआर का अनुमान
(विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत)



नोट: 1. प्रणालीगत स्तर के जीएनपीए का अनुमान तीन अलग-अलग, किन्तु पूरक अर्थमिक्तिक मॉडलों का प्रयोग करते हुए किया गया: मल्टीवेरियट रियेशन, वेक्टर आटोरियेशन (जिसमें, मैक्रो वेरिफेबलस की ऋण गुणवत्ता पर प्रतिक्रिया के प्रभाव तथा पारस्परिक क्रिया प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है) एवं क्वांटाइल रियेशन (जिसमें टेल रिस्क को हिसाब में लिया जाता है तथा समष्टि आर्थिक आघातों के अस्थिर प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है)। इन तीनों मॉडलों का औसत जीएनपीए चार्ट में दिया गया है।
2. सीआरएआर का अनुमान यह मानकर लगाया गया है कि पूंजी रिज़र्व में 25 प्रतिशत का न्यूनतम लाभ अंतरण किया गया है जो परंपरागत पूर्वानुमान के अनुसार है।
स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

¹⁵ आघातों (मानक विचलन के गुणक के रूप में) की मात्रा समय (तिमाही अवधि) के साथ बढ़ाई गयी।
¹⁶ ये दबावग्रस्त परिदृश्य कठोर और रुढ़िवादी मूल्यांकनपरक हैं जो कि कल्पित हैं। यहाँ संदर्भ में शामिल अत्यंत प्रतिकूल आर्थिक स्थितियों के संबंध में यह समझा जाए कि वे पूर्वानुमान अथवा प्रत्याशित परिणाम हैं।
¹⁷ जीएनपीए अनुपात का प्रणालीगत स्तर इस अनुमान पर आधारित है कि इसमें आगे भी एनपीए होगा (एक्यूआर परिदृश्य पश्चात) जो भविष्य में जीएनपीए अनुपात के लिए सहयोगी घटक होगा।

चार्ट 2.21 बैंक समूहवार जीएनपीए अनुपात एवं सीआरएआर का अनुमान (विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत)



नोट: 1. बैंक समूहवार जीएनपीए का अनुमान दो अलग-अलग, किन्तु पूरक अर्थमतिक मॉडलों का प्रयोग करते हुए किया गया है; मल्टीवेरियेट रिगेशन, वेक्टर आटोरिगेशन। दोनों मॉडलों का औसत जीएनपीए चार्ट में दिया गया है।
 2. सीआरएआर का अनुमान परंपरागत पूर्वानुमान के तहत पूंजी रिजर्व में न्यूनतम लाभ अंतरण 25 प्रतिशत की दर पर किया गया है। इसमें हित धारकों द्वारा किया गया किसी प्रकार का पूंजी अंतर्वेशन शामिल नहीं है।
स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

प्रतिशत का सबसे कम सीआरएआर दर्ज कर सकते हैं (चार्ट 2.21)।

2.26 क्षेत्रगत ऋण जोखिम के लिए किए गए समष्टिगत दबाव परीक्षण से पता चलता है कि अत्यधिक दबावग्रस्त परिदृश्य में, चुनिंदा सात क्षेत्रों में, लोह और इस्पात उद्योग (जिसका मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार 30.4 प्रतिशत के साथ जीएनपीए अनुपात सबसे अधिक था) का जीएनपीए अनुपात मार्च 2017 तक बढ़कर 33.6 प्रतिशत

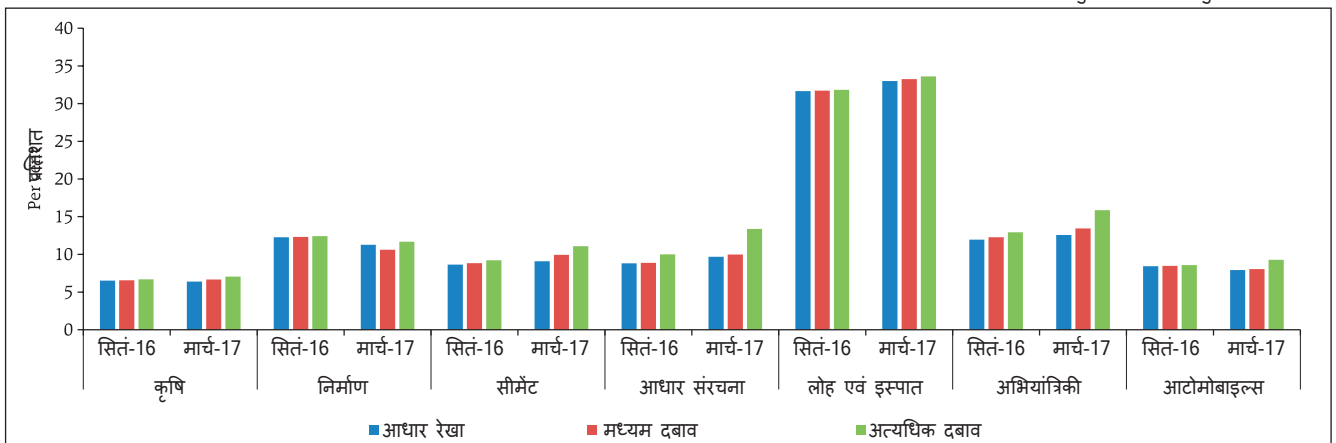
तक हो सकता है जिसके बाद अभियांत्रिकी (10.9 प्रतिशत से बढ़कर 15.9 प्रतिशत) और आधारभूत संरचना (7.1 प्रतिशत से बढ़कर 13.4 प्रतिशत) का क्रम आता है (चार्ट 2.22)।

संवेदनशीलता विश्लेषण : बैंक स्तर पर¹⁸

2.27 विभिन्न परिस्थितियों²¹ में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों²⁰ की सुरक्षितता और लचीलापन जांचने के लिए एकल घटक पर कई संवेदनशीलता दबाव जांच¹⁹ (टॉप-डाउन)

चार्ट 2.22: विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत अनुमानित क्षेत्रगत जीएनपीए

(कुल अग्रिमों की तुलना में प्रतिशत)



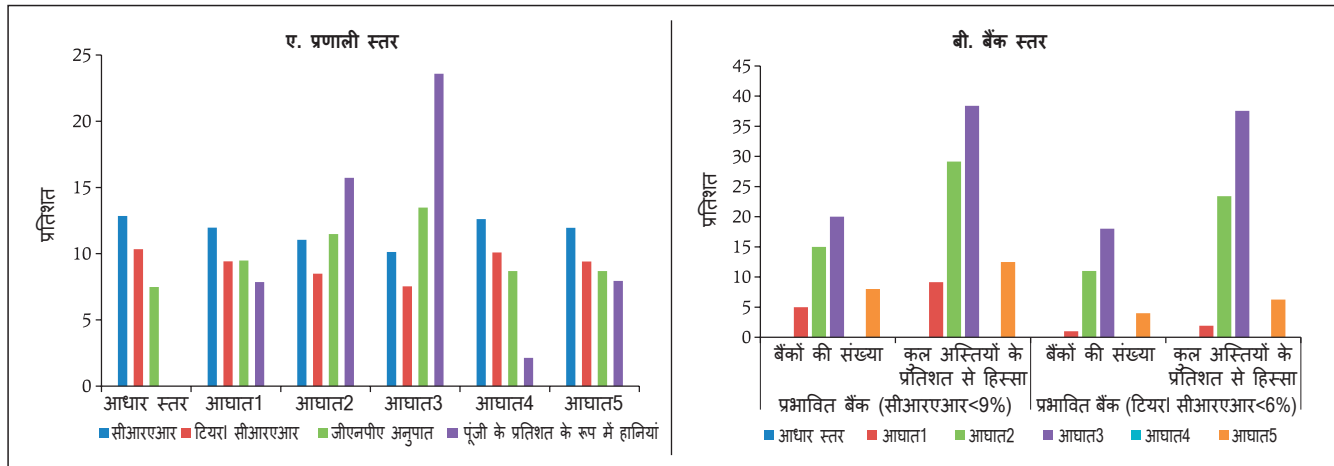
स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

¹⁸ संवेदनशीलता विश्लेषण ऋण जोखिम के लिए समष्टिगत दबाव परीक्षण के लिए अतिरिक्त रूप में किया गया है। जहां पूर्व के आघात आस्ति गुणवत्ता (जीएनपीए) पर आरोपित किए गए थे, वहीं बाद वाले आघात प्रतिकूल समष्टि-आर्थिक स्थितियों पर आरोपित गए। इसके साथ ही, समष्टिगत दबाव परीक्षण प्रणाली, प्रमुख बैंक समूह और क्षेत्रगत स्तर पर किए गए जहां संवेदनशीलता का विश्लेषण प्रणालीगत और बैंक स्तर पर अलग-अलग किए गए।

¹⁹ दबाव परीक्षण की विस्तृत जानकारी के लिए अनुबंध 2 देखें

²⁰ कुल बैंकिंग क्षेत्र की 99 फीसदी परिसंपत्तियों के लेखांकन के लिए 60 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नमूने के लिए एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण तनाव परीक्षण आयोजित किया गया।

चार्ट 2.23: ऋण जोखिम- आघात और असर



आघात 1: जीएनपीए पर 1 एसडी का आघात
 आघात 2: जीएनपीए पर 2 एसडी का आघात
 आघात 3: जीएनपीए पर 3 एसडी का आघात
 आघात 4: पुनर्चित अग्रिमों में से 30 प्रतिशत सकल अनर्जक अस्तित्व बन गए (अवमानक श्रेणी)
 आघात 5: पुनर्चित अग्रिमों में से 30 प्रतिशत को बड़ा खाता में डाला गया(हानि श्रेणी)- बड़े खाते में डाला गया
 नोट: चुनिंदा 60 एससीबी की प्रणाली
 स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ की गणनाएं।

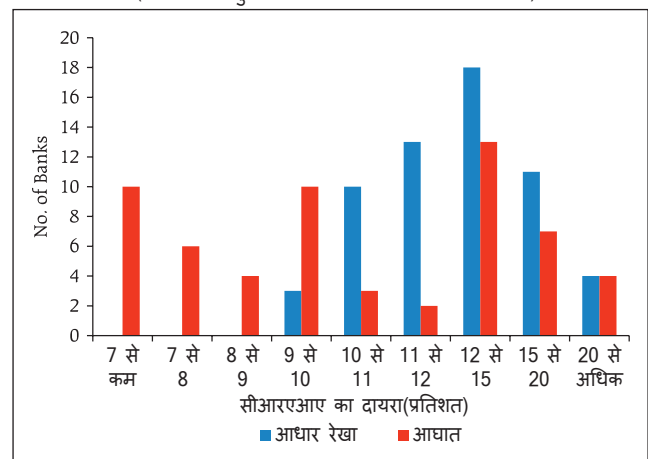
किए गए। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण, ब्याज दर और चलनिधि जोखिम के संबंध में लचीलापन का टॉप-डाउन संवेदनशीलता विश्लेषण के माध्यम से अध्ययन किया गया जिसके लिए अत्युच्च सत्यापासी शॉक का उपयोग किया गया। यही शॉक बॉटम-अप दबाव जांच के लिए चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर उपयोग में लाए गए। पाए गए परिणाम मार्च 2016 के आंकड़ों पर आधारित हैं।

ऋण जोखिम

2.28 बैंकों पर हुए विभिन्न स्टैटिक क्रेडिट आघात के असर से यह पाया गया कि सीआरएआर का प्रणालीगत स्तर 9 प्रतिशत की न्यूनतम आवश्यकता से ऊपर बना रहा। 3 एसडी²² का तीव्र आघात (अर्थात, 60 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का औसत सकल एनपीए अनुपात 7.5 प्रतिशत से 13.5 प्रतिशत तक बढ़ जाने की स्थिति में) देने पर यह पाया गया कि प्रणालीगत सीआरएआर और टियर-I सीआरएआर क्रमशः 10.1 और 7.5 प्रतिशत तक नीचे आ गया। तीव्र आघात की स्थिति में प्रणालीगत स्तर पर पूंजीगत हानि लगभग 23.6 प्रतिशत हो सकती है। ऐसे आघात लाभ पर अधिक असर करेंगे क्योंकि यदि सकल एनपीए अनुपात 0.74 एस.डी बढ़कर 9.0 प्रतिशत हो जाना है तो अनुसूचित वाणिज्य बैंक 2015-16 का अपना सारा वार्षिक लाभ गंवा देंगे।

अलग-अलग बैंकों की बात को तो दबाव जांच के नतीजों से यह पाया गया कि 20 बैंक, जिनकी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल अस्तियों में 38.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, सकल एनपीए में 3 एसडी की बड़ी वृद्धि हो जाने पर वे आवश्यक सीआरएआर बनाए रखने में विफल हो सकते हैं। इन दबाव जांच का सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर गहरा असर पड़ा। सरकारी क्षेत्र के 17 बैंकों का सीआरएआर 9 प्रतिशत तक नीचे आ गया (चार्ट 2.23 और 2.24)।

चार्ट: 2.24 सीआरएआर के अनुसार बैंकों का वितरण (जीएनपीए अनुपात पर 3 एसडी के आघात के अंतर्गत)



नोट: चुनिंदा 60 एससीबी की प्रणाली
 स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ की गणनाएं।

²¹ विभिन्न कल्पित परिदृश्यों के तहत निर्धारित किए गए आघात अत्यधिक हैं किंतु संभव हैं।

²² जीएनपीए अनुपात के मानक विचलन का अनुमान 2003 के तिमाही आंकड़ों के आधार पर किया गया है। एक एसडी आघात एनपीए में लगभग 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बराबर होता है।

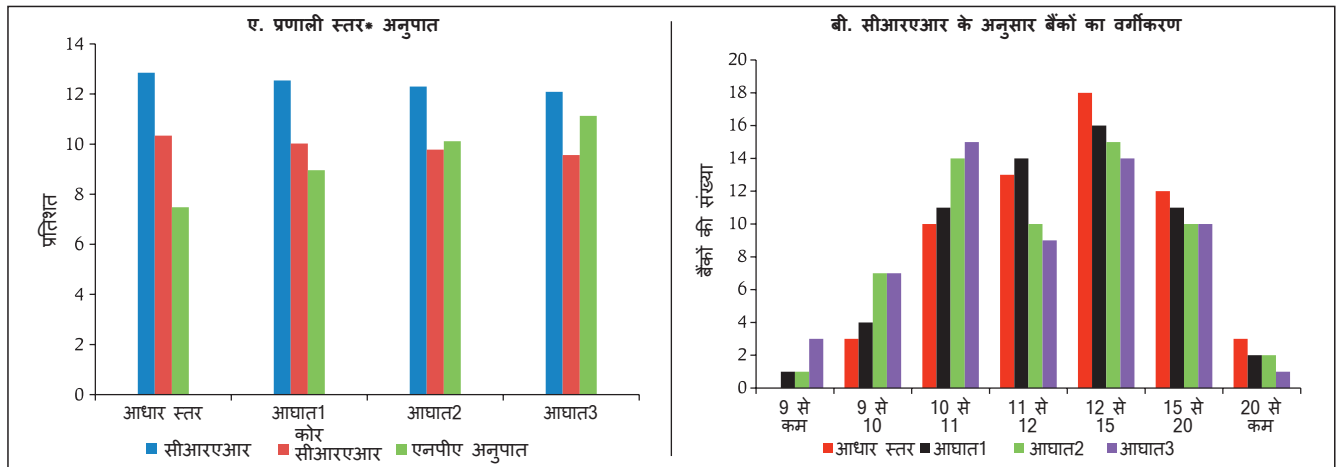
ऋण संकेंद्रण जोखिम

2.29 बैंकों पर ऋण संकेंद्रण जोखिम संबंधी दबाव जांच की गई जिसमें अलग-अलग सर्वोच्च ऋणधारकों को उनके अपन-अपने ऋण के अनुसार शामिल किया गया। इस जांच में यह पाया गया कि (तीन अलग-अलग परिस्थितियों में) तीन बैंकों पर विशिष्ट असर²³ पड़ा जिनकी आस्तियां लगभग 5.3 प्रतिशत के बराबर थीं। ये बैंक इनमें से कम से कम किसी एक परिस्थिति में 9 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखने में विफल हो सकते हैं। संभाव्य परिस्थितियों में सर्वोच्च व्यक्तिगत ऋणधारकों की चूक से लगभग 3 प्रतिशत पूंजीगत हानि हो सकती है। सर्वोच्च दो व्यक्तिगत ऋणधारक यदि चूक करते हैं तो पूंजीगत हानि 5 प्रतिशत और यदि सर्वोच्च तीन व्यक्तिगत ऋणधारक चूक करते हैं तो यह हानि 6 प्रतिशत हो सकती है। सर्वोच्च तीन व्यक्तिगत ऋणधारक यदि चूक करते हैं तो कर-पूर्व-लाभ (पीबीटी) पर 112 प्रतिशत असर पड़ सकता है। सर्वोच्च व्यक्तिगत ऋणधारक यदि चूक करते हैं पीबीटी में 45 प्रतिशत तक की हानि हो सकती है और यदि सर्वोच्च दो व्यक्तिगत ऋणधारक चूक करते हैं तो यह हानि 81 प्रतिशत हो सकती है। यदि यह माना जाए कि सर्वोच्च

एक, दो और तीन ऋणधारक चूक करेंगे तो प्रणालीगत स्तर पर सीआरएआर पर 31, 55 और 76 आधार अंकों का असर पड़ेगा (चार्ट 2.25)।

2.30 उच्च व्यक्तिगत ऋणधारकों के दबावग्रस्त अग्रिमों का विचार करें तो बैंकों के ऋण संकेंद्रण जोखिम संबंधी दबाव जांच में 8 बैंकों पर जिनकी कुल एकत्रित आस्तियां 12.1 प्रतिशत है, (अलग-अलग परिदृश्यों में) अच्छा खासा असर पड़ा²⁴ और वे इनमें से किसी एक परिस्थिति होने पर भी 9 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखने में विफल हो सकते हैं। संभाव्य परिस्थितियों में यदि दबावग्रस्त सर्वोच्च ऋणधारक विफल होते हैं तो पूंजीगत हानि 4 प्रतिशत तक हो सकती है। सर्वोच्च दो दबावग्रस्त ऋणधारक यदि विफल होते हैं तो पूंजीगत हानि 6.9 प्रतिशत और यदि सर्वोच्च तीन दबावग्रस्त ऋणधारक विफल होते हैं तो यह हानि 9.4 प्रतिशत हो सकती है। सर्वोच्च तीन दबावग्रस्त ऋणधारक यदि विफल होने हैं तो पीबीटी पर 162 प्रतिशत असर पड़ सकता है। सर्वोच्च दबावग्रस्त ऋणधारक यदि विफल होते हैं तो पीबीटी में 70 प्रतिशत की हानि हो सकती है और यदि सर्वोच्च दो दबावग्रस्त ऋणधारक चूक करते हैं तो यह

चार्ट 2.25: ऋण संकेंद्रण जोखिम: वैयक्तिक उधारकर्ता- एक्सपोजर

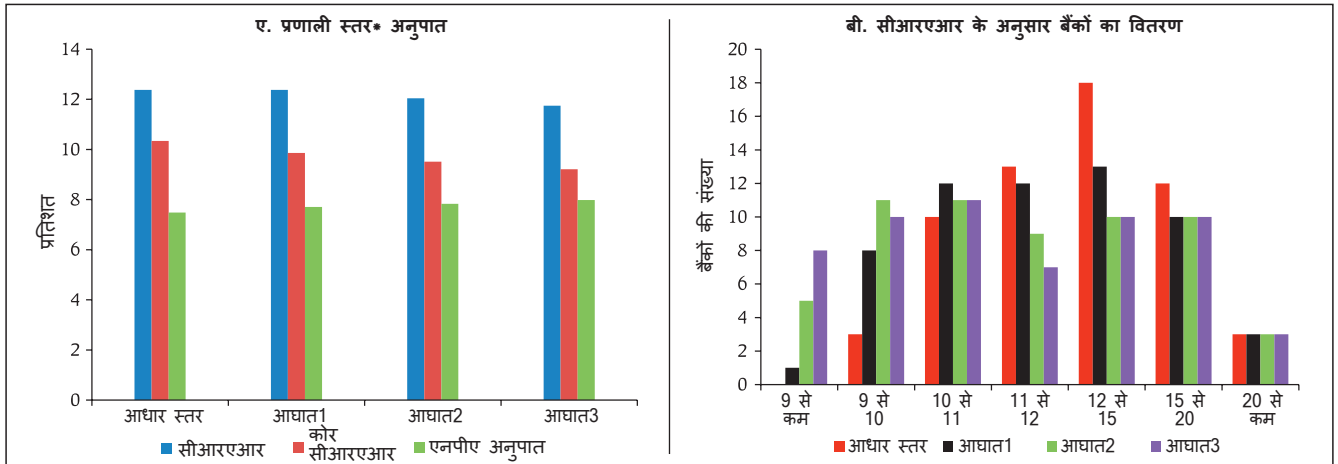


आघात 1: शीर्षतम वैयक्तिक उधारकर्ता चूक करता है
 आघात 2: शीर्ष दो वैयक्तिक उधारकर्ता चूक करता है
 आघात 3: शीर्ष तीन वैयक्तिक उधारकर्ता चूक करता है
नोट: चुनिंदा 60 एससीबी की प्रणाली
स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ की गणनाएं।

²³ चूककर्ता के मामले में, उधारकर्ता को अवमानक की श्रेणी में माना जाएगा। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए अनुबंध 2 देखें।

²⁴ विफल होने पर, उधारकर्ता को हानि की श्रेणी में माना जाएगा। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए अनुबंध 2 देखें।

चार्ट 2.26: ऋण संकेंद्रण जोखिम: वैयक्तिक उधारकर्ता- दबावग्रस्त अग्रिम



आघात 1: शीर्षतम दबावग्रस्त वैयक्तिक उधारकर्ता चूक करता है
 आघात 2: शीर्ष दो दबावग्रस्त वैयक्तिक उधारकर्ता चूक करता है
 आघात 3: शीर्ष तीन दबावग्रस्त वैयक्तिक उधारकर्ता चूक करता है
 नोट: *चुनिंदा 60 एससीबी की प्रणाली
 स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ की गणनाएं।

हानि 120 प्रतिशत हो सकती है। यदि यह माना जाए कि सर्वोच्च एक, दो और तीन दबावग्रस्त ऋणधारक विफल होते हैं तो प्रणालीगत स्तर पर सीआरएआर पर 47,81 और 110 आधार अंकों का असर पड़ेगा (चार्ट 2.26)।

2.31 सामूहिक ऋणधारकों संबंधी जानकारी के आधार पर, 10 अलग-अलग परिस्थितियों में बैंकों के ऋण संकेंद्रण जोखिम की दबाव जांच करने पर यह पाया गया कि प्रणालीगत स्तर पर 6 प्रतिशत और 9 प्रतिशत तक

की हानि²⁵ हो सकती है यदि यह माना जाए कि सर्वोच्च एक सामूहिक ऋणधारक या सर्वोच्च दो सामूहिक ऋणधारक चूक करते हैं। यदि सर्वोच्च पाँच सामूहिक ऋणधारक चूक करते हैं तो पूंजी में 18 प्रतिशत की हानि हो सकती है और अत्युच्च दबाव परिस्थितियों में यदि दस सर्वोच्च सामूहिक ऋणधारक चूक करते हैं तो यह हानि 28 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। ऐसी अत्युच्च स्थिति में लगभग 25 बैंक अपना 9 प्रतिशत सीआरएआर स्तर बनाए रखने में विफल हो जाएंगे (सारणी 2.4)।

सारणी 2.4: ऋण संकेंद्रण जोखिम: समूह उधारकर्ता - एक्सपोज़र

आघात	प्रणालीगत स्तर*			बैंक स्तर		
	सीआरएआर	मुख्य सीआरएआर	एनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानियां	प्रभावित बैंक (सीआरएआर<9%)	
आधार रेखा (आघात पूर्व)	12.9	10.3	7.5	---	बैंकों की संख्या	बैंकिंग प्रणाली में कुल आस्तियों का हिस्सा(% में)
आघात 1	शीर्ष 1 सामूहिक उधारकर्ता चूक करते हैं।	12.2	9.7	10.6	6	0.1
आघात 2	शीर्ष 2 सामूहिक उधारकर्ता चूक करते हैं।	11.7	9.2	12.8	9	8.2
आघात 3	शीर्ष 3 सामूहिक उधारकर्ता चूक करते हैं।	11.3	8.8	14.6	13	14.4
आघात 4	शीर्ष 4 सामूहिक उधारकर्ता चूक करते हैं।	11.0	8.5	16.3	16	20.8
आघात 5	शीर्ष 5 सामूहिक उधारकर्ता चूक करते हैं।	10.7	8.1	17.7	18	24.4
आघात 6	शीर्ष 6 सामूहिक उधारकर्ता चूक करते हैं।	10.4	7.8	19.0	20	24.6
आघात 7	शीर्ष 7 सामूहिक उधारकर्ता चूक करते हैं।	10.1	7.6	20.2	23	43.2
आघात 8	शीर्ष 8 सामूहिक उधारकर्ता चूक करते हैं।	9.9	7.3	21.4	25	48.7
आघात 9	शीर्ष 9 सामूहिक उधारकर्ता चूक करते हैं।	9.7	7.1	22.4	27	51.6
आघात 10	शीर्ष 10 सामूहिक उधारकर्ता चूक करते हैं।	9.6	7.0	23.4	28	51.6

नोट: *चुनिंदा 60 एससीबी की प्रणाली
 स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ की गणनाएं।

²⁵ चूककर्ता के मामले में, उधारकर्ता को अवमानक की श्रेणी में माना जाएगा। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए अनुबंध 2 देखें।

क्षेत्रगत ऋण जोखिम

2.32 उद्योग क्षेत्र को दिए गए ऋण संबंधी ऋण जोखिम की जांच क्षेत्रगत ऋण दबाव परीक्षण के माध्यम से करते हुए सकल एनपीए अनुपात को शॉक दिया गया और परिणामतः सकल एनपीए में एक निश्चित प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई। संवेदनशीलता विश्लेषण के परिणामों

से यह पता चलता है कि लाभप्रदता पर, जो कि पहले से कम है, संभाव्य शॉक का असर ध्यान देने योग्य होगा। उपक्षेत्रों पर पड़ने वाले शॉक से बैंकों की लाभप्रदता (पीबीटी) पर भी असर पड़ेगा, जबकि पूंजी पर सीमित असर होगा (सारणी 2.5)।

सारणी 2.5: क्षेत्रगत ऋण जोखिम: उद्योग -आघात एवं असर
(एनपीए अनुपात पर उत्तरोत्तर आघात:एनपीए अनुपात में नियत प्रतिशत अंकों की वृद्धि)

(प्रतिशत)

क्षेत्र		(ए) उद्योग	(ए 1) जिसमें से: केमिकल और केमिकल उत्पाद			(ए 2) जिसमें से: टेक्सटाइल			(ए 3) जिसमें से: आधार मेटल एंड मेटल उत्पाद(लोहा एवं इस्पात)									
क्षेत्र का प्रोफाइल																		
कुल अग्रिमों में क्षेत्र का हिस्सा		41.68	2.31			2.98			5.90									
पुनर्चित मानक अग्रिमों में क्षेत्र का हिस्सा		82.05	1.99			6.40			12.59									
कुल एनपीए-समय स्तर में क्षेत्र का हिस्सा		67.94	3.03			5.58			20.09									
क्षेत्रगत पुनर्चित मानक अग्रिम अनुपात		7.91	3.46			8.61			8.58									
प्रणाली का पुनर्चित मानक अग्रिम अनुपात		4.02	4.02			4.02			4.02									
आघात	पुनर्चित मानक अग्रिमों & पर आघात	अन्य मानक अग्रिमों#	उद्योग			(ए 1) जिसमें से: केमिकल और केमिकल उत्पाद			(ए 2) जिसमें से: टेक्सटाइल			(ए 3) जिसमें से: आधार मेटल एंड मेटल उत्पाद(लोहा एवं इस्पात)						
			क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर*			क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर*			क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर*						
			प्रणालीगत स्तर ओअर एनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि	प्रणालीगत स्तर ओअर एनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि	प्रणालीगत स्तर ओअर एनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि	प्रणालीगत स्तर ओअर एनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि				
आघात पूर्व की स्थिति			12.20	7.48	-	9.81	7.48	-	13.98	7.48	-	25.48	7.48	-				
आघात-1	0	2	14.20	8.31	4.51	77.86	11.81	7.53	0.20	3.46	15.98	7.54	0.25	4.36	27.48	7.60	0.43	7.41
आघात-2		5	17.20	9.56	11.27	194.65	14.81	7.60	0.50	8.65	18.98	7.63	0.63	10.89	30.48	7.78	1.07	18.53
आघात-3		10	22.20	11.65	22.54	389.29	19.81	7.71	1.00	17.30	23.98	7.78	1.26	21.79	35.48	8.07	2.15	37.06
आघात-4	15	2	15.38	8.81	6.10	105.26	12.33	7.54	0.22	3.83	17.27	7.58	0.32	5.54	28.77	7.67	0.56	9.74
आघात-5		5	18.38	10.06	12.86	222.05	15.33	7.61	0.52	9.02	20.27	7.67	0.70	12.07	31.77	7.85	1.21	20.86
आघात-6		10	23.38	12.14	24.13	416.70	20.33	7.72	1.02	17.67	25.27	7.82	1.33	22.97	36.77	8.15	2.28	39.39
आघात-7	15	2	15.38	8.81	8.48	146.37	12.33	7.54	0.28	4.82	17.27	7.58	0.51	8.74	28.77	7.67	0.93	16.05
आघात-8		5	18.38	10.06	15.24	263.16	15.33	7.61	0.58	10.01	20.27	7.67	0.88	15.28	31.77	7.85	1.57	27.16
आघात-9		10	23.38	12.14	26.51	457.81	20.33	7.72	1.08	18.66	25.27	7.82	1.52	26.17	36.77	8.15	2.65	45.69

नोट: & नए एनपीए की आस्ति श्रेणी के संबंध में मान्यताएं:

आघात1-3 शॉक रहित पुनर्चित मानक अग्रिम

आघात 4-6 अवमानक श्रेणी की तुलना में पुनर्चित मानक अग्रिम

आघात7-9 हानि श्रेणी की तुलना में पुनर्चित मानक अग्रिम

आघात के अंतर्गत क्षेत्रगत एनपीए में नियत प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। मानक अग्रिमों (पुनर्चित मानक अग्रिमों के अलावा) में से उत्पन्न होने वाले नए एनपीए के आघात पड़ने की स्थिति में अवमानक हो जाने की परिकल्पना की गई है।

* चुनिंदा 60 एससीबी की प्रणाली

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

2.33 ढांचागत खंड के लिए भी क्षेत्रगत ऋण दबाव परीक्षण किया गया था जिसमें पॉवर, ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्यूनिकेशन के कुछ उपक्षेत्रों को शामिल किया गया। इन परीक्षणों से पाया गया कि ढांचागत खंड को शॉक देने से बैंकों की लाभप्रदता पर अच्छाखासा असर पड़ेगा,

जिसमें पॉवर और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से आने वाला एकल क्षेत्र शॉक का असर सर्वाधिक महत्व का है (सारणी 2.6)।

2.34 कतिपय विशिष्ट उद्योगों के संबंध में क्षेत्रगत ऋण परीक्षण का विश्लेषण भी किया गया। इस विश्लेषण में इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और सीमेंट

सारणी 2.6: क्षेत्रगत ऋण जोखिम: आधारभूत संरचना -आघात एवं असर (एनपीए अनुपात पर उत्तरोत्तर आघात:एनपीए अनुपात में नियत प्रतिशत अंकों की वृद्धि)

(प्रतिशत)

क्षेत्र			(ए) आधारभूत संरचना			(ए 1) जिसमें से: ऊर्जा			(ए 2) जिसमें से: यातायात			(ए 3) जिसमें से: दूरसंचार						
क्षेत्र का प्रोफाइल																		
कुल अग्रिमों में क्षेत्र का हिस्सा			14.22			7.82			2.87			1.50						
पुनर्चित मानक अग्रिमों में क्षेत्र का हिस्सा			34.43			20.89			8.64			1.03						
कुल एनपीए-समग्र स्तर में क्षेत्र का हिस्सा			13.90			5.97			4.33			1.09						
क्षेत्रगत पुनर्चित मानक अग्रिम अनुपात			9.73			10.73			12.08			4.09						
प्रणाली का पुनर्चित मानक अग्रिम अनुपात			4.02			4.02			4.02			4.02						
आघात	पुनर्चित मानक अग्रिमों पर आघात	अन्य मानक अग्रिमों	(ए) आधारभूत संरचना						(ए 1) जिसमें से: ऊर्जा			(ए 2) जिसमें से: यातायात			(ए 3) जिसमें से: दूरसंचार			
			क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर*			क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर*			क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर*			क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर*		
				प्रणालीगत स्तर ओअर एनपीए अनुपात	पंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि		प्रणालीगत स्तर ओअर एनपीए अनुपात	पंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि		प्रणालीगत स्तर ओअर एनपीए अनुपात	पंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि		प्रणालीगत स्तर ओअर एनपीए अनुपात	पंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि
आघात पूर्व की स्थिति			7.31	7.48	-	-	5.71	7.48	-	-	11.28	7.48	-	-	5.42	7.48	-	-
आघात-1	0	2	9.31	7.77	1.16	20.06	7.71	7.64	0.61	10.55	13.28	7.54	0.24	4.14	7.42	7.51	0.16	2.75
आघात-2		5	12.31	8.19	2.90	50.14	10.71	7.87	1.53	26.38	16.28	7.62	0.60	10.34	10.42	7.56	0.40	6.87
आघात-3		10	17.31	8.90	5.81	100.29	15.71	8.26	3.06	52.76	21.28	7.77	1.20	20.68	15.42	7.63	0.80	13.74
आघात-4	15	2	10.77	7.97	1.53	26.42	9.32	7.76	0.83	14.41	15.09	7.59	0.33	5.73	8.03	7.52	0.18	3.03
आघात-5		5	13.77	8.40	3.27	56.50	12.32	8.00	1.75	30.24	18.09	7.68	0.69	11.94	11.03	7.57	0.41	7.15
आघात-6		10	18.77	9.11	6.18	106.65	17.32	8.39	3.28	56.62	23.09	7.82	1.29	22.28	16.03	7.64	0.81	14.03
आघात-7	15	2	10.77	7.97	2.53	43.67	9.32	7.76	1.44	24.87	15.09	7.59	0.58	10.06	8.03	7.52	0.22	3.80
आघात-8		5	13.77	8.40	4.27	73.75	12.32	8.00	2.36	40.70	18.09	7.68	0.94	16.27	11.03	7.57	0.46	7.92
आघात-9		10	18.77	9.11	7.17	123.90	17.32	8.39	3.88	67.08	23.09	7.82	1.54	26.61	16.03	7.64	0.86	14.79

नोट: &नए एनपीए की आस्ति श्रेणी के संबंध में मान्यताएं:

आघात-1-3 शॉक रहित पुनर्चित मानक अग्रिम

आघात 4-6 अवमानक श्रेणी की तुलना में पुनर्चित मानक अग्रिम

आघात-7-9 हानि श्रेणी की तुलना में पुनर्चित मानक अग्रिम

आघात के अंतर्गत क्षेत्रगत एनपीए में नियत प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। मानक अग्रिमों(पुनर्चित मानक अग्रिमों के अलावा)में से उत्पन्न होने वाले नए एनपीए के आघात पड़ने की स्थिति में अवमानक हो जाने की परिकल्पना की गई है।

* चुनिंदा 60 एससीबी की प्रणाली

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

सारणी 2.7: क्षेत्रगत ऋण जोखिम: चुनिंदा उद्योग
(एनपीए अनुपात पर उत्तरोत्तर आघात:एनपीए अनुपात में नियत प्रतिशत अंकों की वृद्धि)

(प्रतिशत)

क्षेत्र		अभियांत्रिकी				ओटोमोबाइल				निर्माण			सीमेंट				
क्षेत्र का प्रोफाइल																	
कुल अग्रिमों में क्षेत्र का हिस्सा		2.28				1.00				1.22			0.73				
पुनर्रचित मानक अग्रिमों में क्षेत्र का हिस्सा		3.50				1.10				2.00			1.31				
आघात	वर्तमान क्षेत्रगत जीएनपीए अनुपात पर क्रमागत आघात	अभियांत्रिकी				ओटोमोबाइल				निर्माण			सीमेंट				
		क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर*			क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर*			क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर*			क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर*		
			प्रणालीगत स्तर और एनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि		प्रणालीगत स्तर और एनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि		प्रणालीगत स्तर और एनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि				
आघात पूर्व की स्थिति	11.5	7.5	-	-	8.3	7.5	-	-	12.2	7.5	-	-	13.4	7.5	-	-	
आघात-1	2	13.5	7.5	0.2	3.2	10.3	7.5	0.1	1.2	14.2	7.5	0.1	1.8	15.4	7.5	0.1	0.9
आघात-2	5	16.5	7.6	0.5	7.9	13.3	7.5	0.2	3.1	17.2	7.5	0.3	4.4	18.4	7.5	0.1	2.2
आघात-3	10	21.5	7.7	0.9	15.8	18.3	7.6	0.4	6.1	22.2	7.6	0.5	8.8	23.4	7.6	0.3	4.4

टिप्पणी: # आघात के क्षेत्रगत एनपीए में अनुपात(एनपीए अनुपात पर उत्तरोत्तर आघात-वर्तमान एनपीए अनुपात पर अतिरिक्त) में नियत प्रतिशत की वृद्धि मानी गई है। मानक गई है। मानक अग्रिमों से उत्पन्न होने वाले नए एनपीए को आघात पड़ने की स्थिति पर विभिन्न आर्स्टि श्रेणियाँ (वर्तमान पैटर्न के अनुसार) में वितरित किया गया माना गया है।

*चुनिंदा 60 एससीबी की प्रणाली

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां स्टॉफ की गणनाएं।

उद्योग को शामिल किया गया। संवेदनशीलता विश्लेषण के नतीजों में पाया गया कि ऐसे शॉक से लाभप्रदता पर असर पड़ेगा जिससे इंजीनियरिंग क्षेत्र से होने वाला एकल उद्योग शॉक सर्वाधिक महत्व का है (सारणी 2.7)।

ब्याजदार जोखिम

2.35 बैंक की निवेश प्रयोजन वाली ऐसी प्रतिभूतियाँ जो बिक्री के लिए उपलब्ध है (एफएएस) और जो व्यापार के लिए रखी गई हैं (एचटीएफ), उनके प्रतिफल वक्र में 2.5 प्रतिशत के अंकों की समांतर वृद्धि से जो ब्याज-दर जोखिम उत्पन्न हुआ वह काबू में रखने योग्य प्रतीत होता है क्योंकि प्रणालीगत स्तर पर सीआरएआर पर लगभग 97 आधार अंकों का असर होगा। यदि अलग-अलग स्तर पर देखें तो छः बैंक, समग्र आस्तियां 11.6 प्रतिशत बनती हैं, बुरी तरह प्रभावित हुए और उनका सीआरएआर 9 प्रतिशत से नीचे चला गया। प्रणालीगत स्तर पर पूंजीगत हानि लगभग 8.6 प्रतिशत आकलित की गई थी। 2.5 प्रतिशत वे संभाव्य शॉक के कारण बैंकों की परिपक्वता तक आधारित (एचटीएम) निवेशसूची के प्रतिफल वक्र में

समांतर वृद्धि हुई जिसे यदि बाजार भाव से दर्शाया जाता है तो सीआरएआर में लगभग 227 आधार अंकों की लक्षणीय गिरावट आती है और 20 ऐसे बैंक बुरी तरह प्रभावित होते हैं जिनका सीआरएआर 9 प्रतिशत से नीचे गिर गया हो। प्रतिफल वक्र में समांतर गिरावट (2.5 प्रतिशत अंक) के संभाव्य शॉक से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंकिंग बहिर्यो²⁶ में उनके अंतिम वार्षिक पीबीटी में 45 प्रतिशत तक आय का असर होगा।

सारणी 2.8: ब्याज दर जोखिम-बैंक समूह-आघात एवं असर
(250 आधारभूत अंकों के आधार के तहत आईएनआर प्रतिफल वक्र में समानांतर ऊपर की ओर परिवर्तन)

(प्रतिशत)

	पीएसबी		पीवीसी		एफबी	
	एफएएस	एचएफटी	एफएएस	एचएफटी	एफएएस	एचएफटी
मॉडिफाइड इयूरेशन	4.2	4.7	2.4	3.9	1.2	2.0
कुल निवेश में हिस्सा	35.4	0.6	35.1	5.1	81.0	18.5
सीआरएआर में कमी (बीपीएस)	123		43		105	

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां स्टॉफ की गणनाएं।

²⁶ बैंकिंग बहिर्यो में आय के प्रभाव की गणना सिर्फ एक वर्ष के लिए की गई है जिसमें दर के प्रति संवेदनशील आस्तियों एवं देयताओं के एक्सपोजर अंतराल पर विचार किया गया है और एफएएस एवं एचएफटी पोर्टफोलियो पर विचार नहीं किया गया है।

चलनिधि जोखिम

2.36 सामान्यतः सांविधिक चलनिधि अनुपात में किए गए निवेश आकस्मिक तरलता संबंधी आघात को बर्दाश्त करने में बैंकों की मदद करते हैं। तरलता संबंधी जोखिम के विश्लेषण में बैंकों के बाबत उस परिदृश्य के प्रभाव को शामिल किया जाता है जहां जमाराशियों के निकालने का तांता लग जाता है तथा स्वीकृत साख के अप्रयुक्त अंश को प्राप्त करने की मांग बढ़ जाती है (इसमें अनाहरित कार्यशील पूंजी सीमा एवं अनाहरित वादाकृत साख सीमा शामिल की जाती है)। परिकल्पित स्थिति में गैर बीमाकृत जमाराशियों²⁷ के आहरण में वृद्धि होगी एवं उसके साथ ही साख/ऋण के लिए मांग बढ़ जाएगी जिसके परिणामस्वरूप स्वीकृत कार्यशील पूंजी ऋण एवं अपने ग्राहकों के प्रति क्रेडिट वादे की पूर्ति हेतु अप्रयुक्त सीमा के आहरण में वृद्धि होगी। यह अनुमान लगाया जाता है कि बैंक अपने उक्त दो कर्तव्यों की पूर्ति के लिए किसी बाह्य निधि की मदद के बिना अपने सांविधिक चलनिधि में किए गए निवेश के स्टाक से उसे(सांविधिक चल निधि अनुपात पोर्टफोलियो के पूर्ण अथवा एक अंश का प्रयोग करके) पूरा करेंगे। ऐसे निवेशों पर 10% हेयर कट/ मार्जिन परिकल्पित था। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संबंध में मार्च 2016 के डेटा पर आधारित दो दृष्टिकोण वाले टेस्ट/परीक्षण²⁸ किए गए थे।

2.37 पहले मामले में, यह कल्पना की गयी थी कि दबावग्रस्त स्थिति में तरलता संबंधी अपेक्षा की पूर्ति हेतु बैंकों को सांविधिक चलनिधियों में किए निवेश और अतिरिक्त नकदी प्रारक्षित अनुपात गत पूर्ण राशि उपलब्ध होगी जो संकट के दौरान विशिष्ट नीति के तहत प्रयोग में आएगी।

2.38 विश्लेषण से पता चलता है कि संकट की अवस्था में तरलता संबंधी दबाव होने पर अधिकांश बैंक (नमूने में शामिल 60 में से 49 बैंक) जमाराशियों के आकस्मिक तथा अप्रत्याशित आहरण की 25% मांग के साथ ही साथ अपनी वादागत क्रेडिट लाइन के 75% की पूर्ति सांविधिक चलनिधि में किए गए निवेश से पूरा कर सकेंगे (सारणी 2.9)।

2.39 दूसरा दृष्टिकोण तरलता कवरेज अनुपात³⁰ प्रणाली पर विचार करता है जिसमें सुलभ उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां³¹ बैंकों को प्रारंभिक आघातों को सहन करने में मदद करेंगी।

2.40 तरलता कवरेज अनुपात प्रणाली में अधिकांश बैंक (नमूने में शामिल 60 बैंकों में से 44 बैंक) अपनी उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों का प्रयोग करके जमाराशियों के लगभग 10% तक आकस्मिक एवं अप्रत्याशित आहरण तथा अपने ग्राहकों के प्रति साख सीमा संबंधी किए गए वादे के 75% अंश तक के प्रयोग के लिए हुई मांग के परिदृश्य / आघात को सहन/बर्दाश्त करने में सफल होंगे (तरलता कवरेज अनुपात के अंतर्गत मान्यताप्राप्त)(सारणी

सारणी - 2.9 चलनिधि जोखिम - आघात एवं असर
(चलनिधि सहयोग(सपोर्ट) के लिए बेशी सीआरआर के साथ में संपूर्ण एसएलआर का प्रयोग करते हुए)

आघात	संचयी (गैर बीमाकृत) जमाराशियों का आहरण (प्रतिशत)	संदर्भित प्रणाली के लिए उपलब्ध चलनिधि -युक्त आस्तियां (कुल आस्तियों का प्रतिशत)	परीक्षण में असफल ²⁹ होने वाले बैंकों की संख्या (चुनिदा 60 में से)	एससीबी की कुल आस्तियों की तुलना में दबावपूर्ण परिदृश्य में असफल होने वाले बैंकों की आस्तियों का हिस्सा (प्रतिशत)
आधार रेखा	-	20.9	-	-
आघात 1	10	12.4	1	0.6
आघात 2	20	6.7	4	1.5
आघात 3	25	3.7	11	12.1
आघात 4	30	1.6	30	46.4

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

²⁷ वर्तमान में, कुल जमाराशियों में गैर बीमाकृत जमाराशियों का हिस्सा लगभग 69 प्रतिशत है (स्रोत: डीआईसीजीसी, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में सांख्यिकी की हैंडबुक)।

²⁸ चलनिधि आघातों में गैर बीमाकृत जमाराशियों के हिस्से का आहरण तथा वचनबद्ध ऋण शृंखलाओं (स्वीकृत कार्यशील पूंजीगत सीमाओं के अप्रयुक्त हिस्से के साथ ही साथ उनके ग्राहकों के प्रति ऋण प्रतिबद्धताओं को भी शामिल किया गया है) की 75 प्रतिशत मांग भी शामिल है।

²⁹ दबावपूर्ण परिदृश्यों (आघात पड़ने पर) के अंतर्गत अपनी चलनिधि युक्त आस्तियों (दबावपूर्ण परिस्थितियों में चलनिधि युक्त आस्तियों का भंडार ऋणात्मक हो गया) की मदद से अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाने पर एक बैंक परीक्षण में असफल हुआ।

³⁰ चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी टूलस तथा एलसीआर प्रकटीकरण मानकों के संबंध में बासेल-III ढांचे के संबंध में दिशा निर्देश जो दिनांक 9 जून 2014 के परिपत्र डीबीओडी.बीपी बीसी 120/21.04.098/2013-14 के माध्यम से जारी किए गए। एलसीआर की शुरुआत चरणबद्ध ढंग से की जा रही है, जिसके तहत 1 जनवरी 2015 से न्यूनतम अपेक्षा 60 प्रतिशत है तथा 1 जनवरी 2019 को न्यूनतम 100 प्रतिशत तक पहुंचना आवश्यक है।

³¹ दबाव परीक्षण करने के लिए, एचक्यूएलए की गणना में अपेक्षित सीआरआर के अतिरिक्त अंश, एसएलआर निवेश के अतिरिक्त अंश, एनडीटीएल के 2 प्रतिशत एसएलआर निवेशों (एमएसएफ के अधीन) तथा एनडीटीएल के 8 प्रतिशत के अतिरिक्त एसएलआर निवेशों (28 नवंबर 2014 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी. सं 52/21.04.098/2014-15 एवं 11 फरवरी 2016 के परिपत्र डीबीआर. बीपी. बीसी. सं 77/21.04.098 के अनुसार) को शामिल किया गया।

2.10)। किसी ऐसे संकट के समय जिसमें हर बार बढ़े हुए आघात आएँ, बैंक विशिष्ट नीतिगत उपायों के तहत अपेक्षानुसार पैरा 2.38 (सारणी 2.9) में यथा विवेचित शेष सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए किए गए निवेशों का प्रयोग करते हुए जमा राशियों के संबंध में और आहरणों की पूर्ति करने में समर्थ होंगे।

समग्र दबाव परीक्षण

2.41 चुनिंदा नमूनागत बैंकों³² के संबंध में 31 मार्च 2016 की संदर्भ तारीख के अनुसार दबावग्रस्त संतुलन परीक्षणों (संवेदनशीलता विश्लेषण) की शृंखला को अंजाम दिया गया। चुनिंदा बैंकों द्वारा किए गए दबावग्रस्त संतुलन परीक्षणों के परिणाम यह पुष्टि करते हैं कि विभिन्न प्रकार के अधिक आघातों से उबरने के लिए चयनित बैंकों में क्षमता उपलब्ध है। सामान्यतः टॉप डाउन स्ट्रेस टेस्ट के परिणामों की पुष्टि करते हुए बाटम अप स्ट्रेस टेस्ट यह इंगित करता है कि अधिकांश बैंक आर्थिक आघातों को बरदास्त कर सकते हैं हालांकि इनका (झटकों का) प्रभाव कतिपय बैंकों पर ज्यादा था जिनकी अनर्जक आस्तियों पर दबाव (झटके) का परीक्षण किया गया था क्योंकि उनका दबावग्रस्त सीआरएआर विनियामक न्यूनतम 9% की पूंजी पर्याप्तता से कम था (चार्ट 2.27)।

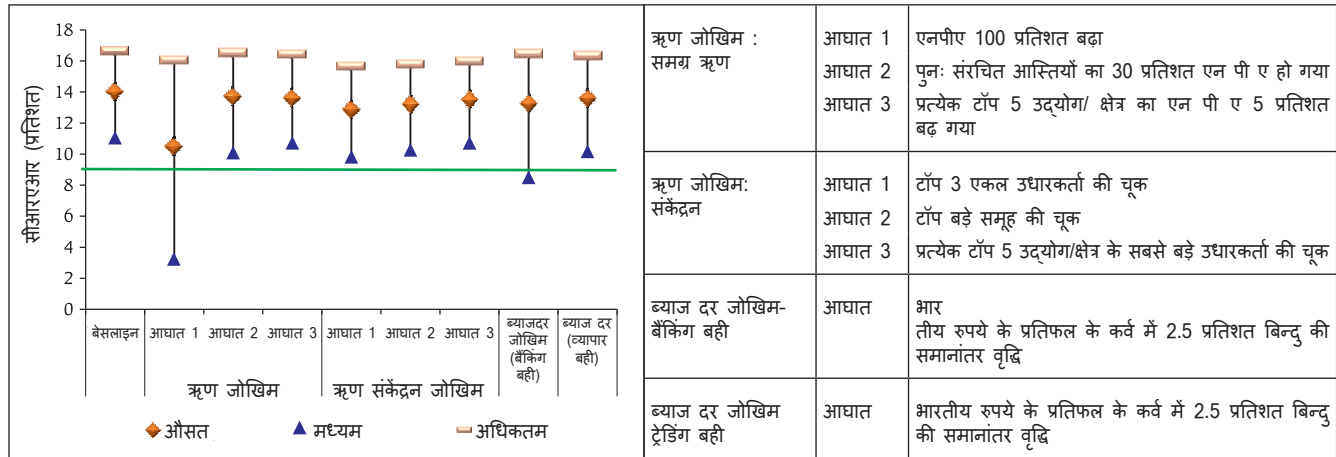
सारणी 2.10 चलनिधि जोखिम - आघात एवं असर - एनसीआर निधि प्रणाली (चलनिधि सहयोग(सपोर्ट) के लिए एचक्यूएलए का प्रयोग करते हुए)

आघात		संदर्भित प्रणाली के लिए उपलब्ध चलनिधि -युक्त आस्तियां (कुल आस्तियों का प्रतिशत)	परीक्षण में असफल होने वाले बैंकों को संख्या (चुनिंदा 60 में से)	एससीबी की कुल आस्तियों की तुलना में दबावपूर्ण परिदृश्य में असफल होने वाले बैंकों को आस्तियों का हिस्सा (प्रतिशत)
आधार रेखा	-	11.4	-	-
आघात 1	5	5.1	3	1.2
आघात 2	7	4.0	6	4.5
आघात 3	10	2.5	16	29.6
आघात 4	12	1.7	25	41.8

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

2.42 तरलता जोखिम के लिए बाटम अप दबाव परीक्षण के परिणाम चुनिंदा बैंकों पर तरलता संबंधी आघातों का प्रभाव अधिक दर्शाते हैं। विभिन्न परिभाषाओं का प्रयोग करते हुए तरलता आस्ति अनुपात³³ विभिन्न परिस्थितियों में (चुनिंदा) बैंकों की तरलता स्थिति को अलग-अलग प्रदर्शित करते हैं। परिणाम यह दर्शाते हैं कि सांविधिक चलनिधि में निवेश एवं प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात ने बैंकों को जमाकर्ताओं द्वारा अचानक और अप्रत्याशित

चार्ट 2.27 बाटम-अप दबाव परीक्षण - ऋण एवं बाजार जोखिम - सीआरएआर पर प्रभाव

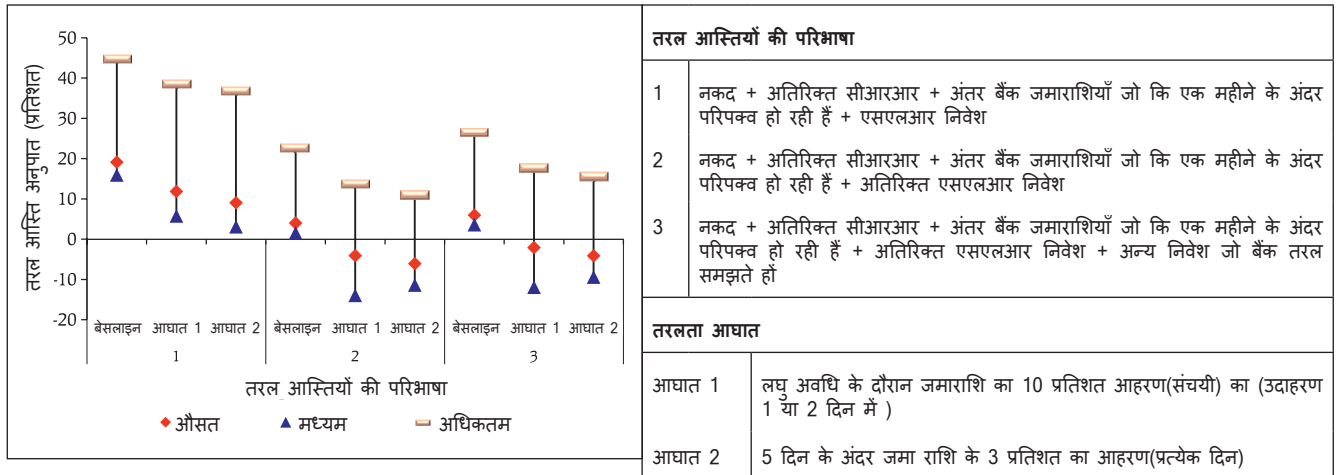


स्रोत: चुनिंदा बैंक (बाटम अप दबाव परीक्षण)

³² 15 चुनिंदा बैंकों पर नमूने के लिए विभिन्न आघातों का दबाव परीक्षण किया गया। टॉप डाउन तथा बाटम अप दबाव परीक्षण के लिए भी उन्हीं (एक ही प्रकार के) आघातों की प्रणाली अपनाई गयी थी। ब्योरे अनुबंध 2 में दिए गए हैं। up stress tests. Details of these are given in Annex 2.

³³ तरलता आस्ति अनुपात = तरल आस्ति *100/कुल आस्ति। आघात परिदृश्य के अंतर्गत, नकारात्मक तरलता आस्तियां अनुपात आवश्यक जमा आहरण में कमी के प्रतिशत को दर्शाता है।

चार्ट 2.28 बॉटम अप दबाव परीक्षण - तरलता जोखिम



नोट: कुछ बैंकों का तरल आस्ति अनुपात परंपरागत (conservative) तरल आस्ति परिभाषा 2 और 3 के अधीन नकारात्मक दायरे में चला गया।
 स्रोत: चुनिंदा बैंक (बॉटम-अप दबाव परीक्षण)

आहरण करने के दबाव की दशा में तरलता / नकदी की उपलब्धता से सहायता की है (चार्ट 2.28)।

बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का दबाव परीक्षण

2.43 चुनिंदा नमूना बैंकों³⁴ के संबंध में 31 मार्च 2016 की संदर्भ तारीख के अनुसार उनके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के संबंध में बॉटम अप दबाव परीक्षण (संवेदनशील विश्लेषण) श्रंखला आजमायी गई। ब्याज दरों पर आर्थिक झटके 100 से 250 आधार अंकों के बीच थे जबकि विदेशी मुद्रा दर के संबंध में 20 प्रतिशत मूल्य वृद्धि/मूल्य

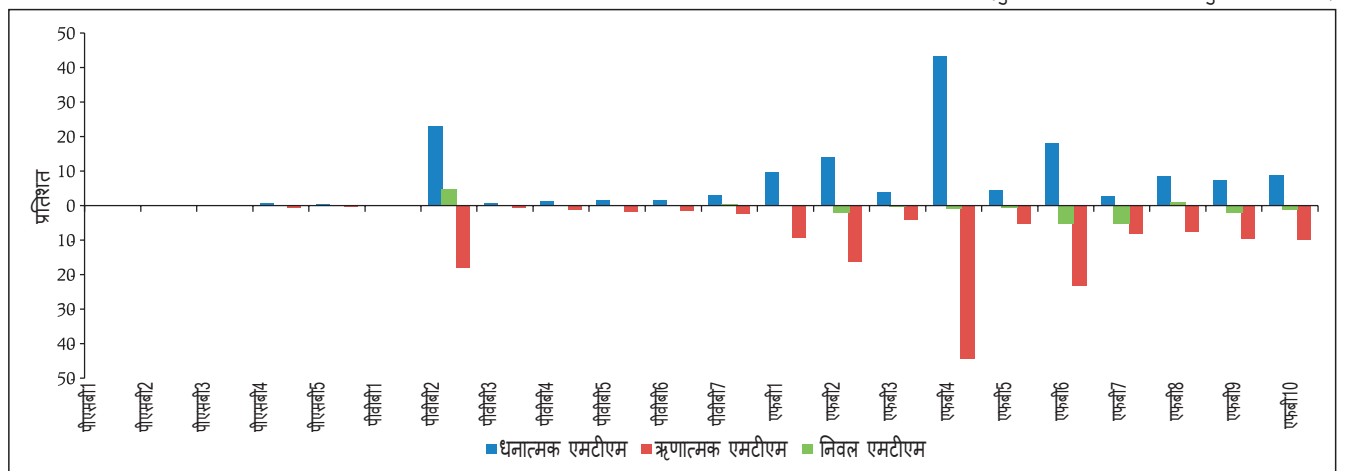
ह्रास आघातों का अनुमान किया गया था। एकल आधार पर मद विशेष आघात के लिए दबाव परीक्षण किया गया था।

2.44 नमूने में मार्केट-टू-मार्केट (एमटीएम) का प्रमुख प्रभाव विदेशी बैंकों की विभिन्न लेखा प्रणालियों के कारण अलग - अलग रहा (चार्ट 2.29)।

2.45 दबाव परीक्षण परिणामों ने यह दर्शाया कि नमूना बैंकों पर ब्याज दर आघात का औसत निवल प्रभाव लगभग नगण्य था। विदेशी मुद्रागत आघातों की स्थिति

चार्ट 2.29 : कुल डेरिवेटिव के एमटीएम - चुनिंदा बैंक - मार्च 2016

(तुलन-पत्र गत आस्तियों की तुलना में प्रतिशत)

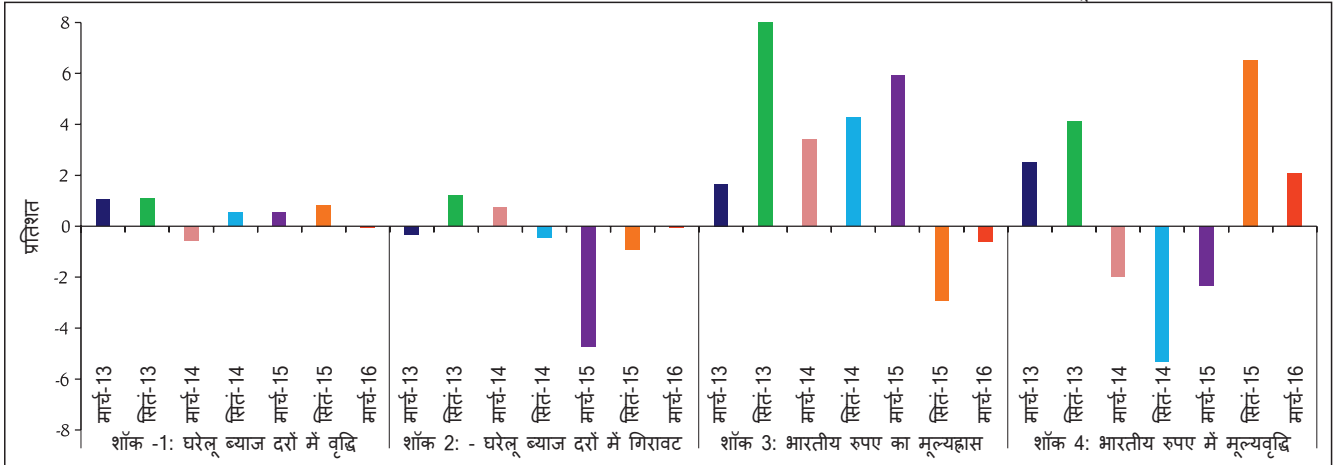


टिप्पणी: पीएसबी - सरकारी क्षेत्र के बैंक, पीवीबी-निजी क्षेत्र के बैंक, एफबी - विदेशी बैंक
 स्रोत: नमूना बैंक (डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर बॉटम-अप दबाव परीक्षण)

³⁴ 22 नमूने बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर दबाव परीक्षण किए गए। ब्योरा अनुबंध 2 में दिया गया है।

चार्ट 2.30: दबाव परीक्षण-चुनिंदा बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर आघातों का असर (आघात पड़ने पर निवल एमटीएम में परिवर्तन)

(पूँजी-निधियों के प्रतिशत के रूप में)



टिप्पणी: आधार रेखा के संदर्भ में पड़ने वाले आघात के कारण निवल एमटीएम में परिवर्तन
 स्रोत: नमूना बैंक (डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर बॉटम-अप दबाव परीक्षण)

में भी मार्च 2016 को प्रभाव तुलनात्मक रूप से कमतर था (चार्ट 2.30)।

भाग - II

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

निष्पादन

2.46 प्रणालीगत स्तर पर³⁵ अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर सितंबर 2015 एवं मार्च 2016 के बीच 12.7 प्रतिशत से बढ़कर 13.0 प्रतिशत हो गया। हालांकि भिन्न-भिन्न देखा जाए तो 6 बैंक सीआरएआर के न्यूनतम अपेक्षित 9 प्रतिशत के स्तर को बनाए रखने में असफल रहे। एसयूसीबी के सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में जीएनपीए में काफी कमी हुई और ये 7.7 प्रतिशत से घटकर 6.4 प्रतिशत हो गया तथा इसी अवधि के दौरान उनका प्रावधान कवरेज अनुपात³⁶ 50.9 प्रतिशत से बढ़कर 56.6 प्रतिशत हो गया। आस्तियों के प्रतिफल (आरओए) में गिरावट से वह 0.8 से 0.6 प्रतिशत तथा समान अवधि के दौरान चलनिधि अनुपात³⁷ में मामूली गिरावट से वह 35.0 प्रतिशत से 34.8 प्रतिशत हो गया।

लचीलापन-दबाव परीक्षण

ऋण जोखिम

2.47 एसयूसीबी के संबंध में ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार आंकड़ों

का प्रयोग करते हुए दबाव परीक्षण किया गया। एसयूसीबी के सीआरएआर के संबंध में ऋण जोखिम आघातों का प्रभाव चार अलग-अलग परिदृश्यों³⁸ के अंतर्गत प्रेक्षित किया गया। परिणामों से यह प्रदर्शित हुआ कि सबसे खराब परिदृश्य (जीएनपीए में दो एसडी /विचलन की वृद्धि, जिसे हानि अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है) को छोड़कर एसयूसीबी का प्रणालीगत स्तरीय सीआरएआर विनियामकीय अपेक्षा के अनुसार न्यूनतम स्तर के ऊपर बना रहा। हालांकि, अलग-अलग बैंकों के संबंध में देखा जाए तो सबसे खराब परिदृश्य के अंतर्गत काफी अधिक संख्या (52 में से 30) में बैंक सीआरएआर के अपेक्षित स्तरों को पूरा नहीं कर पाएंगे।

चलनिधि जोखिम

2.48 चलनिधि जोखिम के संबंध में दबाव परीक्षण दो अलग-अलग परिस्थितियों के अंतर्गत किए गए - 1 से 28 दिवसीय समयावधि (टाइम बकेट) में नकदी बहिर्प्रवाह में i) 50 प्रतिशत; एवं ii) 100 की वृद्धि संभावित थी। इसके आगे, यह माना गया कि दोनों परिदृश्यों के अंतर्गत नकदी अंतर्प्रवाह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दबाव परीक्षण के परिणामों से संकेत मिलता है कि दबाव के परिदृश्य (52 बैंकों में से 25 बैंक परिदृश्य । तथा 38 बैंक परिदृश्य II के अंतर्गत) में एसयूसीबी पर भारी असर पड़ेगा और उनको चलनिधि दबाव का सामना करना होगा।

³⁵ 52 एसयूसीबी की प्रणाली।

³⁶ प्रावधानीकृत कवरेज अनुपात = एनपीए के लिए प्रावधान *100/जीएनपीए।

³⁷ चलनिधि अनुपात = (नकद + बैंकों से प्राप्य+एसएलआर निवेश)*100/कुल आस्तियां।

³⁸ चार परिदृश्य इस प्रकार हैं : (i) जीएनपीए (अवमानक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत) में 1 एसडी का आघात, (ii) जीएनपीए (अवमानक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत) में 2 एसडी का आघात, (iii) जीएनपीए (हानि अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत) में 1 एसडी का आघात, तथा (iv) जीएनपीए (हानि अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत) में 2 एसडी का आघात । एसडी के आकलन में 10 वर्षों के आंकड़ों का प्रयोग किया गया था । दबाव परीक्षण के ब्यौरों के लिए अनुबंध 2 देखें ।

भाग - III

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

2.49 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के पास 11,682 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ पंजीकृत थीं, जिनमें से 202 जमा स्वीकार करने वाली (एनबीएफसी-डी) तथा 11,480 जमा स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी-एनडी) थीं। 220 जमा स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण (एनबीएफसी-एनडी-एसआई)³⁹ थीं। सभी एनबीएफसी-डी तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआई, रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं के साथ ही पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं तथा प्रावधानीकरण मानदंडों जैसे विवेकपूर्ण विनियमों के अधीन हैं।

निष्पादन

2.50 एनबीएफसी सेक्टर के समग्र तुलन पत्र का वर्ष दर वर्ष आधार पर मार्च 2016 में 15.5 प्रतिशत का विस्तार हुआ जबकि पिछले साल में यह विस्तार 15.7 प्रतिशत था। ऋण तथा अग्रिमों में 16.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा उधार राशि में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी - 2.11)।

2.51 एनबीएफसी क्षेत्र का वित्तीय निष्पादन पिछले 2 वर्षों में अपरिवर्तित रहा। मार्च 2015 और मार्च 2016 के बीच कुल आय के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ 18.3 प्रतिशत रहा और इसी अवधि में आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) 2.2 प्रतिशत था। आस्तियों (आरओई) पर प्रतिफल बढ़कर 10.3 प्रतिशत से 10.6 प्रतिशत हो गया (सारणी 2.12)। एनबीएफसी सेक्टर के लिए विनियामक मानदंडों को एससीबी के लिए लागू मानदंडों के निकट लाया गया, इस सेक्टर (आरओइ तथा आरओए) का कार्य निष्पादन बैंकों के कार्यनिष्पादन से अच्छा पाया गया।

आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता

2.52 कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में एनबीएफसी क्षेत्र का जीएनपीए मार्च 2016 में घटकर 4.6 प्रतिशत हो गया जो सितंबर 2015 में 5.1 प्रतिशत था। समान अवधि के दौरान, कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में, एनएनपीए 2.9 प्रतिशत से घटकर 2.5 प्रतिशत हो गया (चार्ट-2.31)।

सारणी 2.11: एनबीएफसी क्षेत्र का समेकित तुलन पत्र : वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि

(प्रतिशत)

मद	मार्च-15	मार्च-16
1. शेयर पूंजी	6.3	4.8
2. आरक्षित(प्रारक्षित) निधि एवं बेशी	13.5	14.3
3. कुल उधार	16.9	15.3
4. वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	14.1	31.8
कुल देयताएं/आस्तियां	15.7	15.5
1. ऋण एवं अग्रिम	17.1	16.6
2. निवेश	11.5	10.8
3. अन्य आस्तियां	10.6	12.7
आय/व्यय		
1. कुल आय	15.3	15.8
2. कुल व्यय	15.5	15.8
3. निवल लाभ	15.0	15.6

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां

सारणी 2.12 : एनबीएफसी क्षेत्र का वित्तीय निष्पादन

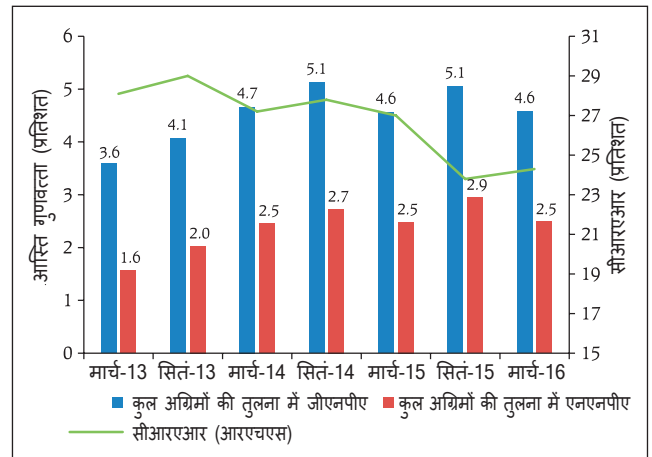
(प्रतिशत)

मद	मार्च-15	मार्च-16
1. कुल आस्तियों की तुलना में पूंजी बाजार में एक्सपोजर (सीएमई)	7.4	8.5
2. लीवरेज अनुपात	3.7	3.9
3. कुल आय की तुलना में निवल लाभ	18.3	18.3
4. आरओए	2.2	2.2
5. आरओई	10.3	10.6

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.31: एनबीएफसी क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता

(प्रतिशत)



स्रोत: भारिबैं को पर्यवेक्षी विवरणियाँ

³⁹ एनबीएफसी-एनडी - एसआई वे एनबीएफसी - एन डी हैं जिनकी आस्तियां रु 5 बिलियन या उससे अधिक हैं।

2.53 मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, एनबीएफसी⁴⁰ से यह अपेक्षा है कि वे निर्धारित न्यूनतम पूंजी अपने पास रखें, जो टियर-1⁴¹ तथा टियर - II पूंजी को समाहित करते हुए उनकी समग्र जोखिम - भारित आस्तियों के 15 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। एनबीएफसी का सीआरएआर मार्च 2016 में बढ़कर 24.3 प्रतिशत हो गया जो सितंबर 2015 में 23.8% था (चार्ट - 2.31)। अलग-अलग स्तर पर, मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार, सात एनबीएफसी विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुरूप न्यूनतम 15 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखने में असफल रहीं।

लचीलापन - दबाव परीक्षण

प्रणालीगत स्तर

2.54 पूर्णरूपेण एनबीएफसी क्षेत्र के लिए ऋण जोखिम के संबंध में दबाव परीक्षण मार्च 2016 को समाप्त अवधि के लिए तीन परिदृश्यों/परिस्थितियों के अंतर्गत किए गए : (i) जीएनपीए में 0.5 एसडी की वृद्धि हुई, (ii) जीएनपीए में 1 एसडी की वृद्धि हुई, तथा (iii) जीएनपीए में 3 एसडी की वृद्धि हुई। परिणाम यह प्रदर्शित करते हैं कि पहले और दूसरे परिदृश्यों में इस क्षेत्र का सीआरएआर थोड़ा प्रभावित हुआ किंतु तीसरे परिदृश्य/तीसरी परिस्थिति में यह 24.3 प्रतिशत से घटकर 23.3 प्रतिशत रह गया। हालांकि, यह विनियामकीय अपेक्षा के निर्धारित न्यूनतम 15 प्रतिशत के स्तर से काफी ऊपर था।

एकल एनबीएफसी

2.55 उन्हीं तीन परिदृश्यों के अंतर्गत समान अवधि के लिए एकल एनबीएफसी के लिए भी दबाव परीक्षण किए गए। परिणाम यह प्रदर्शित करते हैं कि परिदृश्य (i) एवं (ii) के अंतर्गत 5 प्रतिशत कंपनियाँ विनियामकीय अपेक्षा के निर्धारित न्यूनतम पूंजी के स्तर को नहीं बनाए रख पाएंगी, जबकि तीसरे परिदृश्य/परिस्थिति के अंतर्गत 8 प्रतिशत कंपनियाँ विनियामकीय अपेक्षा के निर्धारित न्यूनतम स्तर को नहीं बनाए रख पाएंगी।

भाग - IV

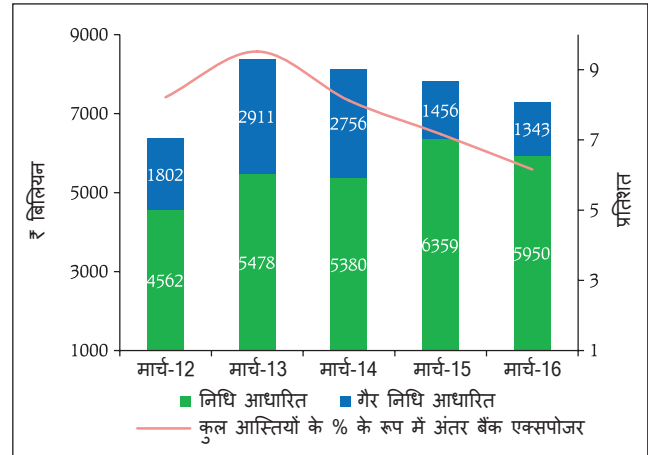
परस्पर संबद्धता⁴²

अंतर बैंक बाजार की प्रवृत्तियाँ⁴³

2.56 अंतर बैंक बाजार मार्च 2016 में रुपए 72 ट्रिलियन के पण्यावर्त (टर्नओवर) साथ निरंतर गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसमें मार्च 2015 से 6 प्रतिशत की गिरावट हुई। अंतर बैंक बाजार में निधि आधारित एक्सपोजर मार्च 2016⁴⁴ में लगभग 12 प्रतिशत हिस्से के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार वृद्धि को दर्शाता है(चार्ट 2.32)।

2.57 बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रभुत्व रहा है तथा निजी बैंकों का हिस्सा पिछले दो वर्षों में हुई सतत वृद्धि को दर्शाता है। अंतर-बैंक बाजार में सभी बैंकों की हिस्सेदारी यद्यपि व्यापक रूप में बंटी हुई है, जैसा कि

चार्ट 2.32 अंतर बैंक बाजार का आकार (टर्नओवर)



स्रोत: भारिबै पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

⁴⁰ रु 5 बिलियन या उससे अधिक के आस्ति आकार वाली जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी तथा गैर-जमा स्वीकारने वाली एनबीएफसी।

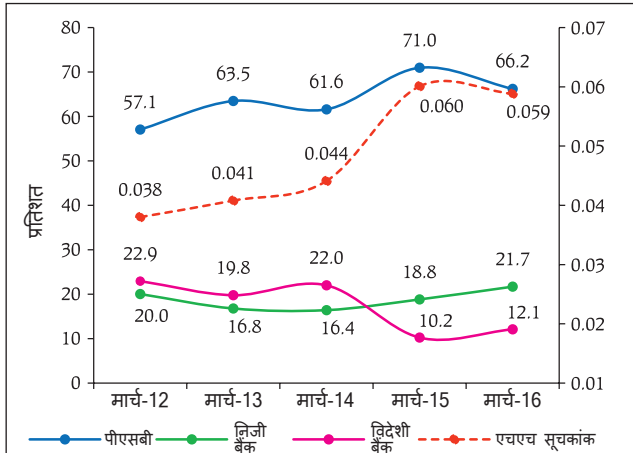
⁴¹ 10 नवंबर 2014 को जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एनबीएफसी - एनडी - एसआई (रु 5 बिलियन या उससे अधिक के आस्ति आकार वाली) तथा जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी के लिए संशोधित न्यूनतम टियर-1 पूंजी को 10 प्रतिशत (पहले, टियर-1 पूंजी 7.5 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए थी) कर दी गयी है और इनको चरणबद्ध ढंग से उसे पूरा किया जाना है (मार्च 2016 के अंत तक 8.5 प्रतिशत तथा मार्च 2017 के अंत तक 10 प्रतिशत)।

⁴² विश्लेषण में प्रयुक्त नेटवर्क मॉडल का विकास वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से प्रोफेसर शरी मार्कोसे (इस्सेक्स विश्वविद्यालय) तथा डॉ. साइमॉन गिआनसाटे (बेथ विश्वविद्यालय) ने किया।

⁴³ बैंक, आपस में काल, नोटिस तथा अन्य अल्पावधि बजारों में लेनदेन करने के अलावा एक दूसरे के दीर्घावधि मीयादी लिखतों में भी निवेश करते हैं। वर्तमान विश्लेषण में जिए अंतरबैंक बाजार का जिक्र किया गया है वह बैंकों के बीच अल्पावधि एवं दीर्घावधि-सभी बकाया एक्सपोजरों का जोड़ है।

⁴⁴ नेटवर्क विश्लेषण संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय एक्सपोजर पर विचार करता है। डेरिवेटिव लेनदेनों के संबंध में जीसीपी द्वारा केंद्रीकृत रूप में समाशोधित सौदों को वर्तमान विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है, चूंकि गैर निधि आधारित एक्सपोजर का काफी हिस्सा जैसे फोरेक्स, फारवर्ड आदि अब अधिकतर मानकीकृत है और जीसीपी के द्वारा समाशोधित होते हैं। इन्हें इस विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि गैर निधि आधारित अंतर बैंक बाजार में इसमें आकार में धीरे-धीरे घटोती हुई है।

चार्ट 2.33 - अंतर-बैंक बाज़ार में विभिन्न बैंक समूहों का हिस्सा



स्रोत: भारिबैं पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

मार्च 2016 (चार्ट 2.33) की स्थिति के अनुसार हरफिनडाल - हर्समैन सूचकांक (एचएच इंडेक्स) के लगभग 0.06 होने से पता चलता है।

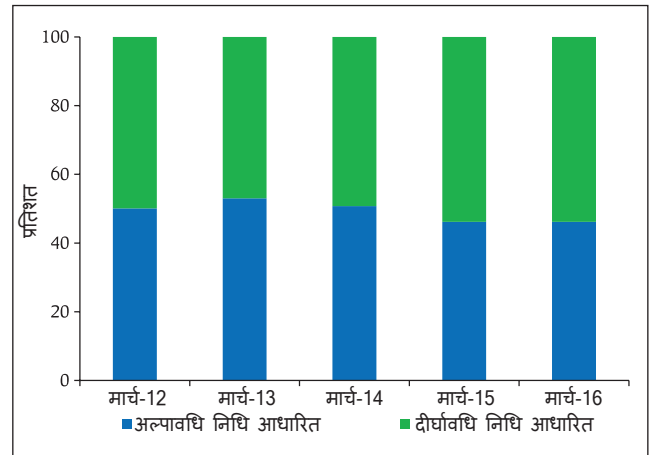
2.58 सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि अंतर बैंक बाजार चलनिधि उपलब्ध करने वाला स्रोत है। तथापि भारतीय परिपेक्ष्य में बैंकों के बीच द्विपक्षीय दीर्घावधि लेन-देन (एक्सपोज़र) वर्ष दर वर्ष लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2016 को अंतर-बैंक बाज़ार में निधि आधारित एक्सपोज़र का लगभग 54 प्रतिशत दीर्घावधि प्रकृति का था। (चार्ट 2.34)

2.59 यद्यपि अल्पावधि निधि आधारित अंतर-बैंक बाज़ार के समग्र आकार में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ था, किन्तु जमा प्रमाणपत्र के हिस्सा में तीव्र गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई थी। मार्च 2012 में अल्पावधि अंतर-बैंक बाज़ार में कॉल मनी और सीडी की संयुक्त रूप से हिस्सेदारी 71 प्रतिशत से अधिक रिकार्ड की गई थी, जिसमें मार्च 2016 में इसमें लगभग 36 प्रतिशत की गिरावट आई थी। इसी अवधि के दौरान, अन्य अल्पावधि अंतर-बैंक एक्सपोज़र की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गयी थी। (चार्ट 2.35)

नेटवर्क संरचना तथा संबद्धता

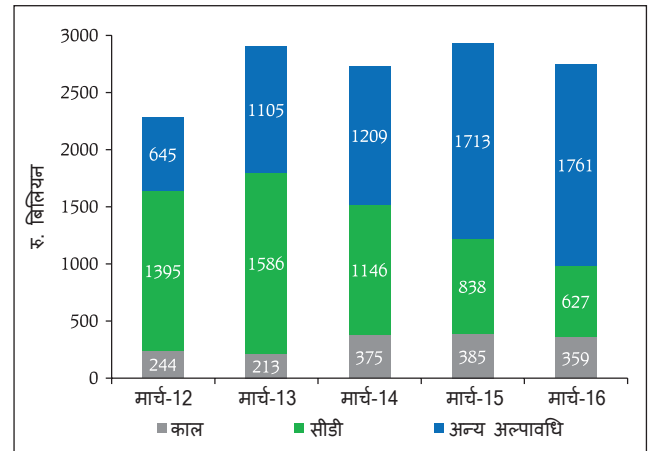
2.60 बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क की संरचना⁴⁵ लगातार त्रिस्तरीय बनी रही जिसमें कतिपय बैंको का प्रणाली वर्चस्व

चार्ट: 2.34 अंतरबैंक बाजार में निधि आधारित दीर्घावधि तथा अल्पावधि एक्सपोज़र का हिस्सा।



स्रोत: भारिबैं पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

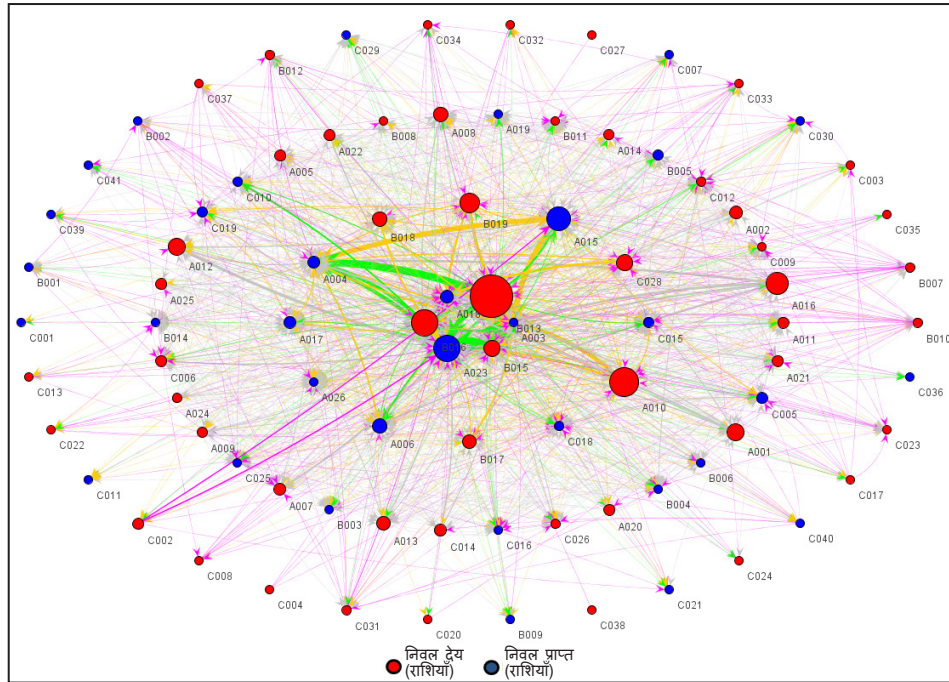
चार्ट 2.35: अल्पावधि निधि आधारित अंतरबैंक बाजार की संरचना



नोट: अन्य अल्पावधि में अल्पावधि जमा एवं अल्पावधि उधार आदि भी शामिल हैं।
स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियाँ

⁴⁵ बैंकिंग प्रणाली के नेटवर्क को दर्शानेवाले जिस डायग्राम का चित्रण किया गया है वह एक त्रिस्तरीय संरचना है, जहां अलग-अलग बैंकों का एक दूसरे के साथ नेटवर्क में कनेक्टिविटी स्तर की डिग्री भिन्न-भिन्न है। वर्तमान विश्लेषण में, सर्वाधिक कनेक्टेड बैंक, अधिकतम आंतरिक कोर (नेटवर्क डायग्राम के केंद्र में) में हैं। बैंकों को उनके सापेक्षिक कनेक्टिविटी के स्तर के आधार पर मिड कोर, बाहरी कोर तथा परिधि (डायग्राम में केंद्र के आस-पास संबंधी सकेद्री वृत्त) में रखा गया है। त्रिस्तरीय नेटवर्क डायग्राम में लिंक की कलर कोडिंग, नेटवर्क में भिन्न-भिन्न स्तरों से (उदाहरण के लिए, हरा लिंक इनर कोर में बैंकों से उधारी का प्रतिनिधित्व करता है) उधारी को दर्शाते हैं। प्रत्येक बॉल एक बैंक का प्रतिनिधित्व करता है तथा उनका आकलन सिस्टम में स्थित अन्य बैंकों की तुलना में निवल स्थिति के आधार पर किया गया है। बकाया एक्सपोज़र के आधार पर प्रत्येक बैंक को जोड़ने वाली लाइन का आकलन किया गया है।

चार्ट: 2.36 भारतीय बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना (मार्च 2016)



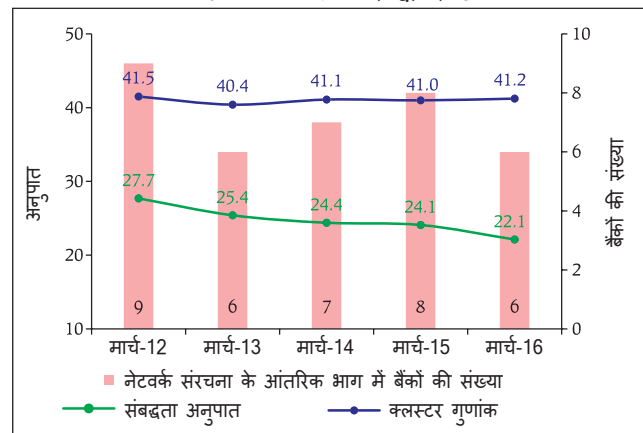
स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

बना रहा (चार्ट 2.36)। बैंकिंग प्रणाली में अंतर जुड़ाव के अंश को जुड़ाव अनुपात⁴⁶ से मापा जा सकता है जिसने घटोतरी की प्रवृत्ति दर्शाई है, इससे यह परिलक्षित होता है कि बैंको के बीच लिंक/ जुड़ाव में कमी आई है। प्रमुख बैंक नेटवर्क प्लॉट के अधिकतम अंदरूनी चक्र के रूप में दर्शाए गए हैं। मार्च 2012 से मार्च 2016 के दौरान ऐसे बैंकों की संख्या 9 से 6 के बीच रही है। इस क्लस्टर के गुणांक⁴⁷ स्थानीय जुड़ाव को दर्शाते हैं, जो मार्च 2012 से मार्च 2016 के दौरान तदनु रूप बने रहे हैं, जिससे यह इंगित होता है कि उल्लिखित अवधि में बैंकिंग नेटवर्क में क्लस्टरिंग/ समूहन में परिवर्तन नहीं हुआ है (चार्ट 2.37)।

वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क

2.61 वृहद वित्तीय प्रणाली के दृष्टिकोण से एससीबी, एएमसी-एमएफ, बीमा कंपनियों, एनबीएफसी, यूसीबी और अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बीच निधियों का प्रवाह महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता है। एएमसी-एमएफ और बीमा कंपनियां वित्तीय प्रणाली में सबसे बड़े

चार्ट 2.37 बैंकिंग प्रणाली की संबद्धता सांख्यिकी



स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

⁴⁶ संबद्धता अनुपात: यह एक आकड़ा है जो पूर्ण ग्राफ में सभी संभव संबंधों के सापेक्ष बिन्दुओं के बीच संबंधों की सीमा की माप करता है।

⁴⁷ क्लस्टर गुणांक: नेटवर्क में क्लस्टरिंग यह माप करती है कि प्रत्येक बिन्दु (Nodes) आपस में कितना संबद्ध है। विशिष्ट रूप से, इस बात की अधिक संभावना हो सकती है कि किसी बिन्दु के दो पड़ोसियों (वित्तीय नेटवर्क के मामले में बैंक के प्रतिपक्षी) आपस में भी पड़ोसी हो। नेटवर्क के लिए क्लस्टर गुणांक का अधिक होना, प्रणाली में विद्यमान उच्च स्तर पर स्थानीय परस्पर संबद्धता के अनुरूप होती है।

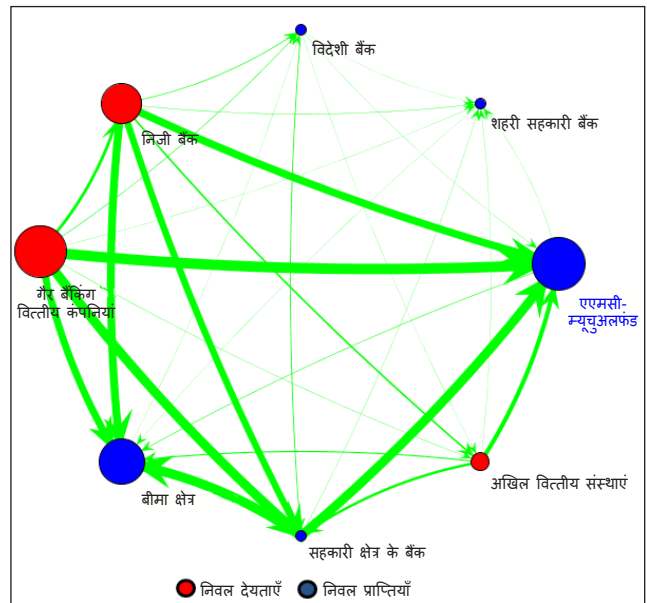
निधि उपलब्ध करने वालों के रूप में अग्रणी स्थान ग्रहण करती है जबकि एससीबी और एनबीएफसी क्रमशः सबसे बड़ी निधि प्राप्तकर्ता होती हैं। सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र एससीबी में से पीसीबी विदेशी बैंक दोनों निवल प्राप्तकर्ता की स्थिति एवं निजी क्षेत्र के बैंक निवल भुगतानकर्ता की स्थिति ग्रहण कराते हैं। इसके अलावा विश्लेषण में शामिल चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने भी वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। (चार्ट 2.38 और सारणी 2.13)

एएमसी-एमएफ तथा बीमा कंपनियों एवं एससीबी की अन्योन्यक्रिया (अंतर्संबंध)

2.62 भारतीय वित्तीय प्रणाली में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अलावा दो सबसे प्रमुख सेक्टर बीमा कंपनियाँ और एएमसी-म्यूचुअल फंड हैं। ये तीनों क्षेत्र मिलकर वित्तीय प्रणाली के 80% से अधिक हिस्सा हैं। मार्च 2016 के अंत में एएमसी-म्यूचुअल फंड का वित्तीय प्रणाली में प्रबंधन के तहत कुल परिसंपत्तियों का लगभग 36 प्रतिशत एक्सपोसर्स⁵² था जबकि वित्तीय प्रणाली में बैंकिंग और बीमा क्षेत्र का एक्सपोजर क्रमशः 15 एवं 10 प्रतिशत था⁵³।

2.63 बीमा और म्यूचुअल फंड क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र का संयुक्त एक्सपोजर रु. 176 बिलियन था जो कि मार्च 2016 में बैंकिंग क्षेत्र⁵⁴ की कुल परिसंपत्तियों का मात्र 0.2 प्रतिशत था। उसी अवधि में एएमसी-म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों का बैंकिंग क्षेत्र में संयुक्त एक्सपोजर लगभग 4.9 ट्रिलियन था जो कि संबंधित एएमयू का क्रमशः 19 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत था। जबकि एएमसी-म्यूचुअल फंड का बैंकिंग में एक्सपोजर मुख्य रूप से अल्पकालिक लिखत (रु.1.4 ट्रिलियन) के माध्यम से था वहीं बीमा कंपनियों का बैंकिंग में काफी एक्सपोजर मुख्य

चार्ट: 2.38: वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क प्लॉट



स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियाँ तथा स्टॉफ की गणनाएं।

सारणी 2.13: इंडर सेक्टर परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ

(₹ बिलियन में)

	प्राप्तियाँ	देयताएँ
एससीबी	3585	6494
एएमसी-एमएफ ⁴⁸	4508	265
बीमा कंपनियाँ ⁴⁹	3709	117
एनबीएफसी ⁵⁰	393	4615
यूसीबीएस ⁵¹	123	22
अखिल भारतीय एफआई (नाबाई, एक्सिस बैंक, एनएचबी, सीडबी)	1309	2114

टिप्पणी: प्राप्य राशियाँ और देय राशियाँ में एक ही समूह से संबंध रखने वाली संस्थाओं के बीच किए गए लेनदेन शामिल नहीं किए गए हैं।

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियाँ तथा स्टॉफ की गणनाएं।

⁴⁸ नमूने में 22 एएमसी-म्यूचुअल फंड शामिल हैं जो म्यूचुअल फंड क्षेत्र के एएमयू के 90 प्रतिशत से अधिक को कवर करते हैं।

⁴⁹ नमूने में 21 बीमा कंपनियाँ शामिल हैं जो बीमा कंपनियों की कुल परिसंपत्तियों के 90 प्रतिशत से अधिक को कवर करती हैं।

⁵⁰ यह एनबीएफसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला नमूना है और इसमें 34 कंपनियाँ शामिल हैं। (इसमें जमा स्वीकारने एवं जमा न स्वीकारने वाली प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण दोनों प्रकार की कंपनियाँ शामिल हैं।)

⁵¹ इस नमूने में 20 एससीबी शामिल हैं।

⁵² वित्तीय प्रणाली के प्रति में एएमसी-म्यूचुअल फंड, एससीबी और बीमा कंपनियों के एक्सपोसर के साथ साथ इस समूह की संस्थाओं के प्रति एक्सपोसर को भी शामिल किया गया है।

⁵³ मार्च 2016 की समाप्ति तक बीमा कंपनियों की परिसंपत्तियों से संबंधित कुल डेटा उपलब्ध नहीं था। अतः इस संदर्भ में दिसम्बर 2015 तक के डेटा का प्रयोग किया गया है।

⁵⁴ केवल घरेलू परिचालन से संबंधित ऑन-बैलेंस शीट की परिसंपत्तियों पर ही विचार किया गया है।

रूप से लम्बी अवधि के लिखत (रु.2.2 ट्रिलियन) (टेबल 2.14) के माध्यम से था।

एससीबी, एएमसी-म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों का एनबीएफसी के साथ अंतरसंबंध

2.64 जहां, एससीबी शेष वित्तीय प्रणाली से निवल निधियों के प्राप्तकर्ता थे वहीं, एनबीएफसी शेष प्रणाली से निधियों के सबसे बड़े निवल प्राप्तकर्ता बनी रही। मार्च 2016 को एनबीएफसी पर बैंकिंग क्षेत्र के बकाया का एक्सपोजर ₹2 ट्रिलियन के करीब था। इसके अलावा, एनबीएफसी में एएमसी-एमएफ का एक्सपोजर मार्च 2012 एवं मार्च 2016 के बीच वृद्धिशील प्रवृत्ति को दर्शाता है (सारणी 2.15)।

संक्रामकता का विश्लेषण (कंटेजिअन एनालिसिस)

2.65 संक्रामकता विश्लेषण, नेटवर्क टूलों का प्रयोग करते हुए किया जाने वाला (आस्ति) दबाव परीक्षण है जो एक या अधिक बैंकों के विफल होने की स्थिति में संभावित हानि का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा किसी एक बैंक द्वारा शुरू हुई हानि की सीमा उसके प्रणालीगत महत्व की सूचक है। किसी भी एक बैंक के विफल हो जाने से संक्रमण की शुरुआत हो सकती है, एतदर्थ वर्तमान विश्लेषण के लिए शीर्ष निवल उधारकर्ताओं एवं निवल ऋणदाताओं को संक्रमण के कारक बैंक (ट्रिगर बैंक) माना गया है। सैद्धान्तिक रूप से, किसी निवल उधारकर्ता बैंक से ऋण शोधन क्षमता की विफलता संक्रामकता को प्रारम्भ करेगी जबकि निवल ऋणदाता बैंक से चलनिधि (मांग) की संक्रामकता प्रारम्भ होगी। हालांकि, वास्तविकता में ऋण शोधन क्षमता में विफलता तथा चलनिधि मांग संक्रामकता- दोनों एक साथ घटित होने की संभावना है क्योंकि हर बैंक किसी न किसी का निवल उधारकर्ता अथवा ऋणदाता होता है। बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष उधारकर्ता तथा शीर्ष ऋण दाता के असफल होने पर प्रणाली में उनकी टियर-1 प्रणाली के आधार पर होने वाले असर का आकलन करने के लिए विश्लेषण किया गया (सारणियाँ 2.16 और 2.17)। संक्रामकता⁵⁵ के संबंध में विशिष्ट अनुमानों के अधीन, शीर्ष निवल उधारकर्ता बैंक की विफलता बैंकिंग प्रणाली की (संयुक्त ऋण शोधन क्षमता चलनिधि संक्रामकता के अंतर्गत) टियर-1 पूंजी के 37 प्रतिशत का नुकसान के रूप में परिणत हो सकती है, जबकि शीर्ष ऋण दाता बैंक की विफलता टियर -1 पूंजी के 38 प्रतिशत के नुकसान के रूप में परिणत हो सकती है। यह देखा जा सकता है कि बैंक डी, जो निवल

सारणी 2.14: बैंकों में बीमा कंपनियों और एएमसी-एमएफ के एक्सपोजर का पैटर्न (मार्च 2016)

(रु. बिलियन)

	एएमसी-एमएफ			बीमा कम्पनियाँ		
	अल्पवधि लिखतों में निवेश	पूँजीगत लिखतों में निवेश	बांड एवं अन्य दीर्घवधि लिखतों में निवेश	अल्पवधि लिखतों में निवेश	पूँजीगत लिखत में निवेश	बांड एवं अन्य दीर्घवधि लिखतों में निवेश
पीएसबी	1058	140	153	139	455	723
पीवीबी	357	550	137	45	508	551
एफबी	25	0	9	2	0	0
सभी एससीबी	1439	690	300	186	963	1275

स्रोत: भारिबैं पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

सारणी 2.15: एनबीएफसी में एससीबी, एएमसी-एमएफ तथा बीमा कंपनियों का एक्सपोजर

(₹ बिलियन)

	मार्च-12	मार्च-13	मार्च-14	मार्च-15	मार्च-16
एससीबी	1513	1453	1516	1595	2029
एएमसी-एमएफ	425	624	756	1008	1489
बीमा कंपनियाँ	780	880	965	1080	1038

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियाँ

सारणी 2.16: निवल उधारकर्ता बैंकों से प्रारम्भ हुई संक्रामकता (बैंकिंग प्रणाली की कुल टियर-1 पूंजी की प्रतिशत हानि)

शीर्ष निवल उधारकर्ता बैंक	ऋण शोधन क्षमता की संक्रामकता	चलनिधि की संक्रामकता	ऋण शोधन क्षमता एवं चलनिधि की संयुक्त संक्रामकता
बैंक ए	6.8	1.0	36.8
बैंक बी	3.8	0.5	4.1
बैंक सी	2.6	0.2	2.8
बैंक डी	3.8	8.8	40.3
बैंक ई	2.0	0.1	2.0

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियाँ तथा स्टॉफ की गणनाएं।

सारणी 2.17: निवल उधारदाता बैंकों द्वारा प्रारम्भ की गई संक्रामकता (बैंकिंग प्रणाली की कुल टियर-1 पूंजी की प्रतिशत हानि)

शीर्ष निवल उधारदाता बैंक	ऋण शोधन क्षमता की संक्रामकता	चलनिधि की संक्रामकता	ऋण शोधन क्षमता एवं चलनिधि की संयुक्त संक्रामकता
बैंक 1	0.1	20.4	37.5
बैंक 2	0.7	17.0	38.8
बैंक 3	4.0	7.7	42.4
बैंक 4	0.8	3.3	2.7
बैंक 5	0.7	12.6	38.5

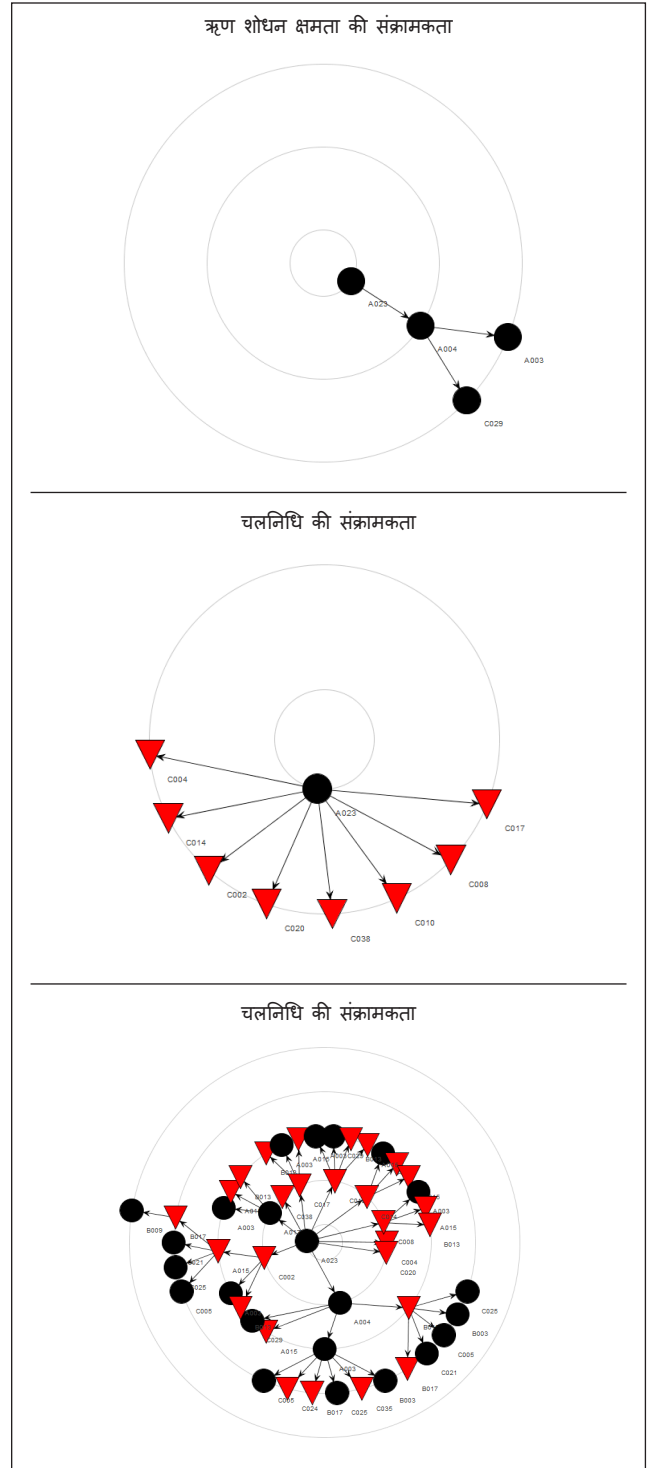
स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियाँ तथा स्टॉफ की गणनाएं।

⁵⁵ कृपया आकलन प्रणाली के लिए अनुबंध 2 देखें।

उधारकर्ता बैंकों में चौथे स्थान पर है, की विफलता निवल शीर्ष उधारकर्ता बैंकों की तुलना में अधिक गंभीर नुकसान में परिणत हुआ, क्योंकि शीर्ष निवल उधारकर्ता बैंक की संबद्धता बेहतर है।

2.66 संयुक्त संक्रामकता के मामले में अधिकतर बैंक विफल होते हैं, क्योंकि बैंकों के आस्ति व देयता पक्षों दोनों के माध्यम से संक्रामकता फैलती है, जबकि एकल (स्टैंड अलोन) मामले में फैलाव एक-पक्षीय [अर्थात या तो आस्ति पक्ष या देयता पक्ष] होता है और इसलिए आम तौर पर संयुक्त संक्रामकता का प्रभाव काफी गंभीर होता है और एकल अलोन संक्रामकता के साथ इसकी समानुयतिकता (तारतम्यता) नहीं होती (चार्ट 2.39)।

चार्ट 2.39: उसी ट्रिगर बैंक से प्रभावित बैंक



नोट: सबसे भीतरी रिंग में जो काला सर्कल है वह ट्रिगर बैंक है। बाहरी रिंग पर अन्य काले घेरे तथा लाल त्रिभुज प्रभावित बैंकों (ऋण शोधन क्षमता संक्रमण में असफलता को काले में तथा तरलता संक्रमण में असफलता को लाल रंग में) को दर्शाते हैं। प्रत्येक बाहरी रिंग संक्रमण के एक दौर तथा तीर प्रभाव की दिशा की ओर इशारा करते हैं।
स्रोत: भारिबे की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

अध्याय III

वित्तीय क्षेत्र विनियमन

यह अध्याय दो भागों में विभक्त है। भाग-I 'वित्तीय प्रणाली संरचना (configuration) के अधिकतम उपयोग' जैसे बड़े थीम पर प्रकाश डालता है, जबकि भाग II वित्तीय क्षेत्र¹ से संबन्धित विनियामी और विकास के मुद्दों पर चर्चा करता है। यह थीम वित्तीय प्रणाली के आकार की संरचना से संबन्धित दुविधाओं के कुछ अंशों और रियल अर्थ-व्यवस्था के सपोर्ट की प्रभावशीलता पर चर्चा करता है। यह चर्चा वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया, संसाधनों के आबंटन के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली की विभिन्न संरचनाओं के अंतर्गत वित्तीय जोखिम शेयर करने पर दृष्टिपात करती है। भाग-I घरेलू वित्तीय बाजार के परिदृश्य की संक्षिप्त समीक्षा करते हुए समाप्त होता है।

भाग -I

वित्तीय प्रणाली हेतु अधिकतम उपयोग संरचना- बैंक बनाम बाजार

3.i वित्तीय क्षेत्र मूलतः बचत के जरिये उत्पादक परियोजनाओं के लिए रियल इकॉनमी की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करता है। चूंकि रियल इकॉनमी की गतिविधियां व्यापक और विशाखीकृत होती जाती हैं, अतः वित्तीय क्षेत्र से भी अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आकार और व्यापकता दोनों में वृद्धि करे, ताकि आर्थिक उन्नति और विकास² की प्रक्रिया सहज/ सुगम हो सके। जबकि आर्थिक उन्नति और वित्तीय क्षेत्र के विकास के बीच महत्वपूर्ण संबंध है, इनके कारण दुतरफा हो सकते हैं। आर्थिक सूचना सृजित करना और वितरित करना, संसाधनों का आबंटन करना, संसाधनों के उपयोग की निगरानी करना और नियंत्रण रखना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जोखिम के विविधीकरण और प्रबंधन वित्तीय क्षेत्र के प्रमुख कार्यों के रूप में पहचाने गए हैं जो आर्थिक उन्नति³ में सहायता करते हैं। जिस सटीकता और लचीलेपन के साथ वित्तीय प्रणाली इन व्यापक कार्यों को अंजाम देती है उससे संबन्धित प्रणाली की स्थिरता परिभाषित होती है, जो परिणामतः सतत आर्थिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है।

3.ii हालांकि अधिक विकसित वित्तीय प्रणाली से सामान्यतः अधिक मजबूती की अपेक्षा की जाती है,

तथापि यह देखा गया है कि कतिपय आकारों और जटिलता के स्तर के उपरांत वित्तीय विकास के लाभ स्थिरता के लिए अनुत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। वैश्विक वित्तीय संकट के अनुभव से यह प्रमुख सीख मिली है कि महत्वपूर्ण विनियामक सुधारों एवं नवोन्मेष और विनियमन⁴ के बीच संतुलन जरूरी है।

3.iii वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट(एफएसआर जून 2015)⁵ की थीम में संतुलित विनियामक रुख एवं पर्यवेक्षी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि विनियमन स्वयं नवोन्मेष में बाधक न बने, बल्कि यह सुनिश्चित हो कि वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय बाजारों के लक्ष्य और प्रोत्साहनों में संतुलन बना रहे ताकि सभी स्टैक होल्डरों के लिए सक्षमता का अधिकतम उपयोग करने का वृहत्तर लक्ष्य प्राप्त हो और आर्थिक उन्नति को सपोर्ट मिले।

3.iv वैश्विक वित्तीय संकट के बाद पुनर्विनियमन के द्वारा पूरे विश्व में वृद्धिशील पूंजी के सुरक्षित भंडार के जरिए संभवतः एक अधिक लचीला (रेसिलिएंट) बैंकिंग क्षेत्र सुनिश्चित हुआ है। इस बीच वित्तीय बाजारों से संसाधनों का प्रवाह बैंकों की मध्यस्थता की तुलना में तेजी से बढ़ा है, जिससे वित्तीय जोखिम सहभागिता में वृद्धि

¹ जून 2015 से प्रारम्भ, जून अंक में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसी एक थीम पर आधारित द्विवाषिक प्रकाशन का अंग होता है।

² बेजहट, वाल्टर (1973) लोमबर्ड स्ट्रीट: मुद्रा बाजार से संबंधी विवरण: मैक कीनोन, रोनाल्ड I. (1973) आर्थिक विकास में पूंजी एवं मुद्रा' और शॉ एडवर्ड (1973) 'आर्थिक विकास में वित्तीय गहनता।

³ लेविन (2005), 'वित्त और विकास: सिद्धांत और साक्ष्य', आर्थिक विकास खंड 1 की पुस्तिका।

⁴ सहाये एट अल (2005) रेथीकिंग फाइनेंशियल दीपेनिंग: स्तबिलिटी एंड ग्रोथ इन एमेजिंग मार्केट। उपलब्ध-<https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1508.pdf>.

⁵ वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2015 (अध्याय III, इकाई।)

परिलक्षित हुई है। यद्यपि बैंकों के प्रभुत्व वाली वित्तीय प्रणाली अथवा बाजार के प्रभुत्व वाली प्रणाली में से कौन बेहतर है, इस बात के निष्कर्षतः साक्ष्य नहीं हैं, तथापि वैश्विक वित्तीय संकट ने दोनों प्रणालियों की खामियों को उजागर कर दिया है। वित्तीय मध्यस्थता के इन दोनों चैनलों ने अपने अतिरेक से कुछ अर्थ व्यवस्थाओं को हल्के और भारी झटके भी दिए हैं जिनका उनके क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत असर हुआ है।

3.v इन घटनाओं ने वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में नए आयाम जोड़े हैं- ऊर्ध्वाधर जिसमें निधियाँ बचतकर्ताओं से उपयोगकर्ताओं को मिलती हैं और क्षैतिज जिसमें निधियाँ बाजार के सहभागियों में आपस में संचलित होती हैं। पहले किए गए उल्लेख में जिस अतिरेक का जिक्र है वह संभवतः क्षैतिज मध्यस्थता⁶ के अधिक बढ़ने का परिणाम है। इसके अलावा उधार का एक महत्वपूर्ण अंश मौजूदा आस्तियों के वित्त पोषण पर खर्च होता है और अनेक वित्तीय प्रणालियों ने ऐसा कोई तंत्र नहीं स्थापित किया है जिससे यह पता चल सके कि नए उधार का कितना अंश नई आस्तियों के अर्जन पर खर्च हुआ।

3.vi इस रिपोर्ट की विशेष थीम वित्तीय प्रणालियों की विभिन्न संरचनाओं के साथ साथ कारपोरेट गवर्नेंस संरचना के जरिए वित्तीय मध्यस्थता, संसाधनों के आबंटन की सटीकता एवं वित्तीय जोखिम सहभागिता की प्रक्रिया पर नज़र डालती है।

बैंक प्रभुत्व वाली और बाजार प्रभुत्व वाली वित्तीय प्रणालियाँ

3.vii परंपरागत तौर पर किसी अतिरेकी वित्तीय मध्यस्थता का खास गुण यह है कि बैंक प्रभुत्व वाली प्रणाली (यूरोप और जापान) में बैंकों की तुलना में पूंजी बाजार की भूमिका कम होती है एवं बाजार प्रभुत्व वाली प्रणाली (अमेरिका) में बैंकों की तुलना में बाजार आधारित प्रणाली की भूमिका अधिक होती है और कहीं ऐसी भी प्रणाली है जो इन दोनों के बीच में आती है (जैसे यूके)। वित्तीय बाजारों के विकास के विभिन्न चरणों में किसी मौजूदा फ्रेमवर्क की असफलता से अथवा विभिन्न प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप नीतिगत उपायों के कारण

उत्पन्न हुए। उदाहरण के लिए अमेरिका में, 1929 में बाजार की तीव्र गिरावट के कारण द ग्लास स्टेयागल एक्ट बनने और अंतर्राज्यीय बैंकों पर प्रतिबंध होने से बैंकों की भूमिका की तुलना में बाजारों को प्रशय मिला। यूके में पूंजीबाजार का विकास अपनी उत्पत्ति के लिए इंग्लैंड द्वारा लड़े गए युद्धों के कारण है जिसमें लंदन पूंजी बाजार सरकार के लिए निधियाँ जुटाने का प्रमुख साधन बन गया। यद्यपि एंग्लो सेक्शन मार्केट आधारित प्रणाली के बजाय जर्मनी और जापान बैंक प्रभुत्व वाले देश हैं। इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं जैसे जर्मनी में hausbank निजी क्षेत्र में विकसित हुआ जबकि जापान में सरकार के सक्रिय सहयोग से mainbank विकसित हुआ।

संस्थाएं बनाम बाजार: प्रतिस्पर्धा अथवा पूरकता

3.viii वित्तीय संस्थाओं बनाम बाजार के संबंध में मोटे तौर पर दो दृष्टिकोण हैं। प्रथम दृष्टिकोण यह मानता है कि वित्तीय संस्थाएं और बाजार वित्तपोषण के संसाधनों की प्रतिस्पर्धा में हैं (Dewatripont and Maskin 1995; Allen and Gale 1997; Boot and Thakor 1997)। प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण के अनुसार बाजारों के उपयोग से दूरी रखते हुए वित्तीय संस्थाएं भावी जोखिम सरलीकरण सेवाएँ उपलब्ध करा सकती हैं, जबकि बाजार ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, इस दृष्टिकोण के अनुसार बाजार अपूर्ण होते हैं (बाजार आधारित प्रणाली में) और निवेशकों के विश्वास तथा बाजार सूचना के द्वारा आस्तियों के मूल्य में बार-बार उतार चढ़ाव होने के कारण घरेलू और अन्य निवेशकों को वृहत्तर जोखिम में डाल देते हैं। हालांकि, बाजारों से प्रतिस्पर्धा होने पर संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली लाभों संबंधी जोखिम सहभागिता कम हो जाएगी, चूंकि बाजार द्वारा वित्तीय संस्थाओं के साथ जोखिम सहभागिता संविदाओं के जरिए बाजार द्वारा दिए जाने वाले प्रतिफल बट जाएंगे (Allen and Gale 1997)।

3.ix अन्य दृष्टिकोण दर्शाता है कि बैंक तथा पूंजी बाजार सह विकास वित्तीय प्रणाली के एकीकृत भाग हैं जहां वे न केवल प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि एक दूसरे पर आश्रित होते हैं तथा सहविकास करते हैं (Bossone, 2010; Song and Thakur, 2010)।

⁶ की जॉन (2016) कंपेक्ससिटि, नॉट साइज़ इज द रियल डेंजर इन बैंकिंग, फाइनेसीयल टाइम्स, अप्रैल 12

3.x यह दृष्टिकोण 'बाजार' को स्वयं लक्ष्य के रूप में देखने के बजाय, बैंकों तथा बाजारों के सह-अस्तित्व तथा उनके सह-विकास का समर्थन करता है एवं इस अवधारणा पर निर्भर है कि उधारकर्ता की वित्त प्राप्त करने की क्षमता वित्तीय प्रणालीगत दो प्रतिरोधकों से ग्रसित है अर्थात् प्रमाणन प्रतिरोधक - जिसमें उधारकर्ता की ऋण प्राप्त करने संबंधी सूचना अपूर्ण होती है और वित्तीय प्रतिरोधक - जिसमें उधारकर्ता को बाहरी वित्तीय लागत से उत्पन्न कारकों का सामना करना पड़ता है। इस दृष्टिकोण को इस बात से संबल मिलता है कि प्रमाणन प्रतिरोधक के कारण ऐसी संभावना बन सकती है कि ऋण सक्षमता युक्त उधारकर्ता को ऋण देने से त्रुटिवश मना कर दिया जाए और वित्तीय प्रतिरोधक अत्यधिक लागत को बढ़ा दे जिससे अच्छे निवेश के अवसर पर रोक लग सकती है। इसलिए 'अनुपूरक दृष्टिकोण' के अनुसार बैंक प्रमाणन प्रतिरोधक का शमन करने में बेहतर होते हैं क्योंकि उन्हें ऋण विश्लेषण में विशेषज्ञता हासिल होती है, जबकि पूंजी बाजार उधारकर्ता की प्रतिभूति पर ज्यादा तरल बाजार उपलब्ध कराते हुए वित्तीय प्रतिरोधक का बेहतर निपटान संभव कर सकता है जिससे उधार लेने की लागत कम हो जाती है (सॉन्ग एंड ठैकोर, 2010)⁷। दूसरे शब्दों में, अब तक की बैंकों के प्रभुत्व वाली वित्तीय प्रणाली में यदि बैंकों द्वारा समग्र जोखिम को बांटने का प्रयास किया जाता है तो भी बैंकों की भूमिका को कम नहीं आँका जा सकता, क्योंकि वे प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में क्रेडिट स्क्रीनिंग करते हैं तथा वे पूंजी बाजार में लागत का पता लगाने तथा जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में एक अत्यावश्यक इनपुट के रूप में सूचना उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। हालांकि, बैंकों द्वारा क्रेडिट स्क्रीनिंग के माध्यम से एकत्रित की गई सूचना का प्रसार काफी घट सकता है यदि सक्रिय द्वितीयक बाजार का अभाव हो।

3.xi सॉन्ग एंड ठैकोर (2010) इसके अतिरिक्त यह भी तर्क देते हैं कि इस प्रकार की सह-निर्भरता बैंकों तथा बाजारों को दो चैनलों अर्थात् - जोखिम के प्रति संवेदनशील बैंक पूंजी के प्रतिभूतिकरण तथा विनियामक अपेक्षाओं के जरिये जोड़ती है। प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत, क्रेडिट स्क्रीनिंग के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम उधारकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता (विश्वसनीय तथा दीर्घकालिक प्रतिभूति बाजार के विकास हेतु गुणवत्तापारक ऋण सुनिश्चित करने की

महत्ता) को प्रमाणित करता है तथा बाजार वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाता है। पूंजी बाजार का विकास वित्तीयन प्रतिरोधक को सरल बनाता है तथा बैंकों के लिए पूंजी लागत को कम करता है। इससे बैंकों को जोखिम पूर्ण ऋणों के लिए अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध होने में मदद मिलती है जिससे वे अन्यथा दूर रहते। इस प्रकार अनुपूरक मॉडल बैंकों और बाजारों को प्रतिसूचना स्रोत उपलब्ध कराता है जिसे वे बैंकों द्वारा ऋण विश्लेषण और बाजारों द्वारा वित्तीय उपलब्धता को सर्वोत्तम रूप में व्यवहृत कर सकते हैं। इस प्रकार की पारस्परिक समझ के अभाव में इस बात की संभावना हो सकती है कि विनियामक नीतियाँ असमान हों एवं उधारकर्ताओं को ऋण प्रणाली के साथ खिलवाड़ करने का अवसर मिल जाए जो कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी मसले का रूप ले सकता है।

3.xii कारपोरेट गवर्नेंस में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार करते समय एलेन और गेल (1997) ने यह टिप्पणी की है कि वित्तीय प्रणाली की सावधानीपूर्वक तुलना मौजूदा नियंत्रक सिद्धांतों को समर्थन प्रदान नहीं करती है। कुछ देशों में बाजारों के लिए कारपोरेट नियंत्रण सामान्यतः मौजूद नहीं होता है, एवं बैंकों की भूमिका का निगरानी तंत्र कमजोर होने के साक्ष्य हैं। बैंकों में फर्मों को उचित संसाधन मुहैया कराने की निगरानी के प्रत्यायोजन से उनकी भूमिका को बल मिलता है। इससे अर्थव्यवस्था में विविधीकरण और समय-समय पर उठने वाले उतार-चढ़ाव को सुगम बनाने में जोखिमों की भागीदारी हो जाती है, कारपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित होता है तथा फर्मों के साथ सुदीर्घ बने सम्बन्धों से असंतुलक सूचना समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिलती है। (एलेन एवं कारलेटी, 2008)। दूसरे शब्दों में उधारकर्ताओं को अनुशासित रखने में बैंकों की भूमिका में और पूंजी बाजार में बाजार अनुशासन को सुनिश्चित रखने में सूक्ष्म अंतर है।

3.xiii कुछ अध्ययन इस बात का भी सुझाव देते हैं कि बैंकों की गतिविधियाँ पूंजी बाजार में बढ़ाने से फर्मों में इक्विटी धारण करने के जरिए निष्पादकता संबंधी लाभ प्राप्त हो सकते हैं (बोसॉन एण्ड ली 2004 ली एंड मासूलियस 2004)। बड़े पूंजी बाजार में पहुँच होने से बैंकों को जोखिम प्रबंधन के लिए अधिक निष्पादक लिखतों की उपलब्धता से उनकी लागत कम हो जाती है और प्रतिष्ठा बढ़ जाती है

⁷ इकोनॉमिक जर्नल वाल्यूम 120।अंक 547। सितंबर 2010 ' फाइनेंशियल सिस्टम आर्किटेक्चर तथा को-एवोल्यूशन ऑफ बैंक एंड कैपिटल मार्केट्स।

जिससे वे वित्तीय बाजार में आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। हालांकि, पूंजी बाजार की सशक्तता से उत्पन्न सूचनात्मक बाह्य कारकों से केवल उन बैंकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ जाती है जो सूचना के प्रभावी लाभ लेने के साधनों से सन्नद्ध हैं, जबकि उक्त व्यवस्था में कम सज्जित बैंकों को अनिवार्यतः दंड भोगना पड़ता है (बोसॉन 2010)।

क्या बैंक वित्तीय प्रणाली में विशेष दर्जा बनाए रख सकेंगे?

3.xiv कुछ एक कारक ऐसे हैं जो विश्व की वित्तीय संस्थाओं में बैंकिंग संस्थाओं को विशेष दर्जा प्रदान करते हैं। भुगतान प्रणाली और नकदी वितरण में अपनी विशिष्ट भूमिका के कारण बैंक प्रणालीगत जोखिम से दो-चार हो सकते हैं जो उन्हें अन्य वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बनाता है। जमा स्वीकार करने वाली वित्तीय संस्थाओं के रूप में सीमित देयता संयुक्त स्टॉक बैंकिंग कंपनियाँ विशिष्ट स्थिति में होती हैं चूंकि वे सभी मांग जमा राशियों को, मांग करने पर देने का वचन देती हैं जबकि वे नकदी के कारोबार में संलग्न होती हैं (नकदी जमाराशियों को कम तरल ऋणों में परिवर्तित करती है) और परिपक्वता पर (अल्पावधि जमाराशियों से दीर्घावधि ऋणों के रूप में) उनका रूपान्तरण करती है।

3.xv इन मामलों को सुलझाने के लिए किए गए नवोन्मेषी उपायों और पूरक विनियामक पहल ने वास्तव में प्रतिभूतिकरण और वृहत्तर जोखिम सहभागिता को बढ़ावा दिया है। तथापि, जिन परिस्थितियों के कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हुए, उन्हें ध्यान में रखते हुए जिन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, वे हैं बैंकों द्वारा जोखिम उनको अंतरित करना जिनमें उन्हें संभालने की क्षमता नहीं थी। ऐसी स्थितियों में खतरे का कारण अपारदर्शी बाजार और उनकी ओर से पर्याप्त ध्यान न देना है, जिनसे अपेक्षा थी कि वे विशेषकर ऋण जोखिम के अंतिम वितरण पर खास ध्यान देंगे। इसी प्रकार पारदर्शी और नकद पूंजी बाजार के अभाव में उनके होने की परिकल्पना करना और कृत्रिम साधनों द्वारा परिसंपत्ति की कीमतों में घटोत्तरी के जरिए संसाधनों के आबंटन को संक्रमित/विरूपित करना है। यदि वसूल की गई राशि परिसंपत्ति के सही/उचित मूल्य से कम होगी तो बाजार सहभागियों के प्रत्युत्तर में कतिपय अन्तर्जात विषमताएँ आ सकती हैं।

3.xvi निक्षेप बीमा एक और भिन्न क्षेत्र है जो बैंकों को विशिष्ट बनाता है। इस संबंध में कोई यह तर्क कर सकता है कि आंशिक निक्षेप बीमा से बैंकों को जोखिमपूर्ण उधार देने के विकल्प को प्रोत्साहन मिलता है तथा पूंजी अपेक्षाएँ

ऐसे लोभ को संवरित करने से रोकती हैं। तथापि प्रतिभूतिकरण और क्रेडिट डिफाल्ट स्वाप्स जैसे नवोन्मेषी उत्पादों ने मूलतः उस स्वरूप को बदल दिया है जिससे अब तक बैंकिंग कारोबार होता था और अधिक दक्षतापूर्ण पूंजी के उपयोग के जरिए उधारदाता और उधारकर्ता के बीच रिश्ते भी बदल गए हैं। दूसरी ओर निक्षेप बीमा में तथाकथित सन्निहित नैतिक मुश्किल को विकल्पतः आवर्धित रूप में दर्शाया जा सकता है क्योंकि बैंक, जैसा कि अनेक पाठ्य पुस्तकों में अब भी सुझाया गया है, बचतकर्ताओं से मौजूदा राशि ही निक्षेप के रूप में स्वीकार करते हैं और उधारकर्ताओं को उधार देते हैं: - वे ऋण का सृजन करते हैं जबकि मुद्रा कुछ भी नहीं होती है, वे उधारकर्ता को ऋण देते हैं एवं उधारकर्ता के मुद्रा खाते में ही राशि जमा करते हैं (टर्नर 2013)।

3.xvii वित्तीय क्षेत्र के विकास और संरचना से संबन्धित एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम है राजनैतिक हस्तक्षेप पूर्ण भूमिका जो वित्तीय प्रणाली के विभिन्न चरणों में भिन्न - भिन्न अंश और रूप में साकार हो सकती है (सॉन्ग एंड ठैकोर, 2012)। किसी वित्तीय क्षेत्र के विकास के प्रारम्भिक चरण में, यह भूमिका सामान्यतः सरकार द्वारा बैंकों की पूंजी में अंशदान अथवा आर्थिक सहायता के रूप में परिलक्षित हो सकती है, जो प्रत्यक्ष उधार देने संबंधी निर्धारण सहित हो सकती है अथवा बिना निर्धारण के, ताकि व्यापक बैंकिंग उधार को सुनिश्चित किया जा सके। वित्तीय क्षेत्र के विकास के मध्यवर्ती चरण और उन्नत चरण में सूचना प्राप्त करना और उसका प्रसंस्करण करना कम लागत वाला कार्य हो जाता है तथा बैंकों का लाभ बढ़ता है जिससे पूंजी के लिए उनकी निर्भरता सरकार पर घट जाती है। हालांकि उन्नत स्थिति में राजनीतिक हस्तक्षेप निदेशित उधार देने के रूप में हो सकता है (जिसका सैद्धान्तिक अर्थ जोखिमपूर्ण उधारकर्ताओं को बैंक द्वारा उधार देना है जो अन्यथा वित्तीय सुविधाओं से वंचित हो जाते।

परंपरागत बैंकिंग संस्थाओं और बाजारों द्वारा चुनौतियों का समाधान करना

3.xviii वैश्विक स्तर पर, आर्थिक संकट के उपरांत भावी बैंकिंग के संबंध में चर्चा और मूलभूत प्रश्न अभी तक जारी हैं। ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए स्विजरलैंड में पूर्ण मुद्रा (volgelled) संबंधी पहल एक शीर्ष उदाहरण है जिसका उद्देश्य किसी बैंक द्वारा उसके पूंजी आधार के अनुसार उधार देना है, न कि जमाकर्ताओं से प्राप्त जमा राशियों से ऋण देना। जबकि बैंकिंग उद्योग वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान उभरी समस्याओं के समाधान में व्यस्त है

और संकटोत्तर विकसित विनियमों को लागू करने की जदोजहद में लगा हुआ है, उन्नत प्रौद्योगिकी से समर्थित/संवर्धित वित्तीय सेवाओं के वैकल्पिक रूपों का प्रादुर्भाव भी परंपरागत बैंकिंग कारोबार के लिए चुनौती है।

3.xix इससे बाजारों में संस्थागत सहभागिता में कमी हुई, हालांकि वैश्विक वित्तीय संकट के कारण विनियामक सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई, साथ ही विभिन्न केंद्रीय बैंकों द्वारा भारी पैमाने पर आस्ति खरीद कार्यक्रम लागू किए गए जिनसे बाजार की तरलता और कीमत प्रणाली में हस्तक्षेप हुए। दूसरी ओर बैंकों द्वारा तुलनपत्र में सुधार करने की पहल और कम पूंजी की अड़चनों की चुनौती के कारण अर्थव्यवस्थाओं में ऋण की मांग को पूरा करने के लिए अन्य प्रकार के वित्तीय मध्यस्थों की आवश्यकता हुई महसूस हुई। हालांकि इस पहल से यह अपेक्षित हुआ है कि विनियामक पैरामीटरों को पुनर्निरूपित किया जाए और तत्संबंधी कार्यान्वयन इस प्रकार हो कि न्यू फ्रेमवर्क नवोन्मेष और वित्तीय स्थिरता कायम करने को संतुलन कर सके।

3.xx यद्यपि नवोन्मेषी शक्तियाँ संस्थाओं और बाजारों के कार्यों एवं वित्तीय प्रणाली की संरचना में परिवर्तन को प्रभावित करना जारी रखेंगी, विनियमों के प्रति रुझान भी बैंकों के प्रभुत्व वाली प्रणाली से खासकर बाजार आधारित प्रणाली तथा सामान्यतः वित्तीय प्रणाली के विकास को प्रभावित करेगी। जबकि यह आवश्यक है कि उपलब्ध विनियामक क्षमता को नीतिगत वातावरण और रणनीतिक नवोन्मेष से संतुलित किया जाए, उत्तरवर्ती अपेक्षा को इस प्रकार उन्नत किया जाए कि वह आर्थिक विकास की प्रक्रिया से नैसर्गिक रूप में मेल खा सके। कभी - कभी आवश्यक नवोन्मेष इसलिए भी नहीं चल सकते हैं कि नीति-निर्धारण नवोन्मेषी प्रभाव/उपायों जैसे Success failure paradox और feedback rigidity paradox⁸ पर प्रतिकूल असर डालती है। निष्कर्षतः चूंकि नवोन्मेष का अधिकांश अंश प्रौद्योगिकी संवरित है वित्तीय प्रणाली के सभी स्टैकहोल्डरों के समक्ष यह चुनौती है कि वे प्रौद्योगिकी के नकारात्मक पहलुओं से इसकी सुरक्षा करें। (बॉक्स 3.1)

बॉक्स 3.i: प्रौद्योगिकी : सकारात्मकता और नकारात्मकता की सहमूर्ति

वित्तीय स्थिरता संबंधी पिछली रिपोर्टों में वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण के प्रभावों पर छिटपुट चर्चा हुई है जिसमें से अंतिम विशेषकर साइबर धमकियों से उत्पन्न चुनौतियों के संबंध में सावधान करता है जिन पर संस्था⁹ विशेष में शामिल मुद्दों पर बोर्ड के स्तर पर चर्चा किए जाने की अपेक्षा है। हालांकि प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण विकसित होती हुई वित्तीय प्रणाली का अभिन्न अंग हैं, उनसे संबंधित संभावित जोखिमों पर प्रारम्भ में कम ध्यान दिए जाते हैं, और विनियमित वित्तीय संस्थाओं के लिए अथवा उस मामले में विनियामकों के लिए भी उनके असर का आकलन करना और भावी परिचालनों संबंधी जोखिमों के लिए पूंजीगत अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध कराना मुश्किल होता है।

जबकि हाल ही में केंद्रीय बैंक से की गई चोरी प्रमुखता से यह इंगित करती है कि सुस्थापित वैश्विक भुगतान प्रणाली कैसे आसानी से खतरे में पड़ जाती है। आईओ एक्टिव द्वारा प्रकाशित लेख से यह स्पष्ट होता है कि उचित साइबर सुरक्षा

तंत्र के अभाव में किस प्रकार कार की रिमोट हैकिंग किसी इको सिस्टम (जटिल नेटवर्क अथवा आपस में जुड़ी हुई प्रणाली)को खतरे में डाल सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी की बोलचाल की भाषा में 'सेवा नकारना' एक ऐसी चीज़ है जो डरावनी प्रतीत होती है। जबकि मौजूदा साइबर सुरक्षा प्रणाली सशक्त प्रतीत होती है क्योंकि उसने अनेकों साइबर हमले सुरक्षात्मक रूप से झेले हैं, बड़े हुए नेटवर्क युक्त वैश्विक वित्तीय प्रणाली के संबंध में मल्टी सिग्मा चूक संबंधी घटना एक ऐसी बात है जिसके सभी स्टैक होल्डरों द्वारा सुरक्षा की जानी आवश्यक है।

विनियमन सामान्यतः नवोन्मेषी उपायों के संबंध में अड़चन के रूप में नहीं आना चाहिए बल्कि नवोन्मेषी शिखर की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। इसलिए सभी विनियमों का उद्देश्य लोक कल्याण को किसी नवोन्मेषी प्रयास से बढ़ाना है और इस बाबत किसी प्रतिगामी क्रिया को रोकना है। इस संबंध में रोचक बात यह है कि वित्तीय बाजार के

(जारी...)

⁸ आर गांधी 'वित्तीय स्थिरता - मुद्दे और चिंताएँ: क्या हम सही लक्ष्यों पर निशाना लगा रहे हैं?' फरवरी 5, 2016. https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?id=988s. पर उपलब्ध है।

⁹ वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2015 में रघुराम राजन द्वारा लिखित प्रस्तावना में।

विनियामकों को 'इनसाइडर ट्रेडिंग' के नए रूप से निपटना है और इस संबंध में एतदर्थ दी गई परिभाषा का कड़ाई से अनुपालन करना है। चूंकि डेटा का डिजिटलीकरण डिजिटल अपराधियों को एक ऐसा नुस्खा उपलब्ध करवाता है जिससे वे डेटा चुरा सकें और गैर सार्वजनिक कारपोरेट सूचना के जरिए पैसे कमा सकें।

साइबर धमकियों का समाधान करना विभिन्न विधिक क्षेत्रों में उनकी क्रास बार्डर पहुँच के कारण जटिल होती है। दूसरी ओर साइबर धमकियों के संबंध में सूचना की स्वैच्छिक सहभागिता के प्रयास में कमी के कारण इसकी पुनरावृत्ति को रोकना कठिन होता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान वित्तीय प्रौद्योगिकी में निरंतर उन्नति ने महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। स्टार्ट अप्स द्वारा प्रवर्तित फिनटेक मूलतः वित्तीय समाधानों से युक्त ऐसी प्रौद्योगिकी है जो एप्लीकेशनों और उत्पादों के विकास में ही डिजिटल नवोन्मेषी अवरोध ही

उत्पन्न नहीं करती है बल्कि बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र के कारोबारी मॉडलों पर भी असर डालती है।

यह कहावत कि बिना श्रम के फल नहीं मिल सकता है, इसी के तहत यह कहा जा सकता है कि फिनटेक ने ग्राहकों के अनुभव में आश्चर्यजनक परिवर्तन किया है जिसमें स्मार्ट कांट्रेक्ट से लेकर सरल 'Shake for Balance' प्रणाली बैंक एप्प¹⁰ में रहती है जो त्वरित और शीघ्र डिलीवरी चैनल का कार्य करती है। हालांकि हैकिंग धमकियों के स्तर में वृद्धि और सेवाएँ न देने की धमकी से भारी तादात में अड़चनें आने की संभावना है जो न केवल जोखिम से संबन्धित ग्राहक के संबंध में संवेदनशील जानकारी तक पहुँच सकते हैं और साइबर धोखाधड़ियाँ कर सकते हैं। इसलिए श्रम साध्य प्रभावी निगरानी का कार्य और सूचना प्रौद्योगिकी से संबन्धित प्रबंधन प्रणाली और डाटा सुरक्षा जोखिम को संभालना अवरोधक नवोन्मेषों के निवल लाभ में वृद्धि करते हैं।

भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए बैंकों और बाजार के बीच बेहतर संतुलन की खोज

3.xxi हालांकि भारत की वित्तीय प्रणाली में बैंकों का प्रमुख स्थान है तथापि हाल की प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि गैर बैंक स्रोत के जरिए आने वाले संसाधन बैंकों के समतुल्य हैं। चूंकि बैंक तुलनपत्र को आवश्यक रूप में दुरुस्त करने में लगे हुए हैं तथा कारपोरेट सेक्टर का एक वर्ग डिलीवरेजिंग की ओर अग्रसर हो रहा है, अतः ऋण प्रदान करना अन्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी बनती है। बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की वृद्धि धीमी होने के मद्देनजर, ऐसा प्रतीत होता है कि पूंजी बाजार वाणिज्यिक क्षेत्र की आवश्यकताओं की वित्तीय सहायता कर रहा है (चार्ट 3.1)। हालांकि अल्पावधि कर्ज लिखतों और निजी नियोजन (कर्ज प्रतिभूतियों के दीर्घावधि सार्वजनिक निर्गम के बदले) मार्ग में वृद्धि यह इंगित करती है कि डेट (कर्ज) बाजार को अभी लंबा रास्ता तय करना है जब वे बैंक ऋण एवं शेयर जोखिम के संबंध में प्रभावी रूप में अनुपूरक का दर्जा हासिल कर पाएंगे।

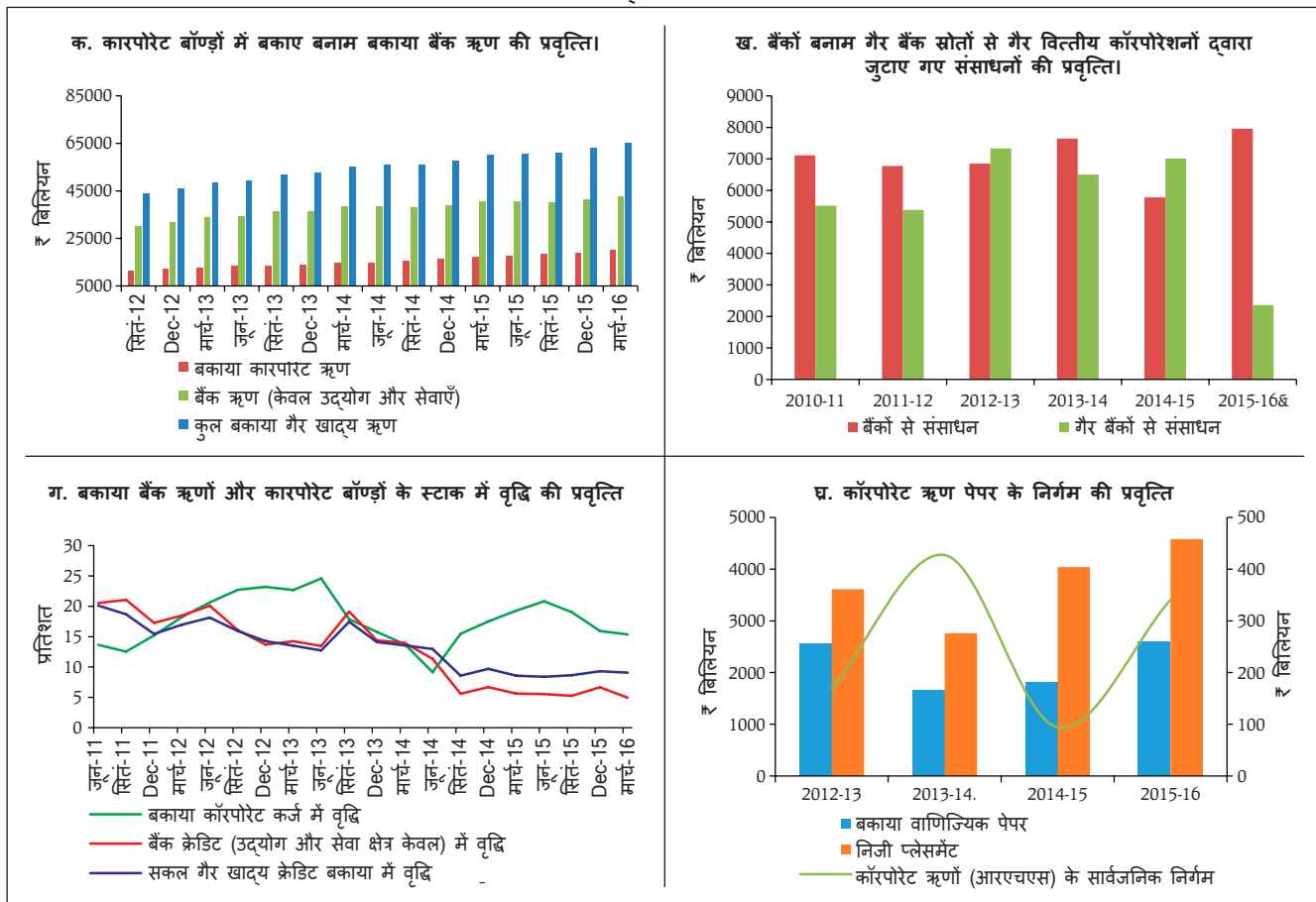
3.xxii घरेलू वित्तीय बाजार के सूक्ष्म अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपने संसाधनों/पूंजी आबंटन के निर्णय के सशक्त नेटवर्क का प्रदर्शन करने वाले उधारकर्ताओं के

एक वर्ग के लिए बैंक क्रेडिट उपलब्ध कराते हैं। परिणामतः बिना नेटवर्क वाले लघु उधारकर्ताओं को ऋण देने को कम वरीयता दी जाती है, केवल उनको छोड़कर कर के जिन्हें निदेशित उधार देना जिम्मेदारियों में शामिल है, जिससे उनके कार्य में असंतुलन पैदा होता है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि संकेंद्रित जोखिम पैदा होता है, जिससे बचना चाहिए। दूसरी ओर एक चौथाई सदी पूर्व प्रारम्भ हुए आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन के बावजूद बॉन्डों के वित्तीयन के संबंध में पूंजी बाजार की व्यापकता और गहराई में कमी है। वित्तीय मध्यस्थता में संस्थागत और बाजार चैनलों द्वारा संप्रति महसूस किए जाने वाले अवरोध हालांकि तर्कसंगत लगते हैं। दोनों चैनलों को एक दूसरे का अनुपूरक और सह विकसित होने के लिए अनुपूरक इको सिस्टम लागू करने की आवश्यकता है।

3.xxiii मौजूदा हालात में बैंकों की बहियों में बड़े जोखिमों के संकेन्द्रण से उत्पन्न चिंता उचित है, समग्र आबंटनीय दक्षता और आर्थिक कल्याण पर प्रभाव डाले बिना बॉन्ड वित्तीयन के लिए संसाधन आबंटित करना एक चुनौती है। महत्वपूर्ण चुनौतियाँ वे हैं जो ऋणों और बॉन्डों के लेखाओं से उत्पन्न हुई है, द्वितीयक बाजार में बॉन्डों के लिए तरलता उपलब्ध होने में विघ्न और मियादी बैंचमार्क का अभाव उनमें से प्रमुख हैं।

¹⁰ एक प्रमुख लोकप्रिय और प्रभावी मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन (स्वीडन के प्रमुख रिटेल बैंक अर्थात स्वीडिश बैंक द्वारा सर्वप्रथम इस्तेमाल) जो ग्राहकों को अपने मोबाइल फोन को हिलाने पर उसके बैंक खातेगत शेष राशि की जानकारी दे देता है।

चार्ट संख्या 3.1 : बैंकों और गैर बैंक स्रोतों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों का प्रवाह



नोट: चार्ट 'ख' 2015-16 के अस्थायी आंकड़े दर्शाता है।
स्रोत: भा.रि.बैं., सेबी

3.xxiv सर्वप्रथम बॉण्डों का लेखा व्यवहार ऋणों की भांति नहीं है क्योंकि उनमें अंतरण की भिन्नता है। इसके अलावा अधिकांश ऋण संबन्धित बैंक की बैचमार्क फ्लोटिंग दर पर आधारित होते हैं जबकि सामान्यतः बॉण्ड निश्चित कूपन उत्पाद हैं। इसलिए बाजार जोखिम के दृष्टिकोण से भी बॉण्डों और ऋणों में समानता नहीं है और यह बात लेखांकन प्रणाली महत्वपूर्ण मुद्दा बना देती है।

3.xxv दूसरी, बैंकों की बहियों में कारपोरेट बाँडों की निष्क्रिय धारिता बाँडों के गैर बैंक धारकों को निर्गमकर्ता की मौजूदा क्रेडिट हैसियत की कोई सूचना नहीं देती है। फिर भी, गैर तरल बाण्ड का तात्पर्य यह होता है कि बॉण्डों की लागत का असर ज्यादा है एवं मूल्यांकन मानदंड जिसमें ये उच्च लागत शामिल नहीं होती हैं, बैंकों को उनकी ट्रेडिंग के लिए प्रोत्साहन कम कर देती है। तरलता के अभाव में किया गया कोई भी मूल्यांकन

सैद्धांतिक ही होता है। इसके अलावा मूल्यांकन प्रक्रिया में बैंक प्रमुख घटक होते हैं, ऐसी स्थिति में बॉण्डों की खरीद की स्थिति ज्यादा बनती है जिसे नकारा नहीं जा सकता है।

3.xxvi इसके अलावा चूंकि कारपोरेट बॉण्डों के निर्गम का आकार तुलनात्मक रूप से छोटा होता है, समग्र निर्गम को कुछ अंशधारकों में, विशेषकर 'Buy-and-hold' टाइप के निवेशकों (बैंकों सहित) जो उनकी परिपक्वता तक उन्हें धारण किए रखना चाहेंगे, के बीच निष्क्रिय चयन प्रक्रियागत मूल्यांकन के तहत वितरण में प्रोत्साहन जोखिम बना रहेगा जो उनके वास्तविक निपटान / भुगतान के समय की काल्पनिक स्थिति होगी जो चयनित की तुलना में प्राप्त मूल्य से काफी भिन्न हो सकता है। इस प्रकार द्वितीयक बाजार गैर तरल सृजित होने पर बॉण्डों के मूल्यन में बाह्य नकारात्मक तत्व स्वयं उत्पन्न कर

देता है जो द्वितीयक बाजार में नकारात्मक प्रतिसूचना के तहत उसको और प्रभावित कर देता है। ऐसा इसलिए होता है कि पूर्वोल्लिखित तत्वों के कारण मार्केट क्लियरिंग न करने वाले मूल्यन के कारण ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश करने के इच्छुक आखरी निवेशकों को प्राथमिक बाजार में बेहतर मोलभाव करने का मौका मिल जाता है। द्वितीयक बाजार में प्राथमिक निवेशकों की कम रुचि होने से बैंकों के पास ऐसी प्रतिभूतियों की कम इनवेंटरी होगी जो द्वितीयक बाजार की तरलता में बाधक होगी।

3.xxvii तीसरा बिन्दु यह है कि भिन्न लेखा व्यवहारों और द्वितीयक बाजार की तरलता में मुश्किल आने से बैंकों के समक्ष उनके कारपोरेट बॉन्ड पोर्टफोलियो के संबंध में मूल्यन तटस्थ होने पर कम विकल्प उपलब्ध होंगे। मानक अवधि के विशेष बेंचमार्क की अनुपस्थिति में ऋण बहियों की कीमत का निर्धारण आवश्यक होगा जो बैंक के विशिष्ट बेंचमार्क से रूपान्तरण हेतु आवश्यक है। ऐसे बेंचमार्क स्थापित करने और उनमें ब्याज दर की सुविधा देने से बैंकों को नियत कूपन दर बॉन्ड बहियों को फ्लोटिंग अथवा फ्लोटिंग दर वाले कारपोरेट ऋण बहियाँ नियत दर वाली आस्तियों पर आधारित होंगी जिससे लेखा संबंधी मुद्दे कम संगत होंगे। यह भी बहुत आवश्यक है कि

कारपोरेट बॉन्डों की तुलना में उनके प्रतिस्पर्धी कारपोरेट ऋण के मूल्यन का मानकीकरण स्वाप के जरिए हो सकेगा जो अंतर्लयित परिसंपत्ति स्वाप बाजार के विकास से फलीभूत होगी और इस प्रकार उसी दायी के लिए ऋण कारपोरेट बॉन्ड आधारित प्रक्रिया को सख्त बनाएगी। ऐसे परिसंपत्ति स्वाप क्रेडिट डेरिवेटिव्स के मूल्य निर्धारण के लिए आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार करेंगी।

3.xxviii दूसरे शब्दों में इस सब का तात्पर्य यह होता है कि संस्थागत और बाजार आधारित मध्यस्थ ब्याज दर डेरिवेटिव के लिए अनुरूप बाजार हेतु पूरक की भूमिका अदा करने के करीब होते हैं। इससे प्रतिभूतिकरण बाजार को मदद मिलेगी जो असंतुलित सूचना की मौजूदा अधिकता से तरलता को पंगु बना देती है।

3.xxix अंत में निजी नियोजन बाजार में वृहत्तर पारदर्शिता लाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि द्वितीयक बाजार की ट्रेडिंग को प्रोत्साहन मिल सके और बड़े उधारकर्ताओं पर परोक्ष रूप में कारपोरेट बॉन्ड मार्केट में अधिक आमद को प्रोत्साहन मिले। इससे बाजार आधारित और बैंक आधारित वित्त के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा।

भाग II भारत में वित्तीय क्षेत्र - विनियमन और विकास

जहां वैश्विक विनियामक सुधारों के परिणामस्वरूप बैंकों के पूंजी अनुपात में सुधार हुआ है, वहीं वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण का निरंतर प्रवाह और स्थिर लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियां भी होंगी।

भारत में जहां बैंकिंग क्षेत्र तुलन पत्र की त्रुटियों को ठीक करने के लिए जुझ रहा है, वहीं अन्य संस्थाओं, जैसे गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों को बृहतर भूमिका अदा करनी होगी, यहां तक कि पूंजी बाजार को ऋण पहुंच सुविधाजनक करना आवश्यक होगा और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी और व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए इक्विटी वित्तपोषण करना होगा।

पारस्परिक निधि के विस्तृत होते जा रहे क्षेत्र के साथ, भारत का प्रतिभूति बाजार निरंतर बढ़ रहा है, जिस में निवेशक की जनसंख्या का बृहतर भाग शामिल है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पात्र विदेशी निवेश, लिखत और घरेलू बाजार के उचित सूक्ष्म ढांचे के अनुसार आवश्यक लचीलेपन के अभाव में विदेशी बाजारों की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं। पण्य डेरिवेटिव बाजार की गहराई भौतिक बाजार संरचना में आवश्यक सुधारों के साथ बढ़नी चाहिए।

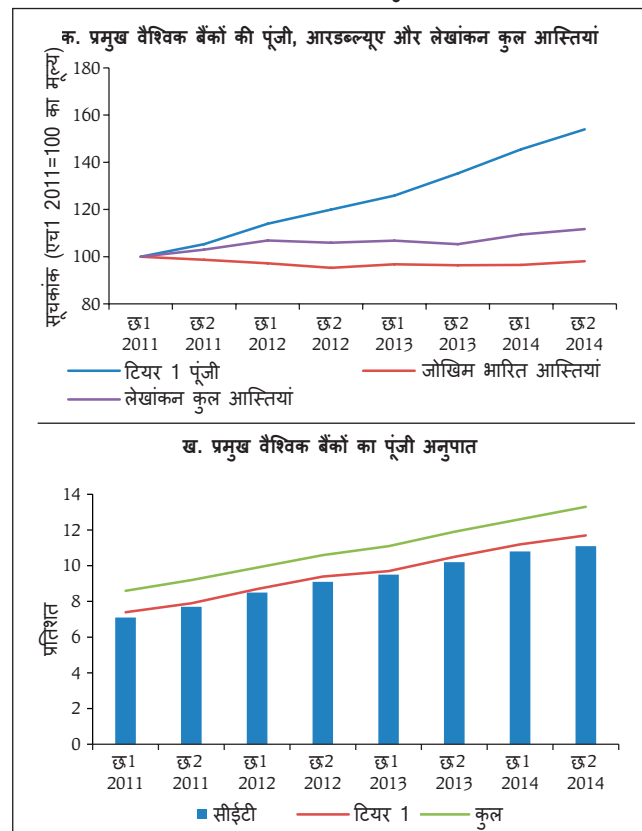
पुनः सुरक्षा गतिविधियों से जोखिमों के संभाव्य केंद्रीकरण के लिए उनका उचित मूल्यांकन और प्रबंध किया जाना आवश्यक है, जबकि bancassurance के अंतर्गत संभाव्य गलत विक्रय पर जांच पड़ताल करनी चाहिए। जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की ओर बढ़ता कदम और सेवानिवृत्ति आयोजना परामर्शदात्री सेवाओं को औपचारिक रूप देने की ओर बढ़ने से पेंशन क्षेत्र के विकास में सहायता होगी।

अंतरराष्ट्रीय विनियामक सुधार कार्यसूची - प्रगति और दुविधा

3.1 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के पूर्ववर्ती अंकों में जहां संकट पश्चात अंतरराष्ट्रीय विनियामक सुधारों को बनाने और कार्यान्वित करने में हुई प्रगति को नोट किया गया है, वहीं गति निर्धारण करने में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भी और कुछ सम्मत सुधारों के प्रभाव का निर्धारण करने में अंतर समझने पर जोर दिया गया है। इससे पता चलता है कि सुधारों के अधिकतम ठोस प्रभावों में से एक बैंक के बृहतर और बेहतर गुणवत्ता के पूंजी बफरों (चार्ट 3.1) में दिखाई दिया है और लीवरेज में क्रमिक रूप से घट दिखाई दी है¹¹।

3.2 बैंकों को अधिक जोखिम उठाने से रोकने के लिए विविध विनियामक नुस्खों में से एक है, बासेल III के अंतर्गत वैश्विक निवेश का प्रस्तावित नया उपचार और ऐसे निवेशों पर विशाल सीमाएं लागू करने की संभावनाएं बैंकों के लिए आगे जाकर विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में पूंजी आवश्यकताओं को बढ़ा सकता है। ऐसे विनियमों में सरकारी प्रतिभूति बाजार के प्रतिप्रभाव हो सकते हैं। जहां विनियमों को मजबूत बनाते समय यह अपेक्षा की जाती है कि दीर्घावधि में एक निवल सकारात्मक प्रभाव हो, चुनौती यह है कि बैंकों के गिरते

चार्ट 3.1: प्रमुख वैश्विक बैंकों की पूंजी अनुपात और जोखिम - भारत आस्तियों की प्रवृत्तियां*



नोट: * प्रमुख बैंकों को 'समूह 1 बैंकों' के रूप में शामिल किया गया है, जिसकी व्याख्या 'बीसीबीएस मॉनिटरिंग रिपोर्ट' में की गई है जिसमें वे बैंक शामिल हैं जिनके पास पाउंड 3 बिलियन से अधिक टियर 1 पूंजी है और जो अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय हैं।

स्रोत: बीसीबीएस बासेल III मॉनिटरिंग रिपोर्ट (सितंबर 2015)

¹¹ वित्तीय स्थिरता बोर्ड वार्षिक रिपोर्ट 2015

राजस्व और सिकुड़ते सीमान्त और अन्य पहलुओं जैसे द्रुत तकनीकी परिवर्तनों से उत्पन्न गतिविधियों के सामने कारोबार मॉडेल और रणनीतियों पर पुनः कार्य करने की आवश्यकता द्वारा चिह्नित वर्तमान संक्रमण चरण का प्रबंध करना। इस संदर्भ में, बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अच्छे अभिशासन प्रणाली के महत्व को पहचानें और विश्वास और कारोबार वृद्धि के बीच शृंखला (संपर्क) का अंतरराष्ट्रीयकरण स्थापित करें ताकि अधिक विस्तृत विनियमनों के लागत निहितार्थ और सूक्ष्म पर्यवेक्षण की सीमा को देखते हुए सही संतुलन ढूंढा जा सके।

3.3 वैश्विक वित्तीय क्षेत्र को कदाचार और अनाचार रवैये से हुई कई घटनाओं, जिनके परिणामस्वरूप कई मामलों में भारी वित्तीय दंड वसूल किए गए हैं, के कारण जनता के विश्वास, संस्थाओं की विश्वसनीयता और एकात्मता और बाज़ार तंत्र में लगी ठेस के प्रभाव से उबरना है। बासेल समिति द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण (बीसीबीएस) पर निर्दिष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस तत्वों का¹² लक्ष्य जनता का आत्मविश्वास बढ़ाना, बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और स्वस्थता बढ़ाना तथा बोर्ड स्तर की गवर्नेंस और क्षतिपूर्ति प्रथाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही से संबंधित मामलों पर जोर देने के साथ बैंकों और पर्यवेक्षकों लिए एक ढांचा प्रदान करना है। ऐसे ढांचे में और अन्य विनियामकों में जोखिम संस्कृति और क्लायंट सुरक्षा के महत्व पर थोड़ी चर्चा की जाती है। इस दौरान नये यूएस विनियामक प्रस्तावों के अंतर्गत, बैंकिंग और वित्त कार्यपालकों को कठोर बोनस स्थगन और कर वसूली का सामना करना पड़ा है। यूके, जो अब यूरोपीयन यूनियन (ईयू) के नियमों का अनुपालन कर रहा है, ने वरिष्ठ बैंकों पर वेतन और बोनस पर कर वसूली नियम पहले ही लगाया है। उनकी ओर से, वित्तीय संचालन प्राधिकरण (एससीए) और यूरोपीयन प्रतिभूति और बाज़ार प्राधिकरण (ईएसएमए) 'अनबंडलिंग' के लिए सहायता करती है जहां ब्रोकर की अनुसंधान लागत का वहन प्रबंधक द्वारा किया जाना होता है और न कि क्लायंट द्वारा। वर्ष 2015 की समीक्षा में, एफसीए के मुख्य निष्कर्षों में से एक यह था कि 'आतिथ्य' आस्ति प्रबंधन उद्योग में बदल गया जो हमेशा ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए

बनाया गया प्रतीत नहीं होता। इस संदर्भ में वित्तीय उत्पादों का गलत विक्रय भारतीय संदर्भ में उसी किस्म का हो सकता है।

घरेलू वित्तीय प्रणाली

बैंकिंग क्षेत्र

3.4 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ने आस्ति गुणवत्ता, पूंजी स्तर और भारतीय बैंकों, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा सामना की जानेवाली चुनौतियों से संबंधित लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित किया था। जबकि भारतीय बैंकों के निष्पादन मापदंड में खराबी मूल रूप से आर्थिक गिरावट के कारण हुई थी, अन्य पहलू, जैसे गवर्नेंस में कमजोरी, मूल्यांकन और जोखिम प्रबंध प्रक्रिया और कार्पोरेट क्षेत्र के अतिरिक्त लीवरेज के साथ बैंकों का अविवेक और कुछ मामलों में दुराचार के कारण हुई है।

3.5 बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख हिस्सावाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ, सरकार ने बैंकों के बोर्ड ब्यूरो की स्थापना तथा मुख्य निष्पादन संकेतकों (केपीआई) को शामिल करते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों¹³ के गवर्नेंस, पूंजी-आधार और निष्पादन में सुधार के मामलों के संपूर्ण विस्तार को संबोधित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

3.6 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के जून 2015 के अंक में आस्ति गुणवत्ता¹⁴ में खराबी के साथ अरैखिक तुलन पत्र जोखिम वृद्धि पर आधारित वर्तमान आस्ति गुणवत्ता मामलों पर शीघ्रता से संबोधित करने के प्रमुख महत्व पर जोर दिया गया। विपद्यस्त औद्योगिक क्षेत्रों के संबंध में सरकार द्वारा किये गये उपायों के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बुनियादी संरचना और महत्वपूर्ण उद्योग और रणनीतिक ऋण पुनर्निर्माण के लिए (एसडीआर) योजना को लचीले स्वरूप की दीर्घावधि परियोजना ऋण प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों को पुनरुज्जीवित करने के लिए संयुक्त उधारकर्ता मंच के निर्माण के लिए भी कदम उठाए हैं। बड़े ऋणों पर केंद्रीय सूचना निक्षेपागार (सीआरआईएलसी) के निर्माण के साथ, ऐसे विनियामक कदमों के कारण बैंकों को आस्ति गुणवत्ता समस्याओं की पहचान, अर्थक्षम आस्तियों¹⁵ के समय पर पुनर्निर्माण और अव्यवहार्य

¹² बीसीबीएस (2015) 'कार्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स फॉर बैंक्स' जुलाई <http://www.bis.org/bcb/publ/d328.pdf> पर उपलब्ध।

¹³ 'इंद्रधनुष' भारत सरकार की पहल <http://financialservices.gov.in/Pressnote/Indardhanush.pdf> पर उपलब्ध।

¹⁴ भारिबैं (2015) 'डज़ ऑगमेंटेशन ऑफ कॅपिटल रिड्यूस् रिस्क?' बॉक्स 3.2 मद (वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2015 का पृष्ठ 46)

आस्तियों की वसूली अथवा बिक्री करने के लिए तत्पर कदम उठाना संभव होगा। ये सभी उपाय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाथ में लिए गए आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) में समाप्त हुए।

3.7 जहां लघु अवधि में स्टॉक मार्केट मूल्यांकन में बैंकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, वहीं भारतीय बैंक उनके बृहतर स्टॉक मार्केट सूचकांक की तुलना में उनके निष्पादन के अनुसार उनके वैश्विक समकक्ष व्यक्तियों से अच्छी दशा में प्रतीत होते हैं (चार्ट 3.2)।

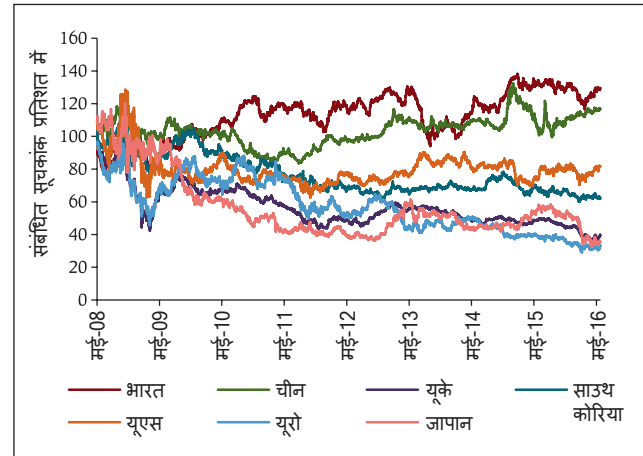
आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर)

3.8. एक्यूआर ने 36 बैंकों (सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों) को शामिल किया जो एससीबी के कुल अग्रिमों के 93 प्रतिशत गिना गया। एक्यूआर के अंतर्गत समीक्षित नमूना कुल ऋण बकाया के 80 प्रतिशत से अधिक और सीआरआईएलसी के माध्यम से रिपोर्ट किये गये बैंकिंग प्रणाली के खातों के 5 प्रतिशत हो गए। बैंकों का वस्तुनिष्ठ अनुपालन, जिसके साथ प्रयोज्य आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मानदंड और अपवादों को विधिमान्य बनाने के लिए किये गए अभ्यास को आस्ति वर्गीकरण/प्रावधानीकरण में विचलन के रूप में पर्यवेक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया। एक्यूआर अभ्यास के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे:

- बैंक स्तर पर आस्ति गुणवत्ता और प्रणाली स्तर पर संपूर्ण रूप में मूल्यांकन का परीक्षण करना।
- अनुत्पादक आस्तियों को पहचानने/बैंकों के माध्यम से अतिरिक्त प्रावधानीकरण में, विचलन के मामलों में एकसमान पेश आना (बर्ताव करना)।
- प्रावधानीकरण को शीघ्र अंतिम रूप देना और विचलन संप्रेषण को सुनिश्चित करके अतिरिक्त प्रावधानीकरण आवश्यकताओं की योजना बनाने में बैंकों को पर्याप्त समय का प्रबंध करना ताकि वे मार्च 2017 तक साफ और पूरी तरह से प्रावधान किया गया तुलन पत्र प्रस्तुत कर सकें।

बैंकों को समीक्षा के निष्कर्ष सूचित किए गए ताकि विनियामक नुस्खों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

चार्ट 3.2 : बाज़ार सूचकांक से संबंधित बैंकिंग सूचकांक में प्रवृत्तियां



स्रोत : ब्लूमबर्ग

3.9 इस प्रकार एक्यूआर का महत्व इस प्रकार है: क) क्रिलिक (CRILC) द्वारा सुविधा प्रदत्त बैंकिंग प्रणाली में आस्ति गुणवत्ता मामलों के प्रति सर्वांगीण दृष्टिकोण की आवश्यकता; ख) सन्निहित नैतिक जोखिम का प्रभाव न्यूनतम करने के लिए विनियामक सहनशीलता संकल्पना का औचित्य स्थापित करने का निर्णय; ग) यह समझना कि संचयी आधार पर आस्ति गुणवत्ता में सीमान्त खराबी के कारण किसी उधारकर्ता द्वारा चूक की संभावना का खतरा होगा और उसे पहले ही पहचानने से इष्टतम समाधान होगा।; घ) यह विश्वास कि जीडीपी अनुपात का कम ऋण और ऋण तथा खपत वृद्धि की अधिक संभावना से बैंकिंग उद्योग को प्रोत्साहित करना आवश्यक था ताकि विरासत से आ रहे मामलों पर काबू और नये और चिरस्थायी मार्ग पर नए सिरे से प्रारंभ किया जा सके। उपर्युक्त को देखते हुए एक्यूआर के पीछे जो तत्वज्ञान था, वह था कि जबकि अनुत्पादक आस्तियों का वर्गीकरण लेखांकन मानदंडों पर आधारित है, वहीं ऋण संविभाग में अनुत्पादक आस्तियों का अनुपात स्वयं ऋण संविभाग की निहित गुणवत्ता के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं देता। इस प्रकार एक्यूआर का उद्देश्य है कि बैंक, लेखांकन निहिताशय के परे हटकर उनके आस्ति संविभाग की ऋण जोखिम का पुनर्मूल्यांकन करें। जबकि एक्यूआर के परिणामस्वरूप कुछ बैंकों में लाभप्रदता पर लघु अवधि में अभूतपूर्व दबाव आ गया, बैंक के तुलन-पत्रों को साफ करने से यह अपेक्षा है कि लेखांकन नंबर में अधिक विश्वास के माध्यम से उनकी अधिक ऋण देने की क्षमता

¹⁵ भारिबैं (2014) अर्ली रेकगनिशन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस: प्रॉम्ट स्टेप्स फॉर रिसोल्यूशन एण्ड फेयर रिकवरी फॉर लेंडर्स : फ्रेमवर्क फॉर रिटिलाइजिंग डिस्ट्रेस्ड एसेट्स इन इकॉनॉमी:जॉइंट लेंडर्स फोरम (जेएलएफ) करेक्टिव एक्शन प्लान (सीएपी) 'रिफाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट लोनस 'सेल ऑफ एनपीएज बाय बैंक्स। <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/NPA300114REF.pdf> पर उपलब्ध।

को बढ़ाने और लंबे समय तक माध्यम में आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने से बाजार मूल्यांकन को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

3.10 तदनंतर, प्रणाली के स्तर पर ऋण जोखिम के उच्च केंद्रीकरण के निर्माण को देखते हुए कुछ विशाल कार्पोरेट इकाइयों को एकल बैंकों से बृहत निवेश के परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए जोखिम आधारित पूंजी ढांचे की पूर्ति करने के लिए एक सरल बृहत निवेश ढांचा¹⁶ प्रस्तावित किया है। यह ढांचा वित्तीय वर्ष 2017-18 के वित्तीय वर्ष से किसी एकल ऋणकर्ता को बृहत् उधार के संबंध में अतिरिक्त जोखिम भार और मानक आस्तियों के लिए अधिक प्रावधानीकरण प्रस्तावित करता है।

3.11 दबावग्रस्त आस्तियों के साथ डील करने की उधारदाता की क्षमता को और मजबूत करने के लिए रिज़र्व बैंक ने "दबावग्रस्त आस्तियों (एस4ए)¹⁷ के स्थायी ढांचे के लिए योजना" पर विशाल दबावग्रस्त लेखों के समाधान के लिए इष्टतम संरचना के रूप में दिशानिर्देश

तैयार किए हैं, जो दबावग्रस्त उधारकर्ता और बकाया ऋण तथा चिरस्थायी ऋण में द्विभाजन और ईक्विटी/अर्ध ईक्विटी लिखत के लिए धारणीय ऋण स्तर के निर्धारण पर जोर देते हैं। इससे जब उधारकर्ता पलट जाता है तब उधारदाता को अच्छा पहलू प्रदान करके वास्तविक कठिनाइयों का सामना करनेवाली इकाइयों के वित्तीय ढांचे को पुनः कार्य करने का दूसरा अवसर देकर सही आस्तियों को पुनः मार्ग पर लाने में सहायता मिलेगी।

उदभूत दिवाला और समाधान ढांचा

3.12 एक प्रभावी विधिक ढांचा जो समय पर दिवाला और शोधन अक्षमता का समय पर समाधान करके ऋण बाजार को सहायता करेगा, उद्यमिता को प्रोत्साहन देगा, कारोबार करने में सहजता बढ़ाएगा और अधिक आर्थिक वृद्धि और विकास की ओर अधिक निवेश की सुविधा प्रदान करेगा। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अध्यादेश से आगे बैंकों को समस्याग्रस्त आस्तियों में सहायता मिलने की संभावना है। (बॉक्स 3.1)

बॉक्स 3.1 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016

मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 (आईबीसी 2016) सक्रिय हुई और भारत के राजपत्र¹⁸ में अधिसूचित हुई। इस प्रकार आईबीसी, 2016 एकल कानून बना और वह दिवाला और शोधन अक्षमता को पुनर्गठन और शोधन अक्षमता से संबंधित विविध कानूनों को समेकन और संशोधन के साथ डील करता है। आईबीसी एकल व्यक्ति, कंपनी, सीमित देयता भागीदारी, भागीदारी फर्म और वित्तीय सेवा प्रदाताओं के अलावा अन्य विधिक इकाइयों, जैसा कि अधिसूचित किया गया हो और रुग्ण कंपनियों को या तो अपना कारोबार समेटने में अथवा इंजीनियरों को पलटने में और निवेशकों के लिए बाहर निकलने के लिए आसान बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण ढांचा निर्माण करने पर लक्ष्य केंद्रित करता है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की मुख्य-मुख्य बातें

- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संहिता) स्वच्छ, सुसंगत और त्वरित पहचान के लिए वित्तीय कठिनाई और कंपनियों के समाधान और सीमित देयता इकाइयों के लिए, यदि निहित कारोबार अर्थक्षम पाया जाता हो

तो, शीघ्र प्रक्रिया प्रदान करती है। संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत चूक के पहले मामले में दिवालियापन का समाधान शुरू किया जा सकता है और दिवालियापन समाधान की प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर पूरी करनी होती है।

- एकल व्यक्तियों के लिए संहिता दो भिन्न प्रक्रियाएं प्रदान करती हैं, जैसे - 'नयी शुरुवात' और 'दिवालियापन समाधान' और 'नयी शुरुवात' प्रक्रिया लागू करने के उद्देश्य से ऋणकर्ता के लिए अर्हता मानदंड निहित करती है।
- राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) को निर्णायक प्राधिकरणों के रूप में क्रमशः कंपनी के लोगों और फर्मों के लिए और एकल व्यक्तियों के लिए दिवाला, परिसमापन और शोधन अक्षमता के समाधान के लिए पदनामित कर दिया गया है।
- संहिता दिवाला व्यावसायिक, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों और सूचना उपयोगिता के विनियमन के लिए

(जारी...)

¹⁶ भारिबैं (2016) डिस्कशन पेपर ऑन फ्रेमवर्क फॉर एनहान्सिंग क्रेडिट सप्लाय फॉर लार्ज बॉरोअर्स थ्रू मार्केट मेकैनिज्म।

¹⁷ भारिबैं (2016): 'स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स' अधिसूचना जून

<https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?ID=10446&Mode=0> पर उपलब्ध।

¹⁸ दी गॅजेट ऑफ इंडिया, 28 मई 2016 <http://egazette.nic.in/WriteReadData/2016/169882.pdf> पर उपलब्ध।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड को स्थापन करने के लिए सहायता करती है।

- दिवाला व्यावसायिक, कोड में बल दिये गये दिवालियापन समाधान, परिसमापन और दिवाला कार्यवाही को पूर्ण करने में सहायता करेंगे। दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां व्यावसायिक मानदंड, आचारनीति की संहिता को विकसित करेंगे और दिवाला व्यावसायिकों के लिए पहले स्तर के विनियामक होंगे जो ऐसे व्यावसायिकों के लिए

प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग का विकास करेंगे। सूचना उपयोगी सेवाएं ऐसी कार्यवाहियों को सहायता करने हेतु वित्तीय जानकारी इकट्ठा करेंगे, क्रमवार लगाएंगे, अधिप्रमाणित करेंगे और प्रसार करेंगे।

- संहिता (भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता निधि) ऐसे व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान, परिसमापन और शोधन अक्षमता हेतु एक निधि स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है।

3.13 वित्तीय इकाइयों के लिए समाधान तंत्र के लिए अलग से डील करना आवश्यक है। इस संबंध में वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा निर्धारित विस्तृत दिशानिर्देशों के समरूप कतिपय कदम उठाए गए हैं। वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान व्यवस्था पर एक कार्यकारी समूह ने अपनी रिपोर्ट मई 2014 में प्रस्तुत की, जिसने यह सिफारिश की, कि या तो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) को एफआरए में रूपांतरित करके अथवा जो डीआईसीजीसी को किसी नियम के अंतर्गत शामिल करेगा, ऐसी एक वित्तीय स्थिरता एजेंसी (एफआरए) स्थापित की जाए। रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन (आरसी) की स्थापना की सहायता के लिए सरकार ने सितंबर 2014 में¹⁹ कार्य बल की स्थापना की। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप यूनियन बजट 2016-17 ने बैंकों में, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय क्षेत्र की इकाइयों में शोधन अक्षमता की स्थिति के साथ डील करने के लिए एक विशेषीकृत समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए एक विस्तृत 'वित्तीय फर्मों के समाधान पर संहिता' प्रस्तावित की। वित्तीय फर्मों के समाधान पर प्रारूप संहिता निकालने के लिए सरकार द्वारा मार्च 2016 में एक समिति स्थापित की गई।

बैंकों द्वारा संपार्श्विक प्रबंधन को मजबूत करने की आवश्यकता

3.14 बैंकिंग क्षेत्र (विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंक) में दबावग्रस्त आस्तियों के उभरते स्तर के इर्दगिर्द चर्चा से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संपार्श्विक प्रबंधन ढांचे की कुछ कमजोरियां सामने आयी हैं। खराब ऋणों के एक महत्वपूर्ण भाग की वसूली के कमजोर निष्पादन, संपार्श्विक प्रबंध में त्रुटियों के कारण हो सकता है, जिसके साथ

अपर्याप्त सुरक्षाकवर, बहुविध उधारदाता को उसी सुरक्षा के साथ गिरवी/दृष्टिबंधक की घटनाएं, कपटपूर्ण दस्तावेजीकरण, बहुविध निधिकरण और अति मूल्य निर्धारण भी शामिल हैं। सहायता संघ और बहुविध बैंक वित्तपोषण के मामलों में कुछ बैंकों की प्रवृत्ति अग्रणी बैंकों द्वारा किये गये मूल्यांकन अथवा अधिकतम निवेश वाले बैंक पर अधिकांश निर्भर रहने की हो गई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में से अधिकांश के पास संपार्श्विकों की निगरानी के लिए केंद्रीकृत डेटा बेस नहीं है, यह कार्य अक्सर अधिकांशतः अतिभारित शाखाओं पर छोड़ा जाता है, अतः इसका विपरीत प्रभाव निगरानी प्रक्रिया की क्षमता पर पड़ता है। एक ऐसा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम संपार्श्विक प्रबंध ढांचा, जिसमें संपार्श्विकों पर एक मजबूत केंद्रीकृत डेटाबेस शामिल हो, बैंकों को केवल निरंतर आधार पर संपार्श्विकों की निगरानी रखने में सहायता करेगा, अपितु धोखाधड़ी से उत्पन्न होनेवाले मामलों का समय पर पता लगाएगा।

3.15 दी सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्युरिटाइजेशन एसेट रिकन्स्ट्रक्शन एण्ड सिक्युरिटी इंटरैस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई) भारतीय वित्तीय बाजार बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक बन रहा है जिसमें बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के अति आवश्यक ऋण जोखिम प्रबंध को लंबी दौड़ में सहायता करने की संभाव्य क्षमता है। सीईआरएसएआई के संरक्षण के अंतर्गत अचल आस्तियों का पंजीकरण वर्ष 2011 से परिचालित किया गया है। हाल ही में सीईआरएसएआई को एक मजबूत चल आस्ति पंजीकरण को सहायता करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इस के साथ ही सीईआरएसएआई को केंद्रीय अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पंजीकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के

¹⁹ भारत सरकार ने वर्तमान एजेंसियों और रेसोल्यूशन कॉर्पोरेशन मिलाकर नई एजेंसियों के अपग्रेडेशन के लिए रोड मैप निर्धारित करने के लिए टास्क फोर्स की स्थापना की है। <http://pib.nic.in/newsite/printrelease.aspx?relid=110163> पर उपलब्ध।

स्वस्थ ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए संपार्श्विक और केवाईसी रजिस्ट्रों को महत्व देने और विशेष रूप से सूक्ष्म तथा लघु उद्यमियों और गरीबों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की उनकी भूमिका के कारण सीईआरएसएआई की भूमिका महत्वपूर्ण है।

बॉण्ड वित्तपोषण को प्रोत्साहन देना

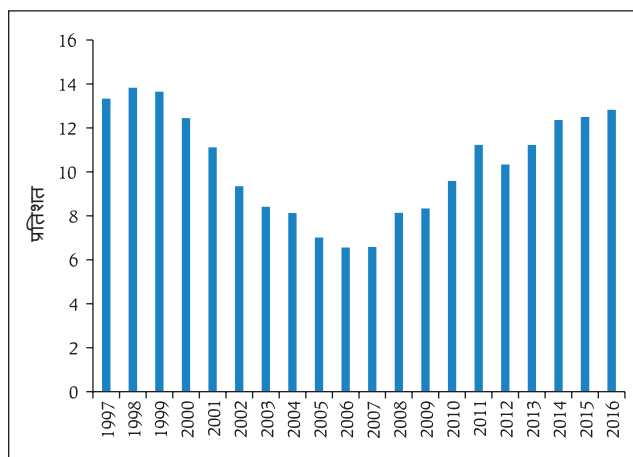
3.16 चलनिधि के नए मानदंडों के तहत और प्रतिभूतिकरण और ब्याज दर के डेरिवेटिव के लिए जोशपूर्ण बाजार के अभाव में बैंक दीर्घावधि वित्तपोषण के लिए बाध्य हो गए हैं। तथापि, भारत में बुनियादी सुविधा के वित्तपोषण के लिए मांग-आपूर्ति में बहुत अधिक अंतर के कारण दीर्घावधि कंपनी ऋण बैंकों पर और ऐसे ऋण निर्गमों को²⁰ ऋण बढ़ाकर देना शामिल करने में सहायता के विविध प्रकारों के लिए अन्य पदनामित विशेषीकृत विकास वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर रहना जारी बना रहेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंको को विवेकाधीन सीमाओं²¹ के अधीन मूलभूत सुविधाओं और कंपनी/विशेष हेतु साधनों (एसपीवीज़) द्वारा परियोजनाओं के अन्य प्रकारों को निधीयन करने के लिए जारी बाण्डों को अंशतः ऋण वृद्धि प्रदान करने के लिए अनुमति दी है। साथ ही, भारतीय कंपनियों को रुपया मूल्यवर्ग के अपतटीय बॉण्ड जो अक्सर 'मसाला बॉण्ड' के नाम से जाने जाते हैं, जारी करने के लिए भी अनुमति दी गई है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों की वित्तपोषण आवश्यकताएं

3.17 भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों (एमएसएमई) को महत्व देने के कारण, इस क्षेत्र की वित्तपोषण आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना जरूरी होना जारी रहेगा (चार्ट 3.3)।

3.18 परिपक्व बाज़ार में बैंकों के लिए ऋण आरंभ करने और इसके बाद इच्छुक खिलाड़ियों को बांटने में बैंकों की विशिष्ट भूमिका रही है। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि संकट पश्चात प्रतिभूतिकरण कलंक को मिटाया जाए। एमएसएमई की निहित विविधता और तुलनात्मक रूप से ऋण सूचना की रोकी हुई उपलब्धता को देखते हुए

चार्ट 3.3 : कुल बैंक अग्रिमों में लघु उद्योगों²² को ऋण का हिस्सा



स्त्रोत: भारिबैं, डीबीआईई

एमएसएमई वित्तपोषण के मामले में मध्यस्थहीनता का आवश्यक स्तर पाना कठिन होगा। एमएसएमई का एक केंद्रीकृत और साझा किया हुआ डेटाबेस, जिसमें सभी उपलब्ध डेटा शामिल हो, की वजह से एमएसएमई उधार के साथ जुड़ी हुई निहित सूचना असमामित समस्याओं को सुलझाने में सहायता होगी, जिससे प्रतिभूतिकरण में निहित एमएसएमई ऋणों की उधार पात्रता का मूल्यांकन करने में सक्षमता प्राप्त हो सके।

3.19 इस संदर्भ में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने लघु और मध्यम उद्यमियों (एसएमई) को पूंजी बाज़ार से उत्पन्न निधि उपलब्ध करा के और प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करके एक अलग विनियम/मंच के लिए ढांचा देकर प्रोत्साहित किया है। जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में (एनएसई) में 140 लघु कंपनियां सूचीबद्ध हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई)²³ में 8 कंपनियां सूचीबद्ध हैं, वहीं बहुत कम स्टॉक एक्सचेंज में सक्रिय ट्रेडिंग दिखाई देता है। इस के साथ ही, सरकार की विविध ऋण गारंटी योजनाएं एमएसएमई की वित्तपोषण आवश्यकताओं के लिए सहायक तंत्र प्रदान कर रही हैं। यद्यपि सुसज्जित और उचित रूप से निधीयन की गई ऋण गारंटी योजनाएं ऋण गुणवत्ताओं को बनाये रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं, ऐसी योजनाओं

²⁰ दी यूरोप 2020 प्रोजेक्ट बॉण्ड पहल के वही उद्देश्य हैं।

²¹ भारिबैं (2015) परिपत्र, कॉरपोरेट बाण्डों को आंशिक ऋण वृद्धि, सितंबर <https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?id=10035&Mode=0> पर उपलब्ध।

²² प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋणों के लिए वर्तमान वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्योगों से संबंधित डेटा।

²³ यू.के. सिन्हा (2015) अध्यक्ष, सेबी, रिसेंट इन्वेंशन इन दी कैपिटल मार्केट्स, दिसंबर के वार्षिक सम्मेलन, एफआईसीसीआई में भाषण। http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/attachdocs/145.405.8000599.pdf पर उपलब्ध।

बॉक्स 3.2 ऋण गारंटी योजनाओं का विनियमन

भारत सरकार ने निश्चित लक्षित लाभभोगियों को औपचारिक ऋण माध्यमों से अधिक ऋण प्रवाह की सहायता करने के लिए कई ऋण योजनाएं आरंभ की हैं - जैसे सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई) कम आय गृहनिर्माण के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि (सीआरजीएफटीएलआईएच), शैक्षिक ऋणों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफएसईएल) और निपुणता विकास के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएसएसडी)। ऐसी विविध ऋण गारंटी योजनाओं के परिचालन और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था से लाभ को समेकित करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) की स्थापना की। इसके साथ ही कुछ राज्य सरकारों ने देश में शीघ्र बढ़नेवाली ऋण गारंटी परितंत्र और ऋण गारंटी योजनाओं को कार्यान्वित करना प्रस्तावित किया।

ऐसी कई योजनाएं प्रारंभ किए जाने के साथ, एक उचित विनियामक ढांचा और पर्यवेक्षी निगरानी की आवश्यकता पड़ सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार के लिए विशाल लीवरेज और आकस्मिक राजकोषीय देयताओं के लिए निर्माण किए बिना उनके उद्देश्य प्राप्त किए गए हैं। जब कोई ऋण गारंटी योजना उचित रूप से नहीं बनाई और नहीं

कार्यान्वित की गई हो, तो उसका परिणाम ऋण गुणवत्ता में खराबी और उसके उद्देश्य पाने में असफलता में होगा।

ऋण गारंटी योजनाओं के लिए एक मजबूत विनियामक निर्माण से विस्तृत रूप से यह सुनिश्चित होगा कि i) गारंटी योजनाओं के लिए उचित रूपरेखा ii) गारंटियों का जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण iii) लीवरेज, शोधन क्षमता, न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं और अदा किए गए अनुपात पर अधिकतम सीमा के लिए उचित नियम iv) गवर्नेंस, जोखिम प्रबंध और आंतरिक नियंत्रण से संबंधित न्यूनतम आवश्यकताएं v) न्यूनतम ग्राहक सेवा मानदंड। गारंटी योजनाओं का विनियमन योजनाओं की विश्वसनीयता को और जहां योजनाएं जनता के संसाधनों से समर्थित हैं, ऐसे मामलों में संसाधनों का सक्षम उपयोग करने में योगदान देगा। उचित विनियमों के साथ गारंटी उत्पाद अपनी संरचना में अधिक बाजार उन्मुख बन सकते हैं और इस प्रकार निजी ऋण कंपनियों के लिए बाजार में प्रवेश करने के लिए जगह बनाने से और पृथक किये गये उत्पादों में अलग किए जाने से और ऋण गारंटी परितंत्र को अंतरराष्ट्रीय अत्युत्तम प्रथाओं में लाने से सामाजिक लिखत के स्वरूप में कम हो सकते हैं।

का औचित्य स्थापित करना और उन्हें विनियमित करना आवश्यक है (बॉक्स 3.2)।

3.20 एमएसएमई क्षेत्र को विलंबित भुगतानों के निर्गम को विशेष रूप से संबोधित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एमएसएमई के देयक/विनिमय बिलों को भुनाने के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु एक प्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक मंच प्रदान करने के लिए ट्रेड रिसिवेबल्स डिसकाउंटिंग सिस्टम (टीआरडीडीएस) पर विचार किया है। भारत सरकार की अन्य महत्वपूर्ण पहलें जैसे 'मेक इन इंडिया', 'स्किल इंडिया मिशन', 'स्टार्ट अप इंडिया', 'स्टैंड अप इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाएंगे, ऐसी अपेक्षा है।

वित्तीय समावेशन

3.21 इस बात पर यह बहस जारी है कि क्या वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता एवजी है या पूरक²⁴ हैं, और इस बात/तथ्य से इनकार भी नहीं किया जा सकता

है कि वित्तीय सेवाओं की शुरुआत से सामाजिक अस्थिरता और वित्तीय विकास में बाधक बना हो। अतः भारत वित्तीय समावेशन को अत्यधिक महत्त्व देता है। वित्तीय समावेशन के प्रयोजन को पूरा करने के लिए एक मध्यावधि उपायगत कार्य योजना (पाँच वर्ष) तैयार करने के लिए एक समिति²⁵ का गठन किया गया (बॉक्स 3.3)। समिति की सिफारिशों के साथ-साथ जनता से प्राप्त अभिमतों और सुझाओं का कार्यान्वयन करने के लिए समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही समय-समय पर वित्तीय समावेशन के लिए बनी नीतियों को प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन परामर्शदात्री समिति को नवीन मुद्दों (फोकस) के साथ पुनर्गठित किया गया है।

3.22 वित्तीय समावेशन योजना को बैंकों ने अपने-अपने बोर्डों से विधिवत अनुमोदन कराकर प्रस्तुत किया है और यह बैंक के कारोबार कार्यनीति का हिस्सा है। वृहत

²⁴ मोरगन और पॉटीनेस (2014) को कुछ साक्ष्य मिला कि लघु और मध्यम आकार के उद्यम को वित्तीय सहायता से उधार राशियों के शेर में वृद्धि मुख्यतः गैर निष्पादन करने वाली लोन में कमी और संभवतः वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए गए चूक।

²⁵ दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि मार्ग संबंधी समिति।

बॉक्स 3.3 : वित्तीय समावेशन संबंधी मध्यावधि मार्ग पर बनी समिति की प्रमुख सिफारिशें

- बैंकिंग आदतों और जेंडर समावेशन को बढ़ाने के साथ शिक्षा को लिंक करने की दृष्टि से लड़कियों के लिए कल्याणकारी योजना - 'सुकन्या शिक्षा' की शुरुआत।
- अंतिम मिल तक की डेलीवरी की प्रभावशीलता को बढ़ाने और उपयोगिता प्रदान करने के लिए मोबाइल प्रोद्योगिक पर आधारित कम लागत वाली व्यवस्था।
- व्याज सबवेनशन योजना को बंद करते हुए और इस राशि को बहुत कम प्रीमियम वाले यूनिवर्सल फसल बीमा में लगाना।
- बैंकों में सामान्य उत्पाद यथा मांग जमाराशियाँ, एजेंसी और प्रतिभूतियों में सहभागिता तथा कास्ट प्लस वित्तपोषण पर आधारित उत्पाद प्रदान करना और आस्थगित भुगतान, आस्थगित डेलीवरी संसमावेशन को बढ़ा देने के साथ विशेषीकृत व्याज मुक्त विंडोज खोलना।
- जानकारियों के अंतर को पूरा करने के लिए एमएसएमई हेतु व्यवसायिक क्रेडिट इटेर्मीडिएट्रिएस /सला हकार का गठन करना ताकि इसके जरिये बैंक को बेहतर क्रेडिट निर्णय लेने में सहायता मिल सके।
- अंतिम माइल तक सेवा की डेलीवरी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बीजनेस कारेसपोंडेंट (बीसी) और बीसी प्रमाणन के लिए रजिस्ट्री का सृजन करना।
- प्री पेड लिखतों और मोबाइल लेनदेनों के लिए अंतः परिचालनता।
- बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से सरकार द्वारा व्यक्तियों (जी टू पी) को हर संभव भुगतान करना जिससे वित्तीय समावेशन अभियान में सरकार द्वारा वृहत भागीदारी होगी।
- शिकायतों का एसएमएस आधारित पावती को सुनिश्चित करने के लिए प्रोद्योगिकी में ढील देते हुए शिकायत/ शिकायत निवारण प्रणाली और वित्तीय साक्षरता केंद्र नेटवर्क को मजबूत बनाना।
- जिला स्तर पर विभिन्न वित्तीय समावेशन योजना की प्रगति की निगरानी करने के लिए सूचना प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाना।

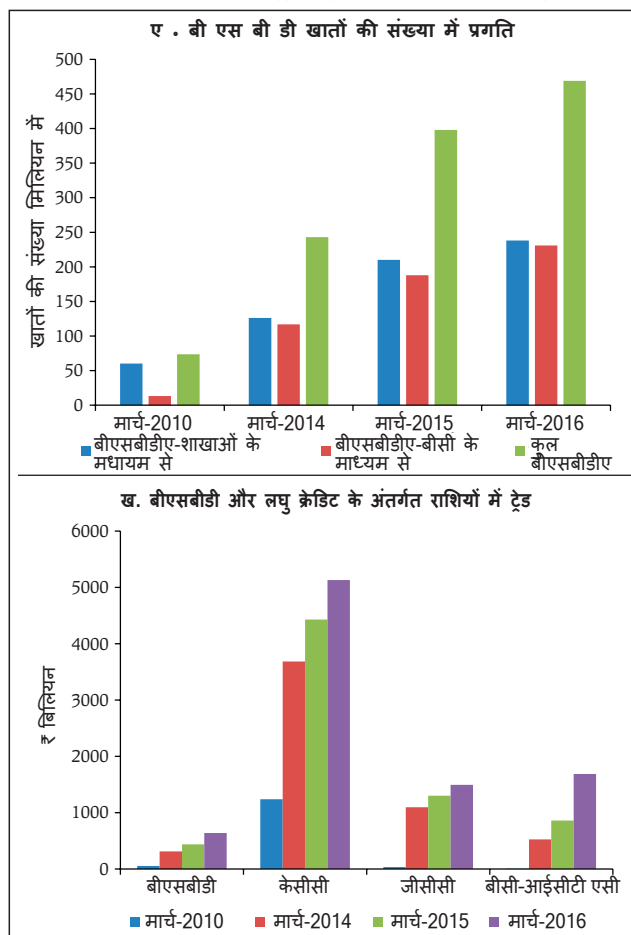
एफआईपी विभिन्न पैरामीटरों सहित आधारभूत बचत बैंक जमा खाता, लघु क्रेडिट्स और बिजनेस करसपोंडेंट इंफारमेशन और संचार प्रौद्योगिकी लेनदेनों में हुई प्रगति से संबंधित आंकड़ों को दर्ज करता है।

3.23 प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत और सरकार के पहल के कारण वर्ष के दौरान बीएसबीडीए को खोलने में काफी वृद्धि हुई और इसके साथ ही लघु क्रेडिटों और बीसी-आइसीटी लेनदेनों, किसान क्रेडिट कार्ड और जनरल क्रेडिट कार्ड (चार्ट-3.4) में भी समानांतर वृद्धि हुई है। इन खातों में बारंबारता और परिचालनों के मूल्य और शेषों को सुधारते हुए बैंक इस संबंध में उनके प्रयासों के संबंध में उनके कारोबार की वृद्धि के लिए छूट ले सकता है। इस अभियान से वित्तीय समावेशन के लिए यह अभियान समग्र आर्थिक वृद्धि को लाभ होगा जो अन्य पहल यथा सब्सिडी के सीधे लाभार्थी को अंतरित करने और अर्थव्यवस्था में नकदी के उपयोग को कम करना।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

3.24 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब बैंकिंग संस्थाएं अपने तुलन पत्र को ठीक करने में ध्यान दे रही हैं। वर्तमान में

चार्ट 3.4: बैंकों के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में प्रगति



स्रोत : आरबीआई

एनबीएफसी विविध वित्तीय जरूरतों विशेषरूप से एमएसएमई और व्यक्तियों का पूरा करते हुए इस अभियान में सहायता कर सकते हैं।

3.25 भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक के गठन के लिए अलग बैंकिंग लाइसेंस की शुरुआत के साथ युनिवर्सल बैंकों के लिए ऑन-टैप लाइसेंसिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना और बैंकिंग उद्योग के लेंडस्कैप में बड़ा बदलाव होने की आशा है जो भविष्य में होगा। इन बदलावों का प्रभाव तभी दिखना शुरू होगा जब कुछ लाइसेंस वाली संस्थाएं और पीबी और एसएफबी कार्य करना शुरू कर दें। यह प्रक्रिया वित्तीय संस्थाओं के विभिन्न श्रेणियों मुख्यतः एनबीएफसी सहित सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का आपस में मिलने के बारे बताता है। इन परिवर्तनों सहित एनबीएफसी²⁶ के लिए संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क को भी लागू किया जा रहा है जिससे विवेकपूर्ण मानदंड कड़े होंगे जो जमा स्वीकारने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी -डी) और सर्वांगी रूप से महत्वपूर्ण जमा नहीं स्वीकारने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एन डी -एस आई) पर लागू होगा और बैंको पर लागू आस्ति वर्गीकरण मानदंड को एक जैसा बनाना। इस तरह, जमा राशियाँ स्वीकारने और /या जनता की निधियों तक पहुँच रखने वाली संस्थाएं जो सर्वांगी रूप से महत्वपूर्ण भी हैं पर पर्यवेक्षी ध्यान केन्द्रित करते समय

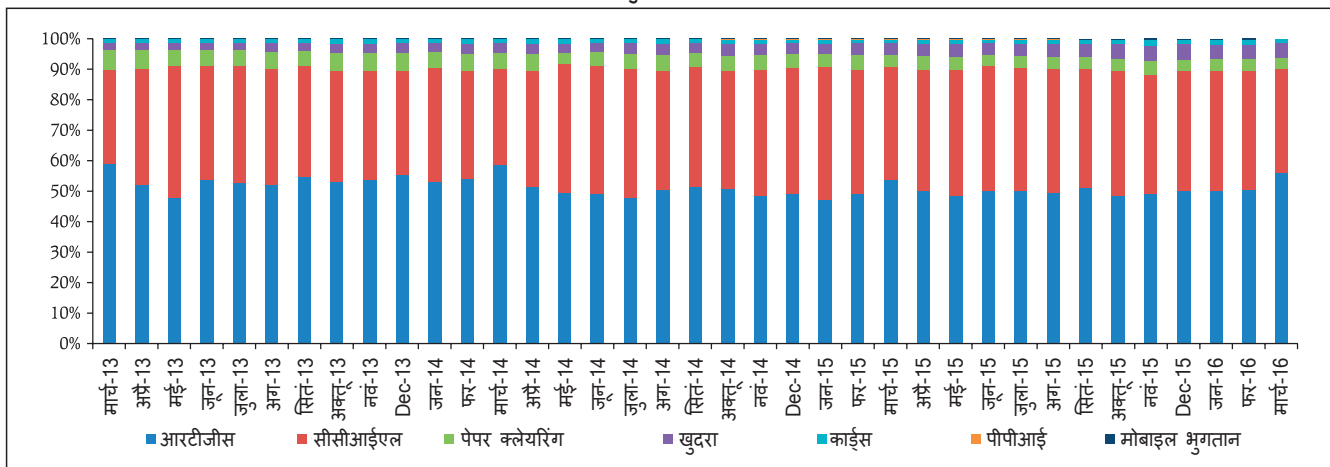
और अन्य एनबीएफसी के लिए एक वृहत परिचालनगत स्वतन्त्रता की अनुमति देने के लिए विनियमों को युक्तियुक्त और उदारीकृत किया गया है।

3.26 आधारिक संरचना वाले क्षेत्र में निधियों के प्रवाह को समयारूप सुनिश्चित करने के लगातार महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के रूप में राष्ट्रीय निवेश और आधारिक संरचना निधि (एनआईआईएफ) को गठित किया है। इसके अतिरिक्त एक अलग श्रेणी जाता है। इस एनबीएफसी आइडीएफ को यह भी अनुमति की एनबीएफसी बनाई गई है जिसे एनबीएफसी इनफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कहा दी गई की वह अपने कुल बकाया उधार राशियों के 10 प्रतिशत तक घरेलू बाजार से कम/लघु अवधि के बांड और वाणिज्य /कमर्शियल पेपर के माध्यम निधियों को जुटाएँ।

भुगतान और निपटान प्रणाली

3.27 भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विज़न का एक बड़ा पहलू यह भी है कि कम नकदी वाले क्षेत्र में बढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को सक्रिय रूप से बढ़ाना। प्रणालीगत बड़ी भुगतान प्रणाली के अंतर्गत समग्र लेनदेन मात्रा का एक बहुत बड़ा भाग रियल टाइम सकल निपटान (आरटीजीएस) और भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड है (चार्ट 3.5)।

चार्ट 3.5 : भुगतान प्रणाली संकेतक



नोट : पी पी आई का अर्थ प्रीपैड भुगतान लिखत
स्रोत : आरबीआई डीबीआई

²⁶ आरबीआई (2015) परिपत्र एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क मार्च
<https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=9623&Mode=0> पर उपलब्ध

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई)

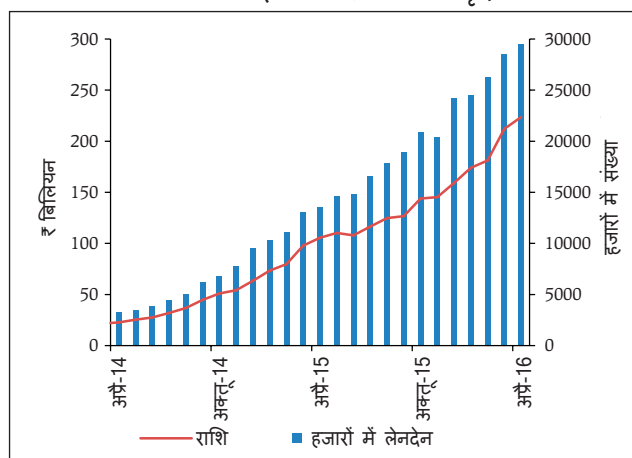
3.28 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा की गई पहल को भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2016 में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की शुरुआत की जो अगली पीढ़ी की ऑन लाइन भुगतान व्यवस्था है। स्मार्ट फोन के बढ़ते उपयोग, स्थानीय भाषा में इंटरफेस की उपलब्धता और व्यापक स्तर पर इंटरनेट तथा डाटा से इस व्यवस्था को लाभ हुआ है। इस व्यवस्था को तत्काल भुगतान सेवा (आईएम्पीएस) प्लेटफार्म पर बनाया गया जिसमें पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है (चार्ट 3.6)।

3.29 यूपीआई ऑनलाइन लेनदेन वाले विशेषताएं जैसे कि सिंगल क्लिक, लेनदेनों के टू-फेक्टर प्रमाणिकरण, मुद्रा प्राप्त करने और अंतरण के लिए भुगतान आइडेंटिफायर के रूप में वर्चुअल पता, सिंगल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए मर्चेन्ट भुगतान, विभिन्न प्रयोजनों- यूटीलिटी बिल्स के भुगतान के लिए पुल और पुश समय निर्धारण, ओवर ट काउंटर भुगतान और बारकोड आधारित भुगतान प्रदान करता है। यह सरल एक्सेसिबिलिटी, सुरक्षित वर्चुअल आइडेंटिफायर और बहु बैंक खातों के लिए सिंगल एप्लीकेशन का उपयोग के रूप में ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाता है। निष्कर्षतः यूपीआई एक डिजिटल डिस्ट्रिब्यूटिव इन्नोवेशन जो न केवल ई-कॉमर्स कारोबार के लिए गेम चेंजर है बल्कि बैंकों को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने में सहायता पहुंचाएगा इसके अलावा मोटेतौर पर मोबाइल वालेट द्वारा हावी कारोबार वाले क्षेत्र में उन्हें प्रवेश करने का अवसर भी प्रदान करता है।

भुगतान प्रणाली में साइबर रीजिलिएंस²⁷

3.30 भुगतान के विकल्पीय प्रकार की ओर प्रवर्जन के बढ़ने से भुगतान प्रणाली के रीजिलिएंस विशेषतौर पर साइबर रीजिलिएंस भुगतान प्रणाली में महत्वपूर्ण बना हुआ है। महत्वपूर्ण सेवाओं का लगातार परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं को प्राथमिक और द्वितीयक साइटों का जोखिम विश्लेषण करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि द्वितीयक साइट उन कारणों से प्रभावित न हो जिनकी वजह से सामान्यतः से प्राथमिक साइट प्रभावित होती है। साइबर रीजिलिएंस के लिए रोकथाम उपायों में जोखिम के पहचान, संगठन

चार्ट 3.6: आई एम पी एस की मात्रा में वृद्धि

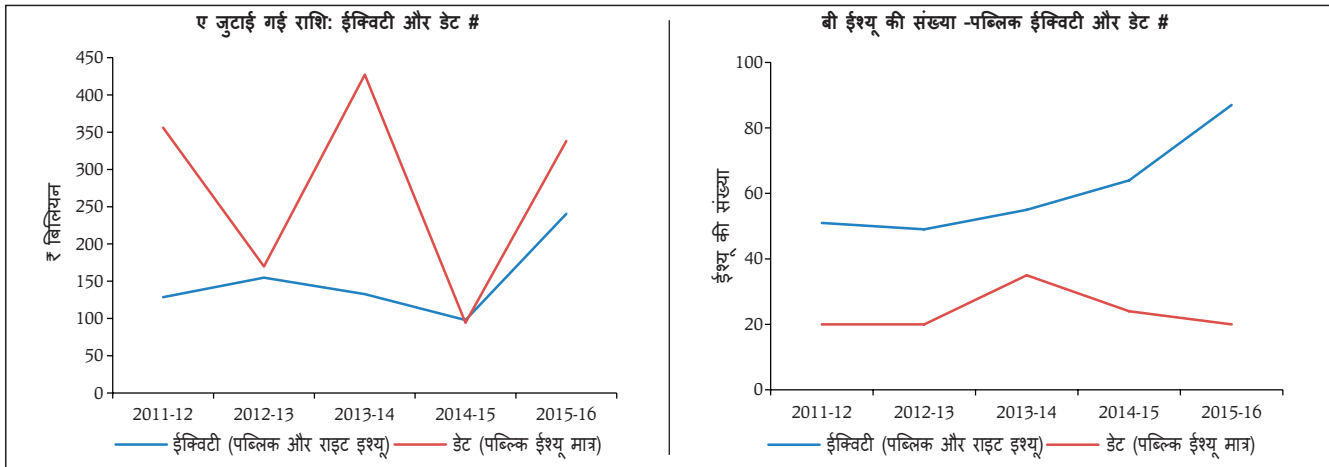


स्रोत: आरबीआई, डीबीआई।

में जागरूकता फैलाना, इमप्लीमेंटेशन लेयरड सिस्टम और सिस्टम कम्पोजेंट एंटी वायरल सोल्यूशन का उपयोग करना, सिस्टम में एक्सेस पाइंट को कम करना, सुरक्षित कोडिंग मानकों को अपनाना, सुरक्षा लेखा परीक्षा और पेनेट्रेशन जांच करवाना, अप्राधिकृत एक्सेस की रोकथाम और आधारिक संरचना नियंत्रणों में कड़ाई करना शामिल है। साइबर रीजिलिएंस एक उद्यम रूपी मुद्दा है और आंतरिक लेखा-परीक्षक साइबर जोखिम पहलों और नीतियों की दक्षता की पुष्टि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

²⁷ बीआईएस (2014), 'वित्तीय बाजार लिखत में साइबर रीजिलिएंस' भुगतान और बाजार संरचना संबंधी समिति, नवंबर

चार्ट 3.7 इक्विटी और डेट पब्लिक इश्यू में प्रवृत्ति



नोट: # इक्विटी डेट (पब्लिक इश्यू मात्र) क्यूआइपी एवं प्रीफ़ीरेंशियल कुल जुटाई गई निधियाँ
 स्रोत: सेबी

पूंजी बाजार

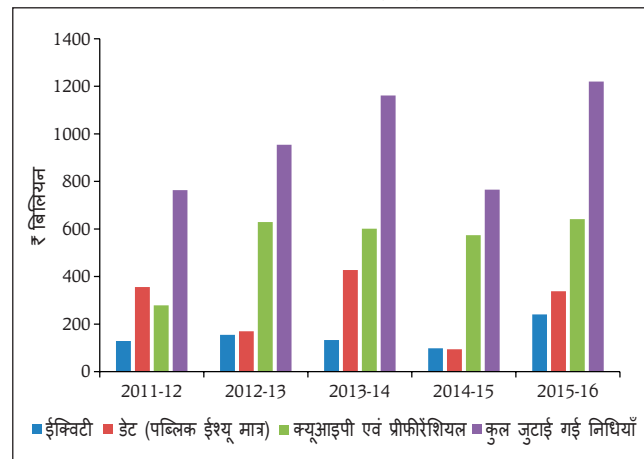
प्राथमिक बाजार

3.31 इक्विटी और डेट के पब्लिक इश्यूएंश के माध्यम से जुटाई गई राशि में 2015-16 में वृद्धि हुई (चार्ट 3.7)। अहर्ताप्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से जुटाई की गई राशि का भाग और प्रीफ़ीरेंश आबंटन उच्च बना हुआ है (चार्ट 3.8)।

3.32 भारत में कारपोरेट बांड निर्गम का बाजार पब्लिक इश्यू की तुलना में प्राइवेट प्लेसमेंट बड़ा है (चार्ट 3.9)। प्राइवेट प्लेसमेंट इश्यू को आमतौर पर कुछ चुनिंदा निवेशकों जैसे क्वालिफाइड संस्थागत खरीददार, उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (एचएनआई) या ओवर-द-टेलीफोन बाजार के व्यवस्थापकों और जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं को दिया जाता है।

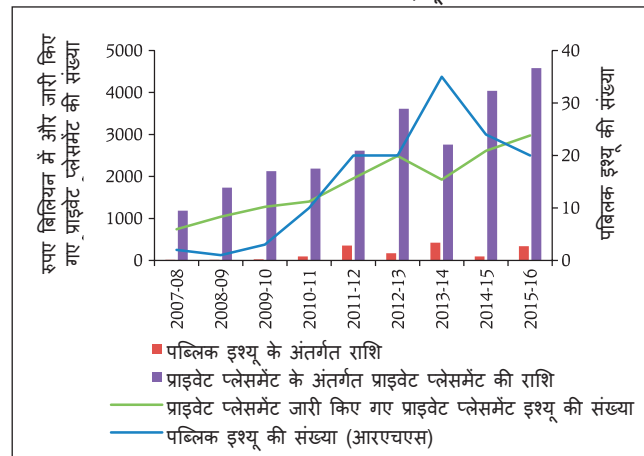
3.33 चूंकि प्राइवेट प्लेसमेंट की कार्यप्रणाली में मूल्य डिस्कवरी में पारदर्शिता की कमी हो सकती है, अतः इस हेतु सेबी ने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर डेट सेक्यूरिटीज के निर्गम के लिए इलेक्ट्रॉनिक बुक कार्यप्रणाली पर आधारित फ्रेमवर्क बनाया है। इसकी शुरुआत के लिए प्राथमिक बाजार में रुपए 5 बिलियन और उससे अधिक के आकार वाले इश्यू, ग्रीन शू ऑप्शन सहित, यदि कोई, डेट प्रतिभूतियों के सभी प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक बुक कार्य प्रणाली का होना आवश्यक है सभी स्टॉक एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए पात्र बनाया जा रहा है। ओवर-द-

चार्ट 3.8 प्राथमिक बाजार गतिविधि



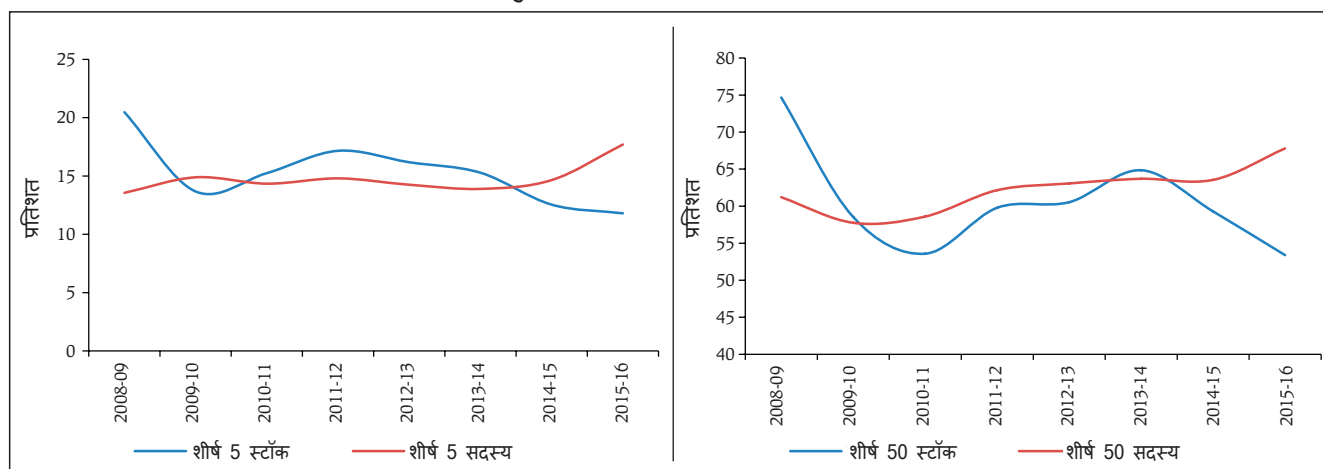
स्रोत: सेबी

चार्ट 3.9 कारपोरेट बॉन्ड इश्यू



स्रोत: सेबी

चार्ट: 3.10: कुल टर्नओवर में शीर्ष स्टॉकों और सदस्यों का शेयर



स्रोत: सेबी

टेलिफोन मार्केट की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक बुक का मुख्य लाभ यह है कि दक्षता में सुधार के साथ-साथ मूल्य डिस्कवरी में पारदर्शिता और ऐसे निर्गमों के लिए लागत और समय में कमी होना है।

द्वितीयक बाज़ार व्यापार में संकेन्द्रण

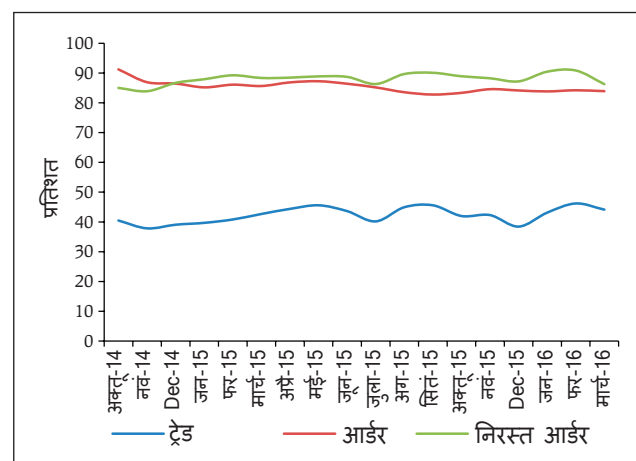
3.34 सूचीबद्ध कंपनियों की एक बड़ी संख्या होने के बावजूद इक्विटी बाज़ार में गतिविधि एक उच्च स्तर के कोन्संट्रेशन को दर्शाता है क्योंकि कुछ स्टॉक में प्रधान रूप से ट्रेड होता है और कुछ संस्थागत सहभागियों द्वारा डोमिनेट होता है। शीर्ष 5 (और शीर्ष 50) स्टॉक के जरिये टर्नओवर का अनुपात से संबन्धित कोन्संट्रेशन में गिरावट हुई है जबकि शीर्ष 5 (और शीर्ष 50) सदस्यों ने टर्नओवर के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई है। दूसरी ओर बढ़ी हुई विनियामक और हल ही में उठाए गए ठोस कदमों का परिणाम यह हुआ कि एल्गोरिथमिक ट्रेड्स में कुछ संतुलन बना हुआ है (चार्ट 3.11)।

ग्रीन बॉन्ड

3.35 ग्रीन बॉन्ड निर्धारित आय होता है, चलनिधि वित्तीय लिखतों को क्लाइमेट-मिटिगेशन परियोजना और अन्य पर्यावरणीय प्रॉजेक्शन गतिविधियों हेतु निधि जुटाने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्रीन बॉन्ड में पिछले

दशक में बड़ी तीव्र गति से वृद्धि हुई है और 2014²⁸ में उसका बकाया मूल्य 53 बिलियन अमरीकी डालर से भी अधिक रहा। विश्व बैंक संसाधनों को जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड को बढ़ावा दे रहा है ताकि पर्यावरणीय प्रॉजेक्शन गतिविधियों के लिए विकास कर रहे देशों यथा इन्डोनेशिया, चाइना, मेक्सिको और भारत के लिए निधि उपलब्ध करा सके। भारत के संदर्भ में भावी राष्ट्रीय निर्धारित योगदान दस्तावेज़²⁹ (आईएनडीसी) को जलवायु सुधार और प्रगति

चार्ट 3.11: एनएसई में एल्गोरिथमिक आर्डर और कुल ट्रेड का अनुपात



स्रोत: सेबी

²⁸ जलवायु बांड पहल (2015) वर्ष 2014 की ग्रीन बांड फाइनल रिपोर्ट [https:// www.climatebonds.net/year-2014-green-bonds-final-report](https://www.climatebonds.net/year-2014-green-bonds-final-report) पर उपलब्ध है।

²⁹ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क से संबंधित सम्मेलन में प्रस्तुत (यूएनएफसीसीसी)

<http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/India/1/INDIA%20INDC%20TO%20UNFCCC.pdf> पर उपलब्ध है।

के लिए कम कार्बन मार्ग को अपनाने के लिए भारत के योगदान के नियत लक्ष्य को सामने रखा है। यह दस्तावेज़ निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तपोषण की जरूरतों को भी बताता है, वहीं प्राथमिक अनुमान सुझाता है कि भारत के जलवायु परिवर्तन कार्रवाइयों को अभी और 2030 के बीच पूरा करने के लिए कम से कम 2.5 ट्रिलियन (2014-15 में) अमरीकी डालर की आवश्यकता होगी। इस संबंध में यह दस्तावेज़ 2015-16 के दौरान नवीकरण किए जाने वाले ऊर्जा परियोजनाओं के निधिकरण हेतु रुपए 50 बिलियन (794 मिलियन अमरीकी डालर) के कर मुक्त आधारिक संरचना वाले बॉन्ड की शुरुआत करने के बारे में बताता है। कुछ संस्थाओं सहित कुछ बैंकों द्वारा ग्रीन बॉन्ड का निर्गम भारत ने देरी से देखा।

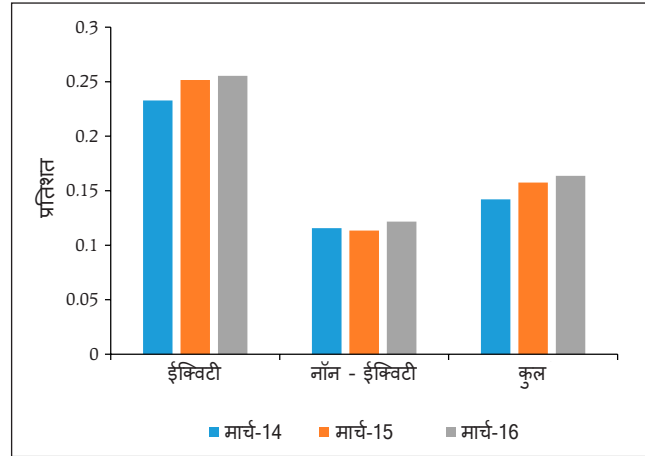
3.36 अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाज़ार एशोसियेशन द्वारा बनाए गए सिद्धांतों³⁰ पर आधारित सेबी वर्तमान में ग्रीन बॉन्ड और संबन्धित डीस्कलोजर जारी करने के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। साथ ही, रिज़र्व बैंक ने उन उद्योगों को वित्तीय सहायता देने पर प्रतिबंध लगाया है जो ओजोन को हानि पहुँचाने वाले पदार्थ का उपयोग /निर्माण करेंगे।

3.37 जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के मुद्दों के समाधान के लिए सरकार और विनियामक संवेदनशील हुई है - इस संबंध में कुछ बड़े मुद्दे यथा ग्रीन गतिविधियों की परिभाषा, ग्रीन वित्तपोषण का क्षेत्र, बौद्धिक संपत्ति अधिकार के विकास के पहलुओं और विकसित देशों से ग्रीन प्रोद्योगिकी के स्थानांतरण तथा पर्यावरणीय जोखिम मूल्यांकन की रूपरेखा को बैंक द्वारा ध्यान पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

म्यूचुअल फण्ड्स

3.38 म्यूचुअल फण्ड्स (एमएफ) ने हाल ही में शीर्ष 15 शहरों(संदर्भ बी -15) से भी अधिक शहरों में अपनी गतिविधि को बढ़ाया है और छोटे स्थानों से सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क संरचना में विनियामक परिवर्तनों और सुधरी हुई वितरण की सहायता से निवेशक आधार के विस्तारण को दर्शाता है। बी 15 शहरों से प्रबंधन के अंतर्गत परिसंपत्तियों के आकार में उद्योग के प्रतिशत दोनों इक्विटी और नॉन इक्विटी सिगमेंट में मार्च

चार्ट 3.12: बी-15 शहरों के म्यूचुअल फंड परिसंपत्तियों का शेयर



स्रोत: सेबी

2014 से मार्च 2016 तक वृद्धि हुई है (चार्ट 3.12)।

3.39 बी -15 शहरों में फोलियो की संख्या में मार्च 2014 में 14.4 मिलियन से 20.9 मिलियन अर्थात लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और सबसे बड़े 15 शहरों (टी -15 शहरों) का मार्च 2016 में फोलियो की संख्या में उसी अवधि के दौरान लगभग 6 प्रतिशत (25.2 मिलियन से 26.8 मिलियन) की वृद्धि हुई है। यह भौगोलिक विविधता को दर्शाता है और भारत में म्यूचुअल फण्ड्स उद्योग में स्थिरता लाता है और निवेशकों के जागरूकता में सुधार के लिए और बाज़ार प्रक्रिया की विश्वसनीयता तथा निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए।

निम्नश्रेणी के कारपोरेट बॉन्ड में म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर

3.40 कारपोरेट बण्ड्स में डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड योजना का एक्सपोजर सितंबर 2015 और मार्च 2016 के बीच उनके एयूएम के प्रतिशत 4 प्रतिशत तक बढ़ा। हालांकि कारपोरेट बॉन्ड में निवेश करने से उच्चतर लाभ मिलता है, जोखिम प्रीमियम बढ़ी हुई कारपोरेट स्ट्रेस के साथ बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि बढ़ी हुई मात्रा में रेटिंग निम्नश्रेणी को दर्शाता है। सेबी ने हाल ही में सेक्टरल एक्सपोजर के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं को 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक संशोधित किया और वित्तीय क्षेत्र में हाउसिंग वित्त कंपनियों के संबंध में अतिरिक्त

³⁰ आइसीएमए (2015) ग्रीन बॉन्ड सिद्धांत https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/green-Bonds/GBP_2015_27-March.pdf पर उपलब्ध

एक्सपोजर सीमाओं को 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कम किया है। साथ ही, सेबी ने ग्रुप लेबल एक्सपोजर के लिए म्यूचुअल फंड योजना के निबल आस्तियों के 20 प्रतिशत विवेकपूर्ण सीमा की शुरुआत किया। कारपोरेट बॉण्ड में डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड योजना का एक्सपोजर जो पिछले छः महीने में निम्नश्रेणी का था जिसमें सितम्बर 2015 की समाप्ति में 1.6 प्रतिशत से मार्च 2016 के अंत में 1.8 प्रतिशत की बहुत कम वृद्धि हुई (चार्ट 3.13)।

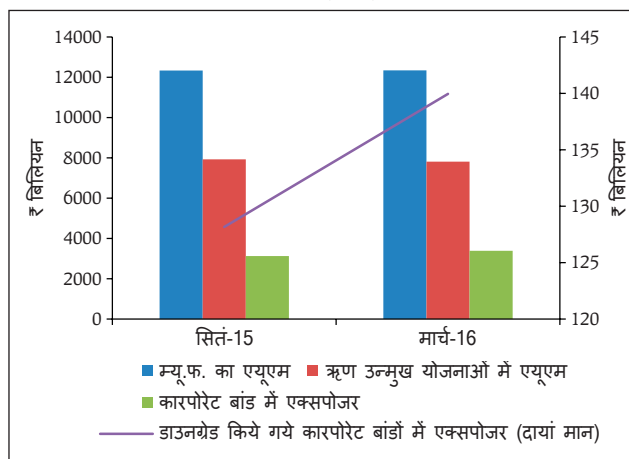
प्रमोटरों के शेयरों को गिरवी रखना

3.41 भारतीय कंपनियों के मामलों में, शेयरों में प्रमोटरों का स्वामित्व तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है, जबकि शेष शेयरों में से अधिकांश शेयरों का स्वामित्व देशी एवं विदेशी वित्तीय संस्थानों के पास था (चार्ट 3.14)। पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में प्रमोटरों के शेयरों के उच्च अनुपात में गिरवी रखे जाने के संबंध में चिंता व्यक्त की गई थी। प्रमोटरों द्वारा एनएसई तथा बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों में उनकी धारिताओं में से गिरवी रखे गये शेयरों के प्रतिशत में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है तथा मार्च 2016 में प्रमोटरों के शेयरों (बीएसई तथा एनएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों के बीच) में से उनके द्वारा गिरवी रखे गये शेयर लगभग 15 प्रतिशत था, जबकि मार्च 2013 में यह 11 प्रतिशत था।

3.42 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार, एनएसई में सूचीबद्ध कंपनियों में से लगभग एक तिहाई कंपनियों (1539 कंपनियां जिन्होंने अपना शेयरहोल्डिंग पैटर्न सूचित किया) ने अपने प्रमोटरों के शेयरों को गिरवी रखा था। एनएसई में सूचीबद्ध शीर्ष की (शीर्ष की 50, 100, 200 और 500) कंपनियों के अंतर-कालिक विश्लेषण दर्शाता है कि उनकी कुल शेयर धारिता के अनुपात के रूप में प्रमोटरों द्वारा गिरवी रखे गये शेयरों का अनुपात 2015-16 में अपरिवर्तित रहा (चार्ट 3.15)।

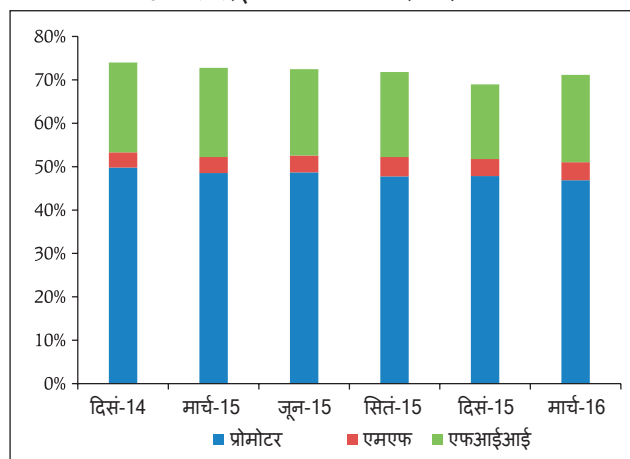
3.43 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार एनएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों में, जिनका बाजार पूंजीकरण 100 बिलियन रुपए से अधिक था, प्रमोटरों द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों का प्रतिशत 4.2 प्रतिशत था जो मार्च 2015 के अंत की स्थिति के समान है।

चार्ट 3.13 ऋण म्यूचुअल फंडों का एयूएम और कारपोरेट बांड में एक्सपोजर



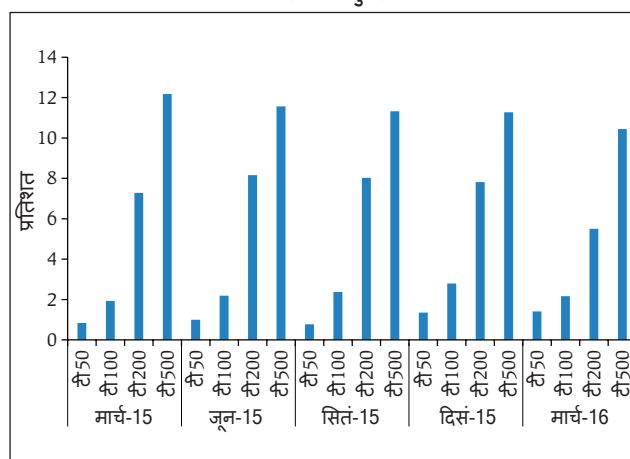
स्रोत: सेबी

चार्ट 3.14 एनएसई निफ्टी कंपनियों के स्वामित्व का पैटर्न



स्रोत: सेबी

चार्ट 3.15 एनएसई में सूचीबद्ध शीर्ष की कंपनियों के प्रमोटरों द्वारा गिरवी रखे गये शेयरों का अनुपात



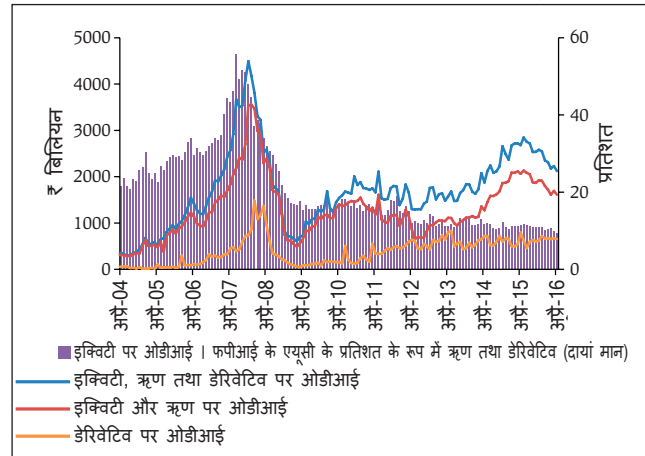
स्रोत: सेबी

सीमापार डेरिवेटिव लिखतों के माध्यम से निवेश

3.44 भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को सुकर बनाने की दिशा में सीमा-पार डेरिवेटिव लिखतों तथा सहभागिता नोट(पीएन) की भूमिका प्रमुख रही है, हालांकि 2015-16 के दौरान इनके मूल्य में कमी आई है (चार्ट 3.16)। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों(एफपीआई) द्वारा प्रत्यक्ष पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सेबी ने उनके प्रवेश संबंधी मानदंड को सुकर बनाने के उपाय किए हैं। साथ ही, सीमापार डेरिवेटिव लिखतों के लिए पात्रता एवं निवेश संबंधी मानदंडों को कठोर बनाने के उपाय किए गए ताकि इन मानदंडों को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों के अनुरूप बनाया जा सके। सीमापार डेरिवेटिव लिखतों के निर्गमों के संबंध में कड़े मानदंडों के कारण बकाया सीमापार डेरिवेटिव लिखतों का कल्पित मूल्य अभिरक्षा में स्थित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में जून 2007 के 55.7 प्रतिशत से घटकर अप्रैल 2016 में 9.3 प्रतिशत हो गया।

3.45 इन लिखतों के संबंध में एक आशंका इनके लाभकारी स्वामी की पहचान की है। परंतु, सेबी ने नियमों में कड़ाई की है जिनके अनुसार केवल सरकारी (सावरीन) फंड और विनियमित संस्थाओं को इन लिखतों में अभिदान करने की अनुमति दी गई है। सीमापार डेरिवेटिव लिखतों का अभिदानकर्ता वित्तीय कार्रवाई दल (एफएटीएफ) के सार्वजनिक वक्तव्य वाले क्षेत्राधिकार में आने वाले देश का निवासी नहीं हो सकता यथा - (क) रणनीतिगत धनशोधन निरोधक (एएमएल) अथवा आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम के संबंध में जिसमें रणनीतिक कमियां हों; और (ख) इन कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रगति न की हो या एफएटीएफ के साथ मिलकर तैयार की गई कार्य-योजना के प्रति प्रतिबद्धता न दर्शाई हो। सीमापार डेरिवेटिव लिखतों के अभिदाताओं को संरक्षित सेल कंपनियां और सेग्रिगेटेड सेल कंपनियां जैसी अपारदर्शी ढांचा बनाए रखने की अनुमति नहीं है। अनिवासी भारतीयों और निवासी भारतीयों को सीमापार डेरिवेटिव लिखतों में लेनदेन करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, काले धन के संबंध में विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई टिप्पणी के आलोक में धनशोधन संबंधी गतिविधियों के लिए इस उपाय के दुरुपयोग को रोकने के लिए अतिरिक्त विनियामक रक्षोपायों की शुरुआत की गई है। विनियामक परिवर्तनों में - सीमापार डेरिवेटिव लिखतों के

चार्ट 3.16 ऑफसोर डेरिवेटिव लिखत और एफपीआई का एयूसी



स्रोत: सेबी

जारीकर्ता एफपीआई द्वारा ग्राहक से संबंधित समुचित सावधानी उपाय के संबंध में धनशोधन निरोध संबंधी भारतीय मानदंड लागू होना, सीमापार डेरिवेटिव लिखतों के अंतरण की अनुमति हेतु सीमापार डेरिवेटिव लिखतों के जारीकर्ता एफपीआई की पूर्व अनुमति, सीमापार डेरिवेटिव लिखतों के अंतरण का संपूर्ण विवरण, नियमित आधार पर केवाईसी की समीक्षा, सीमा पार डेरिवेटिव लिखतों की स्थिति की पुनःपुष्टि प्रस्तुत किया जाना, जारी किए गए ओडीआई के संबंध में संदेहास्पद लेनदेन (एसटीआर), यदि कोई हो, की प्रस्तुति अनिवार्य रूप से वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू) और ओडीआई जारीकर्ता एफपीआई द्वारा नियमित अंतरालों पर प्रणालियों और नियंत्रणों का मूल्यांकन किया जाना शामिल है।

3.46 किए गए परिवर्तन मुख्यतः प्रक्रियागत प्रकृति के होने के कारण उनसे विनियामक ढांचे में बड़ा बदलाव नहीं होगा और इससे दीर्घावधि में एफपीआई प्रभाव प्रभावित होने की संभावना नहीं है। तथापि, समुद्रपारीय डेरिवेटिव लिखतों (विशेष रूप से पार्टिसिपेटरी नोट) की लोकप्रियता के कारणों का विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है और इन पर पर लागू प्रवेश और परिचालनात्मक मानदंडों को और सरल बनाए जाने के साथ-साथ ऐसे उत्पादों से प्राप्त लाभों को बनाए रखने के लिए समुचित विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए।

कृषि पण्य बाजार³¹

3.47 कम उत्पादन, सिंचाई की कम उपलब्धता तथा मानसून पर अत्यधिक निर्भरता के अतिरिक्त, भारतीय

³¹ भौतिक तथा डेरिवेटिव दोनों बाजार

कृषि क्षेत्र की कई अन्य चुनौतियां हैं जिनमें पर्याप्त भंडारण और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का अभाव, भौतिक बाजारों का विखंडन, उत्पादों के भारी मात्रा में नष्ट होना और कृषिगत वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक बार-बार उतार-चढ़ाव होना शामिल हैं। जहां देश के एक भाग में किसी वस्तु की कमी रहती है वहीं दूसरे भाग में उसकी आपूर्ति जरूरत से अधिक होने जैसी स्थिति देखी जाती है, ऐसे में कृषिगत वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

3.48 प्रतिबंधित विपणन व्यवस्थाएं (राज्य सरकार के कानूनों के अंतर्गत), सीमित क्षमता, लॉजिस्टिक्स और परिवहन की लागत एवं वस्तुओं के अंतर-राज्य आवागमन (अधिकांश मामलों में अंतर-जिला चुंगी भी) अकुशलताओं का सृजन करते हैं और कृषिगत वस्तुओं के अच्छी तरह से कार्यक्षम भौतिक बाजारों के निर्माण के प्रयासों में बाधक बनते हैं। इसके अतिरिक्त, जहां भारतीय पण्य बाजार के वैश्विक बाजार से जुड़ने की गति में वृद्धि हो रही है वहीं देश के अंदर इस प्रकार के विखंडित बाजार का होना एक विरोधाभासी स्थिति है।

पण्य डेरिवेटिव बाजार

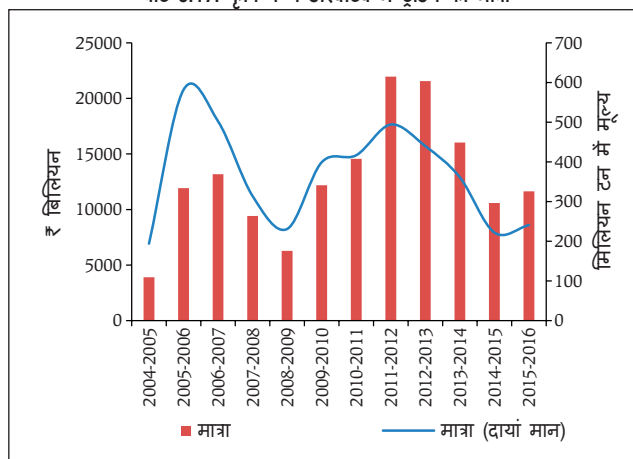
3.49 वर्ष 2003 में राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक पण्य डेरिवेटिव एक्सचेंजों की शुरुआत किया जाना भारत में पण्य जोखिम प्रबंधन व्यवस्था को संस्थागत रूप दिए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। इसने भंडारण क्षमता और गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचे को आधुनिक बनाने और उसमें सुधार करने में भी मदद की है। सरकार द्वारा फॉरवर्ड मार्केट कमीशन (एफएमसी) के विनियमन संबंधी कार्यों को सेबी को सौंपने के बाद एक्सचेंजों की कार्यसीमा तथा स्केल, वित्तीय फर्म तथा अन्य हितधारक संबंधी लाभ में सुधार के चलते इस क्षेत्र का विनियमन सुदृढ़ हुआ है। सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव बाजारों के कार्यकलापों को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय किए जिनमें - राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय डेरिवेटिव एक्सचेंजों के लिए व्यापक जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश जारी किया जाना, ट्रेडिंग, क्लियरिंग और निपटान के ढांचे को प्रतिभूति कानूनों के ढांचे में लाना, वर्तमान बाजार सहभागियों को एक समान विनियामक ढांचे के अनुरूप लाना, बाजारों की बेहतर निगरानी के लिए एक्सचेंज और सेबी में निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करना और हितधारकों

में विश्वास की बहाली करना शामिल है। सट्टेबाजी की दृष्टि से भाग लिये जाने के कारण कृषिगत वस्तुओं की कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए सेबी ने दैनिक मूल्य सीमा और पोजीशन सीमा के संबंध में मानदंड समय-समय पर जारी किए हैं।

3.50 अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 के दौरान जहां बेंचमार्क सूचकांक एमसीडीईएक्स धान्य ने 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की वहीं एमसीएक्स सीओएमडीओएक्स में 2.2 प्रतिशत की गिरावट आई। अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 के दौरान पण्य वस्तुओं के सूचकांक के उतार-चढ़ाव में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई। जहां कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजों में कुल मात्रा तथा कंट्रेक्टों की संख्या में क्रमशः 17.9 प्रतिशत तथा 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं अप्रैल-सितंबर 2015 की तुलना में अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 के दौरान पण्यार्पट (टर्नओवर) में 5.9 प्रतिशत की गिरावट आई। एक्सचेंजों में अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 के दौरान ट्रेड किए गए विभिन्न पण्य समूहों में मूल्य की दृष्टि से देखें तो बुलियन का 32.8 प्रतिशत का सबसे अधिक हिस्सा था, जिसके बाद ऊर्जा (29.9 प्रतिशत), धातु (22.3 प्रतिशत) तथा कृषिगत वस्तुओं (15.3 प्रतिशत) का क्रम था।

3.51 कृषिगत पण्यों के पण्य डेरिवेटिव बाजार में मात्रा की दृष्टि से सुधार दिखाई दिया, हालांकि पिछले 3 वर्षों के दौरान उसमें गिरावट दर्ज हुई थी (चार्ट 3.17)। परंतु अब तक ऐसे प्लेटफॉर्म से किसानों को उल्लेखनीय लाभ मिलता प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त, कमोडिटी

चार्ट 3.17: कृषि पण्य डेरिवेटिव में ट्रेडिंग की मात्रा



स्रोत: सेबी (सभी एक्सचेंजों का समेकित डेटा)

डेरिवेटिव मार्केट में वर्तमान में कुछ कमियां हैं। ये कमियां डेरिवेटिव के प्रकार (मुख्यतः फ्यूचर कंट्रेक्ट तक सीमित), ट्रेडिंग की मात्रा के स्तर तथा चलनिधि, जो थोड़े, वह भी अधिकांशतः निकट महीने के कंट्रेक्ट तक ही सीमित होने के रूप में हैं।

3.52 भविष्य की कीमतों की प्रवृत्ति के सूचक के रूप में पण्य फ्यूचर बाजार आवश्यकतानुसार एहतियाती कार्रवाई करने में मदद करता है। जहां मूलभूत कारक पण्य बाजारों के प्रमुख निर्धारक होते हैं, वहीं वैश्विक वृद्धि में बदलाव, वस्तु विशिष्ट कारक और जलवायु प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तथापि, आप्सन कांट्रेक्ट के अभाव में किसानों के लिए व्यक्तिगत और एग्रीगेटर (और अन्य जोखिम बचावकर्ताओं) के स्तर पर मूल्य जोखिम के प्रबंधन की संभावनाएं भी सीमित हैं, क्योंकि लंबी परिपक्वता वाले फ्यूचर कांट्रेक्टों में तरलता की अपर्याप्तता के कारण किसान फसल संबंधी अपने निर्णय अग्रिम रूप में नहीं ले पाते हैं। मूल्य की खोज संबंधी लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब विभिन्न स्टोक और जोखिम प्रोफाइल वाले उपयोगकर्ता यथा - ग्राहक, उत्पादक, अर्बिट्रेशन करने वाले, व्यापारी और जानकारी के साथ जोखिम उठाने वाले (सट्टेबाज) प्रवेश अथवा एग्रीगेटर स्तर पर डेरिवेटिव प्लेटफार्म का उपयोग करते हैं।

3.53 वर्ष 2016 17 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार पण्य डेरिवेटिव के क्षेत्र में कुछ नए उत्पादों की शुरुआत किया जाना प्रस्तावित है। सेबी का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में इस बाजार में नए उत्पादों और सहभागियों की नई श्रेणियों को शामिल करके इस बाजार का विकास किया जाए जिससे चलनिधि की स्थिति में सुधार हो सके, ताकि सहभागियों के हित में उचित मूल्य की खोज की प्रक्रिया सुविधाजनक हो सके। कृषिगत वस्तुओं के लिए समेकित और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार तैयार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास हाल में राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम), जो अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल नेटवर्किंग है, की स्थापना के प्रयास और विद्यमान कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) बाजार से - इससे जुड़े बाजार को व्यवस्थित करने और एक समान स्पॉट मूल्य निर्धारित करने में

मदद मिलेगी। दृढ़ और सतत प्रयासों से सेबी यह सुनिश्चित करेगा कि आने वाले वर्षों में पण्य डेरिवेटिव बाजार सभी दृष्टि से, अर्थात् प्रौद्योगिकी, नए उत्पाद तथा सहभागियों, जोखिम प्रबंधन, विनियमन, पर्यवेक्षण, निगरानी तथा निवेशक की रक्षा और विधियों के प्रवर्तन की दृष्टि से प्रतिभूति बाजार के समान होगा।

3.54 सेबी द्वारा भंडारण सेवा प्रदाताओं (डब्ल्यूएसपी), भंडारण, आकलनकर्ताओं और उनके द्वारा प्रयुक्त सेवा प्रदाताओं से संबंधित मानदंडों को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए प्रस्तावित कदमों से सुपुर्दगी और निपटान व्यवस्थाएं अधिक कार्यक्षम होने और भंडार गृहों (वेयरहाउस) और पण्य डेरिवेटिव एक्सचेंजों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है। इसका उद्देश्य भंडार गृहों द्वारा भंडारण और वितरण की प्रक्रियाओं के संबंध में अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना है कि भंडार गृहों में उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा संबंधी जानकारी बाजार के सहभागियों और विनियामकों को समय पर उपलब्ध हो सके।

3.55 वित्तीय संस्थाओं और बाजारों के बीच बढ़ते समन्वय के रोडमैप के अंदर वित्तीय संस्थाएं पण्य डेरिवेटिव बाजार की गहराई को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यद्यपि बैंकों को विद्यमान विनियमों के अंतर्गत पण्यों की खरीद करने, उसका भंडारण करने अथवा उसका व्यापार करने की मनाही है, तथापि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत या उसके अतिरिक्त के रूप में दिए गए प्रत्यक्ष और परोक्ष कृषि ऋण के रूप में उनका कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों (पण्य संबंधी) में काफी एक्सपोजर है। जहां भौतिक बाजारों से जुड़ी कमियां और व्यवस्थाएं दक्षता में कमी (कुछ प्रभावशाली सदस्यों के बीच व्यापार) के साथ जुड़कर कई बार कुछ पण्यों के मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव की स्थिति पैदा करती है, परंतु प्रवर्तन संबंधी प्रभावी उपाय ऐसी स्थिति की रोकथाम के लिए कारगर साबित होने के साथ-साथ सट्टेबाजी और मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव को रोकने में भी कारगर हो सकते हैं।

³² सेबी (2016) राष्ट्रीय पण्य डेरिवेटिव एक्सचेंजों में ट्रेड किये गये कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि पण्यों के लिए भण्डारण मानदंडों पर परामर्शी पेपर, जून। यह पेपर http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/attachdocs/146.486.0526503.pdf में उपलब्ध है।

बीमा क्षेत्र

बैंक द्वारा बीमा उत्पादों का वितरण

3.56 बैंकों के माध्यम से बीमा संबंधी उत्पादों की बिक्री किया जाना विश्व भर में आम बात है। यह आय का काफी उपयोगी स्रोत है और ब्याज से इधर स्रोत से प्राप्त आय (शुल्क आधारित आय) के रूप में यह लाभप्रदता को बढ़ाता है। इसे कोर बैंकिंग कारोबार के एक ऐसे पूरक के रूप में देखा जा सकता है जहां ग्राहकों के साथ बैंक के संबंधों का लाभ उठाकर एक ही छत के नीचे विभिन्न बैंकिंग सेवाएं ग्राहक को मुहैया कराई जाती हैं। परंतु, यहां गलत तरीके से बिक्री (मिस-सेलिंग) की संभावना को रोकने की जरूरत है, विशेष रूप से तब जब बैंक-स्टाफ को मिलने वाले निष्पादन आधारित आकर्षक प्रोत्साहन के कारण गलत तरीके से बिक्री की कथित घटनाएं रिपोर्ट की जा रही हों।

रीइंश्योरेंस प्रोग्रामों में जोखिमों के संकेंद्रण से जुड़े मुद्दे

3.57 रीइंश्योरेंस प्राथमिक इंश्योरेंस कंपनियों के लिए जोखिम और पूंजी के प्रबंधन के उपायों में से एक है जिसके जरिए बीमाकर्ता (सीडेंट) उस उच्च जोखिम के लिए बीमा खरीदता है जिसे वह स्वयं पूर्णतः वहन नहीं कर सकता। यह बीमा एक या एकाधिक बीमा कंपनियों (रीइंश्योरर) से खरीदा जाता है। यद्यपि सुदृढ़ पुनर्बीमा कार्यक्रम प्राथमिक बीमा कंपनियों के तुलन पत्र को अप्रत्याशित प्रतिकूल हानियों से बचाकर जोखिम के आकलन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है, तथापि कुछ पुनर्बीमा कंपनियों के पास आकस्मिक देयताओं के बढ़ते संकेंद्रण को देखते हुए पुनर्बीमा कंपनियों की सुदृढ़ता के आकलन की आवश्यकता है। जोखिम की प्रमुख घटनाओं के घटित होने के अप्रत्याशित परंतु संभावित स्थिति के कारण पुनर्बीमा कंपनियां भारी दबाव में आ सकती हैं जिसका असर प्राथमिक बीमा कंपनियों पर भी पड़ सकता है, यहां तक कि कंपनी के दिवालिया हो जाने का संभावित जोखिम भी है।

हरित बीमा (ग्रीन इंश्योरेंस)

3.58 हरित बीमा पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी जोखिमों को कम करने और उसके प्रबंधन में मदद करता है। ऐसी बीमा पॉलिसियां जल, थल और वायु के प्रदूषण से उत्पन्न संभावित देयताओं अथवा पॉलिसीधारक के कारण पारिस्थितिकी और पर्यावरण को होने वाली अनुषंगी हानियों को कवर करती हैं। ये पॉलिसियां न केवल पारिस्थितिकी और पर्यावरण को होने वाली हानियों की

भरपाई करती है बल्कि पारिस्थितिकी को हुई क्षति को ठीक करने में भी मदद करती है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के अंतर्गत तीसरी पार्टी को होने वाली बड़ी राशि की (25000 रुपये से अधिक की) हानियां वर्तमान के बीमा उत्पादों द्वारा कवर नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त, हरित संवर्धन गतिविधियों से जुड़ी सभी कंपनियों अथवा विधिक निकायों को हरित बीमा पालिसियां लेनी पड़ सकती है। अतः, हरित बीमा का प्रस्ताव कंपनियों द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र से जुड़ी लागत को व्यवस्थित करने में मदद करने हेतु भी दिया जा सकता है।

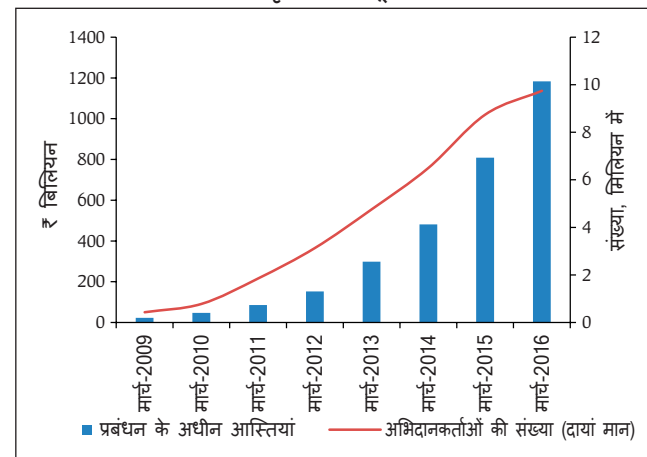
पेंशन क्षेत्र

3.59 नई पेंशन योजना के आकार में अभिदानकर्ताओं की संख्या और प्रबंधन के अधीन स्थित आस्तियां (चार्ट 3.18) की दृष्टि से निरंतर वृद्धि हो रही है।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की दिशा में प्रगति

3.60 बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र के विनियामकों की तरह विभिन्न देशों में पेंशन पर्यवेक्षी प्राधिकारी जोखिम आधारित पर्यवेक्षण दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं। जोखिम आधारित पर्यवेक्षण को पेंशन फंड द्वारा सामना किए जाने वाले अति महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान करने की व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में किया जा सकता है और इनका समाधान पर्यवेक्षक द्वारा पेंशन फंड द्वारा इन जोखिमों के प्रबंधन की स्थिति और उनकी वित्तीय संकट की प्रवणता का आकलन करके किया जाता है। इस जोखिम आधारित पेंशन पर्यवेक्षण के एक प्रमुख भाग की विशेषता पर्यवेक्षण प्राधिकारी द्वारा भविष्य निधि

चार्ट 3.18 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदान की प्रवृत्ति और एयएम



स्रोत: पीएफआरडीए

परिचालन संबंधी अपेक्षाओं के विस्तृत अनुपालन की जांच के बजाय निर्णय लेने की प्रक्रिया और इन निधियों की सक्षमता की समीक्षा करने की और आगे बढ़ने की है।

3.61 राष्ट्रीय पेंशन योजना जैसी निर्दिष्ट अंशदान वाली योजनाओं के मामले में बाजार तथा ऋण जोखिम पूरी तरह निवेशक द्वारा वाहन किया जाता है। इसलिए, किसी प्रकार की विनियामक पूजा के निर्धारण के लिए कोई शर्त नहीं है, केवल पेंशन फंड के लिए 250 मिलियन रुपए की न्यूनतम गोचर निवल मालियत की शर्त है जिसकी समीक्षा समय समय पर की जाएगी। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकारी (पीएफआरडीए) ने पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के अंतर्गत विभिन्न अधिनियमों, नीतियों और दिशा-निर्देशों के जरिए पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए प्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। पेंशन निधियों को घोषणा करने जैसे अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ-साथ लेखा परीक्षकों और रेटिंग एजेंसियां जैसी बाहरी एजेंसी से समीक्षा भी करवानी होती है। वर्तमान में सभी पेंशन फंडों के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली मुख्यतः नियम आधारित है और बाजार के सभी पेंशन फंडों के लिए पर्यवेक्षी ध्यान एक समान है। परंतु, ज्योंही यह प्रणाली परिपक्व होगी और राष्ट्रीय पेंशन योजना और पेंशन योजनाएं पीएफआरडीए के विनियामक दायरे में आ जाएंगी, पर्यवेक्षी संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की ओर अग्रसर होना प्रासंगिक होगा। पीएफआरडीए पहले से पेंशन क्षेत्र में जोखिम मैपिंग और देश में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण फ्रेमवर्क का विकास करने के लिए विश्व बैंक के संपर्क में है। जोखिम आधारित पर्यवेक्षण से विवेकपूर्ण निवेशक वाली व्यवस्था की ओर अग्रसर होने और नियत अंशदान (डीसी) वाली योजनाओं के सदस्यों को आस्तियों के मूल्यों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली अधिकतम हानि को सीमित करने में मदद पहुंचने की आशा है।

पेंशन संबंधी जागरूकता और स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों का एक कैडर विकसित करना

3.62 पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 का लक्ष्य पेंशन क्षेत्र की व्यवस्थित वृद्धि करना और वृद्धावस्था में आय की सुरक्षा की व्यवस्था करना है जिसका तात्पर्य है कि शैक्षिक, क्षेत्रीय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं से ऊपर उठकर सभी को पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगी। सुव्यवस्थित वृद्धि तभी होगी जब समावेशी वृद्धि हो। भारत में संगठित क्षेत्र में सेवानिवृत्ति संबंधी आयोजना

अब तक आयकर बचाने और गारंटीशुदा आए उपलब्ध कराने के लक्ष्य से प्रेरित होती रही है। स्वैच्छिक पेंशन योजनाओं के विस्तार को बढ़ाने की दिशा में आने वाली चुनौतियों में वित्तीय बचतों के बारे में सीमित शिक्षा (जानकारी) और सेवानिवृत्ति आयोजना संबंधी दृष्टिकोण की कमी रही है। पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु योजनाओं के बारे में लोगों तक प्रचार करने की दिशा में परामर्शी सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। संभावित ग्राहक की जरूरत एवं वित्तीय स्थिति और पेंशन उत्पादों की पर्याप्त जानकारी रखने वाले सेवानिवृत्ति परामर्शदाता उन लोगों को परामर्श देने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे जो शिक्षा, वित्तीय शिक्षण, संपत्ति, आय की संभावना, बचत करने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्य की दृष्टि से भिन्न हैं। पीएफआरडीए सेवानिवृत्ति परामर्शदाताओं के लिए विनियम तैयार करने की प्रक्रिया में है जिसमें उनकी पात्रता मानदंड, उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व, उनका पंजीकरण, प्रमाणन, अनुपालन और दंड शामिल है।

पेंशन निधियों के लिए निवेश संबंधी दिशा-निर्देश

3.63 पीएफआरडीए के भविष्य निधि में निवेश संबंधी दिशा-निर्देशों का लक्ष्य उन मानदंडों को स्थापित करना है ताकि अपनी जोखिम अभिरुचि के अनुसार अभिदान कर्ताओं का प्रतिफल अधिकतम हो सके। साथ ही, वित्तीय क्षेत्र तथा अर्थव्यवस्था में होने वाली गतिविधियों के अनुरूप उन मानदंडों की समीक्षा की जाती है। इस दिशा में पीएफआरडीए ने निजी क्षेत्र में निवेश संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

3.64 सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जारी संशोधित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य भविष्य निधि के प्रबंधकों को अधिक गुंजाइश प्रदान करना है जिसके लिए नियत आए वाले लिखतों में निवेशों को 95 प्रतिशत तक सीमित करने के साथ-साथ इक्विटी में 15 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति दी गई है। यह दिशा-निर्देश रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटीएस) और इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्टों (आईएनवीआईटीएस) में निवेश की अनुमति देने के साथ-साथ पेंशन निधियों के अंतर्गत दीर्घकालीन निवेशकों को अधिक प्रतिफल प्रदान करने में मदद पहुंचाने के उद्देश्य के एक भाग के रूप में तैयार किए गए हैं और ये अंतर्निहित लिखतों के चुनाव का बेहतर विकल्प (इक्विटी, कारपोरेट बांड तथा सरकारी बांड) प्रदान करते हैं।

3.65 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भविष्य निधि जैसे संस्थागत निवेशक संभावित आय के श्रोत के रूप में वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) में निवेश के लिए विचार करते हैं क्योंकि यह विविधीकरण के उपाय के रूप में (पोर्टफोलियो के अन्य पारंपरिक आस्तियों के साथ निम्न अथवा ऋणात्मक सह-संबंध के साथ) सहायक होने के साथ-साथ ये कम उतार-चढ़ाव के साथ जोखिम आधारित उच्चतर प्रतिलाभ देते हैं। हाल ही में, वाजपेई समिति की सिफारिशों के आधार पर पीएफआरडीए ने सेबी के पास पंजीकृत श्रेणी I तथा II के एआईएफ में निवेश की अनुमति प्रदान की है। एनपीएस योजनाओं के अंतर्गत सेबी द्वारा विनियमित श्रेणी I तथा II एआईएफ में निधियों के निवेश इस शर्त पर है कि इनमें निवेश संबंधी कुल निधि का अधिकतम 2 प्रतिशत तक निवेश किया जा सकेगा जो वैकल्पिक आस्ति श्रेणियों के 5% की अधिकतम सीमा के भीतर होगी।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद

3.66 दिसंबर 2015 में पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद और उसकी उप समिति की एक-एक बैठक आयोजित हुई।

परिषद की बैठक वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के साथ बजट पूर्व (2016-17) विचार-विमर्श के लिए बुलाई गई थी जिसमें वित्तीय क्षेत्र में विकास के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता के दोहरे लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। उक्त समिति की बैठक में केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री; कारपोरेट बांड बाजार का विकास; पियर टू पियर लेंडिंग; स्टीवर्डशीप कोड³³ प्राप्त करने की आवश्यकता, स्वर्ण पर कार्यकारी दल का गठन, फिनटेक पर एक अंतर विनियामक समूह का गठन; ऋण गारंटी योजनाओं का विनियमन; बहु राज्य सहकारी समितियों द्वारा जमाराशि लेने संबंधी चिंता और घरेलू वित्त पर एक समिति का गठन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। सितंबर 2015 में उप समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कारपोरेट बांड पर एक कार्य दल का गठन किया गया ताकि कारपोरेट बांड बाजार के विकास के लिए समयबद्ध विशिष्ट उपायों को कार्यान्वित किया जा सके। इस कार्यदल में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा वित्तीय क्षेत्र के विनियामक (रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए) का प्रतिनिधित्व था। उप समिति ने इसमें सहायता करने वाले तकनीकी दलों के कार्यों की भी समीक्षा की।

³³ स्टीवर्डशीप कोड सिद्धांतों या दिशानिर्देशों का एक सेट है जो उन संस्थागत निवेशकों के लिए हैं जो कंपनियों में वोटिंग का अधिकार रखते हैं। जैसे, यूके में फाइनेंसियल रिपोर्टिंग काउंसिल द्वारा ऐसा कोड 2010 में जारी किया गया था।

अनुलग्नक 1

प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण

वित्तीय प्रणाली के समक्ष प्रमुख जोखिमों के संबंध में बाजार के प्रतिभागियों सहित विशेषज्ञों की राय जानने के लिए अप्रैल-मई 2016¹ में प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (एसआरएस) किया गया, जो इस श्रृंखला का दसवां सर्वेक्षण है— परिणाम यह सूचित करते हैं कि वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने वाला प्रमुख जोखिम अभी भी वैश्विक जोखिम है— वर्तमान सर्वेक्षण में समष्टि आर्थिक स्थिति संबंधी जोखिम के तुलनात्मक दृष्टि से बढ़ने की धारणा बनी है किंतु वह मध्यम जोखिम श्रेणी में बना रहा। बाजार जोखिम कुछ कम होने की संभावना व्यक्त की गई है जबकि संस्थागत जोखिमों को उच्च जोखिम श्रेणी में रखा गया है (चित्र 1)।

वैश्विक जोखिम के अंतर्गत वैश्विक मंदी से संबंधित जोखिम, कुछ कम हो जाने के बावजूद, उच्च जोखिम श्रेणी में बना रहा जबकि मध्यम जोखिम श्रेणी में वैश्विक मुद्रास्फीति जोखिम में गिरावट देखी गई। समष्टिआर्थिक जोखिम श्रेणी के अंतर्गत घरेलू मुद्रास्फीति का जोखिम मध्यम जोखिम श्रेणी में पहुंच गया जबकि पूंजी प्रवाह संबंधी जोखिम में कमी दिखाई दी। कारपोरेट क्षेत्र का जोखिम उच्च जोखिम श्रेणी में उच्च स्तर पर ही बना रहा। घरेलू आर्थिक संभावना में कमी आने का जोखिम घटकर मध्यम जोखिम की श्रेणी में आ गया है— इसमें, राजनीतिक स्थिरता कायम होने के कारण सरकारी रेटिंग के क्षेत्र में सुस्पष्ट सुधार देखा गया— आश्चर्यजनक रूप से, चालू खाता घाटा (सीएडी) तथा राजकाषीय घाटा के कारण जोखिम की संभावनाएं अपरिवर्तित रहीं जबकि घरेलू मुद्रास्फीति एवं पारिवारिक इकाइयों की बचत के कारण जोखिम की संभावनाओं में कमी आई— समग्ररूप से परिस्थितियों में सुधार होने के बावजूद आधारभूत संरचना के विकास की गति के धीमे होने, पूंजी प्रवाहों, स्थावर संपदाओं की कीमत तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जोखिम बढ़कर उच्च जोखिम की श्रेणी में पहुंच गए हैं— उत्तरदाताओं को यह लगता है कि ईक्विटी कीमतों की अनिश्चितता और निधियन जोखिम में वृद्धि हुई है तथा विदेशी मुद्रा जोखिम में कमी आई है। संस्थागत जोखिमों में से बैंकों की आस्ति गुणवत्ता को अभी भी उच्च श्रेणी जोखिम घटक के रूप में देखा गया और पूंजी आवश्यकता संबंधी जोखिम को बढ़ा हुआ पाया गया (चित्र 2)।

चित्र 1 : प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण में चिह्नित किए गए प्रमुख जोखिम समूह (अप्रैल 2016)

प्रमुख जोखिम समूह	मार्च-16	परिवर्तन	अक्तू -15	परिवर्तन	अप्रैल-15	परिवर्तन	अक्तू -14	परिवर्तन	अप्रैल-14
अ. वैश्विक जोखिम		↓		↑		↔		↑	
आ. समष्टिआर्थिक जोखिम		↑		↓		↓		↔	
इ. बाजार जोखिम		↓		↑		↓		↑	
ई. संस्थागत जोखिम		↑		↔		↑		↓	
उ. सामान्य जोखिम		↔		↓		↑		↓	

टिप्पणी :
जोखिम श्रेणी

बहुत अधिक	अधिक	मध्यम	कम	बहुत कम
-----------	------	-------	----	---------

पिछले सर्वेक्षण के बाद से जोखिम में परिवर्तन		
↑	↔	↓
बढ़ा	अपरिवर्तित रहा	घटा

समय-समय पर किए गए (अप्रैल और अक्तूबर अर्ध वार्षिक आधार पर) प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण यह ज्ञात होता है कि जोखिम संभावनाएं एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरित(कमी/वृद्धि) हो सकती हैं जिसे रंग में परिवर्तन द्वारा दर्शाया गया है— किंतु समान जोखिम श्रेणी (अर्थात्, समान रंग में दर्शाए गए बॉक्स) में भी जोखिम संभावना बढ़/घट सकती है या अपरिवर्तित रह सकती है, जिनको तीर के निशान के माध्यम से दर्शाया गया है— जोखिम संभावनाओं में दर्शाया गया परिवर्तन लगातार दो सर्वेक्षणों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण से संबंधित है।

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण - (अप्रैल 2014 से अप्रैल 2016 (अर्द्ध वार्षिक))।

¹ ये सर्वेक्षण अर्द्ध-वार्षिक आधार पर किए जाते हैं— पहला सर्वेक्षण अक्तूबर 2011 में किया गया था

चित्र 2 : प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण में चिह्नित किए गए विभिन्न जोखिम(अप्रैल 2016)

जोखिम समूह	जोखिम की मद	अप्रैल-16	परिवर्तन	अक्तू-15
अ. वैश्विक जोखिम	वैश्विक मंदी		↓	
	वैश्विक मुद्रास्फीति/पण्य मूल्य जोखिम (कच्चे तेल की कीमतों सहित)		↓	
	अन्य वैश्विक जोखिम		↓	
आ. समष्टिआर्थिक जोखिम	घरेलू मुद्रास्फीति		↑	
	चालू खाता घाटा		↑	
	पूँजीगत अंतर्वाह/बहिर्वाह (एफआईआई का लौटना, एफडीआई में कमी)		↓	
	कॉर्पोरेट क्षेत्र का जोखिम (उच्च लिवरेज/निम्न लाभकारिता)		↑	
	आधारभूत संरचना के विकास की कमी/धीमी गति		↔	
	पारिवारिक इकाइयों की बचत		↑	
	अन्य समष्टिआर्थिक जोखिम		↓	
इ. बाजार संबंधी जोखिम	विदेशी मुद्रा दर का जोखिम		↓	
	इन्विटी मूल्य में उतार-चढ़ाव		↑	
	निधियन जोखिम/चलनिधि जोखिम/ब्याज दर जोखिम		↑	
	बाजार संबंधी अन्य जोखिम		↓	
ई. संस्थागत जोखिम	आस्ति गुणवत्ता में कमी		↑	
	बैंकों की अतिरिक्त पूँजी संबंधी आवश्यकता		↑	
	ऋण का धीमा उठाव		↓	
	संस्थागत अन्य जोखिम		↑	
उ. सामान्य जोखित	प्राकृतिक आपदा/प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां		↑	
	अन्य सामान्य जोखिम		↔	

टिप्पणी :
जोखिम श्रेणी

बहुत अधिक	अधिक	मध्यम	कम	बहुत कम
-----------	------	-------	----	---------

पिछले सर्वेक्षण के बाद से जोखिम में परिवर्तन		
↑	↔	↓
बढ़ा	अपरिवर्तित रहा	घटा

समय-समय पर किए गए (अप्रैल और अक्टूबर अर्ध वार्षिक आधार पर) प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि जोखिम संभावनाएं एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरित(कमी/वृद्धि) हो सकती हैं जिसे रंग में परिवर्तन द्वारा दर्शाया गया है। किंतु समान जोखिम श्रेणी (अर्थात्, समान रंग में दर्शाए गए बॉक्स) में भी जोखिम संभावना बढ़/घट सकती है या अपरिवर्तित रह सकती है, जिनको तीर के निशान के माध्यम से दर्शाया गया है। जोखिम संभावनाओं में दर्शाया गया परिवर्तन लगातार दो सर्वेक्षणों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण से संबंधित है।

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण - (अक्टूबर 2015 और अप्रैल 2016)।

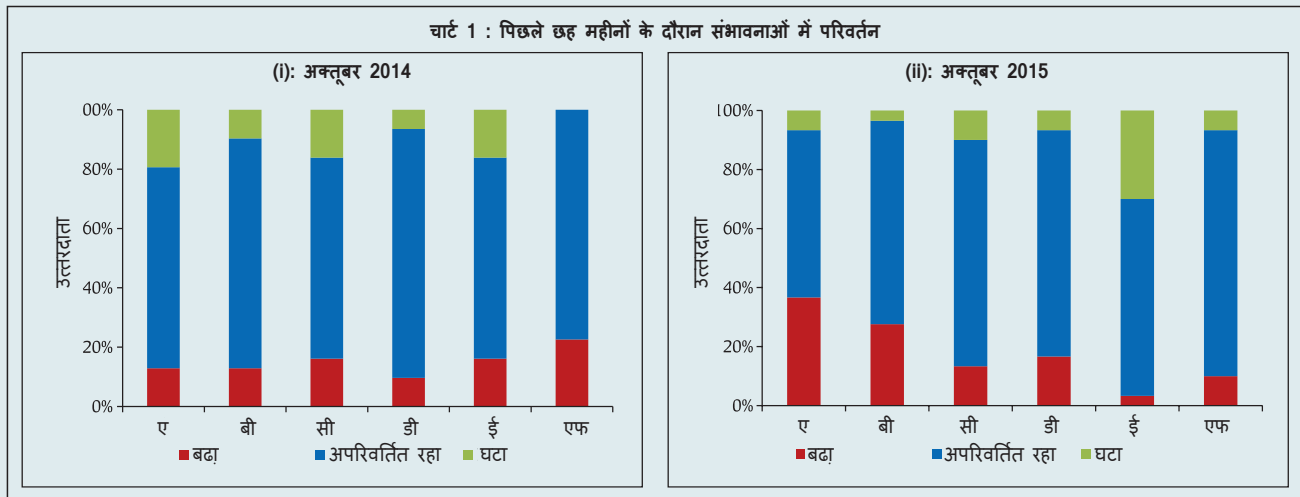
हाल में जो सर्वेक्षण हुआ उसके सहभागियों का मानना है कि अल्पावधि में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में बड़ा असर डालने वाली किसी घटना के होने की संभावना मध्यम है लेकिन मध्यावधि में यह संभावना अत्यधिक हो सकती है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उनका विश्वास मध्यम स्तर का रहा जबकि बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं ने दर्शाया कि पिछले छः महीनों में उनका विश्वास मामूली सा बढ़ा है। भारतीय वित्तीय प्रणाली में उत्तरदाताओं का उच्च विश्वास बने रहने के बाद भी यह महसूस किया गया कि आगे आने वाले समय में (अल्पावधि से मध्यावधि) भारतीय वैश्विक प्रणाली में अत्यधिक प्रभाव डालने वाली घटना घटित होने की संभावना 'मध्यम' स्तर की है (चित्र-3 और चार्ट - 1)।

चित्र-3 : उच्च प्रभाव वाली घटना होने की संभावना (अप्रैल 2016)		
असर	अप्रैल - 16	अक्तू - 15
ए. आगामी अवधि में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उच्च प्रभाव वाली घटना होने की संभावना (अल्पावधि में : 1 वर्ष तक)		
बी. आगामी अवधि में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उच्च प्रभाव वाली घटना होने की संभावना (मध्यम अवधि में : 1 से 3 वर्ष तक)		
सी. आगामी अवधि में भारतीय वित्तीय प्रणाली में उच्च प्रभाव वाली घटना होने की संभावना (अल्पावधि में : 1 वर्ष तक)		
डी. आगामी अवधि में भारतीय वित्तीय प्रणाली में उच्च प्रभाव वाली घटना होने की संभावना (अल्पावधि में : 1 से 3 वर्ष)		
ई. समग्र रूप में वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में विश्वास		
एफ. भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में विश्वास		

टिप्पणी :
जोखिम श्रेणी

जोखिम	बहुत अधिक	अधिक	मध्यम	कम	बहुत कम
ए - डी					
ई - एफ	अति विश्वसनीय	विश्वसनीय	काफी विश्वसनीय	बहुत विश्वसनीय नहीं	विश्वसनीय नहीं

स्रोत : भार.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण - (अप्रैल 2016)

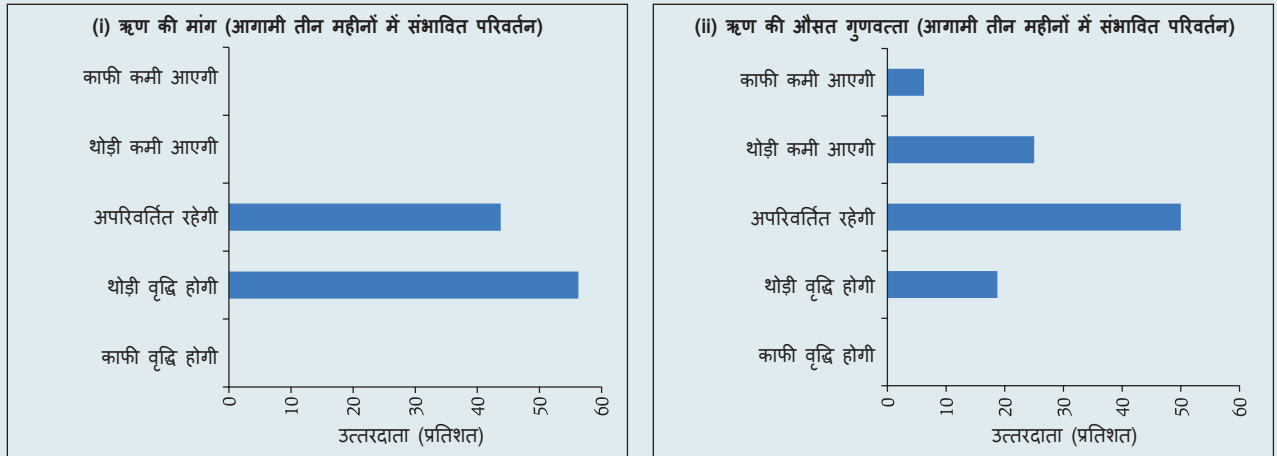


नोट: ए. वैश्विक वित्तीय प्रणाली में आने वाले समय में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने वाली है (अल्पावधि में : 1 वर्ष तक)।
 बी. वैश्विक वित्तीय प्रणाली में आने वाले समय में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने वाली है (मध्यावधि में : 1 से 3 वर्ष तक)।
 सी. भारतीय वित्तीय प्रणाली में आने वाले समय में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने वाली है (अल्पावधि में : 1 वर्ष तक)।
 डी. वैश्विक वित्तीय प्रणाली में आने वाले समय में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने वाली है (मध्यावधि में : 1 से 3 वर्ष तक)।
 ई. समग्र रूप से वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर भरोसा।
 एफ. समग्र रूप से भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर भरोसा।

स्रोत : भार.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण - अक्टूबर 2015 से अप्रैल 2016

अगले तीन महीनों में ऋण की मांग में होने वाले संभाव्य परिवर्तन के मामले में अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना था कि इसमें बहुत कम वृद्धि होगी जबकि अन्य यह समझते थे कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऋण की औसत गुणवत्ता के संबंध में अधिकांश उत्तरदाताओं ने यह व्यक्त किया कि अगले तीन महीनों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन एक बड़े समूह का यह भी मानना था कि गुणवत्ता और भी खराब हो सकती है (चार्ट 2)

चार्ट 2 : ऋण की मांग तथा उसकी गुणवत्ता संबंधी संभावना



स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण - अप्रैल 2016.

अनुबंध 2
कार्यप्रणालियां

2.1 कारपोरेट क्षेत्र

2.2.1 कारपोरेट क्षेत्र स्थिरता संकेतक और मानचित्र

कारपोरेट क्षेत्र स्थिरता संकेतक और मानचित्र निम्नलिखित पद्धति को अपनाकर बनाए गए हैं:

डाटा: गैर सरकारी गैर वित्तीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का तुलन पत्र डाटा।

आवधिकता: वार्षिक(1992-93 से 2011-12)। 2012-13 से 2015-16 तक विश्लेषण के लिए अर्ध वार्षिक तुलन पत्र डाटा का उपयोग किया गया है।

प्रत्येक आयाम में उपयोग में लाए गए अनुपात को सारणी 1 में दर्शाया गया है।

सारणी 1: कारपोरेट स्थिरता मानचित्र और कारपोरेट स्थिरता संकेतक बनाने के लिए उपयोग में लाए गए अनुपात	
आयाम	अनुपात
लाभप्रदता	आरओए (सकल लाभ/कुल आस्तियां)#; परिचालन लाभ/बिक्री#; कर पश्चात लाभ/बिक्री #।
लिवरेज	ऋण/आस्तियां, ऋण/इक्विटी: (ऋण को कुल उधार के रूप में लिया गया है)
सातत्य	ब्याज करवरेज अनुपात (ईबीआईटी की तुलना में ब्याज खर्च)#: ब्याज खर्च /कुल व्यय
तरलता	शीघ्र विक्रेय आस्तियां/ वर्तमान देयताएं (त्वरित अनुपात)#:
कुल कारोबार	कुल बिक्री/कुल आस्तियां #,

जोखिम से प्रतिलोम संबंध है

प्रथमतया, अनुपातों को मानक सामान्य वेरिएट में परिवर्तित किया गया [$Z = \frac{x-\mu}{\sigma}$]। उसके बाद Z' को रिलेटिव डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करते हुए 0 और 1 के बीच जोड़ा गया [$d = \frac{z - \min(z)}{\max(z) - \min(z)}$]। जोखिम प्रतिलोम अनुपात (#) (जोखिम के प्रति) के लिए '1' के पूरक का उपयोग किया गया। प्रत्येक आयाम के लिए कंपोजिट इंडेक्स व्युत्पन्न किया गया जो कि संबंधित 'd' का सामान्य औसत था (प्रधान घटक विश्लेषण से भी समान भार प्राप्त होते हैं)। प्रत्येक आयाम के लिए कंपोजिट इंडेक्स का उपयोग करके मानचित्र तैयार किया गया है।

कारपोरेट क्षेत्र का समग्र स्थिरता संकेतक 5 आयामों का औसत भार है। भारों को प्रधान घटक विश्लेषण (पीसीए) का उपयोग करके ज्ञात किया गया है। 5 आयामों के लिए व्युत्पन्न भार निम्न प्रकार हैं:

लाभप्रदता	लिवरेज	सातत्य	तरलता	कुल कारोबार
25%	25%	25%	10%	15%

2.1.11 एनजीएनएफ कंपनियों की दुर्बल कर्ज चुकौती क्षमता का बैंक ऋण पर असर का विश्लेषण

1. मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियों (बीएसआर) से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के कुल बैंक ऋण तथा निजी गैर-वित्तीय निगमों [अर्थात गैर सरकारी गैर वित्तीय (एनजीएनएफ) सार्वजनिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां] को दिए गए बैंक ऋण से संबंधित आंकड़ों का पता चलता है। इस प्रयोजन से, कुल बैंक ऋण में एनजीएनएफ कंपनियों को दिए गए बैंक ऋण के हिस्से का आकलन किया गया है।
2. कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) डाटाबेस के नमूने का प्रयोग करते हुए नमूने में दी गई समस्त एनजीएनएफ कंपनियों की कुल बैंक उधारियों में "कमजोर" एनजीएनएफ कंपनियों की बैंक उधारी के अनुपात की गणना की गई है। इसी प्रकार ने

नमूने में दी गई कुल बैंक उधारों में “लीवरेजयुक्त” एनजीएनएफ कंपनियों की बैंक उधारी के अनुपात की गणना की गई है।

- “कमजोर” और “लीवरेजयुक्त कमजोर” कंपनियों के कारण बैंक ऋण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए उपर्युक्त पैरा 2 में निकाले गए अनुपात को बीएसआर ऋण डाटा (उक्त पैरा 1) पर लागू किया गया है। इस प्रकार कुल बैंक ऋण में प्रतिशत के रूप में “कमजोर” कंपनियों को दिए गए बैंक ऋण के हिस्से तथा कुल बैंक ऋण में प्रतिशत के रूप में “लीवरेजयुक्त कमजोर” कंपनियों को दिए गए बैंक ऋण के हिस्से का आकलन किया गया।

2.2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

2.2.1 बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक

बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक किसी दी गई अवधि के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता पर प्रभाव डालने वाली स्थितियों और जोखिम घटकों में होने वाले परिवर्तनों का समग्र अनुमान प्रदर्शित करते हैं। बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक में पांच संयुक्त सूचकांकों का प्रयोग किया गया है जिनके पांच आयाम हैं - मजबूती, आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता, चलनिधि और कार्यकुशलता। प्रत्येक संयुक्त सूचकांक बनाने में जिन अनुपातों का प्रयोग किया गया है उन्हें सारणी 2 में दिया गया है:-

सारणी 2: बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक बनाने के लिए प्रयुक्त अनुपात				
आयाम	अनुपात			
मजबूती	सीआरएआर #	टिअर II पूंजी के प्रति टिअर-I पूंजी #	पूंजी और आरक्षी के प्रति कुल आस्ति के रूप में लीवरेज अनुपात	
आस्ति-गुणवत्ता	कुल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए	कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए	सकल एनपीए के प्रति अवमानक अग्रिम #	मानक अग्रिमों की तुलना में पुनःसंचित- मानक- अग्रिम
लाभप्रदता	आस्तियों पर प्रतिफल #	निवल ब्याज मार्जिन #	लाभ में वृद्धि #	
चलनिधि	कुल आस्तियों की तुलना में चलनिधि आस्तियां #	कुल आस्तियों की तुलना में ग्राहक जमा राशियां #	ग्राहक की जमाराशियों की तुलना में गैर-बैंक अग्रिम	कुल जमाराशियों की तुलना में 1 वर्ष की अवधि के भीतर परिपक्व होने वाली जमाराशियां
कार्यकुशलता	आय की तुलना में लागत	स्टाफ खर्च की तुलना में व्यवसाय (क्रेडिट+ जमाराशि) #		कुल खर्च की तुलना में स्टाफ व्यय

नोट: # जोखिम से प्रतिलोम संबंध है।

प्रत्येक संयुक्त सूचकांक जो बैंक की कार्यप्रणाली के आयाम का प्रतिनिधित्व करता है, वह शून्य और 1 के बीच का मान लेता है। प्रत्येक सूचकांक इसके निर्माण के लिए प्रयुक्त नमूना अवधि के दौरान एक संबंधित पैमाना होता है जिसमें उच्च मान का अर्थ होता है कि उस आयाम में जोखिम अधिक है। अतः किसी विशेष आयाम में सूचकांक का मान बढ़ना यह दर्शाता है कि उस आयाम में अन्य अवधियों की तुलना में संबंधित अवधि में जोखिम में वृद्धि हुई है। किसी आयाम के लिए प्रयोग में लाए गए प्रत्येक अनुपात द्वारा बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक भारित औसत निकाला जाता है जिसमें भारों को बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों की तुलना में किसी बैंक की व्यक्तिगत आस्तियों के अनुपात के रूप में निरूपित किया जाता है। किसी नमूना अवधि के लिए प्रत्येक सूचकांक का सामान्यीकरण निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर किया जाता है :

$$\frac{X_t - \min(X_t)}{\max(X_t) - \min(X_t)}$$

जिसमें X_t अनुपात के मूल्य को t समय पर प्रदर्शित करता है। प्रत्येक आयाम के संयुक्त सूचकांक की गणना, उस आयाम के लिए प्रयुक्त सामान्यीकृत अनुपातों के भारित औसत के रूप में की जाती है जहां भार, सीएएमईएलएस रेटिंग के अनुमान हेतु

निर्धारित अंकों पर आधारित होते हैं। इन पांच संयुक्त सूचकांकों के सामान्य औसत के रूप में बैंकिंग स्थिरता संकेतक का निर्माण किया जाता है।

2.2.11 मैक्रो-दबाव परीक्षण

मैक्रोइकोनॉमिक आघातों के प्रति बैंकों की समुत्थानशक्ति सुनिश्चित करने के लिए, क्रेडिट जोखिम के लिए मैक्रो दबाव परीक्षण किया गया। मैक्रोइकोनॉमिक चरों के कार्य के रूप में एक क्रेडिट जोखिम संकेतक का निर्माण किया गया जिसमें विविध अर्थमितीय नमूनों का उपयोग किया गया जो चुनिंदा बैंकिंग प्रणाली को समग्रतः मैक्रोइकोनॉमिक चरों से संयुक्त करता है। जिन समय-श्रृंखला अर्थमितीय नमूनों का उपयोग किया गया वे इस प्रकार हैं: (i) बहुभिन्नरूपी रीग्रेशन को नमूना प्रणाली स्तरीय विपथन अनुपात के साथ; (ii) वेक्टर ऑटोरीग्रेशन (वीएआर) को नमूना प्रणाली स्तरीय विपथन अनुपात के साथ; (iii) क्वान्टाइल रीग्रेशन को नमूना प्रणाली स्तरीय विपथन अनुपात के साथ; (iv) बहुभिन्नरूपी रीग्रेशन को नमूना बैंक समूह-वार विपथन अनुपात के साथ, (v) वीएआर को नमूना बैंक समूह-वार विपथन अनुपात के साथ, और (vi) क्षेत्रगत सकल एनपीए के लिए बहुभिन्नरूपी रीग्रेशन। समग्र बैंकिंग प्रणाली में विपथन अनुपात के मौजूदा और पिछले मान शामिल होते हैं जबकि मैक्रोइकोनॉमिक चरों में आधार कीमत संवृद्धि पर जीवीपी, भारत औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर), सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, जीडीपी की तुलना में निर्यात अनुपात ($\frac{EX}{GDP}$), जीडीपी की तुलना में चालू खाता शेष अनुपात ($\frac{CAB}{GDP}$) और जीडीपी की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा अनुपात ($\frac{GFD}{GDP}$) शामिल होते हैं।

जहां बहुभिन्नरूपी रीग्रेशन, बैंकिंग प्रणाली के सकल एनपीए और पूंजी पर चुनिंदा मैक्रोइकोनॉमिक चरों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है वहीं वीएआर नमूना, बैंकों की पूंजी और एनपीए अनुपात पर समग्र आर्थिक दबाव स्थिति के प्रभाव को दर्शाता है और यह फीडबैक प्रभाव को भी संज्ञान में लेता है। इन पद्धतियों में, विपथन अनुपात¹ के सशर्त मध्यमान का अनुमान लगाया जाता है और यह माना जाता है कि क्रेडिट गुणवत्ता के स्तर में परिवर्तन होने के बावजूद क्रेडिट गुणवत्ता पर मैक्रो-चरों का प्रभाव समान रहेगा, जो कि हमेशा सत्य नहीं रह सकता है। इस अनुमान में छूट देने के लिहाज से क्रेडिट गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए क्वान्टाइल रीग्रेशन को अपनाया गया, जिसमें सशर्त मध्यमान के स्थान पर सशर्त क्वान्टाइल का अनुमान लगाया जाता है।

नमूना ढांचा

जीएनपीए अनुपात और/अथवा स्लिपेज अनुपात (एसआर) पर मैक्रोइकोनॉमिक आघातों के प्रभावों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित बहुभिन्नरूपी नमूने अपनाए गए:

प्रणाली स्तरीय नमूने

प्रणाली स्तरीय जीएनपीए का अनुमान लगाने के लिए तीन भिन्न परंतु आपस में सम्पूरक अर्थमितीय नमूनों का उपयोग किया गया: बहुभिन्नरूपी रीग्रेशन, वीएआर (जो मैक्रो चरों और सहसंबद्धता प्रभावों के संबंध में क्रेडिट गुणवत्ता के प्रभावों के विषय में प्राप्त फीडबैक को भी संज्ञान में लेता है) और क्वान्टाइल रीग्रेशन (जो क्षुद्र जोखिमों के साथ निपट सकता है और मैक्रोइकोनॉमिक आघातों के विषम-रेखीय प्रभावों को भी संज्ञान में लेता है)। इन नमूनों से प्राप्त प्रक्षेपणों के औसत का उपयोग सीआरएआर पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना करने में किया गया है।

• बहुभिन्नरूपी रीग्रेशन

यह विश्लेषण संपूर्ण वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के लिए समग्र स्तर पर विपथन अनुपात के संबंध में किया गया।

$$SR_t = \alpha_1 - \beta_1 SR_{t-2} - \beta_2 \Delta GVA_{t-1} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP} \right)_{t-1} + \beta_5 \Delta CPI_{t-4} + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP} \right)_{t-2} + \beta_7 \text{Dummy}$$

जहां, $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ और $\beta_7 > 0$.

¹ स्लीपेजअवधि के दौरान एनपीए में हुई नई अभिवृद्धि से है। स्लीपेजका तात्पर्य स्लीपेज अनुपात = नया एनपीए/अवधि की शुरुआत में मानक अग्रिम

• वीएआर मॉडल

अंकन रूप में, मध्यमान-समायोजित वीएआर के क्रम (order) p (VAR(p)) को इस प्रकार लिखा जा सकता है:

$$y_t = A_1 y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + u_t ; t=0,1,2,3,\dots$$

जहां, $y_t = (y_{1t}, \dots, y_{kt})$ समय t पर चर का एक वेक्टर (Kx1), $A_i (i=1,2,\dots,p)$ निर्धारित (KxK) कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हैं और $u_t = (u_{1t}, \dots, u_{kt})$ एक K-आयामी व्हाइट न्वाइज़ या नवोन्मेषी प्रक्रिया है।

वीएआर मॉडल का अनुमान लगाने के लिए, विपथन अनुपात, डब्ल्यूएएलआर, सीपीआई(संयुक्त) मुद्रास्फीति, आधारभूत कीमत पर जीवीए संवृद्धि और जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल राजकोषीय घाटे का चुनाव किया गया। न्यूनतम सूचना दृष्टिकोण आधार पर और अन्य उपचारों के साथ ही वीएआर के समुचित क्रम का चुनाव किया गया और इसके लिए क्रमांक 2 उचित पाया गया। तदनुसार, क्रम 2 के वीएआर (VAR(2)) का अनुमान लगाया गया और एआर की बहुपदीय अभिलाक्षणिक मूल के आधार पर नमूने की स्थिरता की जांच की गई। चूंकि सभी मूल इकाई की परिधि के भीतर पाई गई अतः इस चुने गए नमूने को स्थिरता की शर्त पूरी करने वाला पाया गया। चुने गए वीएआर के संवेग अनुक्रिया प्रणाली का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के मैक्रो इकोनॉमिक आघातों के प्रभावों का निर्धारण किया गया।

• क्वान्टाइल रीग्रेशन

0.8 पर विपथन अनुपात के सशर्त क्वान्टाइल का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित क्वान्टाइल रीग्रेशन का प्रयोग किया गया:

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-2} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP} \right)_{t-3} + \beta_5 \Delta CPI_{t-5} + \beta_6 \text{Dummy}$$

बैंक समूह स्तरीय पद्धति

बैंक समूह-वार एसआर का अनुमान दो अलग-अलग परंतु आपस में सम्पूरक अर्थमितीय नमूनों का उपयोग करते हुए लगाया गया: बहुभिन्नरूपी रीग्रेशन और वीएआर। इन नमूनों से प्राप्त प्रोजेक्शन के औसत का उपयोग सीआरएआर पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना करने में किया गया।

• बहुभिन्नरूपी रीग्रेशन

विभिन्न बैंक समूहों के विपथन अनुपात का नमूना बनाने के लिए, विभिन्न बैंक समूहों के लिए निम्नलिखित बहुभिन्नरूपी रीग्रेशन का उपयोग किया गया:

सरकारी क्षेत्र के बैंक:

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-2} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{CAB}{GDP} \right)_{t-3} + \beta_5 \Delta CPI_{t-1} + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP} \right)_{t-2}$$

निजी क्षेत्र के बैंक:

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-1} + \beta_3 RWALR_{t-2} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP} \right)_{t-1}$$

विदेशी बैंक:

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} + \beta_2 WALR_{t-2} + \beta_3 \Delta CPI_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP} \right)_{t-5} + \beta_5 \text{Dummy}$$

• **वीएआर मॉडल**

विभिन्न बैंक समूहों के स्लिपेज अनुपात को मॉडल करने के लिए नीचे दिए गए समष्टि चरों के आधार पर विभिन्न स्तर के अलग-अलग वीएआर मॉडलों का आकलन किया गया था:

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक: आधारभूत मूल्य वृद्धि पर जीवीए, सीपीआई (संयुक्त)- मुद्रास्फीति, डब्ल्यूएएलआर, जीडीपी अनुपात की तुलना में सीएबी और स्तर 2 के जीडीपी अनुपात की तुलना में जीएफडी।

निजी क्षेत्र के बैंक: आधारभूत मूल्य वृद्धि पर जीवीए, वास्तविक डब्ल्यूएएलआर और स्तर 1 के जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात।

विदेशी बैंक: सीपीआई (संयुक्त)- मुद्रास्फीति, डब्ल्यूएएलआर और स्तर 2 के जीडीपी अनुपात की तुलना में जीएफडी ।

सेक्टर स्तर के मॉडल

सेक्टर स्तर पर बहु-चरीय रीग्रेशन

विभिन्न सेक्टरों पर समष्टि-आर्थिक आघातों के प्रभाव का आकलन संकलित जीएनपीए अनुपात को प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग से प्रयोग करते हुए बहु-चरीय रीग्रेशन मॉडल के द्वारा किया गया था। आश्रित चरों में विलंबित जीएनपीए, आधार मूल्य वृद्धि पर जीवीए (संकलित या सेक्टर स्तरीय), सीपीआई (संयुक्त)-मुद्रास्फीति, डब्ल्यूएएलआर और जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात शामिल हैं।

स्लिपेज से जीएनपीए का अनुमान

स्लिपेज अनुपातों से जीएनपीए की गणना जिसका ऊपर वर्णित क्रेडिट जोखिम अर्थमितीय मॉडल द्वारा आकलन किया गया था, वह निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित थी: 11 प्रतिशत क्रेडिट वृद्धि: मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर तिमाही में क्रमशः 9.6 प्रतिशत, 7.9 प्रतिशत, 6.5 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत वसूली दर; मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर तिमाही में बढ़े खाते डालने की दर क्रमशः 5.5 प्रतिशत, 4.8 प्रतिशत, 3.7 प्रतिशत और 4.6 प्रतिशत।

कर उपरांत लाभ (पीएटी) का आकलन

बैंकों के कर उपरांत लाभ (पीएटी) के विभिन्न घटकों जैसे कि ब्याज से आय, अन्य आय, परिचालनगत व्यय और प्रावधानों का विभिन्न समय श्रृंखला अर्थमितीय मॉडलों (जैसा की नीचे दिया गया है) का प्रयोग करके अनुमान लगाया गया था। अंत में, पीएटी का आकलन निम्नलिखित समीकरण के आधार पर किया गया था:

$$\text{पीएटी} = \text{एनआईआई} + \text{ओओआई} - \text{ओई} - \text{प्रावधान} - \text{आयकर}$$

जहां एनआईआई निवल ब्याज आय, ओओआई अन्य परिचालन आय और ओई परिचालनगत व्यय है।

निवल ब्याज आय (एनआईआई): एनआईआई ब्याज से आय और ब्याज पर व्यय के बीच अंतर को कहते हैं जिसका आकलन निम्नलिखित रीग्रेशन मॉडल के उपयोग से किया गया था;

$$LNII_t = -\alpha_1 + \beta_1 \times LNII_{t-1} + \beta_2 \times LNGVA_SA_{t-1} + \beta_3 \times Adv_Gr_{t-1} + \beta_4 \times Spread_t$$

LNII, NII का लॉग है। LNGVA_SA नाममात्र के जीवीए का विभिन्न अवसरों के अनुसार समायोजित लॉग है। Adv_Gr अग्रिमों की वर्ष-दर-वर्ष होने वाली वृद्धि दर है। ब्याज अर्जक आस्तियों द्वारा अर्जित औसत ब्याज और देयताओं पर अदा किए गए औसत ब्याज का अंतर स्प्रेड कहलाता है।

अन्य परिचालनगत आय (ओओआई): अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ओओआई का आकलन निम्नलिखित रीग्रेशन मॉडल के आधार पर किया गया था:

$$LOOI_t = -\alpha_1 + \beta_1 \times LOOI_{t-1} + \beta_2 \times LNGDP_SA_t$$

LOOI को OOI का लॉग कहा जाता है।

परिचालनगत व्यय (ओई): अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के परिचालनगत व्यय का आकलन ऑटो-रीग्रेसिव मूविंग एवरेज (एआरएमए) मॉडल के आधार पर किया गया था।

प्रावधान: आवश्यक प्रावधान का आकलन निम्नलिखित रीग्रेशन मॉडल का उपयोग करके किया गया है:

$$P_Adv_t = \alpha_1 + \beta_1 \times P_Adv_{t-1} - \beta_2 \times RGVA_Gr_{t-2} + \beta_3 \times GNPA_{t-1} - \beta_4 \times Dummy$$

P_Adv कुल अग्रिमों के अनुपात की तुलना में किया गया प्रावधान है। RGVA_Gr वास्तविक जीवीए की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि है। GNPA कुल अग्रिमों की तुलना में सकल गैर निष्पादन आस्तियों का अनुपात है। Dummy एक कल्पित समयावधि है।

आयकर: लागू होने वाले आयकर की गणना कर लगाए जाने से पूर्व लाभ का 35 प्रतिशत मानकर की गई है जो पिछले रुझानों के अनुरूप ही कर से पहले लाभ की तुलना में आयकर का अनुपात है।

पूंजी पर्याप्तता पर जीएनपीए का प्रभाव

अंत में, सीआरएआर पर जीएनपीए प्रभाव का आकलन पिछले खंड के अनुसार अनुमानित पीएटी के आधार पर किया गया था। जोखिम-भारित आस्तियों (आरडबल्युए) की संवृद्धि को बेसलाइन के अंतर्गत 11 प्रतिशत, मध्यम जोखिम के अंतर्गत 13 प्रतिशत और गंभीर जोखिम की स्थिति में 15 प्रतिशत माना गया। ऐसा माना गया था कि नियामक पूंजी वृद्धि न्यूनतम स्तर पर बनी रहेगी यदि पणधारकों द्वारा पूंजी लगाने पर विचार किए बिना लाभ का न्यूनतम 25 प्रतिशत अनिवार्य रूप से आरक्षित खाते में अंतरित किया जाता है। जीएनपीए अनुपात के आकलित मूल्य को 'तुलन-पत्र दृष्टिकोण' का प्रयोग करके पूंजी अनुपात में परिवर्तित किया गया जिसके अंतर्गत तुलन-पत्र में मौजूद पूंजी पर प्रभाव प्रावधान और निवल के माध्यम से पड़ता है।

2.2.III एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण - दबाव परीक्षण

तिमाही निगरानी के एक हिस्से के रूप में क्रेडिट जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम इत्यादि को जांचने हेतु दबाव परीक्षण किया जाता है और वाणिज्यिक बैंक द्वारा इन आघातों को सहन करने की क्षमता का अध्ययन किया जाता है। यह विश्लेषण अलग से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली के स्तर पर भी किया जाता है।

क्रेडिट जोखिम

बैंकों की आघात सहनशक्ति का पता लगाने के लिए क्रेडिट पोर्टफोलियो के कुछ चुनिंदा सेक्टरों के साथ-साथ संपूर्ण पोर्टफोलियो के लिए जीएनपीए स्तर को बढ़ाकर आघात दिया जाता है। क्रेडिट संकेद्रण जोखिम का परीक्षण करने के लिए मान लिया जाता है कि उच्च निजी उधारकर्ताओं और सबसे बड़े समूह उधारकर्ताओं ने चूक की। यह विश्लेषण संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली तथा अलग से बैंकों दोनों ही स्तरों पर किया जाता है। जीएनपीए की कल्पित वृद्धि को अवमानक, संदिग्ध और हानि श्रेणियों में वितरित कर दिया गया जिसे एनपीए की मौजूदा स्थिति के अनुरूप समान अनुपात में किया गया। फिर भी, उच्च उधारकर्ताओं (व्यैक्तिक के साथ-साथ समूह के) का प्रयोग करके क्रेडिट संकेद्रण जोखिम के लिए माना गया कि कल्पित आघात के अंतर्गत अतिरिक्त जीएनपीए केवल अवमानक श्रेणी में वितरित हुआ। दबावग्रस्त उधारकर्ताओं का प्रयोग करके क्रेडिट संकेद्रण जोखिम जात करने के मामले में यह माना गया कि कल्पित आघात के अंतर्गत अतिरिक्त जीएनपीए का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हानि श्रेणी पर पड़ा। इन दबावग्रस्त आस्तियों के परीक्षण हेतु प्रयुक्त प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड विभिन्न आस्ति श्रेणियों के लिए निर्धारित मौजूदा औसत प्रावधानीकरण पर आधारित थे। प्रावधान संबंधी अपेक्षाओं को अवमानक, संदिग्ध और हानि अग्रिम श्रेणियों के लिए क्रमशः 25 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत माना गया। इन मानदंडों को दबाव की स्थिति में परिगणित अतिरिक्त जीएनपीए पर लागू किया गया। जीएनपीए में कल्पित वृद्धि के परिणामस्वरूप एक तिमाही के लिए अतिरिक्त जीएनपीए पर हुई आय की हानि को वृद्धिशील प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के अतिरिक्त कुल हानि में भी शामिल किया गया था। अनुमानित कुल हानि को बैंकों की पूंजी से घटाया गया और इस प्रकार प्राप्त प्रावधानीकरण संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता को औसत जोखिम भारित आस्ति से गुणा करके उसे बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों से घटाया गया और दबावग्रस्त पूंजी पर्याप्तता अनुपातों की गणना की गई।

ब्याज दर जोखिम

भारतीय रुपए के प्रतिफल वक्र में उतार-चढ़ाव के कारण कल्पित आघातों के अंतर्गत पोर्टफोलियो के मूल्य में गिरावट या आय में कमी के आधार पर हानि हो सकती थी। दबावग्रस्त सीआरएआर का पता लगाने के लिए इन अनुमानित हानियों को बैंकों की पूंजी से घटाया गया।

ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में ब्याज दर जोखिम के संबंध में (एचएफटी+एएफएस) मूल्यांकन प्रभाव (पोर्टफोलियो में हानि) की गणना के लिए एक आवधिक विश्लेषण दृष्टिकोण पर विचार किया गया था। इन निवेशों पर पोर्टफोलियो में हुई हानि की गणना लगाए गए आघातों के आधार पर प्रत्येक समय बकेट में की गई थी। इसके परिणामस्वरूप हुई हानि/लाभ का प्रयोग करके प्रभावित सीआरएआर का पता लगाया गया था। एचटीएम पोर्टफोलियो में ब्याज दर आघातों का अलग से किए गए एक अभ्यास में आवधिक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए ब्याज वहन करने वाली आस्तियों के प्रत्येक समय बकेट में मूल्यांकन हानियों की गणना की गई। एचटीएम पोर्टफोलियो पर परीक्षणों के लिए मूल्यांकन प्रभाव की गणना इस धारणा के अंतर्गत की गई थी कि एचटीएम पोर्टफोलियो का मूल्य बाजार दर के सापेक्ष आँका गया होगा।

बैंकिंग बही पर ब्याज दर जोखिम के प्रभाव का मूल्यांकन 'आय दृष्टिकोण' के माध्यम से किया गया। आघातों के प्रभाव का आकलन दर संवेदी आस्तियों और देयताओं के एक्सपोजरों के बीच अंतर के कारण हुई आय की हानि की गणना के आधार पर किया गया क्रमशः एएफएस और एचएफटी पोर्टफोलियो को प्रत्येक समय बकेट में अलग-अलग जिसमें एक वर्ष के लिए शामिल नहीं किया गया था।

चलनिधि जोखिम

चलनिधि दबाव परीक्षणों का उद्देश्य इस बात का अंदाजा लगाना है कि किसी अप्रत्याशित चलनिधि निकासी की स्थिति का सामना बिना किसी बाह्य चलनिधि की सहायता के करने में बैंक कितना सक्षम है। इस संबंध में विभिन्न प्रकार के परिदृश्य अचानक जमाकर्ताओं का विश्वास खोने के कारण उनके द्वारा अलग-अलग अनुपातों (जमा प्रकारों के आधार पर) में अप्रत्याशित जमाराशियां निकालने के अलावा स्वीकृत/प्रतिबद्ध/गारंटीकृत क्रेडिट (अनाहरित कार्यशील पूंजी स्वीकृति सीमा, अनाहरित प्रतिबद्ध क्रेडिट और लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटी को हिसाब में लेते हुए) के अप्रयुक्त अंश के लिए मांग का नजारा पेश करते हैं। यह दबाव परीक्षण बैंकों की यह क्षमता जांचने के लिए किए गए थे कि क्या क्रेडिट के लिए की जाने वाली किसी आकस्मिक मांग को अपनी तरल आस्तियों की सहायता से पूरा करने में सक्षम हैं।

चलनिधि दबाव परीक्षण निम्नलिखित धारणाओं के आधार पर किए गए हैं:

- यह माना गया कि बैंक जमाराशियों के दबावग्रस्त आहरण और क्रेडिट के लिए अतिरिक्त मांग को केवल तरल आस्तियों की बिक्री के माध्यम से पूरा कर लेंगे।
- निवेशों की बिक्री उनके बाजार मूल्य पर 10 प्रतिशत के कमीशन के साथ की जाएगी।
- दबाव परीक्षण को 'स्थिति' मोड के अंतर्गत किया जाएगा।

बॉटम-अप यानी निम्न से उच्च दबाव परीक्षण

15 चयनित अनसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बॉटम-अप दबाव परीक्षण किया गया। इन चयनित बैंकों को एक समान सेनेरियो और शॉक-साइज वाला सेट दिया गया। इन परीक्षणों में मार्च 2016 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया। बैंकों ने प्रत्येक मामले में हानि की गणना करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का उपयोग किया।

चयनित बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का दबाव परीक्षण

यह दबाव परीक्षण डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के अनुमानित मूल्य के संबंध में 22 प्रमुख बैंकों के एक प्रतिनिधित्व नमूना सेट के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को केंद्र में रखकर किया गया। नमूने में प्रत्येक बैंक को उनके संबंधित डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर दबाव की स्थितियों में उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए कहा गया।

देशी बैंकों के मामले में, उनके घरेलू और विदेशी दोनों परिचालनों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को शामिल किया गया। विदेशी बैंकों के मामले में उनकी केवल स्थानीय (भारतीय) स्थिति को अध्ययन में शामिल किया। चूंकि डेरिवेटिव कारोबार के मामले में

प्रभावी हेजिंग प्रचलित हो गई थी, इसलिए उसे दबाव परीक्षणों से मुक्त रखा गया, जबकि अन्य सभी कारोबार परीक्षण में शामिल किए गए थे।

दबाव परिस्थितियों के अंतर्गत परीक्षण हेतु स्पॉट अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपए और घरेलू ब्याज दरों को मानदंडों को रूप में समेकित करते हुए चार संवेदनशीलता परीक्षणों को शामिल किया गया।

सारणी 3 : संवेदनशीलता विश्लेषण के संबंध में आघात

घरेलू ब्याज दरें		
आघात 1	एक दिवसीय	+2.5 प्रतिशतता अंक
	1 वर्ष तक	+1.5 प्रतिशतता अंक
	1 वर्ष से अधिक	+1.0 प्रतिशतता अंक

घरेलू ब्याज दरें		
आघात 2	एक दिवसीय	-2.5 प्रतिशतता अंक
	1 वर्ष तक	-1.5 प्रतिशतता अंक
	1 वर्ष से अधिक	-1.0 प्रतिशतता अंक

विनियम दरें		
आघात 3	अमेरिकी डॉलर/ भारतीय रुपया	+20 प्रतिशत

विनियम दरें		
आघात 4	अमेरिकी डॉलर/ भारतीय रुपया	-20 प्रतिशत

2.3 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण - दबाव परीक्षण

क्रेडिट जोखिम

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में मार्च 2016 की समाप्ति की स्थिति के अनुसार उनके आस्ति पोर्टफोलियो का प्रयोग करके क्रेडिट जोखिम के विषय में दबाव परीक्षण किया गया जो एकल घटक पोर्टफोलियो विश्लेषण पर आधारित था। निम्नलिखित चार अलग-अलग परिदृश्यों के अंतर्गत सीआरएआर पर इसके प्रभाव का अध्ययन ऐतिहासिक मानक विचलन (एसडी) का प्रयोग करते हुए किया गया।

- परिदृश्य I : जीएनपीए पर मानक विचलन (एसडी) का आघात (अवमानक अग्रिमों में वर्गीकृत)
- परिदृश्य II : जीएनपीए पर 1 मानक विचलन (एसडी) का आघात (अवमानक अग्रिमों में वर्गीकृत)
- परिदृश्य III : जीएनपीए पर 0.5 मानक विचलन (एसडी) का आघात (हानि अग्रिमों में वर्गीकृत)
- परिदृश्य IV : जीएनपीए पर 2 मानक विचलन (एसडी) का आघात (हानि अग्रिमों में वर्गीकृत)

चलनिधि जोखिम

1 से 28 दिनों की समयावधि में नकदी प्रवाह के आधार पर एक चलनिधि दबाव परीक्षण भी किया गया जिसमें नकदी के बाह्य प्रवाह यानी आउटफ्लो के 20 प्रतिशत से अधिक असंतुलन [नकारात्मक अंतर (नकदी इनफ्लो से नकदी आउटफ्लो घटाकर)] होने की स्थिति में इसे दबावग्रस्त माना गया।

- परिदृश्य I : 1 से 28 दिनों की कालावधि में नकदी बहिर्वाह का 50 प्रतिशत तक जाना (नकदी के प्रवाह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा)
- परिदृश्य I : 1 से 28 दिनों की कालावधि में नकदी आउटफ्लो का 100 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ना (नकदी के प्रवाह में बिना किसी परिवर्तन के)

2.4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण - दबाव परीक्षण

क्रेडिट जोखिम

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (इसमें जमा स्वीकार करने वाली और जमा स्वीकार नहीं करने वाली, दोनों प्रकार की और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कंपनियां शामिल थीं) के क्रेडिट जोखिम के संबंध में दबाव परीक्षण किया गया, जिसमें मार्च 2016 की समाप्ति के अनुसार मौजूद उनके आस्ति पोर्टफोलियो का उपयोग किया गया। ये परीक्षण एकल घटकीय संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थे। तीन विभिन्न परिस्थितियों के तहत सीआरएआर पर इसके प्रभाव का अध्ययन ऐतिहासिक मानक विचलन के आधार पर किया गया :

- परिदृश्य I : मौजूदा स्तर से जीएनपीए में 0.5 मानक विचलन (एसडी) की बढ़ोतरी
- परिदृश्य II : मौजूदा स्तर से जीएनपीए में 1 मानक विचलन (एसडी) की बढ़ोतरी
- परिदृश्य III : मौजूदा स्तर से जीएनपीए में 3 मानक विचलन (एसडी) की बढ़ोतरी

जीएनपीए में परिकल्पित वृद्धि को अवमानक, संदिग्ध और हानि श्रेणियों में उसी अनुपात में वितरित कर दिया गया जिस अनुपात में जीएनपीए का मौजूदा स्टॉक उपलब्ध था। प्रावधानीकरण की अतिरिक्त आवश्यकताओं को वर्तमान पूंजी की स्थिति से समायोजित कर दिया गया। दबाव परीक्षण एक-एक एनबीएफसी स्तर के साथ समग्र स्तर पर भी किया गया।

2.5 अंतर-संबद्धता - नेटवर्क विश्लेषण

मैट्रिक्स अल्जेब्रा, नेटवर्क विश्लेषण का मूल आधार होता है जिसमें वित्तीय क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय एक्सपोजरों का इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टम में एक संस्था की दूसरी संस्थाओं को दी गई उधारियों अथवा उनसे ली गई उधारियों को एक वर्गाकार मैट्रिक्स में रखा जाता है और तब उन्हें नेटवर्क ग्राफ में प्रस्तुत किया जाता है। सिस्टम में अंतरसंबद्धता के स्तर को मापने के लिए नेटवर्क मॉडल में विभिन्न सांख्यिकीय पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ अति महत्वपूर्ण पद्धतियां निम्नलिखित हैं:

संबद्धता : इस सांख्यिकीय पद्धति से एक पूर्ण ग्राफ में सभी संभव श्रृंखलाओं से संबंधित नोड्स के बीच की श्रृंखलाओं का विस्तार मापा जाता है। एक निर्देशित ग्राफ में $K = \sum_{i=1}^N k_i$ के बराबर बाहरी अंशों की कुल संख्या को दर्शाती है और N नोड्स की कुल संख्या के रूप में है, ग्राफ की संबद्धता $\frac{K}{N(N-1)}$ के रूप में दी गई है।

क्लस्टर गुणांक : नेटवर्क में क्लस्टरिंग द्वारा यह आंका जाता है कि प्रत्येक नोड एक-दूसरे के साथ किस प्रकार अंतर-संबद्ध है। विशेषकर, इस बात की प्रबल संभावना रहती है कि किसी नोड के दो पड़ोसी (वित्तीय नेटवर्क के मामले में बैंक के प्रतिपक्षी) आपस में भी पड़ोसी होंगे। किसी नेटवर्क के लिए उच्च क्लस्टरिंग गुणांक का मतलब यह होता है कि प्रणाली में उच्च स्थानिक अंतर-संबद्धता मौजूद है। k_i , निकटवर्ती प्रत्येक बैंक के लिए उनके बीच सभी प्रकार के संभावित संबंध की कुल संख्या $k_i(k_i-1)$ है। मान लेते हैं कि E_i एंजेट 'i' बैंक के k_i निकटवर्तियों के बीच वास्तविक संबद्धता को दर्शाता है अर्थात् 'i' के k_i के निकटवर्ती हैं और वो आपस में भी निकटवर्ती हैं। i बैंक के लिए क्लस्टरिंग गुणांक C_i को इस समीकरण के माध्यम से व्यक्त किया जाता है:

$$C_i = \frac{E_i}{k_i(k_i-1)}$$

समग्र रूप में नेटवर्क का क्लस्टरिंग गुणांक (सी) सभी C_i का औसत होता है:

$$C = \frac{\sum_{i=1}^N C_i}{N}$$

निकटतम मार्ग की दूरी : यह नेटवर्क के किसी भी एक नोड और अन्य नोडों में से प्रत्येक के बीच मौजूद सीधी श्रृंखलाओं की औसत संख्या बताता है। जिन नोडों के बीच निकटतम मार्ग होता है उन्हें प्रणाली में हब के रूप में चिन्हित किया जाता है।

इन-बिटवीननेस सेंट्रलिटी : यह सांख्यिकीय पद्धति यह बताती है कि निकटतम मार्ग की दूरियां किस प्रकार एक विशिष्ट नोड के बीच से होकर गुजरती हैं।

केंद्रीयता का आईजेनवेक्टर माप : किसी नेटवर्क में किसी नोड (बैंक) का क्या महत्व है, इसे आईजेनवेक्टर केंद्रीयता के द्वारा मापा जाता है। यह दर्शाता है कि किसी नोड के पड़ोसी उससे कितना संबद्ध हैं और यह उनकी बाहरी डिग्री या एक नोड के प्रत्यक्ष रूप से कितने 'पड़ोसी' हैं, उससे कहीं ज्यादा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह अल्गोरिथम नेटवर्क के सभी नोड्स को उससे संबंधित केंद्रीयता अंक प्रदान कर देती है और किसी नोड का केंद्रीयता अंक, उन सभी नोडों को दिए गए केंद्रीय अंकों के जोड़ के समानुपातिक होता है जिनसे वह जुड़ा होता है। किसी $N \times N$ मैट्रिक्स के लिए, इसमें N विभिन्न प्रकार के आईजेन मान होंगे और जिनके लिए आईजेनवेक्टर समाधान मौजूद होता है। प्रत्येक बैंक का अपना अलग आईजेन मान होता है जो प्रणाली में उसके महत्व को दर्शाता है। नेटवर्क विश्लेषण में इस पद्धति का उपयोग किया जाता है ताकि किसी बैंक के प्रणालीगत महत्व को स्थापित किया जा सके और यह अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है।

स्तरीकृत नेटवर्क संरचना : विशिष्ट रूप से वित्तीय नेटवर्क में स्तरीकृत संरचना का उपयोग देखा जाता है। स्तरीकृत संरचना एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें विभिन्न संस्थाएं अन्य नेटवर्क के साथ विविध अनुपातों में या स्तरों पर संबद्ध होती हैं। मौजूदा विश्लेषण में सर्वाधिक संबद्ध बैंक (केंद्रीयता के आईजेनवेक्टर के मापन के आधार पर) सबसे भीतरी केंद्र में होते हैं। इसके उपरांत बैंक मध्य केंद्र, बाहरी केंद्र और परिधि में (चित्र में केंद्र के चारों ओर संबंधित संकेंद्रित चक्रों में) उनकी संबद्धता के आधार पर रखा जाता है। बैंकों की संबद्धता की रैंज को प्रत्येक बैंक के आंतरिक डिग्री एवं बाह्य डिग्री के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उसे सर्वाधिक संबद्ध बैंक के ऐसे ही अनुपात से विभाजित किया जाता है। इस अनुपात के सर्वोच्च 10 प्रतिशत के भीतर आने वाले बैंक ही भीतरी केंद्र में स्थान पाते हैं। 90 और 70 प्रतिशत के बीच आने वाले बैंक मध्य केंद्र में वर्गीकृत किए जाते हैं और तीसरे स्तर पर 40 और 70 प्रतिशत के बीच की रैंकिंग वाले बैंकों को रखा जाता है। 40 प्रतिशत से कम संबद्धता अनुपात हासिल करने वाले बैंकों को परिधि पर स्थित बैंकों की श्रेणी रख दिया जाता है।

नेटवर्क चार्ट का कलर कोड : नेटवर्क चार्ट में नीली बॉल और लाल बॉल क्रमशः निवल ऋणदाता और निवल उधारकर्ता को दर्शाती हैं। स्तरीकृत नेटवर्क चित्र में लिंकों की कलर कोडिंग नेटवर्क में विभिन्न स्तरों से लिए गए उधार को दर्शाती है (उदाहरण के लिए हरा लिंक भीतरी केंद्र में स्थित बैंकों से लिए गए उधार को दर्शाता है)।

ऋण-शोधन क्षमता संक्रमण का विश्लेषण

संक्रमण विश्लेषण एक प्रकार से दबाव परीक्षण ही होता है जिसके द्वारा एक या एक से अधिक बैंकों के फेल होने के कारण पैदा होने वाले डोमिनो प्रभाव से बैंकिंग प्रणाली को हुए सकल नुकसान का पता लगाया जाता है। इसके तहत हम संक्रमण के उतार-चढ़ाव का अंदाजा लगाने के लिए राउंड बाई राउंड या क्रमिक अलॉगर्थिम के नियमों का प्रयोग करते हैं जिससे आजकल फरपाइन (2003) के द्वारा सभी परिचित हैं। चलिए, एक ट्रिगर बैंक i से शुरुआत करते हैं जो समय 0 में फेल हो जाता है, हम प्रत्येक राउंड या दोहराव के समय संकट में फंसने वाले बैंकों के सेट को D_q , से प्रदर्शित करेंगे, जहां $q=1, 2, \dots$ होगा। इस विश्लेषण हेतु किसी बैंक का मुख्य सीआरएआर 6 प्रतिशत से कम हो जाने पर उसे संकटग्रस्त माना गया है। निवल प्राप्त राशियों को प्राप्तकर्ता बैंक के लिए हानि माना गया है।

चलनिधि संक्रमण विश्लेषण

जहां ऋण शोधन क्षमता संक्रमण के विश्लेषण में निवल उधारकर्ता के असफल होने के कारण प्रणाली को होने वाली संभावित हानि का आकलन किया जाता है, वहीं चलनिधि संक्रमण विश्लेषण में किसी निवल ऋणदाता के असफल होने के कारण प्रणाली को होने वाली हानि का अनुमान लगाया जाता है। विश्लेषण बैंकों के बीच सकल एक्सपोजर के आधार पर किया जाता है। एक्सपोजरों में निधि और डेरिवेटिव आधारित एक्सपोजर शामिल होते हैं। इस विश्लेषण के लिए मूल धारणा यह है कि किसी बड़े निवल ऋणदाता के असफल होने के कारण उत्पन्न हुए चलनिधि दबाव से निपटने के लिए कोई बैंक प्रारंभ में चलनिधि आरक्षित निधि अथवा बफर का उपयोग करेगा। चलनिधि आरक्षित निधि के अंतर्गत आने वाली मदों में (क) सीआरएआर का अधिशेष अतिरिक्त

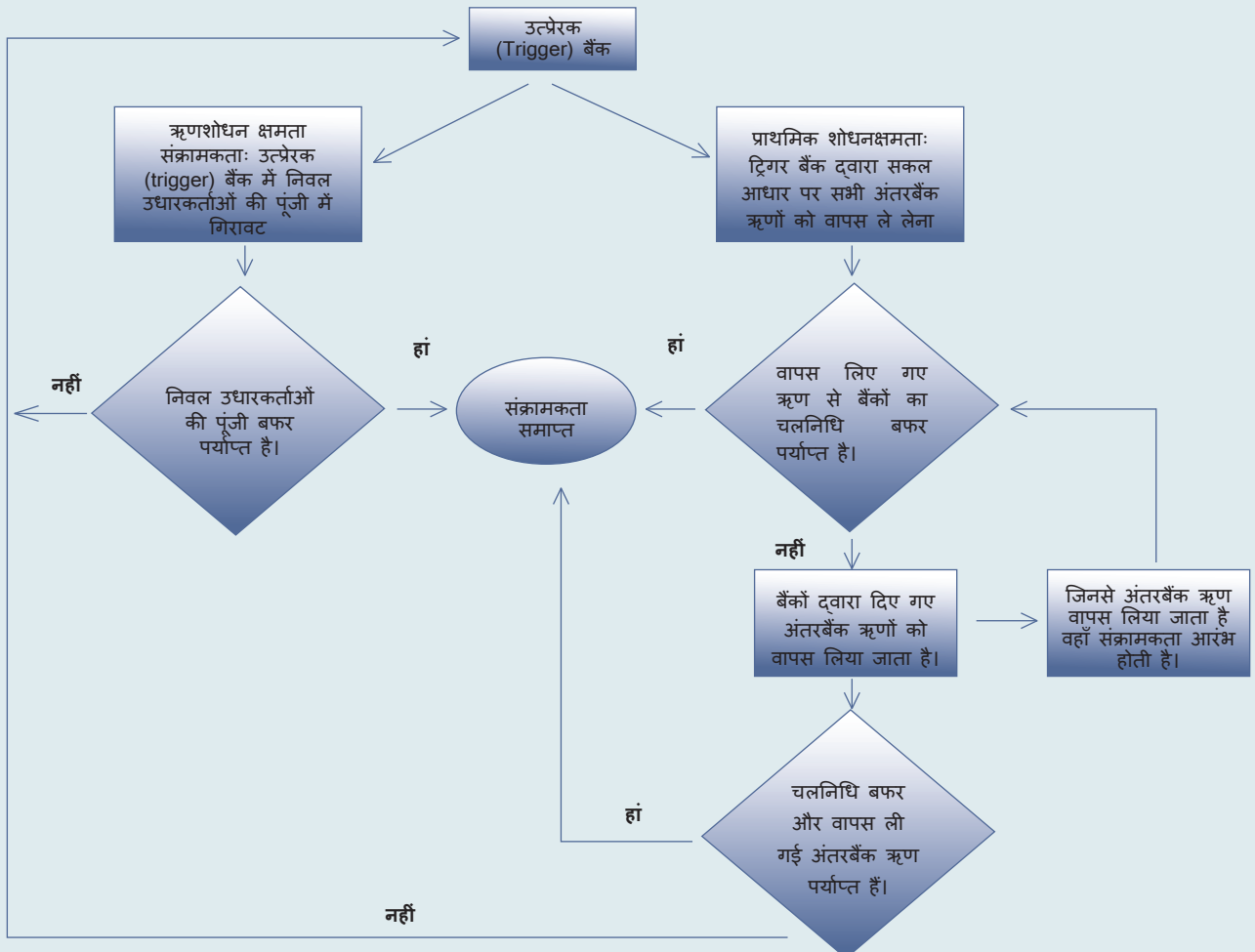
(ख) एसएलआर शेष का अतिरिक्त (ग) उपलब्ध मार्जिनल स्थायी सुविधा और (डी) उपलब्ध निर्यात क्रेडिट पुनर्वित्त शामिल है। यदि बैंक केवल चलनिधि बफर की सहायता से दबाव से निपटने में सक्षम होता है तो फिर इससे आगे कोई संक्रमण नहीं होता है।

तथापि, यदि केवल चलनिधि बफर पर्याप्त नहीं होते हैं तो तब बैंक को उन सभी ऋणों को वापस लेना होगा जो 'वापस लेने योग्य' हैं और जिनके परिणामस्वरूप संक्रमण होता है। यदि विश्लेषण करने के लिए देखा जाए तो केवल अल्पावधि की आस्तियां जैसे कि कॉल मार्केट में उधार दी गई राशि और अन्य बहुत ही अल्पावधि के लिए दिए गए ऋणों को ही वापस लेने योग्य कहा जा सकता है। इसके स्थिति के बाद किसी बैंक का अस्तित्व या तो बना रह सकता है या उसका परिसमापन करना होगा। इस मामले में इस प्रकार के उदाहरण भी हो सकते हैं कि जहां ऋणों की वापसी होने से बैंक का अस्तित्व तो बच गया हो परन्तु इसके कारण होने वाले संक्रमण से अन्य बैंकों के सामने संकट पैदा हो सकता है। इसमें प्रयुक्त दूसरी धारणा यह है कि जब किसी बैंक का परिसमापन किया जाता है तो उस बैंक द्वारा दिए गए ऋणों को सकल गणना के आधार पर वापस मांगा जा सकता है जबकि परिसमापन किए बिना जब बैंक द्वारा दिए गए अल्पावधि ऋणों को वापस मांगा जाता है तो ऋण को निवल आधार पर वापस मांगा जाता है (इस अनुमान के अनुसार, प्रतिपक्षी अपने उसी प्रतिपक्षी के प्रति पहले अपनी अल्पावधि उधारी को कम करना चाहेगा)।

संयुक्त ऋण-शोधन चलनिधि संक्रमण का विश्लेषण

सामान्यतः किसी बैंक की कुछ बैंकों के प्रति सकारात्मक निवल उधारी की स्थितियां और कुछ अन्य बैंकों के प्रति ऋणात्मक निवल उधारी की स्थितियां - दोनों ही होती हैं। इस प्रकार किसी बैंक के विफल हो जाने पर ऋणशोधन संक्रमण तथा चलनिधि संक्रमण दोनों साथ-साथ पैदा हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित फ्लोचार्ट द्वारा बताया गया है :

किसी बैंक के दबाव में आने के कारण संयुक्त ऋणशोधन - चलनिधि संक्रामकता संबंधी फ्लोचार्ट



यह माना जाता है कि प्रारंभकर्ता यानी ट्रिगर बैंक अपने कुछ अंतर्निहित कारण से विफल हुआ अर्थात् यह दिवालिया हो जाता है और इस प्रकार अपने सभी उधारकर्ता बैंकों को प्रभावित करता है। इसी के साथ वह अपनी आस्तियों का परिसमापन शुरू कर देता है ताकि जहां तक संभव हो यह अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। परिसमापन प्रक्रिया के कारण एक चलनिधि संकट उत्पन्न होता है क्योंकि प्रारंभकर्ता बैंक अपने दिए गए ऋणों को वापस मांगाना प्रारंभ कर देता है।

भलीभांति पूंजीकृत ऋणदाता/उधारकर्ता बैंक इस आघात को सह कर अपना अस्तित्व बचा लेते हैं और वे दूसरे बैंकों में इसका संक्रमण नहीं जाने देते। इसके विपरीत, वे ऋणदाता बैंक जिनकी पूंजी एक निश्चित सीमा से कम हो जाती है वो एक नया संक्रमण प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार वे उधारकर्ता बैंक जिनका चलनिधि बफर पर्याप्त होता है वे भी आगे बिना कोई संक्रमण फैलाए, दबाव को सहन कर लेते हैं। परन्तु कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो चलनिधि दबाव का सामना करने में तभी सक्षम हो पाते हैं जब वो अपनी अल्पावधि आस्तियों को वापस मांग लेते हैं। अल्पावधि आस्तियों को वापस मांगने की प्रक्रिया से वे पुनः एक नया संक्रमण प्रारंभ कर देते हैं।

ऋणशोधन क्षमता और चलनिधि दोनों तरफ से ही संक्रमण तभी रुक पाएगा / स्थिर हो पाएगा जब, प्रणाली हानि/आघातों को पूर्णतः अपने भीतर सह ले और भविष्य में उसमें कोई संकट न उभरे।